



Dr. Madhukarrao Wasnik
PWS Arts and Commerce College
Kamptee Road, Nagpur-26

Bibliometrics of the Publication During the year 2017-2018

Se	Title of the Paper	Name of the Author	Title of the Journal	Year of the Publication	Citation Index	Institutional Affiliation as mentioned in the Publication	Number of Citations excluding self-citations
1.	Vimudrikaranka Bhartiya Arthvyavshthapar Prabhav	Dr. Pradnya M. Bagade	Indian Streams Research Journal Vol-7 Issue- 4 ISSN : 2230- 7850	May 2017	Impact Factor 5.1651 (UIF)	-	-
2.	Sheti Aadharit Udyog V Gramin Vikas		Review of Research UGC Approved Vol-6 Issue- 10 ISSN : 2249-894X	July 2017	Impact Factor 3.8014(UIF)	-	-
3.	Bhartatil Daridryacha Abhyas	Dr. Pradnya M. Bagade	Review of Research UGC Approved Vol-6 Issue- 11 ISSN : 2249-894X	Aug- 2017	Impact Factor 5.2331 (UIF)	-	-

4.	Bhartatil Anna Suraksha Swarup V Upay	Dr. Pradnya M. Bagade	Perspectives A National Peer Reviewed Interdisciplinary Research Journal Vol-1 Issue- VII ISSN: 2249 - 5134	Aug 2017	-	Dr.M.W.P.W.S. Arts & Commerce College, Nagpur	--
5.	Chandrapur Jilhyatil Ekatmik Aadivasi Vikas Prakalpaantargat Aadivasinna Rabvinyat Yenarya Krushi V Sanlagna Yojanancha Abhyas	Dr. Pradnya M. Bagade	Riview of Literature Vol- 5 Issue- 9 ISSN : 2347- 2723	April 2018	Impact Factor 3.3754 (UIF)	-	-

Bibliometrics of the Publication During the year 2018-2019

Sr. No	Title of the Paper	Name of the Author	Title of the Journal	Year of the Publication	Citation Index	Institutional Affiliation as mentioned in the Publication	Number of Citations excluding self-citations
1.	Vastu V Seva Karanche Swarup, Fayde, Tote V Parinaam : Ek Aadhava	Dr. Pradnya M. Bagade	Review Of Research Volume-8 Issue-3 ISSN: 2249-894X	Dec- 2018	Impact Factor-5.7631 (UIF)	-	-
2.	Shabari Adiwasi Vitta V Vikas Mahamandal Ek Drushtikshep	Dr. Pradnya M. Bagade	AJANTA Volume- VIII Issue-I ISSN: 2277- 5730	March-2019	Impact Factor-6.399	-	-

Bibliometrics of the Publication During the year 2019-20

Sr. No.	Title of the Paper	Name of the Author	Title of the Journal	Year of the Publication	Citation Index	Institutional Affiliation as mentioned in the Publication	Number of Citations excluding self-citations
1.	Dr. Babasaheb Ambedkaranche aarthik Vichar	Dr. Pradnya Bagade	Review of Research Vol. 8, Issue – 9 ISSN 2249- 894X	June- 2019	-	-	-
2.	Bharatatil Paryatan Udyog : Ek Aarthik Adhyayan	Dr. Pradnya Bagade	Review of Research Vol. 8, Issue – 9 ISSN 2249-894X	June- 2019	-	-	-
3.	Krushi aadharit Udyog v Gramin Vikas	Dr. Pradnya Bagade	Research Journey	21 Dec. 2019	-	-	-

			ISSN- 2348-7143				
4.	Vidarbhatil Ambedkari Chalvalit Mahilanche Yogdan	Dr. Pradnya Bagade	Perspectives Peer Reviewed Vol-1 Issue-VIII ISSN 2249-5134	Feb. 2020	-	-	-
5.	Maharashtrachya Aarthik Vikasat Chhatrapati Shivaji Maharajanचे Yogdan	Dr. Pradnya Bagade	Printing Area Vol – 2 Issue – 65 ISSN- 2394-5303 Impact Factor- 7.387 (UIF)	May 2020	-	-	-

Bibliometrics of the Publication During the year 2020-2021

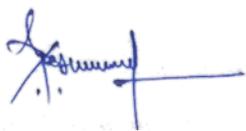
Sr. No.	Title of the Paper	Name of the Author	Title of the Journal	Year of the Publication	Citation Index	Institutional Affiliation as mentioned in the Publication	Number of Citations excluding self-citations
1.	Corona Mahamari Ani Kendra Sarkarche Arthik Pyakej	Dr. Pradnya Bagade	Perspectives, A National Interdisciplinary Annual Research Journal Vol-1 - IX Issue IX ISSN- 2249-5134 Peer Reviewed	July 2020	-	Dr. MWPWS Arts, Commerce & Science College, Nagpur	-
2.	Corona Mahamarimule Stalantarit Majur v Sheti Skhetrawar Zalele Parinam	Dr. Pradnya Bagade & Prof. Alka Patil	Perspectives, A National Interdisciplinary Annual Research Journal Vol-1 Issue- IX ISSN- 2249-5134 Peer Reviewed	July 2020	-	Dr. MWPWS Arts, Commerce & Science College, Nagpur	-

Bibliometrics of the Publication During the year 2021-2022

Sr. No.	Title of the Paper	Name of the Author	Title of the Journal	Year of the Publication	Citation Index	Institutional Affiliation as mentioned in the Publication	Number of Citations excluding self-citations
3	Sarvasamaveshak Vikasache Janak : Gautam Buddha	Dr. Pradnya Bagade	Perspectives, A National Peer Reviewed Resarch Journal Volume- Issue- ISSN -2249-5134	2021	-	Dr. Madukarrao Wasnk P.W.S. Arts, Commerce And Science College, Nagpur.	-

Bibliometrics of the Publication During the year 2022-2023

Sr. No.	Title of the Paper	Name of the Author	Title of the Journal	Year of the Publication	Citation Index	Institutional Affiliation as mentioned in the Publication	Number of Citations excluding self-citations
01.	Swatantrottar Kalatil Bhartacha Aarthik Vikas : Ek Adhyayan	Dr. Pradnya M. Bagade	Perspectives A National Interdisciplinary Annual Research Journal Peer Reviewed ISSN 2249-5134	2022		Dr. Madukarrao Wasnik P.W.S. Arts, Commerce And Science College, Nagpur.	-
02.	An Economic Study of Various Housing Schemes In India	Dr. Pradnya M. Bagade	Review of Research International Recognition Multidisciplinary Research Journal ISSN 2249-894X	Apl-2023	Impact Factor 5.7631 (UIF)	-	-



Principal

Dr. Yeshwant Patil

INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL

International Recognition Multidisciplinary Research Journal

Volume - 7 | Issue - 4 | May - 2017

5.1651(UIF) 2230-7850

विमुद्रीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था
पर प्रभाव



डॉ. प्रज्ञा बागडे

प्रज्ञा बागडे

उपप्राचार्य, विभागप्रमुख-अर्थशास्त्र, पी. डब्ल्यू. एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, नागपुर.

सारांश - 08 नवम्बर, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण का ऐलान किया। इस विमुद्रीकरण में सरकारने 500 एवं 1000 रुपये की नोटों की जगह 500 और 2000 रुपये की नयी नोटें जारी किये। सरकार का इस नोटबंदी का उद्देश काला धन निकालना, आतंकवाद व नक्सलवाद की बुनियादी ताकदे निर्बल करना, टैक्स चोरी के लिये नगद कृ

Editor - In - Chief - H. N. Jagtap



Scanned with OKEN Scanner



विमुद्रीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

डॉ. प्रज्ञा बागडे

उपप्राचार्य, विभागप्रमुख-अर्थशास्त्र, पी. डब्ल्यू. एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, नागपुर.

सारांश

०८ नवम्बर, २०१६ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण का ऐलान किया। इस विमुद्रीकरण में सरकारने ५०० एवं १००० रुपये की नोटों की जगह ५०० और २००० रुपये की नयी नोटें जारी किये। सरकार का इस नोटबंदी का उद्देश काला धन निकालना, आतंकवाद व नक्सलवाद की बुनियादी ताकदे निर्वल करना, टैक्स चोरी के लिये नगद लेनदेन को हतोस्ताहीत करना था। विमुद्रीकरण एक साहसी एवं मौलीक आर्थिक सुधार की पहल है। परंतु इस से देश में खलबली मच गयी, अफरातफरी भी हुयी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पडा। लेनदेन पुरी तरह से सामान्य होने में कुछ महीने लगे। निश्चय ही इस महत्वपूर्ण परिवर्तन पर लागत लगेगी ही लेकीन भविष्य में इससे पर्याप्त लाभ होने की संभावना है।

बीज शब्द विमुद्रीकरण, नोटबंदी, भ्रष्टाचार, कालाधन, नक्सलवाद, कॅशलेश

प्रस्तावना

८ नवम्बर, २०१६ को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा कदम उठाते हुये ५०० और १००० रुपये के नोटों को रात १२ बजे से बंद किये जाने की घोषणा की। सरकार का नोटबंदी करने का उद्देश काला धन बाहर निकालना था। भारत सरकार का मानना था की नोटबंदी से आतंकवाद एवं नक्सलवाद की बुनियादी ताकदे निर्वल हो जायेंगी। देश में शांतीव्यवस्था कायम होगी एवं देश के दुश्मन भी धन उपलब्ध न होने से निर्वल हो जायेंगे। हालांकि, नोटों के प्रयोग और नोट बदलने के लिए ३० दिसम्बर २०१६ तक देश के किसी भी बैंक, डाकघर में जाकर अपने खातों में जमा कर बदलने की सुविधा दी गयी। सरकारने पुराने नोटों की जगह ५०० और २००० के नये नोट जारी किये जो लोगों को बैंको एवं एटीएम के माध्यम से मिलने शुरू हो गये। लेकीन लेनदेन के पुरी तरह सामान्य होने में कुछ महिने लगे और अफरा-तफरी भी

मची। संपूर्ण भारत की अर्थव्यवस्था पर परिणाम। इससे सकारात्मक के साथसाथ नकारात्मक भी परिणाम हुये जिसका अध्ययन होना आवश्यक है।

अनुसंधान का उद्देश

विमुद्रीकरण क्या है, सरकार इस का फैसला क्यों लेती है, भारत में ऐसा कब-कब हुआ है, इस विमुद्रीकरण का जनता पर एवं अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पडा है, इसका अध्ययन होना आवश्यक है। इन्ही उद्देशों को लेकर शोधपत्र प्रस्तुत किया गया है।

परिकल्पनाएँ

१. सरकार का एक साहसी निर्णय।
२. भ्रष्टाचार एवं कालेधन को रोकने के लिये विमुद्रीकरण आवश्यक है।
३. ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक

परिणाम।

क्या है विमुद्रीकरण ?

विमुद्रीकरण का सही तात्पर्य है की जब किसी देश की सरकार अपनी पुरानी मुद्रा को कानुनी रूप से बंद कर देती है, तो इस प्रक्रिया को विमुद्रीकरण कहते हैं। विमुद्रीकरण होने के बाद उस मुद्रा की कोई कीमत नहीं रह जाती है और सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को बदलने की प्रक्रिया एक निश्चित समय के लिये प्रारम्भ की जाती है।

क्यों किया जाता है विमुद्रीकरण ?

मुद्रा कि जमाखोरी, आतंकवाद, अपराध और तस्करी जैसे अपराधिक कामों में भी बडे पैमाने पर नगद लेन-देन होता है, इन सब कामों में लिप्त कई लोग कई बार अधिक मात्रा में नगद राशी अपने पास जमा रखते है। बाजार



में नकली नोट भी प्रचलन में आ जाते हैं। सरकार इन से छुटकारा पाने के लिये पुराने नोट देती है। और नयी तकनीकी से तैयार किये गये ज्यादा सुरक्षित नोट लाती है इतनाही नहीं तो टैक्स चोरी के लिए किये जाने वाले नगद लेनदेन को हतोत्साहित करने के लिये भी सरकार कई बार विमुद्रीकरण का निर्णय लेती है।

भारत में कब-कब हुआ विमुद्रीकरण ?

भारत के साथ-साथ बहुत देशों जैसे पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, घाना, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, इत्यादी देशों में नोटबंदी बहुत वर्ष पहले से ही प्रचलित है। भारत में पहली बार स्वतंत्रता के बाद जनवरी १९४६ में १००० और १०,००० रुपये के नोटों को वापस ले लिया गया था और १०००, ५००० और १०,००० रुपये के नोट १९५४ में पुनः शुरू किये गये थे। १६ जनवरी १९७८ को जनता पार्टी की गठबंधन सरकार ने फिरसे १०००, ५००० और १०,००० रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया था ताकी नकली नोटों और काले धन पर अंकुश लगाया जा सके।

कई बार सरकार पुराने नोट को धीरे-धीरे भी बंद करती है और उसकी जगह उतने ही मूल्य की नई नोट जारी कर देती है। जैसे वर्ष २००५ में मनमोहन सिंग कौंग्रेस नीत सरकार ने ५०० के २००५ के पहले के नोटों का विमुद्रीकरण किया था। वर्ष २००५ से पहले छपे ५०० के नोटों पर वर्ष अंकीत नहीं होता था। सरकार ने बाजार में चल रहे ५०० के नकली नोटों और कालेधन को खत्म करने के लिए यह फैसला लिया था।

८ नवंबर, २०१६ को नरेन्द्र मोदी (बीजेपी) सरकार ने भी विमुद्रीकरण का ऐलान किया प्रधानमंत्री की आधिकारिक घोषणा के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल और आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन में बताया की, सभी मूल्यवर्ग के नोटों की आपूर्ति में २०११ और २०१६ के बिच ४० की वृद्धि हुयी थी। ५०० और १००० रुपये की नोटों की इस अवधि में क्रमशः ७६ और १०८ की वृद्धि हुयी। इस जाली नगदी को भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप नोटों को खत्म करने का निर्णय लिया गया।

साहित्य का पुनरावलोकन

ऑनलाईन एवं वृत्तपत्र प्रतिक्रियाएँ

- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने इस कदम को राष्ट्र की प्रगती में मील का पत्थर बताते हुये साहसीक कदम बताया. उन्होंने कहा की, काले धन के खिलाफ इस लड़ाई में भारत की जनता सच्चे सैनिकों की तरह सहभागी होगी।
- बिहार के मुख्यमंत्री नितिशकुमार ने विमुद्रीकरण का समर्थन किया, और कहा की, यह शेर की सवारी करने जैसा साहसिक निर्णय है।
- मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा की, यह आम आदमी के लिए वास्तविक आजादी है।
- संस्कृती मंत्री महेश शर्मा ने डिट किया की, भ्रष्टाचार, कालेधन और आतंकवाद से लडने के लिए ऐतिहासिक कदम है।
- केजरीवाल ने नोटबंदी को बताया बडा घोटाला, कहा बीजेपी ने अपने दोस्तों को पहले ही आगाह कर दियाएनडीटीवी१२ नवंबर २०१६
- नोटबंदी पर सांसद में हंगामा, सडक पर बिखर गया विपक्ष का भारत बंद (नवभारत टाइम्स)
- केरल की माकपा नीत एलडीएफ सरकार ने सरकार के इस आकस्मिक ऐलान की आलोचना करते हुये कहा की, इस कदम से देश से काला धन खत्म नहीं होगा। केरल के वित्तमंत्री टी. एम. थोमस इसाक ने कहा की, ५०० और १००० के नोट को बंद करना काले धन की समस्या का निवारण नहीं है पूरा कालाधन इस रूप में नहीं होता, बहुत सारा धन विदेशों में जमा है और हवाले के रास्ते से आता है।

विमुद्रीकरण का सकारात्मक प्रभाव

- किसी भी अर्थव्यवस्था से काला धन तबतक खत्म नहीं किया जा सकता जब तक सामाजिक स्तर पर इसका बहिष्कार न हो अभी तक काले धन का निवेश प्रॉपर्टी और सोना-चांदी में किया जाता था जिसमें इनकी कीमत वास्तविक कीमत से हमेशा अधिक रहती थी, अब नोटबंदी के बाद इन क्षेत्रों में कालेधन के इस्तेमाल पर कुछ मात्रा में अंकुश लगेगा।
- देश में सीमापार से नकली नोटों के प्रवाह की गंभीर समस्या थी। सरकार को इसके रोकथाम के लिये नेटवर्क का सहारा लेना पडता था। इस निर्णय से एक झटके में देश से नकली नोट साफ होने में सहायता मिली है। वही नई नोटों के सुरक्षा मानक ज्यादा पुख्ता होने के कारण अर्थव्यवस्था कुछ प्रतिशत नकली नोटा से सुरक्षित रह सकती है।
- कॅशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए जरूरी है की देश में ज्यादा से ज्यादा ट्रांझैक्शन डिजीटल माध्यमों से किया जाए, इससे नगद पर देश की निर्भरता कम होगी। रिजर्व बैंक और अन्य बैंको के साथ-साथ केन्द्र सरकार को नोटों पर कम खर्च करना पडेगा। कॅशलेस इकोनॉमी का फायदा सरकार के साथ-साथ आम आदमी को भी होगा क्योकी उसका पैसा डिजीटल आदान प्रदान में ज्यादा सुरक्षित रहेगा।
- बीते कई दशकों से रियल इस्टेट सेक्टर काले धन के निवेश का सबसे बडा जरीया था। जिस कारण कागजों पर प्रॉपर्टी की खरीद और वास्तविक खरीद में बडा अंतर होता था। इससे सरकार को स्टैप ड्यूटी में बडा नुकसान होता था, जो अभी निश्चित रूप से कम होने की संभावना है।
- नोटबंदी का एक सकारात्मक पहलू यह भी है की, वित्तीय जगत में पारदर्शिता के साथसाथ बैंक अपना कारोबार फैलाने के लिये ज्यादा से ज्यादा कर्ज देने की कोशिश करेंगे। ब्याज दरों में कटीती का ऐलान कर घर खरीदने, कार या अन्य वाहन खरीदने अथवा कारोबार के लिए कर्ज सस्ते दरों में उपलब्ध होगा।
- नोटबंदी से कालेधन पर लगाम के साथसाथ तेजी से बढ़ते डिजिटल पेमेंट से अब बैंको की कमाई में बडा इजाफा देखने को मिलेगा। बैंको के पास एकत्रित हुये धन से उन्हे पुराने घाटे में भी मदत मिलेगी।
- देश में ५०० और १००० रुपये की प्रतिबंधीत करेंसी कुल करेंसी की ८५ प्रतिशत थी। यह दोनो करेंसी देश में भ्रष्टाचार की पोशक थी। नोटबंदी के फैसले के बाद से ही भ्रष्टाचार के लिये करेंसी का इस्तेमाल रुक गया है।

विमुद्रीकरण का नकारात्मक प्रभाव

- भारत एक कृषीप्रधान देश है। ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषीपर निर्भर है। ऐसे में खेती के महत्वपूर्ण समय में नोटबंदी के आदेश से सभी काम बंद हो गये ७० से ८० प्रतिशत उत्पादन खेतों में पड़ा था। मुद्रा के अभाव में किसान उत्पादन की ना ही बिक्री कर पा रहे थे और ना ही मजदुरों को मजदुरी दे पा रहे थे। इस कारण अच्छी फसल होने पर भी उन्हें उचित मूल्य नहीं मील पाया। उनके लिये नोटबंदी आपत्ती बन गयी थी।
- लघु तथा कुटीर उद्योगों के व्यवहार साधारणतः कम पैसे के होते हैं। नोटबंदी के कारण उनके पास नगद पैसा उपलब्ध नहीं हो रहा था जिसके परिणाम स्वरूप उनके व्यवहारों पर बहुत अधिक मर्यादाएँ आ गयी थी। विमुद्रीकरण के कारण नगद की कमी निर्माण हुयी जिस कारण कुल आर्थिक व्यवहार सीमित हो गये।
- विमुद्रीकरण के कारण बैंक कर्मचारी तथा अन्य लोग भी नगद प्राप्ती के लिये एवं मुद्रा परिवर्तन के लिये गलत तरीके अपनाने लगे थे।
- विमुद्रीकरण के कारण भ्रष्ट लोगोंद्वारा जनधन एवं नकली खातों का सहारा लेके अपने काले धन को सफेद करने के प्रयास किये गये हैं।
- विमुद्रीकरण के फैसले से लघु व्यवसाय जैसे टेलेवाले, रिक्शावाले, सब्जीवाले इत्यादी पर खासा प्रभाव पडा है। लघु व्यवसाय के साथसाथ बडे व्यापारों पर भी प्रभाव पडा है।
- लम्बीलम्बी कतारों व भीडभाड में दिल का दौरा पडने से, अस्पतालों में उपचार न मिल पाने के कारण व आत्महत्या की वजह से कई लोगों की मृत्यू की खबर सामने आयी है।
- विमुद्रीकरण के प्रक्रिया में नये नोटों की कमी के कारण तथा देश के कोनोंकोनों में नयी मुद्रा पहुचाने मे असमर्थ होने के कारण बाजार में अघोषित बंदी की स्थिती निर्माण हुयी।
- जो व्यक्ती परिश्रम से अपनी जीविका कमाता है उसे अपना ही धन प्राप्त करने के लिए बाहर लम्बी कतारों में लगना पडा है।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अधिकांश व्यवहार नगद किये जाते है तथा कॅशलेस व्यवहार का अज्ञान होने के कारण एक प्रकार का भय आज भी जनता के मन में है।

निकर्ष

- विमुद्रीकरण हर दस वर्ष में होना चाहीये यह विख्यात अर्थशास्त्री डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने अपने प्रबंध में लिखा है। विमुद्रीकरण से आर्थिक विकास में परिवर्तन आयेगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाना है तो विमुद्रीकरण करना जरुरी है।
- सामान्य तौर पर देखा और कहा जा सकता है की, यह नक्सलवाद को गहरा धक्का है और भ्रष्ट लोगों में बेचैनी आयी है। रियल इस्टेट में दाम कम हो रहे हैं। भ्रष्टाचार में भी भारी कमी आने की उम्मीद है।
- भारत एक नगदचलीत अर्थव्यवस्था है, जब की, जनसंख्या का एक बड़ा भाग तेजी से तकनीक प्रेमी भी बनता जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक लेनदेन के डिजिटलीकरण की दिशा में बढेगी और नगद मुद्रा की भूमिका कम होगी।
- देश में समानांतर अर्थव्यवस्था ने गहरी जडे जमा ली है, जिसके कारण बडे पैमाने पर हवाला लेनदेन, कर चुकाना, बेनामी अचल संपत्ती खरीद, सोने की तस्करी जैसी अवैध गतिविधीयों होती रही है, जिसे रोका जाना जरुरी था, इसलिए विमुद्रीकरण आवश्यक था।
- भारत में विमुद्रीकरण के निर्णय से प्रभावित होकर कुछ अन्य देशों में भी विमुद्रीकरण का निर्णय लिया है जिसमे व्हेनेजुएला और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में अल्पकाल में इस विमुद्रीकरण के कुछ नकारत्मक प्रभाव है, लेकिन दीर्घकाल में अधिक अच्छे, सकारात्मक एवं विकासात्मक परिणाम आयेंगे ऐसी आशा करते हैं।

संदर्भसूची

1. <https://hi.oxforddictionaries.com/> परिभाषा / विमुद्रीकरण
2. https://hindi-webdunia-com/national&hindi&news/demonetization&116120300035_1.html.
3. ५०० और १००० का नोट बंद होने से शेयर बाजार में हाहाकार - बीबीसी - ६ नवम्बर, २०१६
4. नोटबंदी का असर : मणीपुर में अखबारों के दफ्तर हुये बंद - एनडीटीवी - १८ नवम्बर, २०१६.
5. नोटबंदी : जागरण के सर्वे मे ८५ फिसद देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ, (दैनिक जागरण)
6. दै. सकाळ - २२ नवम्बर २०१६.
7. दै. भास्कर - २२ नवम्बर २०१६.
8. पुण्यनगरी - २२ नवम्बर २०१६.

Review of Research



International Online Multidisciplinary Journal

Volume - 6 | Issue - 10 | July - 2017

3.8014(UIF) 2249-894X

शेती आधारित उद्योग व ग्रामीण विकास



प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे

प्रज्ञा बागडे

उपप्राचार्य व विभागप्रमुख, अर्थशास्त्र, पी. डब्ल्यू. एस. कला व वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर.

सारांश :- कृषी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मूलाधार आहे. भारतातील 68 : लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते व त्यातील 58 : लोकसंख्या उपजीविकेसाठी कृषी क्षेत्रावर विसंबून आहे. मोठ्या प्रमाणावरील दारिद्र्या हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे लक्षण असलेले दिसून येते आणि ग्रामीण दारिद्र्या हे बेरोजगारी पृष्ठ क्र. - 01

Editor - In - Chief - Ashok Yakkaldevi





Sr. No	Title And Name Of The Author (S)	Page No
1	शेती आधारित उद्योग व ग्रामीण विकास प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे	1
2	बौद्ध साहित्याची मूलतत्त्वे प्रा. डॉ. विश्वजीत कांबळे	5
3	Efficacy Of Labour Absenteeism In India: An Assessment M. Krishnappa and T. Rajendra Prasad	11
4	A Study Of Social Condition Of The Kota Tribes In Nilgiris District, Tamilnadu K. Reena	18
5	A Comparative Study Of Teaching Competencies Of Teacher Trainees In Two Year And Four Year B.Ed. Programmes Dr. Siddharth Shukla	25
6	Making Sense Of 'Intolerance' Upasona Khound	31
7	Atmospheric Biopollution In Urban And Suburban Area Of Western Mumbai Sunil A. Gosavi	34

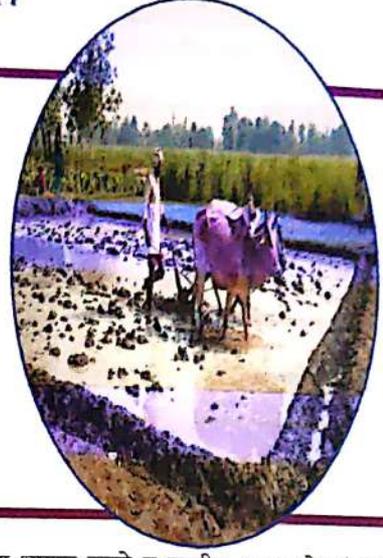


शेती आधारित उद्योग व ग्रामीण विकास

प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे

उपप्राचार्य व विभागप्रमुख, अर्थशास्त्र,

पी.डब्ल्यू.एस.कला व वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर.



प्रस्तावना :

कृषी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मूलाधार आहे. भारतातील ६८ : लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते व त्यातील ५८ : लोकसंख्या उपजीविकेसाठी कृषी क्षेत्रावर विसंबून आहे. मोठ्या प्रमाणावरील दारिद्र्या हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे लक्षण असलेले दिसून येते आणि ग्रामीण दारिद्र्या हे वेरोजगारी व अल्परोजगारीचे फलन आहे. कृषीप्रधान राष्ट्रांचा विकास हा त्या देशातील ग्रामीण विकास व शेती आधारित उद्योगांच्या विकासावर अवलंबून असतो. स्थानिक कच्च्यामाल, कमी भांडवल, अल्प तंत्रज्ञान, रोजगारीची अधिक क्षमता इ. दृष्टीकोनातून शेती आधारित उद्योग हे ग्रामीण भागात स्थापन होतात त्यामुळे त्यांची ग्रामीण भागाच्या विकासातील भूमिका महत्वाची ठरते.

ग्रामीण भागात रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधीची उपलब्धता करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागातील भांडवल व मनुष्य बळाचा प्रभावी वापर व्हावा यासाठी शेती आधारित उद्योगांची स्थापना करून कृषी क्षेत्राचा अर्थात ग्रामीण भागाचा विकास साधने शक्य आहे. प्रस्तुत शोधनिबंधात ग्रामीण भागातील शेती आधारित उद्योगांचे महत्व, त्यांच्या समस्या व संधी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

शेती आधारित उद्योग म्हणजे काय?

भारतातील शेती आधारित उद्योगास कृषी उद्योग, शेतीपूरक उद्योग, ग्रामीण उद्योग, शेती उद्योग असेही म्हटले जाते. ज्या उद्योगात शेतमालावर विविध प्रक्रिया केल्या जातात व ते उद्योग बहुतांशी ग्रामीण भागात सुरु केले जातात त्यांना शेती आधारित उद्योग म्हणतात. अनेक उद्योगधंदे याखाली येतात. उदा. - कापड उद्योग, तेलबिया व तेलापासून होणारी उत्पादने, तंबाखू, फळांवरील प्रक्रिया, मद्यार्क, साखर कारखाने, वनोत्पादने, लाकडाच्या वस्तू, चामड्याच्या वस्तू इ. उद्योगधंदे ह्या वर्गात मोडतात. अल्पभांडवलात आणि अल्पवेळात पूर्ण होणाऱ्या अनेक कृषी उद्योगांना अजूनही वाव आहे.

व्याख्या . The National Council of Applied Economics Research नुसार, 'शेतमालावर प्रक्रिया करणारे व शेतीसाठी लागणारी अवजारे, खते, बी.बियाणे, किटकनाशके इ. निर्माण करणाऱ्या उद्योगांना कृषी उद्योग म्हणतात'.

शेती आधारित उद्योग व इतर उद्योग यात फरक करण्याच्या दृष्टीने नियोजन आयोगाने चार निकष निश्चित केले आहे. हेच निकष पुढे राष्ट्रीय विकास परिषदेकडूनही मान्य करण्यात आले आहेत.

१. शेतीकरीता प्रभावी आदाने (Inputs) निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे.
२. शेतमालावर प्रक्रिया करण्यासाठी व त्यांचे रूपांतर करण्यासाठी मदत करणे.
३. प्रक्रिया केलेल्या वस्तूंना चांगला मोबदला मिळवून देण्याची खात्री देणे.
४. शेतीचे उत्पादन वाढविण्यास मदत करणे.

शेती आधारित उद्योगांचे महत्व .

भारत हा विकसनशील देश असून या देशाच्या ग्रामीण विकासात शेती आधारित उद्योगांची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरत आहे.

१. भारतातील गावांची समृद्धी व पुनर्निर्माण कृषी आधारित उद्योगांच्या माध्यमातूनच शक्य आहे. बिजेन्द्रनाथ बॅनर्जी यांनी विकसीत व औद्योगिक देशांच्या अनुभवावरून असे मत मांडले होते की, देशाच्या एकूण विकासात ग्रामीण व ग्रामीण विकासात कृषी उद्योग महत्वाचे आहेत. कृषी क्षेत्र व औद्योगिक क्षेत्र एकमेकांचे प्रतिस्थापन करू शकत नाही. त्यामुळे ते एकमेकांना पुरक आहेत म्हणून दोन्ही क्षेत्रांचा विकास साधणे गरजेचे आहे.
२. माजी पंतप्रधान मनमोहन सींग यांनी देखील राष्ट्रीय विकास परिषदेतील आपल्या भाषणात म्हटले होते की, कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी दिल्याशिवाय सर्व समावेशक विकासाचे ध्येय साध्य करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे विशेषतः लक्ष देण्याची गरज आहे.
३. ग्रामीण औद्योगिकरणामुळे भांडवलात गतीशीलता आणता येते. उद्योग कौशल्यामध्ये गतीशीलता आणता येते. ग्रामीण लोकांचे शहराकडे होणारे स्थलांतरण थांबवून खेडी ओस व शहरे बकाल होण्यापासून वाचविता येतात.
४. ग्रामीण भागाच्या समतोल विकासासाठी या उद्योगांचे योगदान जास्त आहे. हे उद्योग शहरात केंद्रीत न होता ग्रामीण भागात केंद्रीत होत असल्यामुळे शहरीकरणाचे वाढते दुष्परिणाम टाळता येतात व ग्रामीण भागाचे अस्तीत्व निर्माण होईल.

५. आपल्या देशात भांडवलचा तुटवडा असल्याने कमी भांडवलात हे उद्योग करता येतात. या उद्योगासाठी लागणारा कच्चा माल, हा स्थानिक स्वरूपाचा असल्याने तो कमी किंमतीस व गुणवत्ताधारक मिळतो. त्यामुळे या उद्योगातील उत्पादन कमी खर्चात होण्यास मदत होते.
६. ग्रामीण भागात शेती आधारित उद्योगांच्या विकासांमुळे सामाजिक व आर्थिक सुविधांचा विकास होतो. तसेच साटागूढे, बाजारपेठ, यांच्या विकासासाठी, निर्यात वृद्धी व सहकाराच्या विकास आणि ग्रामीण उपक्रमशीलतेसाठी या उद्योगांचे महत्त्व जास्त आहे.
७. या उद्योगांच्या विकासांमुळे लोकांना वाढत्या प्रमाणात रोजगार मिळत असून त्यांचे उत्पन्न वाढते. त्यामुळे त्यांची ग्रामीण वयत वाढत जाऊन भांडवल निर्मितीस हातभार लागतो.
८. जलद ग्रामीण औद्योगिकरणामुळे विकसनशील देशात रोजगारीच्या संधीमध्ये वाढ होते. ग्रामीण भागातील कृषी आधारित उद्योगात निर्माण झालेल्या रोजगारीमुळे तेथील कृषी क्षेत्राच्या भरभराटीस सहाय्य होते.
९. शेती आधारित उद्योग हे ग्रामीण भागात स्थापन होत असल्यामुळे ग्रामीण बेकारी व ग्रामीण दारिद्र्या कमी होण्यास मदत होते.
१०. कृषी आधारित प्रामोद्योगांमुळे औद्योगिक विकेंद्रीकरण करणे शक्य होते. राष्ट्रीय उत्पन्नाचे समान वितरण होण्यास मदत होते.
११. जगातील अनेक विकसनशील देशांनी ग्रामीण विकासासाठी कृषी आधारित उद्योगांना प्राधान्य दिले आहे.
१२. देशातील आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी व ग्रामीण क्षेत्राचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी या उद्योगांचे महत्त्व आहे.
१३. या उद्योगांमध्ये विविध प्रकारच्या वस्तू निर्माण केल्या जात असल्यामुळे अनेक वस्तूंची खरेदी एकाच छताखाली शक्य होते.
१४. आपल्या देशात नैसर्गिक साधन संपत्ती विपूल प्रमाणात असून तिचा पर्याप्त वापर होण्यासाठी शेती आधारित उद्योग महत्त्वाचे ठरतात.
१५. देशातील आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी व ग्रामीण क्षेत्राचे उत्पादन वाढविण्यासाठी या उद्योगांचे महत्त्व जास्त आहे.
१६. या उद्योगात औषधी वस्तूंचे उत्पादन होत असल्याने डोंगराळ व दुर्गम भागात वास्तव्य असलेल्या आदिवासी समाजाच्या विकासात मदत होते.
१७. पशुपालन, कुक्कुटपालन, मासेमारी, फळ प्रक्रिया इत्यादी उद्योगांसाठी अल्पप्रमाणात तांत्रिक ज्ञान लागते त्यामुळे उत्पादकास तांत्रिक ज्ञानाची आयात करावी लागत नाही.
१८. या उद्योगांचे स्वरूप लहान असल्याने ते अल्पशा जागेत सुरु करता येतात. त्यामुळे उत्पादकास स्थीर घटकांवर जास्तीचा खर्च करावा लागत नाही.
१९. शेती आधारित उद्योगांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत गुणात्मक परिवर्तन करणे शक्य होते.

शेती आधारित उद्योगांसमोरील समस्या.

- १९६० च्या दशकात भारत सरकारने मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. मूळात मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार म्हणजे आव्हानांचे पॅकेज होते.
 १. उद्योगाला लागणारा कच्चा माल साठवून ठेवण्याची पुरेशी व्यवस्था नसल्यामुळे केवळ तीन महीने पुरेल एवढाच कच्चा माल साठवून ठेवता येतो. तसेच तयार उत्पादन साठवून ठेवण्यासाठी व्यवस्था आवश्यक आहे. ती उपलब्ध नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करून महामान उत्पादनाचे फायदे घेता येत नाही.
 २. उत्पादकाला स्वतःला ग्राहकांना विक्री करणे शक्य नाही त्यामुळे मधली व्यापारी लोकांची जी साखळी असते त्यांना बराच वाटा जातो. व्यापाऱ्यांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर २४ प्रतिशत नफा प्राप्त होतो. याचाच अर्थ उत्पादन करणाऱ्या उत्पादकापेक्षा व्यापाऱ्याला १४ प्रतिशत अतिरिक्त नफा मिळतो म्हणजेच उत्पादकांना पुरेसा नफा मिळत नाही.
 ३. जिथे धान्य, फळे आणि भाजीपाला निर्माण होतो तिथे त्या प्रमाणात त्यांच्या संकलनाची, साठवणुकीची आणि निर्यातीसाठीच्या योग्य यंत्रणेची व्यवस्था उपलब्ध नाही परिणामी फळे आणि भाजीपाला यांचे जितके उत्पादन होते त्याच्या ४० टक्क्याहून अधिक उत्पादनाच्या साठवणुकीची योग्य व्यवस्था नसल्याने नासाडी होते. शेती क्षेत्रातील उत्पादकता ही एक चिंतेची बाब आहे.
 ४. उस आणि कापूस ह्या सारखी पिके पैशाची पिके म्हणून शेतकऱ्यांनी स्वीकारली असली तरी त्यांना मिळणाऱ्या दरांच्या तुलनेत त्यांचा उत्पादन खर्च तसेच देशातील आयात. निर्यात धोरण या सर्वांचा परिणाम या पिकांच्या लागवडीवर सातत्याने होत असतो.
 ५. कधी कधी उत्पादन उत्तम दर्जाचे असूनही आय.एस.आय. किंवा एगमार्क यासारखे मानांकन प्राप्त झालेले नसल्यामुळे निर्यातक्षम उत्पादन असतांनाही प्रत्यक्ष निर्यात करणे शक्य झालेले नाही.
 ६. सहकार चळवळीने काही प्रदेशात उत्पादन वाढले खरे पण कालांतराने सहकारी चळवळीतील व्यावसायिक दृष्टीकोणाचा अभाव व राजकारणात प्रवेश करण्यासाठीची एक पायरी म्हणून सहकारी संस्थांचा वापर करणे यातून सहकारी चळवळ आणि उस शेती यावर आरिष्ट निर्माण झाले.
 ७. शेतजमीनीचा वापर अन्य कारणांसाठी वाढत गेल्याने शेतजमीन घटायला लागली. शेती परावलंबी व्हायला लागली आणि त्यातून छोट शेतकरीही कर्जबाजारी झाला व आत्महत्या करू लागला.
 ८. उद्योग स्थापन करण्यासाठी प्रशिक्षणाची गरज असते. त्यामुळे प्रशिक्षणाखेरीज ग्रामीण लोक उद्योग करण्यास धजावत नाही आणि सोयीच्या टिकाणी व सोयीच्या वेळी प्रशिक्षण उपलब्ध होत नाही.
 ९. उत्पादीत मालाच्या विक्रीसाठी, बाजारपेठ विस्तारण्यासाठी मालाला आकर्षक वेष्टनाची गरज आहे. त्यासाठी प्रशिक्षणाची गरज आहे.
 १०. स्थानिक पातळीवर मागणी होत नसल्यामुळे प्रक्रिया, पॅकिंग व वाहतुकीचा खर्च बराच जास्त येतो.
 ११. शिक्षण. प्रशिक्षण सुविधांच्या अभावामुळे कामगारांची कार्यक्षमता वाढविण्यात अनेक अडचणी येतात.
 १२. मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनासाठी भांडवलाची गरज असते. परंतु ते सहजतेने उपलब्ध होत नाही.
 १३. वाहतूक दळणवळणाच्या सोयीचा अभाव असल्यामुळे या उद्योगातील वस्तूंचा बाजारपेठेत होणारा पुरवठा वेळेत होत नाही.
 १४. कच्च्या मालाची कमतरता असल्यामुळे उद्योगांच्या विकासात अडचणी येतात.
 १५. या उद्योगांना भांडवलाच्या तुटवड्यामुळे अनेक प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते.
 १६. विक्री व्यवस्थेत अनेक दोष असल्याने या उद्योगांना चांगले उत्पन्न मिळत नाही.
 १७. भार नियमनामुळे या उद्योगांचा उत्पादन खर्च वाढत आहे.
- याव्यतिरिक्त लोकांच्या आवडी. निवडीनुसार उत्पादन करणे अशक्य होत आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे हे उद्योग मेटकुटीस

आले आहे. या उद्योगांमधील वस्तूंच्या किंमतीचा प्रश्नही जटील झाला आहे.

उपाययोजना :

- अभ्यास करित असतांना कृषी आधारित उद्योगांच्या समस्यांचा विशेष अभ्यास करण्यात आला. त्या समस्यांच्या अनुभवांने काही उपाययोजना या ठिकाणी विशद केल्या आहेत.
- शेती आधारित उद्योगांची स्थापना ग्रामीण भागात करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या आधारभूत सोयी सुविधा जसे बीज, पाणी, रस्ते, अधिकोष, प्रशिक्षण संस्था इ. निर्माण केल्यास ग्रामीण शेती आधारित उद्योग सुरु करण्याची प्रेरणा ग्रामीण लोकांना मिळेल. त्यातून रोजगार निर्मिती, उत्पन्न वाढ, दारिद्र्या निर्मूलन यासारख्या गोष्टी साधल्या जातील.
 - शेती आधारित उद्योग ग्रामीण भागात स्थापन केले तरी त्यामध्ये उत्पादित होणाऱ्या उत्पादनाला देशी बाजारपेठेसोबतच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी म्हणून निर्यातक्षम उत्पादन करण्यासाठी उद्योजकांना प्रेरित करण्यासाठी निर्यातीकरिता आवश्यक सुविधा त्यांना सहज आणि सोपेपणाने उपलब्ध व्हावी यासाठी शासनाने प्रयत्न करावे.
 - भारतात ८० टक्के कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे प्रमाण आहे. हा शेतकरी जे उत्पादन घेतो ते बाजारपेठेत नेल्यानंतर माल चांगल्या दर्जाचा नाही, त्यात ओलावा अधिक आहे, माती अधिक आहे अशी कारणे दाखवून मालाचे वजन मूळात असते त्यापेक्षा किमान १० टक्के कमी मानले जाते. बाजारपेठेच्या यंत्रणेसाठी पून्हा शेतकऱ्याला वेगळे पैसे द्यावे लागतात. अशा पद्धतीने होणारे शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी मुळात उद्योगाचे निकष लावून शेती नियोजन करावयास हवे व उद्योजकाची मानसिकता प्रत्येक गावापर्यंत कधी पोहचेल यादृष्टीने प्रयत्न व्हावेत.
 - शेती आधारित उद्योगांच्या विकासासाठी शेती आधारित उद्योग विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात यावी. ज्या अंतर्गत या उद्योगांसाठी प्रशिक्षण, वित्तपुरवठा, अनुदान देवून ग्रामीण तरुणांना शेती आधारित उद्योग स्थापन करण्यासाठी आकर्षित करता येईल.
 - कृषी आधारित उद्योग ग्रामीण भागातच आणि शेतकरी, शेतमजूर यांनी सहकारी तत्वावर किंवा बचतगटाच्या माध्यमातून सुरु करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे. जेणेकरून ग्रामीण भागातील लोकांच्या उत्पन्न स्तरात वाढ होवून ग्रामीण विकास साधने शक्य होईल.
 - जगभर शेतीमध्ये सातत्याने विविध प्रयोग केले जात आहे. शेतजमीन घटत असतांना अलीकडेच अंतराळात जिनीयाचे फूल फूलविण्याचा प्रयत्न शास्त्रज्ञांनी करून दाखविला आहे. त्यामुळे भविष्यात जमीनीवरच नव्हे तर अन्यत्रही पीक घेण्याच्या पद्धती विकसीत झाल्यातर आश्चर्य वाटू नये. शेतीतील बदलते तंत्र आणि वेगवेगळे प्रयोग आत्मसात करण्याची मानसिकता शेतकरी वर्गामध्ये तयार केली जायला हवी. तसेच नवे तंत्र आणि प्रयोग शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी योग्य व्यवस्था हवी.
 - वेगळा कृषी अर्थसंकल्प दरवर्षी सादर करण्यात यावा जेणेकरून एकूणच कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी आर्थिक तरतूद करणे शक्य होईल. शेती आधारित उद्योगांना विशेष प्राधान्य देवून ग्रामीण विकास पर्यायाने राष्ट्र विकास साधण्यास मदत होईल.
 - या व्यतिरिक्त या उद्योगांच्या विकासाकरिता बँकांनी अल्प व्याजदराने कर्ज पुरवठा करावा, देशातील सींचनव्यवस्थेत सुधारणा करणे व वाढविणे आवश्यक आहे, भारनियमन पद्धत बंद करावी, साठागृहे व गोदाम व्यवस्थेत सुधारणा करावी, नियंत्रित बाजारपेठेची संख्या वाढवावी, वाहतूक व दळणवळण सुविधा गुणवत्ताधारक व आवश्यक इतकी असणे आवश्यक आहे, निर्यातवृद्धीसाठी सरकारने निर्यात कर रद्द करून निर्यातीवरील बंधने दूर करावीत.
 - शेती आधारित उद्योगांच्या विकासासाठी प्रशिक्षण व संशोधन सुविधा उपलब्ध करावी. या उद्योगांना आधुनिक साधनांची खरेदी करण्याकरिता सरकारने कर्जपुरवठा करावा. तसेच उद्योगांच्या विकासासाठी अनुदाने द्यावीत.

संधी.

- आज भारतीय शेती आधुनिकतेकडे वळू पाहते आहे. भारतीय शेतकरी परंपरागत पिकांसोबतच आता नवनवीन उत्पादन घेतो आहे. उत्तम दर्जाच्या शेतमालावर अनेक प्रकारच्या प्रक्रिया केल्या जात आहेत. उर्वरीत माल शीतगुहात साठवतो आहे. नवीन प्रयोग करण्याची क्षमता दिवसेंदिवस वाढत आहे. सर्वात महत्वाचं म्हणजे देश. विदेशातील बाजार समजून घेतो आहे. हे स्वप्नवत वाटणारं चित्र आता भारतातही मोठ्या प्रमाणात दिसू लागलं आहे.
- भारतातील शेतमाल प्रक्रिया उद्योगांचे ग्राहक शंभरावर देशात आहेत आपल्याकडे मॉल्समध्ये शेतमाल प्रक्रिया उद्योगांच्या वस्तू उपलब्ध आहेत त्या वस्तू अमेरिकेतील काही मॉल्समध्ये देखील उपलब्ध आहेत. आपल्याकडे पॅकींग फुडचं महत्त्व वाढत चाललं आहे. मॉल्समध्ये कापून निवडून तयार केलेल्या पालेभाज्यांच्या विक्रीत खूपच वाढ झालेली दिसते.
- सरकार मेक इन इंडिया अंतर्गत तब्बल १४ हजार कोटी रुपये शेती प्रक्रिया उद्योगांसाठी खर्च करणार आहे. देशामध्ये ४२ मेगा फूड पार्क्स उभारले जाणार आहे. त्यापैकी ५ फूड पार्कची उभारणी पूर्ण झालीय. यातून तीन लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होवून सुमारे १२ लाखांवर शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. गुजरात राज्यातील खेडा गावात सुरु केलेल्या अमूल प्रकल्पानं आज विशालकाय रुप धारण केले आहे.

निष्कर्ष.

- कृषी आधारित उद्योग व ग्रामीण विकास ह्याा अध्ययनातून खालील निष्कर्ष निघाले आहेत. आग्राचा पेडा, चित्तल्यांची बाकरवडी, अमूलचं आईस्क्रीम, हल्दीरामची मिठाई, बंगाली मिठाई, महाराष्ट्रीयन पापड या सर्वांनी जागतिक बाजारपेठेत आपलं स्थान मिळवलं आहे. ते स्थान मिळवणं नव्याने पदार्पण केलेल्या उद्योगांनाही शक्य आहे. गरज आहे मी फक्त इच्छा शक्ती आणि परिश्रमाची.
- मेक इन इंडियाच्या संकल्पनेतील ग्रामीण रोजगाराचे, उत्तम दर्जाच्या उत्पादनाचे व निर्यात वाढीचे उद्दिष्ट शेती आधारित उद्योगातून साध्य होईल. यातून ग्रामीण विकास करण्याचे स्वप्न खऱ्या अर्थाने साध्य होईल.
 - शेतातील उत्पादित मालावर प्रक्रिया करणे, खऱ्या अर्थाने कृषी उद्योग मोठ्या प्रमाणात विकसीत होण्याला याव आहे. प्रामुख्याने फळ प्रक्रिया उद्योग मोठ्या प्रमाणात विस्तारावा लागेल.
 - देशातील ग्रामीण भागात कृषी प्रक्रिया उद्योग सुरु केल्यास शेतातील कच्च्या मालाला तेथेच बाजारपेठ उपलब्ध होईल. शेतकऱ्यांची आर्थिक

स्थिती सुधारून व रोजगारात वृद्धी होवून ग्रामीण भागातील होणारे स्थलांतर थांबेल.

४. मेक इन इंडिया अंतर्गत या उद्योगांसाठी ज्या सुविधा व सवलती देऊ केल्या गेल्या आहेत त्याचा फायदा भारतातील शेतकरी व उद्योजक कसा घेणार ही अत्यंत महत्वाची बाब आहे.

५. अन्न प्रक्रिया उद्योगगात दळलेले धान्य, साखर, खाद्यतेल, पेये, फळे आणि भाजीपाला प्रक्रिया व दुग्धजन्य पदार्थ यांचा समावेश आहे. या उद्योगांना प्रोत्साहन मिळावे.

६. मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्यासाठी भांडवलाची गरज असते. परंतु ते सहजतेने उपलब्ध होत नाही.

७. कृषी पर्यटन उद्योगही हा नव्यानेच विकसीत होणारा उद्योग आहे. त्यामध्ये वाढ होणे आवश्यक आहे.

८. कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीत भारताचा सध्या ६ वा क्रमांक आहे तितका कायम राहावा यासाठी विशेष प्रयत्न व्हावे.

संदर्भसूची.

१. ढमढरे एस.डी., भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रथम आवृत्ती २००८, डायमंड पब्लि. पुणे.
२. संतोष दास्ताने, महाराष्ट्र वार्षिक २०१३, नितीन प्रकाशन, पुणे.
३. कविमंडन विजय, कृषी अर्थशास्त्र, मंगेश प्रकाशन, नागपूर.
४. उद्योजक, दिपक देशमुख, मार्च २०१३, एप्रिल २०१३.
५. देसाई दृ. भालेराव, भारतीय अर्थव्यवस्था, निराली प्रकाशन, पुणे.
६. ढाले रविन्द्र, डॉ.पंजाबराव देशमुख यांचे कृषीविषयक आर्थिक विचार, २००६.
७. अर्थसंवाद, जुलै . सप्टेंबर, २०१५.
८. अर्थसंवाद, जानेवारी . मार्च, २०१६.

Review of Research



International Online Multidisciplinary Journal

Volume - 6 | Issue - 11 | August - 2017

5.2331(UIF) 2249-894X

भारतातील दारिद्र्याचा अभ्यास



प्रज्ञा बागडे

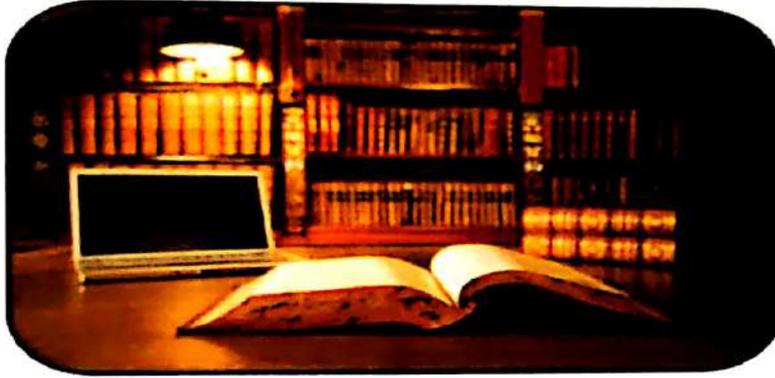
प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे

उपप्राचार्य व विभागप्रमुख, अर्थशास्त्र, डॉ. मधुकरराव नासनिक पी.डब्ल्यू.एस.कला व वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर.

सारांश :- भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून दारिद्र्याची समस्या वास्तव करून राहिलेली आहे. योजना कालावधीमध्ये दारिद्र्या निवारण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करून सुद्धा दारिद्र्याची तीव्रता कमी करण्यात अपेक्षित यश प्राप्त झाले नाही. नव्या आर्थिक धोरणामुळे भांडवलशाही, आर्थिक भक्तेदारी वाढत ...पृष्ठ क्र.- 32

Editor - In - Chief - Ashok Yakkaldevi





Sr. No	Title And Name Of The Author (S)	Page No
1	इतिहास की दृष्टि में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन काल में मलिक ताजुद्दीन – मदिरा पानोत्सव शङ्क्यंत्र (1291ई.) डॉ. नीरज कुमार गौड	1
2	सिनेमाई जनसंचार का ऐतिहासिक व सामाजिक परिप्रेक्ष्य रणजीत कुमार	3
3	भारतीय सिनेमा उद्योग में छविग्रहो का विकासक्रम डॉ. बी.एल. पाटीदार , असि. प्रो. गगन राठौर	7
4	मिलंगना नदी घाटी में पर्यटन के स्थल आरती , रामेंद्र कुमार एवं सौरभ डण्डरियाल	10
5	कोल्हापूर संस्थानातील ख्रिश्चन मिशनन्यांचे शेतीविषयक धोरण प्रा.संदीप नलवडे आणि डॉ. ए. के. मंजुळकर	19
6	समर्थ रामदासलिखित राजकीय पत्रे साँ. प्राची हेमंत पाटेकर (लोणावळा)	22
7	युग पृष्ठ भूमि और नागार्जुन के उपन्यास डॉ. गुंजन पाठक	29

- 8 **भारतातील दारिद्र्याचा अभ्यास**
प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे
- 9 **मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्याची ओळख**
डॉ. तुषार निवृत्ती निकाळजे



REVIEW OF RESEARCH



भारतातील दारिद्र्याचा अभ्यास



प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे

उपप्राचार्य व विभागप्रमुख, अर्थशास्त्र, डॉ. मधुकरराव वासनिक पी.डब्ल्यू.
एस.कला व वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर.

सारांश :

भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून दारिद्र्याची समस्या वास्तव करून राहिलेली आहे. योजना कालावधीमध्ये दारिद्र्याचा निवारण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करून सुद्धा दारिद्र्याची तीव्रता कमी करण्यात अपेक्षित यश प्राप्त झाले नाही. नव्या आर्थिक धोरणामुळे भांडवलशाही, आर्थिक मक्तेदारी वाढत आहे. देशाचा आर्थिक विकासाचा दर वाढत असला तरी उत्पन्नातील विषमतेत वाढ होवून गरीबांची संख्या वाढत आहे. काळ्या पैशाची समस्या गरीबी आणि दारिद्र्याचे एक प्रमुख कारण आहे. सरकारी उपाययोजना व विकास कार्यक्रमांवर खर्च होण्यासाठीचा पैसा खाजगी तिरोजीत जमा होतो. ही मानवी मूल्यातील घसरण हेही भारतातील दारिद्र्याचे एक महत्वपूर्ण कारण आहे. भारताच्या जागतिक महासत्ता बनण्याच्या वाटचालीत दारिद्र्या हा एक मोठा अडथळा ठरतो आहे देशातील दारिद्र्याचा संपूर्णपणे नष्ट केल्याशिवाय भारताला महासत्तेचा दर्जा मिळणार नाही म्हणून या विषयाच्या अभ्यासाचे महत्व आहे.

बीजशब्द - निर्मूलन, मानवी मूल्ये, कुपोषण, उपासमार, दारिद्र्यारेषा, समाजवाद, समाजरचना, लोकसंख्यावाद.

प्रस्तावना-

दारिद्र्या ही एक आर्थिक व सामाजिक घटना असून हे एक वास्तव आहे. स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर काळातही दारिद्र्याची समस्या आढळते. देशाने प्रगतीचे अनेक टप्पे पार केले असले तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर लोकसंख्या, बेकारी, गरीबी, आर्थिक विषमता सारख्या समस्या कायम आहेत. आजही देशातील ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त जनता दारिद्र्यारेषेखालील जीवन जगत आहेत. भारताच्या जागतिक महासत्ता बनण्याच्या वाटचालीतील दारिद्र्या हा मोठा अडसर ठरतो आहे म्हणून या विषयाच्या अभ्यासाला आजही महत्व आहे. शासनाने दारिद्र्याच्या निवारणासाठी अनेक योजना व कार्यक्रम राबविले आहेत. परंतु दारिद्र्या सातत्याने वास्तव करून राहिलेले आहे त्यामुळे दारिद्र्या निर्मूलनाची कार्यरत उपाययोजना अधिक प्रभावी व्हावी, दारिद्र्याच्या विविध अंगांचा आणि सामाजिक बदलांचा, नव्या उपाययोजना, सामाजिक सुरक्षितता ह्या सर्व दृष्टीकोणातून अभ्यासाची आवश्यकता आहे.

शोध निबंधाची उद्दिष्ट्ये -

१. दारिद्र्याच्या सद्यःस्थितीबाबत आढावा घेणे.
२. दारिद्र्याची प्रमुख कारणे शोधणे.
३. दारिद्र्या निवारण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा अभ्यास करणे.

गृहिते -

१. शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी दोषपूर्ण आहे.
२. भारतातील मानवी मूल्यातील घसरण हे दारिद्र्याचे महत्वपूर्ण कारण आहे.

संशोधन पद्धती -

प्रस्तुत शोधनिबंध दुय्यम साधन सामुग्रीवर आधारीत आहे. शोधनिबंध तयार करतांना संशोधकाने विविध प्रकाशित साहित्यांचा दुय्यम साधन म्हणून आधार घेतला आहे. दारिद्र्याच्या समस्येसंदर्भात विविध संदर्भग्रंथ, मासिके, नियतकालिके, आर्थिक पाहणी अहवाल इत्यादींवरून माहिती संकलीत करण्यात आली.

दारिद्र्याची संकल्पना -

भारतात सर्वसाधारणपणे दारिद्र्याची जी व्याख्या केली जाते तिचा आधार अन्न, वस्त्र व निवारा या प्राथमिक किमान गरजांची पूर्तता हा आहे. ज्या कुटुंबाची उत्पन्न पातळी उपभोग खर्चपेक्षा कमी आहे अशा कुटुंबाचा समावेश दारिद्र्यारेषेखाली केला जातो. डॉ. दांडेकर व रथ

यांनी भारतीयांसाठी दररोज २२५० कॅलरीज निकष लक्षात घेवून १९६०.६७ मध्ये दारिद्र्याचे विवेचन केले आहे.

भारतीय नियोजन मंडळाने सहाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात (१९८०.८५) दारिद्र्या या संकल्पनेची व्याख्या केली आहे. त्याचप्रमाणे, ग्रामीण भागात प्रतिदिन प्रतिमाणसी किमान २४०० उष्मांक व शहरी भागात प्रतिदिन प्रतिमाणसी किमान २१०० उष्मांक ज्या व्यक्तीस प्राप्त होत नाही ती दारिद्र्यात आहे असे समजावे.

सन २०००.२००१ च्या जागतिक विकास अहवालात "सुस्थितीपासून संपूर्णपणे वंचित असणे म्हणजे दारिद्र्या होय." अशी दारिद्र्याची व्याख्या केली आहे.

प्रा. अमर्त्य सेन यांच्या मते, "एखाद्या व्यक्तीला त्याने जोपासलेल्या मूल्यांप्रमाणे जगता न येणे म्हणजे दारिद्र्या होय."

जागतिक बँकेने "माणशी दर दिवशी एक डॉलर पेक्षा कमी उत्पन्न मिळविणाऱ्या व्यक्ती म्हणजे दारिद्र्यारेषेखालील व्यक्ती होय." अशी दारिद्र्याची व्याख्या केली आहे.

विविध काळातील दारिद्र्याचा आढावा -

भारतातील दारिद्र्याचा विविध टप्प्यातील आढावा घेतला आहे.

प्राचीन काळ -

प्राचीन काळातही दारिद्र्या अस्तित्वात होते, मात्र उपासमारी सारख्या त्याच्या विपरीत परिणामाची काळजी त्या काळातील मूल्य व्यवस्थेने घेतली होती. समाजात कोणीही उपाशी किंवा भूकेले राहणार नाही हे त्या काळातील मूल्य होते. त्यामुळे समाज उपासमार किंवा दारिद्र्यापासून मुक्त होता. आर्थिक नियमापेक्षा नैतिक मूल्यावर व्यवस्था आधारलेली होती. वितरणाच्या बाबतीत सुद्धा आर्थिक तत्वापेक्षा नैतिक मूल्याचा दर्जा मोठा होता. दारिद्र्याच्या निवारणासाठी सामाजिक सहकार्य आवश्यक असल्याचे तत्कालीन विचारवंतांना मान्य होते. त्यामुळे गरीबांसाठी दान व्यवस्था अस्तित्वात होती. कर रुपाने दिलेल्या रक्कमेतून उपासमारीत असलेल्या लोकांना जगविले आवश्यक आहे असे विचारवंतांनी प्रतिपादन केले. महत्तम सामाजिक हित साध्य करणे हे सरकारचे कर्तव्य मानले होते. अनाथांना सरकारने जगविले पाहिजे असे कौटिल्याचे मत होते. निराधार व असक्षम लोकांच्या बाबतीत सरकारने जबाबदारी मान्य केली होती. वृद्ध व गरीब लोकांना मदत व त्यांचे संरक्षण हे सरकारने आपले कर्तव्य मानले होते. एकंदरीत नैतिक व आर्थिक मूल्ये व्यवस्थेत स्विकारली असल्याने ती व्यवस्था अत्यावश्यक तत्वावर आधारीत होती. थोडक्यात, प्राचीन काळात दारिद्र्या होते, मात्र राज्य कारभार व समाजव्यवस्थेत प्रचलित मूल्यांचा स्वीकार केलेला असल्याने दारिद्र्याचे निवारणही होत होते.

मध्ययुगीन कालावधी -

मध्ययुगीन काळात दारिद्र्या अस्तित्वात होते, मात्र मूल्य व्यवस्थेने कमी.अधिक प्रमाणात त्याचे निवारण केले होते. समाजातील लोकांच्या जीवन आवश्यकतांची सामुहिक तरतूद असल्याने दारिद्र्याची काळजी घेतली होती. उदा. मध्ययुगीन काळातील अनेक राज्यांनी अन्नछत्र व लोकांसाठी विश्वस्त व्यवस्था चालवता याव्यात म्हणून मंदिरे व धार्मिक संस्थांना अनुदाने दिलेली आहेत. सरकार किंवा राजाचा तो एक नैतिक व आर्थिक व्यवहार होता. थोडक्यात, दारिद्र्या अस्तित्वात होते मात्र त्याचा विपरीत परिणाम म्हणजे उपासमारीची समाजात प्रचलित असलेल्या मूल्य व्यवस्थेने काळजी घेतली होती.

ब्रिटिश कालावधी -

ब्रिटिश कालावधीत भारताच्या मूल्यव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल झालेले. निर्वाहापासून नफा प्राप्तीसाठी माणसामाणसात स्पर्धा सुरु झाली. त्याचा परिणाम म्हणून दारिद्र्याची तीव्रता फार वाढली. भारतात ब्रिटिश कालावधीमध्ये संपत्तीचा संचय करू इच्छीणाऱ्या लोकसंख्येच्या नवीन वर्गास प्रोत्साहन देण्यात आले. त्यामुळे नफा प्रेरित अर्थव्यवस्थेत रुपांतर झाले. विज्ञान व तंत्रज्ञानातील विकासाबरोबरच नविन औद्योगिक रचना निर्माण होवून समाजाची नव्याने आर्थिक, सामाजिक व राजकीय जडण.घडण झाल्याने मूल्यव्यवस्थेत बदल झाला. त्यामुळे दारिद्र्याची तीव्रता वाढून ती एक भारतीय अर्थव्यवस्थेची नियमित समस्या म्हणून पुढे आली.

स्वातंत्र्योत्तर कालावधी -

स्वातंत्र्यानंतर भारतात स्वतंत्र राज्यघटना तयार करण्यात आली. समस्यांचे निवारण करण्यासाठी राज्याची मार्गदर्शक तत्वे त्यामध्ये समाविष्ट झाली. आर्थिक नियोजनाबरोबरच लोकशाही समाजवाद व मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. त्याद्वारे समाजवादी समाजरचना निर्माण करण्याचे ठरले. दारिद्र्याचे निवारण करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आले. मात्र सरकारने अवलंबिलेल्या कल्याणकारी धोरणाचा परिणाम म्हणून मृत्यूदर घटल्याने दारिद्र्याची समस्या अधिक गंभीर बनली. ह्या सर्व प्रयत्नात मूल्यव्यवस्थेकडे फारसे लक्ष न दिल्याने दारिद्र्या निर्मूलनास अपयश आले.

भारतातील दारिद्र्याची सद्यःस्थिती -

१९४७ मध्ये स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी आपला देश अत्यंत गरीब व दारिद्र्याने पिचलेला होता मात्र गेल्या ७० वर्षात आपण मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या मालिकेत दाखल झालो आहोत. १९७३.७४ मध्ये जवळपास ५५ टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यारेषेखाली होती परंतु दारिद्र्या निर्मूलन कार्यक्रमांमुळे यात १९९३.९४ पर्यंत ३६ टक्के पर्यंत घट झाली. २००२ पर्यंत २६ टक्के घट झाली. २०११.१२ मध्ये २१.९२ टक्के भारतीय जनता दारिद्र्यारेषेखाली असल्याचे अनुमान होते. रंगराजन ह्यांच्या अहवालामुळे साधारणतः ३६ कोटी ३० लाख नागरीक गरीब म्हणवून घेण्यास पात्र ठरतील याचाच अर्थ आपण विकासाचा विशिष्ट टप्पा गाठला तरी त्या प्रमाणात दारिद्र्या कमी होत नसल्याचे दिसून येते.

सन १९९९.२००० मध्ये दारिद्र्यारेषेखालील लोकांचे सर्वात जास्त प्रमाण ओरिसा ह्या राज्यात होते (४७.१० टक्के), तर दारिद्र्याचे सर्वात कमी प्रमाण जम्मू.काश्मिर या राज्यात होते (३.५० टक्के). सन १९९९.२००० मध्ये भारतात ओरिसा खालोखाल बिहार (४२.६० टक्के), मध्य प्रदेश (३७.४० टक्के), सिक्कीम (३६.४० टक्के), आसाम (३६.१० टक्के), त्रिपुरा (३४.४० टक्के), नागालॅण्ड (३२.७० टक्के), उत्तर प्रदेश (३१.२० टक्के), मणीपूर (२८.५० टक्के), आणि महाराष्ट्र (२५.०० टक्के), दारिद्र्यारेषेखालील लोकसंख्येचे प्रमाण

होते. या व्यतिरिक्त अंदाजानुसार मध्ये २१.०० टक्के, कर्नाटक राज्यात २०.०० टक्के, मिझोरम मध्ये १६.५० टक्के, लक्षद्वीप मध्ये १५.६० टक्के, गुजरात राज्यात १४.१० टक्के व केरळ राज्यात १२.७० टक्के प्रमाण होते.

भारतातील दारिद्र्याची कारणे-

भारतासारख्या विकसनशील देशातील लोकांच्या दारिद्र्यास विविध घटक कारणीभूत आहेत.

- समाजाच्या निर्मितीपासून संपूर्ण मानवी जीवनाच्या इतिहासामध्ये समाजात दारिद्र्याचे होते. मात्र दारिद्र्याच्या विपरीत परिणामाची काळजी त्या त्या काळातील मूल्य व्यवस्थेने घेतली होती. समानता, उत्पन्नाचे मानवतावादी वितरण, गुणवत्ता वस्तूंची तरतूद वगैरे मूल्याधिष्ठीत व्यवस्थेने महत्वाचे घटक आहेत. ह्या मूल्यांची भारतीय अर्थव्यवस्थेत झालेली घसरण हे दारिद्र्याचे एक महत्वपूर्ण कारण आहे.
- वाढती लोकसंख्या किंवा लोकसंख्या वाढीचा वेग मोठा असणे हा प्रमुख घटक आहे. जगात सर्वात जास्त लोकसंख्या वाढीचा वेग आपल्या देशाचा असून याबाबतीत आपण चीनला केव्हाच मागे टाकले आहे. वाढती लोकसंख्या हा घटक दारिद्र्याचे कारण तसेच परिणाम सुद्धा आहे. दारिद्र्य कुटुंबाचा आकार मोठा असतो. त्यामुळे कुटुंबातील सर्वांचे पालनपोषण कुटुंब प्रमुखाला करता येत नाही. त्यामुळे दारिद्र्य कुटुंब आणखीनच दारिद्र्य बनते.
- कमी मजुरी, दिवसेंदिवस वाढत असलेली महागाई, बेरोजगारी, कुपोषण, भूमीहीनता, अपुरी आणि निकृष्ट शेतजमीन, व्यसनाधिनता, अंधश्रद्धा, अनिष्ट प्रथा, वेढबिगारी, पूरक व्यवसाय व स्वयंरोजगार नफ्यात न चालणे इत्यादी विविध घटक भारतीय जनतेच्या दारिद्र्यास कारणीभूत आहेत. भारतासारख्या विकसनशील देशातील लोकांच्या दारिद्र्यास कारणीभूत असणारा आणखी एक महत्वाचा घटक म्हणजे भारतासारख्या विकसनशील देशांची सरकारेच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. याचाच अर्थ असा की, राष्ट्र किंवा राष्ट्राची अर्थव्यवस्थाच जर दारिद्र्य असेल तर त्या राष्ट्रातील बहुसंख्य जनतेला सुद्धा दारिद्र्यातच खितपत पडावे लागते.
- काळ्या पैशाची समस्या सुद्धा भारतातील गरीबी आणि दारिद्र्याचे एक प्रमुख कारण आहे. सरकारी उपाययोजना, सेवा सुविधा व विकास कामांवर खर्च करण्यासाठी सरकारी तिजोरीत जमा होणारा पैसा काळा पैशाच्या स्वरूपात खाजगी तिजोरीत जमा होतो. त्यामुळे देशातील गरीबी व दारिद्र्या निर्मूलनाचे कार्य परिणामकारक होत नाही.
- भारताने स्वातंत्र्यापासून विकासावर लक्ष केंद्रित केले. त्याचे परिणाम काही क्षेत्रातील विकासाच्या माध्यमातून दिसून आले परंतु या विकासाचा फायदा सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचला का? हा खरा प्रश्न आहे.

दारिद्र्याचे दुष्परिणाम -

'दारिद्र्या' ही व्यक्ती समोरीलच नाही तर देशासमोरील गंभीर स्वरूपाची समस्या आहे. दारिद्र्याचे भयंकर परिणाम ज्याप्रमाणे दारिद्र्य व्यक्तीला भोगावे लागतात तसेच राष्ट्राला किंवा सरकारलाही भोगावे लागतात.

- दारिद्र्यामुळे व्यक्तीची, कुटुंबाची प्रगती होत नाही. मुलांना चांगले शिक्षण देता येत नाही. त्यामुळे दारिद्र्य कुटुंबाचा गाडा दारिद्र्याच्या चिखलात अधिकच रुतून वसतो. दारिद्र्यामुळे कुटुंबातील कोणालाच पोटभर व चांगले अन्न मिळू शकत नाही. त्यामुळे दारिद्र्य कुटुंबातील व्यक्तींची कार्यक्षमता अत्यंत कमी राहते. कार्यक्षमता कमी असल्याने मजुरी देखील कमी मिळते. त्यामुळे दारिद्र्याचा प्रश्न अधिकच गंभीर बनतो. दारिद्र्य व्यक्तींना समाजात मान सन्मान प्राप्त होत नाहीच, वरून सर्वत्र अवहेलना होत असते. हा दारिद्र्याचा सामाजिक परिणाम मानता येईल.
- दारिद्र्यामुळे देशाच्या लोकसंख्या वाढीचा वेग वाढून लोकसंख्येच्या आकारात वाढ होते. भारतात एकेका दारिद्र्य कुटुंबात चार ते सहा अपत्ये दिसून येतात. देशात दारिद्र्याचे प्रमाण जेवढे जास्त तेवढा लोकसंख्या वाढीचा वेग आणि लोकसंख्येचा आकार मोठा असतो. दारिद्र्यामुळे देशात अतिरिक्त लोकसंख्येचा प्रश्न निर्माण होतो व अतिरिक्त लोकसंख्येमुळे देशात अनेक आर्थिक व सामाजिक समस्या निर्माण होतात. या समस्यांच्या निराकरणासाठी सरकारला प्रचंड खर्च करावा लागतो. त्यामुळे देशाच्या विकासाचा वेग मंदावतो.
- देशात दारिद्र्यारेषेखालील लोकांची संख्या जर जास्त असेल तर देशाच्या सरकारला दारिद्र्या निर्मूलनाच्या कार्यक्रमावर मोठा खर्च करावा लागतो. यापैकी बराचसा खर्च अनुत्पादक असतो. आरोग्य किंवा औषधोपचार यावर केलेला खर्चही अनुत्पादकच असतो. अशा खर्चांमुळे उत्पादक कामासाठी पैसा कमी पडतो. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासाचा वेग वाढत नाही. राष्ट्राचा विकास कमी गतीने होतो हा दारिद्र्याचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा गंभीर परिणाम होय.
- दारिद्र्यामुळेच भारतात लहान मोठ्या अनेक शहरात मोठ्या प्रमाणात बेसुमार झोपडपट्ट्या उभ्या राहिल्याचे चित्र आहे. गुन्हेगारी, व्यसनाधिनता, देहव्यापार, कुपोषण, बालमृत्यू, उपासमार, भूकवळी इत्यादी अनेक गंभीर समस्या दारिद्र्यामुळेच निर्माण झाल्या असून या समस्यांना केवळ दारिद्र्य व्यक्तींनाच तोंड द्यावे लागत नाही तर सरकारला व समाजालाही या समस्यांशी सामना करावा लागतो आहे.
- भारतासारख्या देशात नक्षलवादी चळवळीचा जन्म होण्यास आणि ही चळवळ अनेक राज्यात पसरण्यास जे विविध घटक कारणीभूत आहेत त्यामध्ये आदिवासींचे दारिद्र्य हा प्रमुख घटक आहे. दारिद्र्यामुळेच गरीब आदिवासींनी सरकारच्या विरोधात शस्त्र उपसले आहे.
- भारतात बाल मजुरीला कायद्याने बंदी असली तरी असंघटीत क्षेत्रात बाल मजूर आढळून येतात. यास दारिद्र्या हाच प्रमुख घटक जबाबदार आहे.

अंशा रितीने दारिद्र्यामुळे अनेक अनिष्ट आर्थिक, सामाजिक, राजकीय परिणाम व्यक्ती, कुटुंब पर्यायाने समाजावर, अर्थव्यवस्थेवर व देशावर घडून येतात.

दारिद्र्या निर्मूलनासाठी शासनाचे प्रयत्न -

कोणत्याही देशात दारिद्र्या अस्तित्वात असणे ही अतिशय गंभीर अशी बाबच नाही तर त्या देशाची प्रतिमा मलीन होणारी बाब आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत नजिकच्या काही वर्षात अमेरिकेसारखी महासत्ता बनण्याची क्षमता आहे. परंतु देशातील दारिद्र्या संपूर्णपणे नष्ट केल्याशिवाय भारताला महासत्तेचा दर्जा मिळू शकणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. देशातील दारिद्र्या संपविण्यासाठी स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत सरकारने अनेक उपाय योजना केल्या आहेत. .

• **सार्वजनिक वितरण व्यवस्था -**

दारिद्र्या निर्मूलन कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा स्वीकार करण्यात आला. या व्यवस्थेअंतर्गत गोरगरीब जनतेला स्वस्त दरात धान्याचे वितरण केले जाऊ लागले. या योजनेचे मूल्यांकन करण्याचे काम नियोजन आयोगातर्फे २००५ मध्ये झाले त्यात या योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत खालच्या दर्जाची असल्याचे दिसून आले.

सद्यःस्थितीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून दारिद्र्यारेषेखालील जनतेला अन्न.धान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून देणे आवश्यक आहे.

• **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना -**

देशात केंद्र सरकारने सप्टेंबर २००५ मध्ये आदेशाद्वारे राष्ट्रीय स्तरावर ग्रामीण रोजगार हमी कायदा पास केला. या योजनेनुसार ग्रामीण भागातील कोणत्याही व्यक्तीला ती श्रमाचे काम करण्यास तयार असल्यास तिला किमान वेतन दराने वर्षाला १०० दिवस रोजगार देण्याची हमी केंद्र सरकारने दिली आहे. स्वयंपाकाचा गॅस आणि मनरेगा मधील अनुदानाच्या थेट बँकेतील हस्तांतरणामुळे भ्रष्टाचारात घट झाली आहे.

• **अन्नसुरक्षा कायदा -**

५ जुलै २०१३ रोजी अन्नसुरक्षा कायदा लागू केला होता आणि राज्य सरकारांना तो ३६५ दिवसांच्या आत लागू करावयाचा होता. त्याची मुदत जुलै २०१४ पर्यंत होती. हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब व छत्तीसगड या राज्यांनी अन्नसुरक्षा कायदा पूर्णपणे लागू केला आहे. तर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार मध्ये तो अंशरूपाने लागू केला आहे. अन्नसुरक्षा कायद्याद्वारे ग्रामीण भागातील ७५ टक्के लोकांना व शहरी विभागातील ५० टक्के लोकांना दरडोई दरमहा ५ किलो धान्य, तांदुळ, गहू आणि भरड धान्य अनुक्रमे ३ रुपये, २ रुपये व १ रुपया किलोप्रमाणे देण्याचा निर्णय घेतला या कायद्यात काही त्रुटी आहेत त्या दूर करून या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होणे आवश्यक आहे.

• **पंतप्रधान जनधन योजना -**

१५ ऑगस्ट २०१४ या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान मोदींनी पंतप्रधान जनधन योजनेची घोषणा केली होती व त्याची सुरुवात करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत देशातील गरीब नागरीकांचे बँक खाते उघडण्यात येतील, त्यांना डेबीट कार्ड देण्यात येतील तसेच या कार्डवरोबर प्रत्येक गरीब कुटुंबाला एक लाख रुपयांचा विमा देण्यात येईल यामुळे गरीबांचे सक्षमीकरण होण्यास मदत होईल. योजनेअंतर्गत आर्थिक समावेशनाला गती आली असून, अटल पेंशन योजनेद्वारे नवीन निवृत्ती योजनांची व्याप्ती वाढत आहे.

• **पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरकुल योजना -**

स्वतःची जागा नसलेल्या दारिद्र्यारेषेखालील लाभार्थ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत स्वतःची जागा खरेदी करण्याकरीता आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना ही नवीन योजना सुरु करण्यात आली. इंदिरा आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आदिवासी घरकुल योजना अंतर्गत १ लाख घरे बांधण्याचे शासनाचे लक्ष्य आहे. त्याचप्रमाणे झोपडपट्टीवासी व मध्यमवर्गीय यांना परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत व २०२२ पर्यंत कोणीही घराविणा राहू नये असा शासनाचा प्रयत्न आहे.

• **गरीबांना मोफत गॅस जोडणी -**

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील गरीब कुटुंबासाठी मोफत गॅस जोडणी योजना जाहीर केली. याद्वारे दारिद्र्यारेषेखालील कुटुंबांना याचा लाभ मिळणार असून त्यासाठी केंद्र सरकारने तब्बल ८ हजार कोटी रु.ची योजना आखली आहे. पंतप्रधान उज्वला योजनेअंतर्गत गरीब कुटुंबातील महिलांच्या नावावरच गॅस जोडणी मिळेल. पंतप्रधानांनी या योजनेमुळे पहिल्या वर्षातच दीड कोटी व.तीन वर्षात पाच कोटी कुटुंबापर्यंत गॅस पोहोचेल असा विश्वास व्यक्त केला.

• **केंद्रीय अंदाजपत्रकातील तरतूदी -**

केंद्रीय अंदाजपत्रक २०१६.१७ यात गरीबांकरीता तरतूदी करण्यात आल्या. त्यात घरातील महिलेच्या नावाने एल.पी.जी. कनेक्शनची योजना, गरीबांच्या फायद्यासाठी २००० कोटीची तरतूद, मनरेगासाठी ३८५०० कोटीची तरतूद, ३ लाख रेशनच्या दुकानात स्वयंचलीत प्रणाली असणार अशा तरतूदी केंद्रीय अंदाजपत्रकात करण्यात आल्या आहेत.

स्वातंत्र्योत्तर काळात दारिद्र्या निर्मूलनासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले आहेत. गरीबांच्या कल्याणासाठी कोट्यावधी रुपये खर्च केले व होत आहेत तरी देखील भारतात दारिद्र्याचे प्रमाण जास्त आहेच.

निष्कर्ष.

- योजनांचा लाभ मागास आणि उपेक्षित समाज घटकापर्यंत पोहचायला हवा तसा पोहचला नाही.
- मूल्यांची घसरण हे भारतातील दारिद्र्याचे प्रमुख कारण आहे.
- देशाचा विकास विशिष्ट वर्गापुरताच मर्यादीत राहिल्याचे दिसते.
- श्रीमंत व गरीब यांच्या उत्पन्नात कमालीची तफावत आहे.
- सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होतांना आढळतात.
- भाववाढीने खरेदी शक्तीत घट होवून दारिद्र्यात वाढ होते.
- सरकारने विविध योजना सुरु केल्या असल्या तरी अंमलबजावणीत दोष आहेत.
- विविध अभ्यासकांच्या, समित्यांच्या दारिद्र्या निर्धारणाच्या निकषांमध्ये विरोधाभास दिसून येतो.

- विकासाच्या वाटेवर गरीबी आणि दारिद्र्याचे निकष आणि परिणामसुद्धा बदलणे आवश्यक आहे.
 - दारिद्र्याच्या स्वरूपात मूलभूत बदल घडून येऊ लागले आहेत याची नोंद दारिद्र्याचा अभ्यास करतांना महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
- भारतातील दारिद्र्याची व्यापकता मोठी व भिन्न आहे. समाजातील सर्व घटकांचे, पर्यायाने गरीबांचे उत्तम सामाजिकीकरण होणे अत्यंत आवश्यक आहे. संपन्न समाज निर्मिती म्हणजेच योग्य सामाजिकीकरण हेच खरे दारिद्र्या निर्मूलनाचे उत्तम स्वरूप होय.

संदर्भ.

१. भारतातील सामाजिक समस्या, प्रकाशक.कुलसचिव, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे, २००७.
२. आर्थिक आणि जागतिक आर्थिक विकास, महाजन मुकुंद, निराली प्रकाशन, २०१०.
३. अर्थसंवाद, आक्टोबर.डिसेंबर २०१२ खंड ३६, अंक ३.
४. अर्थसंवाद, आक्टोबर.डिसेंबर २०१३.
५. दैनिक, महाराष्ट्र टाइम्स, दि. ०२ मे २०१६.
६. दैनिक, लोकमत, दि.०३ जून २०१६.
७. दैनिक, लोकसत्ता, दि. ०८ जुलै २०१४.
८. दैनिक, सकाळ, दि. २६ ऑगस्ट २०१४.

ISSN - 2249-5134

Perspectives

A National Interdisciplinary Annual Research journal
2017

Peer Reviewed
Research Journal for
Interdisciplinary
Studies in Arts,
Commerce &
Social Sciences

Vol. I Issue-VII
August-2017



Dr. Madhukarrao Wasnik
PWS Arts and Commerce College
Kamptee Road, Nagpur-26
(Reaccredited 'B' by NAAC)

मराठी विभाग-

15. भारतातील अन्नसुरक्षा : स्वरूप व उपाय	प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे	45
16. इतिहासलेखनशास्त्र म्हणजे काय ?	प्रा.डॉ.महेंद्र गायकवाड	70
17. फालुन दाफा : शरीर आणि मन यांच्या विकासाकरिता एक प्राचीन प्रभावी उच्च स्तरावरील साधना अभ्यास	डॉ. यशोधरा हाडके	74
18. पंचशीलाचा जागतिक समाज जीवनावर पडलेला प्रभाव : एक अध्ययन	डॉ. कैलाष फुलमाळी	79
19. विदर्भातील अस्पृश्योध्दार आंदोलनात नानासाहेब गवई यांचे योगदान	डॉ. राजु भा. खरडे	82
20. लोकशिक्षणात राजकीय पक्षाची भूमिका"	डॉ. विमल राठोड	85
21. बाबू आवळे यांचे वृत्तपत्रीय लेखन	डॉ. चंद्रशेखर पाटील	87
22. स्त्री आत्मचरित्रात 'आयदान' चे वेगळेपण	प्रा.अमृता डोरलीकर	91
23. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा विद्यार्थ्यांस संदेश	डॉ. निलीमा चौहान	95
24. स्त्रियांचे कैवारी डॉ. भिमराव रामजी आंबेडकर	प्रा. प्रणोती कांबळे	98
25. आधुनिक कृषी व भारतीय कृषी विकासातील प्रमुख योजना व संकल्पना	प्रा. मुरलीधर एस. नाकाडे	100
26. नोकरदारांच्या नुकसान भरपाईचा कायदा 1923 (The Employee's Compensation Act, 1923)	प्रा. विजय जा. पाठक	103
27. समाज प्रबोधक – संत तुकाराम	प्रा. डॉ. राम चौधरी	106
28. डॉ. आंबेडकरांची धम्मदिक्षा एक ऐतिहासीक पर्व	डॉ. रत्नपाल एम. डोहणे	110
29. नोटबंदीचे परिणाम	प्रा. एम. यू. टिपले	112
30. मराठी पौराणिक कादंबरीतील मिथके आणि नवीनता	डॉ. भारती खापेकर	116

भारतातील अन्नसुरक्षा : स्वरूप व उपाय

प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे

सारांश- आधुनिक स्पर्धेच्या युगात भारत एक आर्थिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहत असतांना देशात अन्नसुरक्षेचा मूलभूत प्रश्न एक चित्तेचा विषय ठरला असून ती आजची शोकांतिका आहे. ती सोडविणे हे सध्याचे मूलभूत आव्हान आहे. भारत सरकारने २०१३ मध्ये अन्नसुरक्षा विधेयक संमत करून कल्याणकारी राज्याच्या निर्मितीच्या दृष्टीने एक महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. भारतासारख्या वाढत्या लोकसंख्येच्या देशात अन्नसुरक्षा अत्यंत महत्वाची आहे. देशातील सर्व लोकांना अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे सरकारचे कर्तव्य आहे. देशातील भूकबळीची समस्या केवळ अन्नसुरक्षिततेच्या माध्यमातून कमी होऊ शकते. लोकसंख्यावृद्धी व अन्नधान्य उत्पादनवृद्धी यांचा समन्वय साधून अन्नसुरक्षा धोरण राबविणे महत्वाचे आहे. अन्नधान्य सुरक्षिततेची हमी देण्यासाठी आर्थिक नियोजनाच्या सहाय्याने कृषी क्षेत्राचा विकासाचा दर वाढविणे, शेतीला पाणी, वीज, औषधे, अवजारे, शिक्षण -प्रशिक्षण, संशोधन, शेतमालाला योग्य किंमत व शेतकऱ्याला शेतीसाठी प्रोत्साहन देणे, उत्पादकता व उत्पादन वाढीच्या दृष्टीने अत्याधुनिक तंत्र व यंत्राचा वापर यासारख्या उपाययोजना कराव्या लागतील.

शब्दसंकेत - उत्पादन वृद्धी, अन्नसुरक्षा विधेयक, हरितक्रांती, मानवी कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भूकबळी, कुपोषण

प्रस्तावना -अन्न, वस्त्र व निवारा या मानवाच्या मूलभूत गरजा असून त्यातील अन्न ही सर्वात महत्वाची गरज आहे. प्राचीन कालखंडापासून मानव अन्नासाठी संघर्ष करित आलेला आहे. मानवी उत्क्रांतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर मानवाने आपल्या बुद्धीमत्तेच्या जोरावर प्रगतीचे एक -एक पाऊल पुढे टाकले असले तरी भुकेला अजूनही पर्याय शोधता आला नाही. व्यक्तीच्या अन्न विषयक किमान गरजा जोपर्यंत भागविल्या जात नाही तोपर्यंत व्यक्तीला आर्थिक नियोजनाचे महत्त्व, मानवी कल्याण, सामाजिक न्याय आणि लोकशाही या गोष्टी प्राप्त करून घेणे अशक्य होईल.

स्वतंत्र भारताचे पहिले प्रधानमंत्री पंडीत नेहरु म्हणाले होते की, 'भारताने अन्नधान्याच्या बाबतीत इतर देशांवर अवलंबून राहणे ही बाब लाजीरवाणी तर आहेच, शिवाय ती धोकादायक आहे.' याची दखल घेवून स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर सर्वांसाठी अन्नधान्य सुरक्षा मिळविणे हे आपले राष्ट्रीय उद्दिष्ट ठरविले. तरिही सत्तर वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर अन्नसुरक्षेचा ज्वलंत प्रश्न सोडविणे शक्य झाले नाही. आज जागतिक पातळीवरही अन्नसमस्येच्या आव्हानांना समर्थपणे तोंड देण्यासाठी जागतिक स्तरावरही अन्न सुरक्षेबाबत गंभिरपणे चर्चा करण्यात येत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर अन्नसुरक्षा म्हणजे काय?, अन्नसुरक्षेची सद्यःस्थिती, अन्नसुरक्षेच्या समस्या, अन्न राखीव साठा म्हणजे काय?, अन्नसुरक्षेसंदर्भातील शासकीय धोरण काय? असे अनेक प्रश्न मनात निर्माण होतात. या सर्व प्रश्नांचे थोडक्यात निवारण करण्याच्या करण्याच्या उद्देशाने दुय्यम सामुग्रीचा वापर करून या घटकांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत शोधनिबंधात केलेला आहे.

अभ्यासाची उद्दिष्टे -

१. अन्नसुरक्षा संकल्पना समजून घेणे.
२. भारतातील लोकसंख्यावाढ व अन्नधान्य उत्पादन यांचा अभ्यास करणे.
३. अन्नसुरक्षेचे महत्त्व स्पष्ट करणे.
४. अन्नधान्य सुरक्षा कायद्यातील तरतूदींचा आढावा घेणे.
५. अन्नसुरक्षेसाठी काही महत्त्वपूर्ण सूचना व उपाययोजना सुचविणे.

अभ्यास पद्धती - प्रस्तुत शोधनिबंध हा दुय्यम तथ्य संकल्पनावर आधारित असून यामध्ये विविध मासिके, वार्षिक अहवाल, वर्तमानपत्रातील लेख यांचा आधार घेतला आहे.

अन्नसुरक्षा संकल्पना - अन्नसुरक्षेच्या बाबतीत अनेक तज्ञांनी व्याख्या सांगितल्या आहेत. जागतिक विकास अहवाल 'सर्व लोकांना कोणत्याही वेळी उत्कृष्ट व योग्य जीवन जगण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात अन्न उपलब्धता असणे म्हणजे अन्नसुरक्षा होय.' असे सांगितले आहे.

अन्न व कृषी संघटनेच्या (FAO) मते, 'लोकांना सक्षम व आरोग्यदायी जीवन जगण्यासाठी त्यांच्या अन्नसुरक्षेस पसंतीनुसार व आहारानुसार योग्य सुरक्षित व पोषक अन्नधान्य भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या सर्व कालावधित पुरविणे म्हणजे अन्न सुरक्षा होय' अशी व्याख्या केली आहे.

अन्नसुरक्षेसाठी कोणत्याही देशाला त्यांच्या लोकसंख्येसाठी अन्नधान्याची भौतिक मात्रा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

अन्नसुरक्षा निश्चितीचे घटक -

१. अन्नधान्याची स्वदेशी मागणी - कोणत्याही देशाची अन्नसुरक्षा त्या देशाच्या लोकांकडून अन्नधान्याची मागणी किती प्रमाणात होते यावरून निश्चित होते. भारतात अन्नधान्याची गरज व मागणी यासाठीचे जे अंदाज वर्तविण्यात आले आहेत यामध्ये बरीच तफावत दिसून येते. वाढत्या लोकसंख्येबरोबर अन्नधान्याची स्वदेशी मागणी वाढणार हे निश्चित आहे.

२. दरडोई उत्पादन व उपलब्धता - भारतात तृणधान्य व अन्नधान्याची गरज प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दृष्टीकोणातून पूर्ण केल्यास जास्त असल्याचे दिसून येते. दरडोई अन्नधान्य उत्पादन हा घटक अन्न व पोषण सुरक्षेच्या संदर्भात महत्त्व आहे. भारतात दरडोई उत्पादनात होणारी वाढ सातत्यपूर्ण नाही.

३. अन्न उपभोग प्राधान्यक्रमात होणारा बदल - अन्न व अन्नधान्यावरील उपभोग खर्चाचे प्रमाण घटले तर शरीरसुरक्षेस आवश्यक असणाऱ्या कॅलरीजसुद्धा घटतात. अन्न उपभोगासाठी मागणीचा प्राधान्यक्रम बदलतांना दिसतो.

४. दरडोई उपभोग - अन्नसुरक्षा दरडोई उपभोगावरून निश्चित होते. अन्नसुरक्षेसाठी दरडोई अन्नधान्य उपभोग वाढणे आवश्यक आहे.

भारतातील अन्नसुरक्षेचे वास्तव - भारतासारख्या विकसनशील देशात अन्नसुरक्षा महत्त्वाची आहे. भारतातील अन्नसुरक्षेचे वास्तव खालीलप्रमाणे आहे.

१. World Food Programme नुसार जगातील ५०% उपाशी लोक भारतात राहतात.
२. भारतात ३५% लोकसंख्या अन्न असुरक्षित आहेत.
३. भारतात १५ ते ४९ वर्ष वयोगटातील १० गर्भवती स्त्रियात ३ स्त्रिया कुपोषित असतात.
४. ५ वर्षांपेक्षा कमी वयाची ५०% मुले अल्पपोषित आहेत.

ही आकडेवारी निश्चितच अन्नसुरक्षेसाठी सर्व स्तरावर गांभीर्याने विचार करायला लावणारी आहे. कुपोषणाचा उपासमार टाळण्यासाठी अन्नसुरक्षा हा एकमेव उपाय आहे. भारतात अन्नसुरक्षिततेचा विचार करतांना अन्न व्यवस्थापनास उद्दिष्ट्ये महत्त्वाची ठरतात. १. अन्नधान्याची किंमत स्थिरता टिकवून ठेवणे. २. उत्पादकांना प्रेरणा देणे. ३. उपभोगासाठी अन्नसुरक्षा पुरविणे.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याची गरज - जागतिक मानवी हक्क विषयक जाहीरनामा कलम ११, अन्न व कृषी संघटनेचा अहवाल १९८३, जागतिक विकास अहवाल १९८६, पहिली जागतिक अन्नसुरक्षा परिषद १९७४ आणि जागतिक अन्नसुरक्षा परिषद २००९ नुसार प्रत्येक भूकंप्रस्तांना भूकेपासून मुक्त होण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. सन २०१५ पर्यंत जगाला भूकेपासून मुक्त करण्यासाठी जगातील प्रत्येक देशाने राज्यघटनेमध्ये घटनात्मक दुरुस्ती करून अन्नसुरक्षा कायदा संमत करावा असा निर्णय जागतिक अन्नसुरक्षा परिषदेत घेण्यात आला.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा २०१३, १२ सप्टेंबर २०१३ रोजी संमत करण्यात आला. डिसेंबर २०१२ मध्ये संसदेसमोर सादर करण्यात आलेले विधेयक ऑगस्ट २०१३ मध्ये संमत झाले. त्यापूर्वी ५ जुलै रोजी राष्ट्रपतींनी यासंबंधीचा अध्यादेश काढला होता (राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अध्यादेश २०१३) लोकसभा समितीच्या २७ व्या अहवालात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याचा प्रमुख उद्देश नमूद केला होता तो असा की, अन्नसुरक्षा म्हणजे देशांतर्गत अन्नधान्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी उपलब्धता असणे, तसेच वैयक्तिक पातळीवर पुरेशा प्रमाणात व माफक किंमतीत अन्नधान्य मिळणे तसेच प्रस्तावित कायद्यानंतर अन्नसुरक्षा हा मुद्दा कल्याणकारी पातळीवर न राहता तो अधिकार आहे व दोन तृतीयांश जनता सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत माफक दरात अन्नधान्य प्राप्त करू शकेल.

अन्नधान्य सुरक्षा कायद्यातील तरतूदी -

१. अन्नसुरक्षेची अंमलबजावणी करतांना पहिल्यावर्षी देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येचे प्रमाण असलेल्या ११४ जिल्हांचा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा लागू होईल.
२. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा विधेयकामध्ये एकूण लोकसंख्येचे दोन गट तयार केले. १. प्राधान्य गटातील कुटुंब, २. साधारण गटातील कुटुंब.
३. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा विधेयकातील तरतूदीनुसार ग्रामीण भागातील एकूण कुटुंबांपैकी ५० % कुटुंब आणि शहरी भागातील कुटुंबांपैकी ५० % कुटुंब राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचे लाभधारक होणार आहे.
४. देशातील ६८ % जनतेला अन्नधान्य स्वस्तात मिळण्याची हमी या कायद्यात आहे. यामुळे लाभार्थींना स्वस्त अन्नधान्य मिळणे हा कायदेशीर अधिकार आहे.
५. दारिद्र्य रेषेखालील प्रत्येक व्यक्तीला दरमहा ७ किलो अन्नधान्य त्यात गहू प्रति किलो २ रु., तांदूळ ३ रु. दराने मिळणार आहे.
६. राष्ट्रीय सल्लागार समितीच्या मते, प्राधान्य गटातील शहरी व ग्रामीण कुटुंबाला दरमहा ३५ किलो अन्नधान्य पुरविले जाईल. साधारण गटातील शहरी व ग्रामीण कुटुंबांना दरमहा २० किलो अन्नधान्य किमान आधार किंमतीत पुरवठा करण्याची व्यवस्था केली जाणार.
७. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा विधेयकात निराधार लोकांची आहार व्यवस्था, माता व बालक पोषण, भूकग्रस्तांची समस्या सोडविणे व बहुव्यापक पोषक आहाराची हमी देणे यासाठी वापरण्यात येणार.
८. या विधेयकानुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेबद्दल विकेंद्रीत धान्य वसुली, विकेंद्रीत धान्यसाठा, स्वयं-सहायता गटांचा वापर, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील खाजगी दुकानदारांचे प्रस्थ कमी करणे, सहकारी संस्थांचा वापर करणे, संगणीकरण वापरणे, स्मार्ट कार्ड वापरणे, बायोमेट्रीक तंत्राचा वापर करणे.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा विधेयकावरील आक्षेप -

१. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा विधेयकानुसार केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे व्यवस्थापन करणार असल्यामुळे राज्य सरकारला ते अडचणीचे होणार आहे.
२. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा विधेयकानुसार अन्नसुरक्षेबाबत राज्यापेक्षा केंद्र सरकारचे अधिकार वाढणार आहे.
३. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा विधेयकानुसार केंद्राचा अन्नसुरक्षा आयोग आणि राज्यांना राज्य अन्न सुरक्षा आयोग स्थापन करावा लागणार आहे.
४. मानवी हक्क आयोग आणि अनुसूचित जाती-जमाती आयोग याचा अनुभव विचारात घेता केंद्र आणि राज्यातील प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिक क्लिष्ट व गुंतागुंतीचे झाले आहे.
५. केंद्र व राज्य पातळीवरील स्वतंत्र दोन आयोगामुळे अन्नसुरक्षेचा प्रश्न सुटेल याबद्दल खात्री देता येत नाही.
६. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार यांना अधिक पैसा खर्च करावा लागेल. त्यामुळे दोन्ही सरकारच्या तिजोरीवर ताण पडेल.

७. सरकारने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा विधेयकाची अंमलबजावणी केली तर सरकार जवळ जवळ मोफत द्याने अन्न पुरवठा करणार आहे. त्याचा परिणाम बाजारपेठेवर होईल. एकदा जर बाजारपेठ कोलमडली की अर्थव्यवस्था कोलमडायला लागणार नाही.
८. सरकारला समतोल राखता आला पाहिजे की, बाजारपेठ व अर्थव्यवस्था कोसळणार नाही व गरीबांनाही अन्न पुरवठा करता येईल.
९. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा विधेयकाची अंमलबजावणी करतांना अन्नधान्याचे वितरण पारदर्शी व कार्यक्षम करण्याचे आदेश आहे.
१०. अन्नधान्याचे साठे सडत राहण्यापेक्षा अन्नधान्याचे वाटप करणे आवश्यक असतांना सरकार याकडे लक्षपूर्वक लक्ष करित आहे.
११. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा विधेयकानुसार साठवणूक करतांना नासाडी होणाऱ्या धान्याची बचत करण्याची योजना नाही.
१२. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा विधेयकामध्ये वास्तव दारिद्र्याचे प्रमाण लक्षात न घेतल्यामुळे गरजू लोकांना अन्नधान्याची सुमिळेल याची हमी देता येत नाही.
१३. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा विधेयकानुसार सरकार गरीबांसाठी अन्नधान्य मुक्त करणार आहे. अर्थशास्त्रीय दृष्ट्या ती योग्य आहे काय?

अन्नधान्य सुरक्षेची हमी देण्यासाठी उपाययोजना -

अन्न सुरक्षितता साध्य करण्यासाठी भारत सरकारने प्रभावीपणे व सातत्याने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

- देशातील लोकसंख्येच्या वाढीच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच एकूण अन्नधान्य उत्पादन व टरडोंड अन्न उपलब्धता यात वाढ होण्यासाठीचे धोरण राबवावे.
 - देशातील आर्थिक नियोजनाच्या सहाय्याने कृषी क्षेत्र विकासाचा दर वाढविणे.
 - शेतीला पाणी, वीज, औषधे, अवजारे, रस्ते, वाहतूक, दळणवळण, शिक्षण-प्रशिक्षण, संशोधन, विकास राबवून उत्पादन वाढीस प्रोत्साहन देणे.
 - शेतमालाला योग्य किंमत देण्याचे आणि शेतकऱ्याला शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्याचे धोरण राबविणे.
 - जमीन सुधारणा कार्यक्रम, सेंट्रीय शेती, जैवसेंट्रीय शेती, नैसर्गिक शेती इ. मध्ये वाढ करणारी धोरणे राबविणे.
 - देशातील रोजगार पातळी वाढविण्याबरोबरच दारिद्र्य व आर्थिक विषमतेचे प्रमाण कमी करण्याबाबतचे धोरण राबविणे.
 - देशातील अन्नधान्य आयात कमी करणारे धोरण राबविण्याबरोबरच कडधान्याच्या उत्पादनात वाढ करणे.
 - पडीत, खडकाळ, नापीक, डोंगराळ या प्रकारच्या जमीनीचा वापर करून विविध प्रकारची पिके विकसित करून धोरण राबविणे.
 - देशातील अन्नधान्य साठा वाढविण्याबरोबरच गोदामे वाढविणे व अन्नधान्य नासाडी थांबविण्याचे धोरण राबविणे.
 - शेतीपूरक व जोडव्यवसायांचा विकास करून दुसऱ्या हरीतक्रांतीच्या दिशेने उपाययोजना करणे.
 - देशातील प्रत्येक नागरीकांना जगविण्याची जबाबदारी सरकारची आहे त्याबाबतचे धोरण राबविणे.
 - सार्वजनिक ठिकाणच्या कार्यक्रमातील अन्नधान्याची नासाडी थांबविणे उदा. -लग्न, यात्रा, जत्रा इत्यादी.
- निष्कर्ष** - आज भारत हा कृषीप्रधान देश असूनही अन्नसुरक्षा साध्य करण्यात असमर्थ आहे. यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना लक्ष देणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना फक्त कर्जमाफी देऊन त्यांच्या समस्या सुटू शकत नाही तर सिंचनाच्या मदतीने स्वस्त कृषी अवजारे, वीज इ. सारख्या बाबतीत गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन द्यावे लागेल. त्यामुळे शेतीत अन्नधान्य वाढून अन्न सुरक्षा प्राप्त होण्यास मदत होईल. शेतीत दुसरी हरीतक्रांती घडवून आणणे गरजेचे झाले आहे. त्यासाठी अन्नसुरक्षेचा प्रश्न सुटेल.

अन्नधान्याच्या वाढत्या किंमती, उत्पादनातील हंगामी चढ-उतार, वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी ह्या सव्या अन्नसुरक्षेच्या संदर्भात महत्वाच्या वाटतात. भारतात आजही दारिद्र्यात जीवन जगणाऱ्या लोकांची संख्या मोठी आहे. अन्न साठवणुकीची समस्या, साठेबाजी व सट्टेबाजी, अन्नधान्याची नासाडी इ. समस्या अन्नसुरक्षेच्या संदर्भात आहेत.

आहेत. दारिद्र्य व आर्थिक विषमता, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी अन्नसुरक्षेत अडथळे आणत आहेत. खोटी रेशन कार्ड, धान्याची अपुरी उपलब्धता, नियंत्रण व व्यवस्थापनाचा अभाव ह्या महत्वाच्या समस्या अन्नधान्य सार्वजनिक वितरणात दिसून येतात. एकंदरीत भारतात पुरेशा प्रमाणात अन्न उपलब्धता असून सुद्धा कुपोषण व भूकबळी सारख्या समस्या आहेत.

संदर्भ -

१. एम. एस. स्वामीनाथन, देशाची अन्नसुरक्षा मजबूत व्हावी, दै. लोकमत, दि. २३ मार्च २०११.
२. जे. एफ. पाटील, अन्नसुरक्षा संकल्पना, व्यवस्था व आव्हाने, दै. सकाळ, दि. १३ नोव्हेंबर, २०११.
३. महाराष्ट्र सरकार आर्थिक पाहणी अहवाल, २०१० -११.
४. अर्थसंवाद -जानेवारी -मार्च २०१२, खंड ३५, अंक ४.
५. अर्थसंवाद -एप्रिल -जून २०१२, खंड ३६, अंक १.
६. अर्थसंवाद -जानेवारी -मार्च २०१५, खंड ३८, अंक ४.
७. योजना मासिक, जानेवारी -२०११.
८. योजना मासिक, डिसेंबर -२०१३.

प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे

उपप्राचार्य व विभागप्रमुख, अर्थशास्त्र

पी.डब्ल्यू.एस.कला व वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर

मो. ९६६५०१८४३२



“चंद्रपूर जिल्ह्यात एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पा अंतर्गत आदिवासीना राबविण्यात येणाऱ्या कृषी व संलग्न योजनाचा अभ्यास”

प्रा. प्रशांत लमाने¹, डॉ. प्रज्ञा बागडे²

¹सहाय्यक प्राध्यापक, संतोष भिमराव पाटील महाविद्यालय मंद्रूप.

²सहयोगी प्राध्यापक, पी. डब्ल्यू. एस. महाविद्यालय नागपुर.

प्रस्तावना :

1975 - 76 पासून समुदायाच्या विकासाला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली असून एस. सी. दुबे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाचव्या योजनेत आदिवासी उपयोजना या कार्यक्रमा अंतर्गत भारतातील विविध भागात विखुरलेल्या आदिवासी समुदायाची दारिद्र्य, गरीबी, बेकारी, शेतीचे परंपरागत स्वरूप, अंधश्रद्धा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आरोग्याची अवस्था, निरक्षरता व राहणीमानाची खालची पातळी इत्यादी सर्व समस्या लक्षात होता. या समस्या आदिवासी समुदायातून दूर करून आदिवासी समाजात आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक स्थान निर्माण करून त्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आदिवासी उपयोजना कार्यक्रमाची भारतात 22 राज्यात व 2 केंद्रशासीत प्रदेशात सुरुवात झाली.

संशोधनांची उद्दिष्टे -

- 1) प्रकल्पा अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या कृषी व संलग्न शिर्षाखालील योजनाचा आढावा घेणे.
- 2) प्रकल्पा अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या कृषी व संलग्न शिर्षाखालील योजनावर झालेला खर्च व प्राप्त निधी व लाभार्थ्यांचा अभ्यास करणे.

संशोधन माहिती संकलन व संशोधन पद्धती :

प्रस्तुत संशोधनासाठी प्राथमिक व दुय्यम स्त्रोताचा आधार घेण्यात आला आहे. प्राथमिक स्त्रोतात प्रत्यक्ष मुलाखती अनुसूचीचा उपयोग केला तर दुय्यम स्त्रोतात प्रकल्पा अंतर्गत प्रकाशीत अहवाल व प्रत्यक्ष प्रकल्पातील कार्यालयीन उपलब्ध साहित्याचा उपयोग केला आहे.

प्रस्तुत संशोधनासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील 10 आदिवासी बाहुल्य तालुक्याची निवड केली व 10 तालुक्यातून सहेतूक पद्धतीने उत्तरदात्याची नमुना म्हणून निवड केली आहे.

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाची पार्श्वभूमी :-

पहील्या पंचवर्षीक योजनेत आदिवासी विकास करण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रथम प्रयत्न करण्याची सुरुवात झाली. त्या योजनेत आदिवासी विकासासाठी काही प्रमाणात कार्यक्रमाची आखणी करून कार्यक्रम राबविण्यात आले. परंतु पहील्या योजनेत विशेष फलश्रुती आली नाही.

दुसऱ्या पंचवर्षीक योजनेत आदिवासी विकासाच्या दृष्टीकोनात काही नवीन योजना तयार करण्यात आली त्यात विविध तत्व दृष्टीकोनातून भारतातील आदिवासी विकास करण्यासाठी काही आदिवासी क्षेत्राची निवड करण्यात आल्यामुळे बाकी क्षेत्र विकासाच्या प्रक्रियेत बाहेर राहिले.

तिसऱ्या पंचवर्षीक योजनेत Varriear elevin कमिटीची स्थापना करून आदिवासी विकासासाठी Block System चा अवलंब करून आदिवासी विकास करण्याचा प्रयत्न केला. चवथ्या पंचवर्षीक योजनेत 489 Block ची विभागणी करून आदिवासी विकास करण्याचा याही योजनेत प्रयत्न केला परंतु वरील चारही योजनेत

पुरेशा नियोजना अभावी पुरेशा अभ्यासाविषयी कमतरता असल्यामुळे या योजना कालावधीत आदिवासी समुदायात विकास घडून आलेला नाही. त्यानंतर पाचव्या योजनेत आदिवासी उपयोजनाची सुरुवात करून या योजनेत TSP अंतर्गत विविध योजना राबवून फक्त त्याच्या उत्पन्नात वाढ करणे. एवढाच उद्देश नव्हता तर आदिवासी समुहात शाश्वत आधारावर त्याच्यात क्षमता व कुशलता निर्माण करणे हा होता.

या योजनेत राज्यात व केंद्रशासीत प्रदेशात आदिवासीच्या प्रमाणात निधीची उपलब्धता करून देणे. संपूर्ण नियोजन करण्याच्या दृष्टीकोनातून क्षेत्र विकासाला प्राधान्य देण्यात आले असून आदिवासी क्षेत्रात विविध संसाधन साधनाची शोध घेणे. आदिवासी विकासाच्या दृष्टीकोनातून ठळक रचनेची निर्मिती करणे. प्रशासनाच्या माध्यमातून विविध कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे. या योजनेत 65% आदिवासीचा अंतर्भाव झाला नसल्यामुळे सहाव्या पंचवार्षिक योजनेत माडा, मिमीमाडा व क्षेत्र विकास या माध्यमातून रचना करून आदिवासी उपयोजना 75% आदिवासी समुहाचा अंतर्भाव झाला.

आदिवासी उपयोजनेत भारतातील ज्या राज्याची व केंद्रशासीत प्रदेशाची लोकसंख्या 60% पेक्षा जास्त आहे. अशा राज्यात TSP लागू होत नाही. त्या राज्यांना वेगळी आदिवासी योजना विकासाच्या दृष्टीकोनातून विविध कार्यक्रम राबवून त्याची अंमलबजावणी केली जाते. (आंध्रप्रदेश, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, लक्षद्वीप व दादर & नगर हवेली)

चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प :-

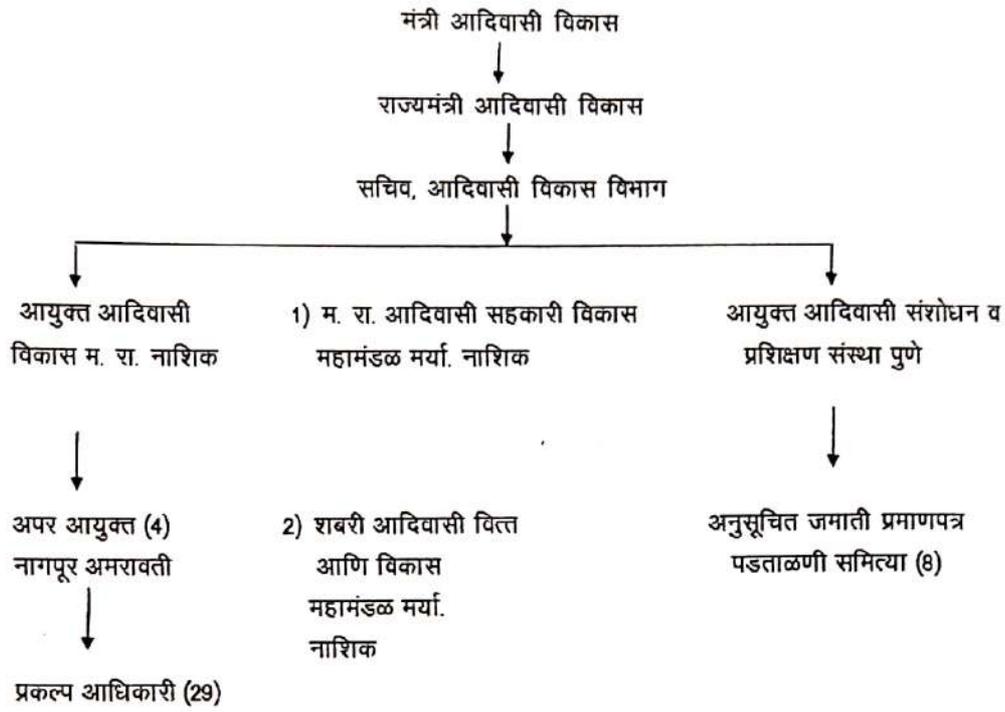
चंद्रपूर जिल्ह्यात 1975 पासून एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पा अंतर्गत आदिवासी समुदायाच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीकोनातून विविध शिर्षाखाली उपाशीर्षाखाली विविध योजना राबवून त्यांची अंमलबजावणी केल्या जाते अध्ययन क्षेत्रात चंद्रपूर एकात्मिक आदिवासी विकास व चिमूर एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प असे दोन प्रकल्प आहेत.

चंद्रपूर (ITDP) – चंद्रपूर, बल्लापूर, राजूरा, जिवती, पुंबूर्णा , सावली, मुल, सिदेवाही, कोरपणा, गोडंपिंपरी तालुक्याचा समावेश आहे.

चिमूर (ITDP) – चिमूर, वरोरा, भद्रावती, नागभिड, ब्रम्हपूरी या तालुक्याचा समावेश आहे.

प्रकल्पाचे प्रशासन –

आदिवासी विकास विभागाकडे सोपविलेल्या कामकाजामध्ये अधिक उत्तरदायी प्रशासन होण्याच्या दृष्टीने 1992 मध्ये या विभागाची पुर्णरचना करण्यात आली.



कृषी व संलग्न सेवा शिर्षाखाली प्रकल्पा अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजना -

प्रकल्पात कृषी व संलग्न सेवा या उपशिर्षाखाली खालील शिर्षाअंतर्गत विविध योजना राबविण्यात येतात त्या खालील प्रमाणे आहेत.

पिकसंवर्धन - आदिवासी शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याची योजना कृषी विभागामार्फत आदिवासी उपयोजनेखाली क्षेत्र, बाह्यक्षेत्र व माडा क्षेत्रात प्रामुख्याने 16 जिल्ह्यात राबविण्यात येते, या योजनेअंतर्गत आदिवासी कुंटूबाना विविध बाबीसाठी पुढीलप्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यात येते. - जमीन विकास कामे जुन्या विहिरीची दुरुस्ती, बैलजोडी व बैलगाडी पुरवठा, 300 मीटर पाईपलाईन, नलिका विहिरी, पंपसंच, नविन विहिरी, पुष्पोत्पादन विकास कार्यक्रम, परसबाग, ताडपत्री पुरवठा, तारेचे कुपण, धान्यकोठी, तुषार/ टिबळ सिंचन संच पुरवठा.

फलोत्पादन -

फलोत्पादन हा आदिवासीसाठी कृषी क्षेत्राशी संलग्न असलेला आदिवासी उत्पन्नदायी ठरणारा महत्वाचा कार्यक्रम आहे. त्यात फलोत्पादन रोप संरक्षण व बागायती रोपमळ्यांची स्थापना /बळकटीकरण या कार्यक्रमाद्वारे लहान व सीमांकीत आदिवासी शेतकऱ्यांना या योजनेतील 100 टक्के अनुदान देण्यात येते.

मुदा व जलसंधारण -

पाणवहाळ विकास कार्यक्रमाखाली पुढील कामे हाती घेण्यात येतात. समतल /श्रेणीबद्ध बांध, बांध बदिस्ती नाला बांध, ब्रशवुड कारणे, झाडा-झुडपांच्या बांधासह मांतीचे बांधकाम, अपवाहन बंधारे भुमीगत बंधारे, लाईव्ह चेक धरणे, शेततळे, सुटया सुटया धोडयाने केलेले बांधकाम इत्यादी.

पशुसंवर्धन- या कार्यक्रम हेतू आदिवासीना केवळ उत्पन्नाचे दुय्यम साधन द्यावे एवढ्या पुरताच मर्यादीत नसून त्यापासून त्यांना सकस आहार सुध्दा मिळू शकतो या कार्यक्रमा अंतर्गत गायी व म्हशीचे वाटप दुभत्या जनावरांचा खाद्य पुरवठा करणे, पैशु वैद्यकीय केंद्राची स्थापना पायाच्या व तोंडाच्या रोगाचे नियंत्रण पशु वैद्यकीय चिकीत्सालयाचे बांधकाम इत्यादीवर अनुदान व खर्च करण्यात येतो.

दुग्ध विकास:- या कार्यक्रमाद्वारे आदिवासीना दुग्ध व्यवसाय विकास व सुधारित पशुपालन पध्दतीचे प्रशिक्षण, उच्च वैदास क्षमतेच्या पाडयांचे वाटप आकड गाभण. म्हशीचे वाटप आदिवासी सहकारी दुग्ध संस्थांना मांडवली अनुदाने देण्यात येते.

मत्स्यव्यवसाय-

आदिवासी क्षेत्रात मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प घेण्यात आल्यामुळे मोठया संख्येने जलाशये निर्माण झालेली आहेत. माच्छीमारी व्यवसायामुळे आदिवासीची आर्थिक निवड पुर्ण होत आहे. त्यासाठी मत्सवीज वाटप अवरुध्द पाण्यात मत्ससंवर्धन. माच्छीमार सहकारी संस्था निर्माण करणे. मासेमारी साधनासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते.

वने - वनविकासाच्या कार्यक्रमात रोपवाटीकेची स्थापना औद्योगिक व व्यापारी प्रयोजनासाठी प्रजातीय वनलागवडी व निकृष वनात साधनसंपत्तीचा विकास किरकोळ जंगल उत्पन्नाचा विकास यांचा समावेश होतो तसेच वनक्षेत्रामध्ये पर्यटन स्थळाच्या विकासासाठी अनुदान देण्यात येते.

सामाजिक वनीकरण - सामाजिक वनीकरणाच्या कार्यक्रमांतर्गत खाजगी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर वनीकरण करणे आणि निवडक व पाणलोट क्षेत्रातील सामुद्रीक जमीनीवरील वृक्षलागवडीचा कार्यक्रम होण्यात येतो.

सहकार - सहकारी चळवळी ही आदिवासी क्षेत्रात आर्थिक विकासाचे एक महत्वाचे साधन ठरले आहे सहकारी संस्थांना भाग आडवल, अंशदान देण्यात येते. कर्ज फेडीसाठी सहकारी साखर कारखान्याचें भाग खरेदीकरिता आणि स्वस्त धान्य दुकान व्यवस्थापनासाठी अनुदान दिले जाते.

कृषी व संलग्न सेवा योजनेवर विविध वर्षात प्राप्त निधी व खर्च निधी

उपशिर्ष	वर्ष	खर्च (लाखात)	प्राप्तनिधी (लाखात)
पिक संवर्धन	2001-02	66.65	75.95
फलोत्पादन	2002-03	90.22	113.05
मुद व जलसंधारण	2003-04	111.25	132.35
पशुसंवर्धन	2004-05	200.23	256.43
दुग्ध शाळा विकास	2005-06	120.13	176.38
मत्स्य व्यवसाय	2006-07	144.47	162.67
वने व वन्य जीवन	2007-08	170.25	193.77
सामाजिक वगीकरण	2008-09	215.19	239.49
धान्यसाठवण गोदामे	2009-10	93.44	146.94
व पणन	2010-11	305.51	418.5
कृषी शिक्षण आणि	2011-12	637	897.18
प्रशिक्षण	2012-13	976.5	1251.92
सहकार	2013-14	1067.1	1185.66
	2014-15	1786.1	2052.98
	2015-16	1861.1	1959.16
	2016-17	1419.52	1494.23

स्त्रोत - चंद्रपूर व चिमूर क्षेत्र प्रकल्प कार्यालय

आदिवासी समाजाची आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती लक्षात होता एकात्मिक क्षेत्र विकास पध्दतीचा अवलंब केला तेव्हा कृषी प्रधानतेकडे लक्ष केंद्रीत करण्यात आले. कृषी व संलग्न सेवा हा त्याचाच परीपाक आहे. या योजनेमध्ये सर्वसाधारणपणे शेतीतील उत्पन्न वाढविणे शेतीशी संलग्न लघु उद्योगाला प्राधान्य देणे जसे पिक संवर्धन, फलोत्पादन गृह व जलसंधारण, पशुसंवर्धन मत्सय व्यवसाय सहकार इत्यादी विविध विभागामार्फत

उत्पन्ननिर्मिती असलेल्या वैयक्तीक लाभाच्या व कुटुंबाच्या लाभाच्या योजनेचा समावेश होतो. अध्ययन क्षेत्रातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत कृषी व संलग्न सेवा या शिर्षावर विविध वर्षाखाली प्राप्तानिधी व खर्च निधी वरील सारणीत दर्शविलेला आहे.

वरील सारणीतील विविध वर्षाखालील प्राप्त निधी व खर्च निधीचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते प्राप्त निधीपेक्षा सर्व वर्षात खर्चनिधीतील तफावत दिसून येते म्हणजे प्राप्त निधीतून कृषी व संलग्न या शिर्षाखाली होणारा खर्च कमी केलेला सारणीत निदर्शनास येते.

कृषी व संलग्न सेवा योजनेवर अध्ययन क्षेत्रात प्राप्तनिधी, खर्च निधी व लाभार्थी

अ. क्र	योजनांची नावे	प्राप्त निधी (लाखात)	खर्च निधी (लाखात)	लाभार्थी	राबविलेले वर्ष
1.	पी.व्ही.सी पाईप पुरवण	857.50	845	19950	2000 ते 2012
2.	कोटेरी कुंपण तार वाटप	23.492	20.13	247	2006 ते 2012
3.	किटक नाशके वाटप	13.18	12.05	658	2000 ते 2003
4.	तेलपंप पुरवण	730.50	723.18	3217	2000 ते 2012
5.	वीजपंप पुरवण	169.83	164.50	793	2000 ते 2000
6.	लोखंडी बैलगाडी पुरवठा	8.30	8.30	62	2006 ते 07
7.	फवारणी पंप पुरवठा	16.20	16.20	1385	2007 ते 09
8.	नवीन विहार बांधकाम	48.47	47.35	59	2002 ते 06
9.	ताडपत्री पुरवठा	52.11	50.15	572	2007 ते 12
10.	ग्रेजर मशीन पुरवठा	16.50	16.00	48	2006 ते 09
11.	टिंबक सिंचन योजना	प्रस्ताव मजुर	अनुदान प्राप्त	नाही.	
12.	वाटररोड डेव्हलपमेंट	25.18	24.25	113	2009 ते 11
13.	रेनवॉटर हार्वेस्टिंग	8.00	योजना कार्य प्रलंबित		
14.	जुन्या विहारीची दुरुस्ती	13.50	12.48	103	2002 ते 09
15.	संदीप खत पुरवठा	2.15	2.05	83	2006 ते 07
16.	किटकनाशके वाटप	13.98	13.00	671	2000 ते 08 2006 ते 08
17.	शेती अवजारे	5.15	4.95	147	2006 ते 08
	एकुण	2003.14	1959.59	28108	

स्रोत - चंद्रपूर व चिमूर क्षेत्र प्रकल्प कार्यालय

आदिवासी समुह हा शेती क्षेत्रावर जास्त प्रमाणात अवलंबून असल्यामुळे शेती क्षेत्राची असणारी परंपरागत पद्धत जागतिकीकरणात निभाव धरणे शक्य नसल्यामुळे आदिवासी समुहाला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शेती क्षेत्रात प्रगती करण्यासाठी आधुनिक तंत्राचा तसेच इतर संलग्नीत बाबीत बदल होणे आवश्यक बाब आहे त्यासाठी आदिवासी समुहाच्या विकासाच्या दृष्टीकोनातून प्रकल्पा अंतर्गत कृषी व उत्पन्न वाढीच्या योजना कार्यक्रम राबविणे आवश्यक आहे.

वरील कृषी संलग्न व उत्पन्न वाढीच्या योजनाची सारणी वरून असे निदर्शनात येते की, चंद्रपूर क्षेत्र प्रकल्पाला व चिमूर क्षेत्र 2003.84 लाख रुपये इतका निधी प्राप्त झाला. असून 1959.59 लाख रुपये निधी 28108 एवढ्या लाभार्थ्यांवर खर्च करण्यात आला तर 99.25 लाख रुपये एवढा निधी प्रकल्पा अंतर्गत खर्च करण्यात आला नाही. तेलपंप व PVC पाईप पुरवठा योजना सलग 12 वर्षात राबविण्यात आल्या असून इतर सर्व

योजनामध्ये प्रशासनाची चालढकल्यांची प्रवृत्ती दिसून येते तसेच टिंबक सिंचन योजना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना, शेतीचे सौर ऊर्जेपासून संरक्षण विहीरीमध्ये इनवेल बोअर करणे इ. योजनाबाबत प्रकल्पाने शासनात पाठपुरावा केलर मात्र प्रकल्पाला आव्हान प्राप्त झाले नाही.

निष्कर्ष -

- (1) प्रकल्पा अंतर्गत कृषी व संलग्न शिर्षाखालील विविध योजना राबविल्या जातात.
- (2) शासनाकडून प्रकल्पाला निधी कमी प्राप्त होतो.
- (3) प्रकल्पामार्फत विविध योजनावर प्राप्त निधी पूर्णता खर्च केल्या जात नाही.
- (4) प्रकल्पा अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेत सातत्य नाही.
- (5) प्रकल्पा अंतर्गत काही योजना काही वर्षान राबविल्या गेल्या.

संदर्भ -

- (1) लोटे रा. ज. आदिवासी समाजाचे समाजशास्त्र, पिंपळापुरे अँड क. पाब्लिशर्स, नागपूर, 2004.
- (2) गारे गोविंद आदिवासी प्रश्न आणि परिवर्तन, अमृत प्रकाशन, औरंगाबाद, 1994
- (3) नागतोडे गौडे गुरुनाथ, संशोधन पध्दती, फडके प्रकाशन, कोल्हापूर, 2011
- (4) वार्षिक आदिवासी उपयोजना अहवाल 2013 - 2014, 2010 - 15, 2015 - 16, 2016 - 17 : महाराष्ट्र शासन, आदिवासी विभाग
- (5) माहिती पुस्तिका सन 2015 - 16 : महाराष्ट्र शासन, आदिवासी विभाग
- (6) संपादीत, जिल्हा सामाजिक व आर्थिक, समालोचन, चंद्रपूर जिल्हा, 2011 - 12 अर्थ व सांख्यिकी संचनलाय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, 2012
- (7) W.W.W. Maharashtra.govt.in itdp
- (8) अर्थसंवाद त्रैमासीक
- (9) योजना मासीक

ISSN: 2249-894X

REVIEW OF RESEARCH



International Online Multidisciplinary Journal

Volume - 8 | Issue - 3 | December - 2018

Impact Factor : 5.7631(UIF)

वस्तू व सेवा कराचे स्वरूप, फायदे, तोटे व परिणाम : एक आढावा



प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे

विभागप्रमुख, अर्थशास्त्र, डॉ. मधुकरराव वासनिक पी.डब्ल्यू.एस.कला व वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर.

प्रस्तावना : कोणत्याही शासनाला आपले दायित्व पूर्ण करण्यासाठी उत्पन्नाची आवश्यकता आहे. कर हा उत्पन्न प्राप्तीचा मोठा व महत्वाचा स्रोत आहे. ज्याचा उपयोग लोक कल्याणाच्या

प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे

Page No :-5

Editor - In - Chief - Ashok Yakkaldevi



Content

Sr. No.	Title and Name of The Author (S)	Page No.
1	कवी गोविंदसुतांची 'अजबळी' एक शोध प्रा. डॉ. सौ. जयश्री संजय सातोकर	1
2	वस्तू व सेवा कराचे स्वरूप, फायदे, तोटे व परिणाम : एक आढावा प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे	5
3	Role Of Public Library In Community Development: An valuative Study On The District Of Dibrugarh And Sivasagar, Assam Mrs. Rashmi Rekha Buragohain and Ms. Jyotirupa Gogoi	11
4	A Comparative Evaluation Of Social Intelligence Between National, State and District Level Male Kabaddi Players Dr. Sharma Kailash and Dr. Bhandeo Milind	27
5	Oromo Indigenous Conflict Resolution Institutions: An Example Of African Indigenous Institutions Muleta Hussain Sedeto and Dr. Irshad Ahmad	31
6	A Vendor-Buyer Inventory Policy For Defective Item With Stochastic Demand And Variable Lead Time Gobindalal Mandal and Dr. Mahendra Rong	41
7	Effectiveness Of Jigsaw Learning In English Subject Jalpa H. Jani	55
8	Music: A Pedagogical Tool For The Cognitive Development Of Autistic Children Averi Sarkar, Dr. Indrani Mukhopadhyay and Dr. K.C. Sahoo	59
9	Impact Of Yogic Practices On Muscular Strength And Flexibility Among Physical Education Male Students Dr. G. Kumaran and bilal Ahmad Hajam	65



वस्तू व सेवा कराचे स्वरूप, फायदे, तोटे व परिणाम : एक आढावा



प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे
विभागप्रमुख, अर्थशास्त्र , डॉ. मधुकरराव वासनिक पी.डब्ल्यू.एस.कला
व
वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर.

प्रस्तावना

कोणत्याही शासनाला आपले दायित्व पूर्ण करण्यासाठी उत्पन्नाची आवश्यकता आहे. कर हा उत्पन्न प्राप्तीचा मोठा व महत्वाचा स्रोत आहे. ज्याचा उपयोग लोक कल्याणाच्या योजनांसाठी केला जातो. देशाच्या कर व्यवस्थेतून शासनाला पाहिजे त्या प्रमाणात महसूल मिळत नसेल तर शासनाला लोक कल्याणकारी योजना कार्यान्वित करण्यात अडचणी निर्माण होतात. म्हणून कोणत्याही देशाच्या मजबूत विकासासाठी प्रशासन आणि शाश्वत विकासाची करप्रणाली ही निर्देशक मानली जाते. कार्यक्षम कर प्रणालीमुळे सामाजिक उद्दिष्टे आणि आर्थिक वृद्धीस चालना मिळण्यासाठी आवश्यक सार्वजनिक निधीची दीर्घकालीन सुनिश्चितता मिळविता येते. करांचे प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर असे दोन प्रकार पडतात. प्रत्यक्ष कर उत्पन्नावर लावले जातात त्याचे संक्रमण करता येत नाही. तर अप्रत्यक्ष कर हा वस्तू व सेवांवर लावला जात असून त्याचे संक्रमण करता येते. या करांचा भार संपूर्णतः उपभोक्ता वर्गावर पडतो. अप्रत्यक्ष कर प्रणालीतील दोषांमुळे कर चुकवेगिरीचे प्रमाण वाढते. परिणामतः सरकारच्या महसूलात घट होवून देशाच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम होतो.

भारतातील कर प्रणालीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था या सर्वांना विविध प्रकारचे कर आकारणीचे अधिकार असल्यामुळे सामान्य नागरिकांपासून, व्यापारी आणि उत्पादकांनाही एकाच वस्तू आणि सेवांसाठी अनेक कर भरावे लागत असे. वस्तूच्या मूळ उत्पादनाच्या ठिकाणापासून ग्राहकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी त्या वस्तूची वाहतूक करतांना अनेक टप्प्यांवर कर भरावा लागत असे. ही स्थिती बदलण्यासाठी संपूर्ण देशभरात कोणत्याही वस्तू किंवा सेवांसाठी एकदाच कर भरण्यात यावा, कोणतीही वस्तू किंवा सेवा जिथे पुरविली जाणार आहे अशा एकाच ठिकाणी कराची आकारणी केली जावी. करांची पुनरावृत्ती टाळल्यामुळे ग्राहकाला कमी दरात वस्तू व सेवा मिळेल. ह्या संकल्पनेतून वस्तू व सेवा कराचा (GST) जन्म झाला.

वस्तू व सेवाकरामुळे (GST) यापूर्वीचे विक्री कर, सेवा कर, एक्साइज कर, लक्झरी कर, मनोरंजन कर आणि वॉट सारखे सर्व कर रद्द होतील. राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध कर प्रणालीला पर्याय म्हणून वस्तू व सेवाकराकडे (GST) पाहिले जाईल. ह्या करप्रणालीमुळे केंद्र व राज्य सरकारला समान वाटा मिळेल.

पार्श्वभूमी

भारताला जरी हा वस्तू आणि सेवा कर (GST) नवीन असला तरी वस्तू व सेवा कराला विश्वात १६५ देशांनी या आधीच स्विकारले आहे. जगात सर्वप्रथम फ्रान्सने १९५४ मध्ये ही करप्रणाली

स्वीकारलेली आहे. कॅनडात १९९१ पासून ह्या कर आकारणीला सुरुवात केली. २०१५ मध्ये मलेशियातही ही कर प्रणाली स्वीकारण्यात आली. भारतात सर्वप्रथम २००३ मध्ये केळकर समितीने सुद्धा कर सुधारणांचा भाग म्हणून वस्तु व सेवा कराची शिफारस केली होती. २००६.२००७ मध्ये केंद्रिय अंदाजपत्रकाच्या वेळी तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी वस्तु व सेवा कर लागू करण्याचा उल्लेख केला.

२८ फेब्रुवारी २००६ रोजी केंद्रिय अर्थमंत्र्यांनी प्रत्येक राज्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या अधिकारीता समितीला वस्तु व सेवा कराचा आराखडा तयार करून वस्तु व सेवा कराच्या विविध पैलू विषयी अभ्यास करून तसा अहवाल सादर करावा असे निर्देश दिलेले. २०१४ मध्ये मोदी सरकार अस्तित्वात आले त्यांनी हे विधेयक राष्ट्राची गरज आहे असे सांगून ६ मे २०१५ रोजी 'जीएसटी बील' लोकसभेत मंजूर करून घेतले. त्यावर राज्यसभेत सखोल विचारमंथन होवून १२२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ऑगस्ट २०१६ ला राज्यसभेत व ८ ऑगस्ट २०१६ ला लोकसभेत मंजूर होवून देशात नवीन कर प्रणाली लागू करण्याच्या अनेक अडचणी दूर झाल्यात. सध्या संपूर्ण जगात जीएसटी लागू करणाऱ्या १६५ देशांच्या पंक्तीमध्ये १६६ वा देश झाला आहे. जीएसटी हा स्वातंत्र्योत्तर काळातील अप्रत्यक्ष कर प्रणाली मधील सर्वात महत्वाचा व मोठा बदल आहे. ह्या बदलामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दुरगामी सकारात्मक परिणाम होणार आहे.

वस्तु व सेवा कर (GST) ची आवश्यकता

भारतातील अप्रत्यक्ष कर प्रणालीतील दोषांमुळे निर्माण झालेल्या समस्यांवर उपाय म्हणून जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. भारतात केंद्र व राज्य सरकारद्वारे अनेक वेगवेगळे अप्रत्यक्ष कर आकारले जात होते. विविध राज्यातील अप्रत्यक्ष करांचे संकलनही समाधानकारक नव्हते, यात कर चुकवेगिरी आणि भ्रष्टाचाराचे प्रमाणही वाढले होते. भारतातील अप्रत्यक्ष कर प्रणालीतील किचकटपणा हा विदेशी गुंतवणूकीसाठी सुद्धा नकारात्मक होता. या सर्व दोषातून मुक्ततेसाठी भारतात 'जीएसटी'ची आवश्यकता होती.

वस्तु व सेवा कर (GST) ची संरचना व स्वरूप

१. CGST (Central Goods & Service Tax) केंद्र सरकारच्या वतीने आकारण्यात येणाऱ्या वस्तु व सेवा कराला 'केंद्रिय वस्तु व सेवा कर' असे म्हणतात.

२- SGST (State Goods & Service Tax) राज्य सरकारमार्फत लावण्यात येणाऱ्या वस्तु व सेवा कराला 'राज्य वस्तु व सेवा कर' असे म्हणतात.

३. IGST (Integrated Goods & Service Tax) आंतरराज्य वस्तु व सेवांच्या पुरवठ्यावर लावण्यात येणाऱ्या वस्तु व सेवा कराला 'एकात्मिक वस्तु व सेवा कर' असे म्हणतात.

अ. राज्यांतर्गत झालेल्या व्यवहारावर कर लागेल व या कराचा ५० टक्के हिस्सा केंद्र सरकारला जाईल तर ५० टक्के राज्य सरकारला मिळेल.

ब. व्यवहार दोन राज्यांमध्ये झाला असेल तर कर आकारण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असून जे राज्य त्या वस्तु व सेवांचा उपभोग घेत आहे त्या राज्याला कराचा अर्धा हिस्सा मिळेल. तर कराचा अर्धा हिस्सा केंद्र सरकारला मिळेल.

क. IGST चा संबंध उपभोगाशी आहे. जे राज्य वस्तु व सेवांचा उपभोग घेतो त्या राज्यालाच कर मिळत असतो. अशी संरचना IGST अंतर्गत करण्यात आली आहे.

वस्तु व सेवा कर (GST) आकारणीचे स्वरूप

सर्वाधिक उपभोगाची पेट्रोलियम उत्पादने, विज.सेवा, कृषी उत्पन्न बाजार समिती इत्यादी जीएसटी च्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आले आहे. वस्तु व सेवा कराच्या आकारणीचे स्वरूप खालील पाच स्तरावर करण्यात आले आहे.

१) ००% वस्तु व सेवा कर

जीवनावश्यक वस्तु जीएसटीमधून मुक्त ठेवल्या आहेत त्या वस्तु व सेवांचा अंतर्भाव यात केलेला आहे. यात ताज्या भाज्या, पॅकबंद न केलेले अन्नधान्य, दूध, दही, अंडी, पीठ, बेसन, ब्रेड, पॅक बंद नसलेले पनीर, मध, फ्रेश मटन, फिश, चिकन, वर्तमान पत्र, शैक्षणिक सेवा, आरोग्य सेवा इ. वस्तूंचा समावेश करण्यात आला आहे.

२) ०५% वस्तु व सेवा कर

या दरात खाद्य तेल, स्किल्ड दूध, साखर, चहापत्ती, भाजलेल्या कॉफीबिया, मसाले, पिज्जा ब्रेड, रस, साबुदाना, केरोसिन, पॅकबंद पनीर, काजू, एल पी जी, पादत्राणे (५०० रु. पर्यंतची), कपडे (१००० रु. पर्यंतचे), रेल्वे तिकीट, लहान हॉटेल, अगरबत्ती या वस्तूंचा समावेश करण्यात आला आहे.

३) १२% वस्तु व सेवा कर

या दरात सॉस, फ्रुट ज्यूस, भुजिया, नमकीन, आयुर्वेदिक औषधी, फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स, बटर, पॅक ड्राय फ्रुट्स, एनिमल फॅट, टुथ पावडर, अगरबत्ती, कलर बुक्स, छत्री, सिलाई मशीन, सेलफोन इ. तसेच नॉन एसी हॉटेल्स, विमान तिकीटे इत्यादीचा समावेश आहे.

४) १८% वस्तु व सेवा कर

जॅम, सॉस, सूप, आईसक्रीम, इस्टेट फ्रुट मिक्सेज, मिनरल वॉटर, फ्लेवर्ड रिफाईंड शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्रीज, केक इत्यादी वस्तूंचा तसेच एसी हॉटेल्स, टेलीफोन सेवा, आयटी सेवा, ब्रान्डेड गारमेन्ट्स वर १८% वस्तु व सेवा कर लावण्यात येईल.

५) २८% वस्तु व सेवा कर

या दरात पेन्ट, डिओडरन्ट, सेव्हिंग क्रीम, हेअर शॅम्पू, डार्ई, सनक्रीम, वॉलपेपर, सीरॅमिक, टाईल्स, च्युइंगम, पान मसाला, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, एटीएम, वेंडींग मशीन, ऑटोमोबाईल्स, मोटर सायकल इत्यादी वस्तूंचा तसेच फाइव्ह स्टार हॉटेल, रेसक्लब, सिनेमागृह इत्यादींचा समावेश आहे.

वस्तु व सेवा कर (GST) ची कार्यपद्धती

१. या करपद्धतीच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण यंत्रणा ही ऑनलाईन असेल.
२. अप्रत्यक्ष कराच्या क्षेत्रामध्ये प्रस्ताविक नीवन वस्तु व सेवा कर प्रणाली अंतर्गत ००,०५,१२,१८ आणि २८ टक्के असे पाच स्तरीय कर व्यवस्था निश्चित केली.
३. कायदेशीर चौकटीमध्ये प्रामुख्याने या कर पद्धतीशी संबंधीत कायदे मंजूर करवून घेणे.
४. जेथे वस्तु व सेवांचा पुरवठा आंतर.राज्य व्यापारामध्ये येतो (IGST) तेव्हा वस्तु व सेवा कराच्या बाबतीत कायदे करण्याचे विशेष अधिकार संसदेस असतील.
५. केंद्राने आकारावयाच्या वस्तु व सेवा कराच्या बाबतीत कायदे करण्याचे अधिकार संसदेस असतील तर राज्यांनी आकारावयाचा वस्तु व सेवा कराच्या बाबतीत कायदे करण्याचे अधिकार राज्य विधान मंडळास असतील.
६. वस्तु व सेवा कराच्या आंतर.राज्य व्यापार किंवा वाणिज्य संबंधी कर आकारण्याचे आणि गोळा करण्याचे अधिकार भारत सरकारला आहे. वस्तु व सेवा कर परिषदेने शिफारस केल्याप्रमाणे संसदेने कायद्याने या कराची विभागणी केंद्र व राज्यांमध्ये करण्यात येईल.
७. यासाठी विविध कर विभागात विभागलेल्या विद्यमान कर्मचारी वर्गाचे एकत्रिकरण करणे आणि त्यांना प्रशिक्षण देणे हा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे.

८. विद्यमान प्रचलित विविध करांसाठी नोंदणीकृत उद्योग किंवा व्यापारी संस्थांना वेगळी नोंदणी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. त्यांची माहिती व डाटा 'जीएसटी' यंत्रणेत स्थलांतरीत करण्यात येईल. नव्याने अर्ज करणाऱ्यांना ऑनलाईन अर्ज करूनच स्वतःची नोंदणी करावी लागेल. पॅन आधारित नोंदणी क्रमांक राहणार आहे.

वस्तु व सेवा कर (GST) चे फायदे

१९४७ नंतर अप्रत्यक्ष कराच्या आकारणीत प्रथमच ग्राहककेंद्री दृष्टीकोन 'वस्तु व सेवा कर' च्या माध्यमातून दिसून येत आहे. त्यामुळे ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर त्याचा सर्वाधिक फायदा सामान्य नागरिकांना होणे अपेक्षित आहे. देशाला या वस्तु व सेवा कराच्या माध्यमातून खालील लाभ अपेक्षित आहेत.

- एकच कर असल्यामुळे करात पारदर्शकता येईल. कर भरण्याच्या व आकारण्याच्या पद्धतीत सहाय्यता आणि सुलभता येईल.
- देशाचा GDP वाढून देशाची आर्थिक विकासाकडे वाटचाल होईल.
- जीएसटी अंतर्गत विविध प्रकारच्या वस्तूंचे सोपे आणि साधे वर्गीकरण झाले असल्यामुळे कर लावतांना वस्तूंचे वर्गीकरण वादग्रस्त ठरणार नाही.
- वस्तु व सेवांच्या किंमती दीर्घकाळपर्यंत स्थिर राहतील, याचा फायदा ग्राहकांना निश्चितच होईल.
- जीएसटीमुळे उत्पादक कंपन्यांना फायदा होवून देशात एकसंध बाजारपेठ तयार होईल.
- ज्या उद्योगांची वार्षिक उत्पादकता २० लाखपर्यंत आहे अशा उद्योगांना जीएसटीमधून मुक्त ठेवण्यात आल्याने त्याचा फायदा लहान उद्योगांना होईल.
- राज्यांना पहिली पाच वर्षे केंद्र सरकार महसुलात तोटा भरून देईल त्यामुळे राज्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यात मदत होईल. ज्या राज्यात ग्राहक वर्ग मोठा असेल त्या राज्यांना करात जास्त वाटा मिळेल.
- पहिली तीन वर्षे राज्यांना १०० टक्के भरपाई दिली जाईल. नंतर चौथ्या वर्षाला ७५ टक्के व पाचव्या वर्षाला ५० टक्के भरपाई दिली जाईल.
- 'एक राष्ट्र एक कर' ही संकल्पना समाजात रुजेल, एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात व्यापार करतांना व्यापाऱ्यांना होणारा त्रास कमी होवून कर व्यवस्थेविषयी विश्वासाचे वातावरण निर्माण होईल.
- देशात वस्तु व सेवांची किंमत एकसारखी असल्यामुळे राज्या.राज्यात व ग्राहकांमध्ये भेदभाव केला जाणार नाही.
- जीएसटीमुळे असंघटीत उद्योगही कराच्या राज्यात येईल त्यामुळे सरकारचे उत्पन्न वाढेल आणि संघटीत व असंघटीत क्षेत्रातील तफावत कमी होईल.
- जीएसटीमुळे अत्यावश्यक वस्तु व सेवा कराचे प्रमाण अल्प ठेवले असल्यामुळे महागाईच्या दरात घट होईल. अत्यावश्यक वस्तु खरेदी करणे सर्वसामान्य उपभोक्त्यांच्या आवाक्यात येईल.
- जीएसटीची जास्तीत जास्त कर मर्यादा २८ टक्क्यांपर्यंत असल्यामुळे ज्या वस्तु व सेवांवर सध्या ३० ते ४० टक्के कर लावले जात होते अशा वस्तूंच्या किंमती कमी होतील.
- जीएसटी लागू होण्याचा सर्वात मोठा फायदा सर्व सामान्य व्यक्तीला होणार आहे. संपूर्ण भारतात कोणतीही वस्तु खरेदी करण्यासाठी एकच कर द्यावा लागेल. सर्व राज्यात एका वस्तूची किंमत सारखीच राहणार आहे.
- जीएसटी लागू झाल्यामुळे एकाच वस्तूसाठी अनेकवेळा कर देण्याची गरज भासणार नाही. कर वसुली करतांना वसुली अधिकाऱ्यांकडून अफरातफर करण्याची संभावना कमी होईल.

वस्तु व सेवा कर (GST) चे तोटे

- जीएसटी ही ऑनलाईन करप्रणाली आहे. लहान व्यापाऱ्यांना ऑनलाईन पद्धतीची पुरेशी माहिती नसल्यामुळे त्यांना कराचे शोधन करण्यासाठी त्रास सहन करावा लागेल.
- जीएसटीमध्ये ज्या वस्तु आणि सेवावर १८ टक्के कर मर्यादा ठरविली आहे. ते कर वाढणार नाही असे आश्वासन नाही. ती कर मर्यादा वाढू शकते. तसेच सध्या ज्या वस्तु आणि सेवावर कमी कर आहे त्या करामध्ये वाढ झाली तर उपभोक्त्यावर भुर्दंड पडेल.
- जीएसटीचा मोठा फटका बांधकाम क्षेत्राला बसणार आहे. नवीन घर व फ्लॅटच्या विक्रीवर १२ टक्के जीएसटी लागू झाल्यामुळे घर आणि फ्लॅटच्या किंमती वाढल्या. फ्लॅटला खरेदीदार मिळणे कठीण झाले आहे. बिल्डर अडचणीत आले आहे. ह्या क्षेत्रात बेकारी वाढण्याची शक्यता आहे.
- जीएसटी लागू होण्यापूर्वी बँका आणि वित्तीय संस्थाद्वारे पुरविल्या जाणाऱ्या सेवावर १८ टक्के जीएसटी लागत आहे. त्यामुळे बँका आणि वित्तीय संस्थांचे व्यवहार महाग झाले आहे. बँकेच्या ग्राहकाला आर्थिक व्यवहाराकरीता आधीपेक्षा जास्त पैसे लागत आहे.
- जीएसटीमध्ये केंद्र व राज्याचा जीएसटी स्वतंत्र असेल अशी तरतूद आहे. परंतु जमा होणारा महसूल राज्याच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. महापालीकेची जकात रद्द होत आहे. त्यामुळे राज्याच्या विकासाला पुरेसा पैसा उपलब्ध होणार नाही.

वस्तु व सेवा कर (GST) चे विविध क्षेत्रावर होणारे परिणाम

पूर्वी अप्रत्यक्ष कराची आकारणी राज्य सरकार व केंद्र सरकार वेगवेगळ्या पद्धतीने करीत असत. कर गोळा करण्याची ही पद्धत क्लिष्ट होती. या क्लिष्ट कर प्रक्रियेमुळे वस्तु व सेवांच्या किंमतीमध्ये वाढ झाल्यामुळे देशात निर्माण होणारी भाववाढ हा करव्यवस्थेचा परिणाम होता. अनेक करामुळे कर भरणाऱ्या घटकांना या कर प्रणालीमुळे अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत असे. या मधूनच गैरकारभार, कर चुकवेगिरी, भ्रष्टाचार, करावर कर असे परिणाम झाले होते. या सर्व बाबींमधून सुटका होण्यासाठी 'एक राष्ट्र. एक कर' ही प्रणाली परिणामकारक राहिल. ह्या दृष्टीने ह्या कर प्रणालीकडे पाहिले जात आहे.

अ) उद्योग क्षेत्रावर परिणाम

- कराचा वाढीव बोझा . औद्योगिक उत्पादन करणाऱ्या लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये आतापर्यंत दिड कोटी वार्षिक उलाढाल असलेल्या उद्योगांनाच केंद्रिय उत्पादन शुल्क भरावे लागत होते. मात्र आता २० लाख रु. वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या व त्या पुढील उद्योगांनाच कर भरावा लागणार आहे.
- कर गोंधळ . आर्थिक वर्ष २०१७ . १८ एप्रिल पासून सुरु झाले, जीएसटी मात्र १ जुलै पासून म्हणजे चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाही अखेर लागू झाले. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीसाठी वेगळी कररचना तर उर्वरीत महिण्यासाठी जीएसटी यामुळे गोंधळ झाला आहे.
- संगणकीय रचनेत बदल . केंद्रिय उत्पादन शुल्क मूल्यवर्धीत कर व सेवा कर भरता यावा यासाठी देशातील जवळपास प्रत्येक एसएमईने विशेष संगणकीय सॉफ्टवेअर किंवा इआरपी तयार करून घेतले आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर यामध्ये त्यांना बदल करावा लागला. नवी प्रणाली वापरण्याचे प्रशिक्षण कर्मचाऱ्यांना द्यावे लागले.
- पेट्रोलियम उत्पादनावर जीएसटी नाही . जीएसटी लागू होईपर्यंत तरी पेट्रोलियम उत्पादनावर तो लावण्यात आला नाही. मात्र भावी काळात यात बदल होऊ शकतो. राज्यांना पेट्रोलियम उत्पादनावर कर लावण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे उत्पादनाशी संबंधीत उद्योगांना टॅक्स इनपेमेंट क्रेडीटचा लाभ मिळेल की नाही याबद्दल अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
- किंमती वाढण्याची शक्यता . जीएसटी ००, ०५, १२, १८, २८ अशा पाच स्तरावर लागू झाली आहे. काही क्षेत्रात पहिल्यापेक्षा अधिक कर लागणार, त्यामुळे काही वस्तु महाग होण्याची शक्यता आहे.

- **विविध राज्यात नोंदणी आवश्यक** . एकाच वेळी अनेक राज्यात व्यवसाय करणाऱ्या एसएमई सह अन्य उद्योगांना प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र नोंदणी करून घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे करपूर्ततेसाठी उद्योगांवर बोझा वाढला आहे.
- **कामकाज खर्च** . जीएसटी ही अप्रत्यक्ष कराची वेगळीच व नवीन पद्धत असल्यामुळे एसएमई ना त्यासाठी बाहेरून सेवा घ्यावी लागत आहे. त्यामुळे त्यांचा कामकाज खर्च वाढत आहे.
- **ऑनलाईन शॉपिंगमुळे समस्या** . अनेक एसएमईनी ऑनलाईन वस्तु विक्री मंच सुरु केलेले आहेत. या वेबसाइटच्या आधारे एसएमई आपल्या मालाची विक्री अनेक राज्यात करतात. आता प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र नोंदणी करावी लागणार असल्यामुळे एसएमई च्या ऑनलाईन विक्री मंचाचे भवितव्य अंधारात दिसत आहे.

ब) बँकींग व सेवा क्षेत्रावर परिणाम

- बँका व बिगरबँक वित्त संस्था यांना प्रत्येक राज्यातील कामकाजासाठी जीएसटी अंतर्गत वेगळी नोंदणी करावी लागणार आहे.
- व्यावसायिक, कारखानदार, व्यापारी व कामगार हे अधिक चांगल्या संधीच्या शोधात एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जात असतील तर त्यांना सेवा देणाऱ्या संस्थेकडे त्यांचे वेगवेगळे पत्ते असतील. त्यामुळे केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
- एकाच बँकेच्या दोन शाखांमधील व्यवहाराकरिता कर लागू शकेल त्यामुळे बँकांची शाखानिहाय डोकेदुखी वाढणार आहे.
- बँकांना स्वतःच्या संगणकीय प्रणालीत बदल करून घ्यावे लागत आहे. खाते नोंदणी पद्धत, प्रशासन, नियंत्रणाची पद्धत यामध्येही बदल करावे लागत आहे.
- डेबीट कार्ड, क्रेडीट कार्ड, इंटरनेट बँकींग, चेक क्लिअरन्स, आरटीजीएस, निधी हस्तांतरण, डिमेट खाते इ. सेवावरील सेवा कर वाढवून १८ टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे या सर्व सेवा वाढल्या आहेत.

क) इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रावर परिणाम

- **स्मार्ट फोन** — स्मार्ट फोनवर एकूण १३.५ टक्के कर लागत होता तो जीएसटी लागू झाल्यानंतर १२ टक्क्यांवर आला आहे. त्यामुळे स्मार्ट फोनच्या किमतीत घट झाली आहे. स्मार्ट फोन तयार करण्यासाठी लागणारे सुटे भाग १२ टक्के जीएसटी अंतर्गत आले आहे. 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत देशात तयार होणाऱ्या स्मार्ट फोनला आणखी सवलती देण्याचे सरकारने ठरविल्यास स्मार्ट फोन आणखी स्वस्त होतील.
- **कॅमेरा, मॉनिटर, टिव्ही** — टिव्ही, कॅमेरा, स्पीकर, संगणक, मॉनिटर यांच्यावर १८ टक्के जीएसटी लागणार आहे. त्यामुळे ह्या वस्तु किंचित महाग होण्याची शक्यता आहे.

ड) मनोरंजन क्षेत्रावर परिणाम

- सर्व प्रकारच्या प्रसारण सेवेसाठी टिव्ही, केबल, डीटीएच फिल्म तसेच डिजीटल माध्यमासाठी १५ टक्के कर द्यावा लागत होता. यावर ८ ते १२ टक्के अन्य कराचाही बोझा होता. जीएसटी नंतर १८ ते २० टक्के कर द्यावा लागत आहे. त्यामुळे ग्राहकावरील बोझा कमी होऊ शकतो.
- **पीव्हीआर सारख्या चित्रपटगृह साखळीसाठी जीएसटी लागू** होणे पथ्यावर पडणार आहे. त्यामुळे चित्रपट निर्मात्यांसाठी जीएसटी लाभदायक होणार आहे.
- **मल्टीप्लेक्सना २७ टक्के कर द्यावा लागत होता.** जीएसटी लागू झाल्यानंतर कराचा बोझा कमी होऊ शकतो.
- **स्थानिक संस्थाकडून लावला जाणारा मनोरंजन कर मूळ जीएसटी बरोबर लावला जाणार आहे.**

इ) जाहिरात क्षेत्रावर परिणाम

- **एफएमसीजी उद्योगांना पूर्ण इनपूट टॅक्स क्रेडीट मिळणार आहे.** त्यामुळे जाहिरातीचा खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे.

- वाहन उद्योगातील कंपन्यांना इनपूट क्रेडीटचा लाभ मिळणार असल्यामुळे वाहनाच्या जाहिरातीवरील खर्च कमी होईल.

निष्कर्ष

वस्तु व सेवा कर (GST) हे भारताच्या अप्रत्यक्ष कर सुधारणा क्षेत्रातील एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक करांचे एकत्रिकरण फक्त एका करात केल्याने समान राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण होईल. करांतील गुंतागुंत कमी होवून भ्रष्टाचाराच्या वाटा बंद होवून विकासाचा वेग वाढेल, आर्थिक क्रियाशिलता वाढेल. कोणत्याही परिवर्तन व्यवस्थेत सुरुवातीला परिवर्तनाचा त्रास सर्वसामान्य जनतेला सहन करावा लागतोच. कारण त्यामागे भविष्यात चांगले फळ मिळेल ही अपेक्षा असते. केंद्र सरकारने येत्या तीन वर्षांपर्यंत राज्य सरकारच्या महसुलातील तोटा १०० टक्के व चौथ्या वर्षी ७५ टक्के व पाचव्या वर्षी ५० टक्के भरून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. याचा राज्य सरकारला फायदा होईल. जीएसटीचे दर सुस्पष्ट असल्यामुळे राज्य सरकार व केंद्र सरकार महसुलाविषयी अंदाज बांधून कल्याणकारी योजनांची आखणी चांगल्या प्रकारे करू शकतील.

एकंदर, जगभरामध्ये दिडशेहून अधिक देशात या प्रणालीचा यशस्वीरीत्या स्विकार केलेला आहे म्हणून भारतातही याची यशस्वीता अपेक्षित आहे.

संदर्भ :

- १) वस्तु व सेवा कर एक दृष्टीक्षेप : वित्त विभाग महाराष्ट्र शासन.
- २) जीएसटी कायदा (तोंड ओळख) अॅड. गोविंद पटवर्धन.
- ३) योजना मासिक : ऑगस्ट २०१७.
- ४) उद्योजक मासिक : २०१७.
- ५) अर्थसंवाद .मराठी अर्थशास्त्र परिषदेचे त्रैमासिक जूलै.सप्टेंबर २००५.
- ६) अर्थसंवाद .मराठी अर्थशास्त्र परिषदेचे त्रैमासिक जूलै.सप्टेंबर २०१६.
- ७) लोकमत समाचार वृत्तपत्र : २० मे २०१७.
- ८) सकाळ ऑनलाईन आवृत्ती : ८ ऑगस्ट २०१६.
- ९) लोकमत ऑनलाईन आवृत्ती : १ जुलै २०१७.



प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे

विभागप्रमुख, अर्थशास्त्र , डॉ. मधुकरराव वासनिक पी.डब्ल्यू.एस.कला व वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर.

ISSN: 2249-894X Impact Factor : 5.7631(UIF)

Volume - 8 | Issue - 9 | June - 2019

REVIEW OF RESEARCH

International Online Multidisciplinary Journal



भारतातील पर्यटन उद्योग : एक आर्थिक अध्ययन



डॉ. प्रा. प्रज्ञा बागडे

अर्थशास्त्र, विभागप्रमुख, डॉ. मधुकरराव वासनिक पी. डब्ल्यू. एस. कला व वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर.

प्रस्तावना : परिवर्तन हा निसर्गाचा नियम आहे, प्राचीन काळापासून मानवाला प्रवास करण्याची आवड आहे. मानवांच्या वस्त्यांची निर्मितीसुद्धा याच माध्यमातून झाली आहे. नवनवीन ठिकाणे

Page No :-21

Editor - In - Chief - Ashok Yakkaldevi



Content

Sr. No.	Title and Name of The Author (S)	Page No.
1	सरगुजिहा बोली : गुरतुर बोली कुसुमलता प्रजापति	1
2	गोटूल : दशा एवं दिशा डॉ.जी.डी.एस.बग्गा , ममता ठाकुर	13
3	भारतातील पर्यटन उद्योग : एक आर्थिक अध्ययन डॉ. प्रा. प्रज्ञा बागडे	21
4	जगदीश चन्द्र कृतः प्रतीकवादी शिल्प-विधि प्रधान उपन्यास नवजोत कौर , डॉ. विनोद कुमार	27
5	कर्णबधीर विद्यार्थ्यांच्या कथनात्मक वाचन आकलनावर स्कॅफोल्डिंग पद्धतीच्या होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास सौ. शर्मिष्ठा ओक , डॉ. वर्षा गटठू	33
6	Impact Of Achievement Motivation On Self Regulated Learning Of Senior Secondary School Students Rekha Dalal and Dr. Indira Dhull	39
7	The Epistemic Discourse Of Indian Philosophies-Svathah And Parataphpramanayavada With Special Reference To Mimansa And Nyaya Philosophy Miss. Nandini Deka	45
8	Profitability Analysis Of NFL And DFCL –A Comparative Study Dr. C. Vadivel and Mrs. S. Sivaselvi	47
9	Effects And In Situation Of The Insolvency And Bankruptcy Code 2016 On Real Estate Regulation And Development Act (RERA) Bansari Joshi	51



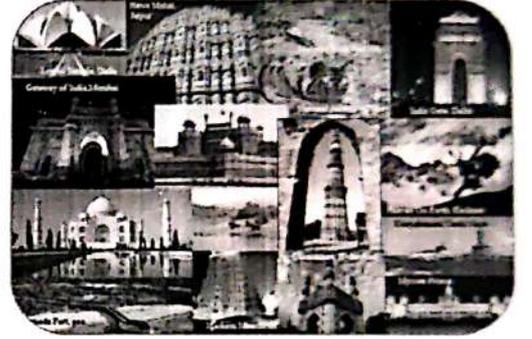
भारतातील पर्यटन उद्योग : एक आर्थिक अध्ययन

डॉ. प्रा. प्रज्ञा बागडे

अर्थशास्त्र, विभागप्रमुख, डॉ. मधुकरराव वासनिक पी. डब्ल्यू. एस. कला व वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर.

प्रस्तावना

परिवर्तन हा निसर्गाचा नियम आहे, प्राचीन काळापासून मानवाला प्रवास करण्याची आवड आहे. मानवांच्या वस्त्यांची निर्मितीसुद्धा याच माध्यमातून झाली आहे. नवनवीन ठिकाणे पाहण्यासाठी, आपल्या सभोवतालच्या वातावरणात बदल व्हावा म्हणून, नवनवीन गोष्टींची माहिती व्हावी, नवीन काहीतरी प्राप्त करता यावे, आनंद उपभोगावा यासाठी मनुष्य सतत प्रवास करित आलेला आहे. यालाच पर्यटन म्हटले आहे. सद्यःस्थितीत पर्यटनाला महत्व प्राप्त झाले असून त्याचा विकास अत्यंत वेगाने होत आहे. आधुनिक काळात हा एक स्वतंत्र राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय उद्योग म्हणून विकसित झाल्याचे दिसून येते. या उद्योगाचे महत्व आर्थिक विकास व रोजगार संधी निर्माण करण्याचे एक साधन आहे ह्या दृष्टीने अधिक आहे. म्हणून ह्या संशोधन पत्रात आर्थिक अध्ययनाच्या दृष्टीकोनातून भारताच्या संदर्भात पर्यटन क्षेत्राचा अभ्यास करण्यात आला आहे.



संशोधनाची उद्दिष्ट्ये

पर्यटन भारताच्या विकासाकरीता मोलाचा वाटा म्हणून विचार केला जाऊ शकतो. उद्योगांना चालना, बेरोजगारांना रोजगारी, तसेच आर्थिक व सामाजिक विकास घडून येऊ शकतो. या दृष्टीने संशोधनाचे महत्व आहे.

१. पर्यटनाची स्थिती अभ्यासणे.

२. पर्यटन ह्या जलद गतीने वाढणाऱ्या उद्योगाचा अभ्यास करणे.

३. पर्यटनामुळे भारताच्या उत्पन्नात व रोजगारातील वाढीचा शोध घेणे.

४. पर्यटनाच्या विकासासाठी

संज्ञा ट्रॅव्हलर (प्रवासी) या शब्दाऐवजी एकोणवीसाव्या शतकांभी वापरण्यात येऊ लागली. देशातील तसेच परदेशातील पूरावास्तू, इतिहास, प्रसिद्ध व निसर्गरम्य स्थळे, प्राचीन कला निर्मितीची केंद्र, पवित्र तिर्थस्थळे, प्रचंड औद्योगिक व इतर प्रकल्प इत्यादींचे आकर्षण ही पर्यटनामागील मुख्य प्रेरणा आहे. ही प्रेरणा सार्वत्रिक व सर्वकालीन असली तरी आधुनिक काळातील ज्ञानप्रसाराची व दळणवळणाची सुलभ साधने विकसित झाल्याने आधुनिक पर्यटन उद्योगास विशेष चालना मिळाली.

असलेली भ्रमंती होय.” हर्मर यांच्या मते, “परदेशी व्यक्तीचे एखाद्या देशात आगमन होणे, भ्रमंती करणे व परत स्वगृही जाणे म्हणजे पर्यटन होय.” जागतिक पर्यटनाच्या मते, “एखादी व्यक्ती आपल्या वास्तवाच्या ठिकाणापासून दुसऱ्या ठिकाणी सलग एका वर्षापेक्षा अधिक काळा न राहता आराम, व्यवसाय आणि इतर कामासाठी प्रवास करते त्या सर्वांचा पर्यटनात समावेश होतो.” इ. स. १९७६ मध्ये ब्रिटन मधील पर्यटन संस्थेने केलेल्या व्याख्येनुसार “पर्यटन म्हणजे लोकांनी राहत्या स्थानापासून काही अंतरावरील स्थायी अल्पकालीन

उपाययोजना सूचविणे.

पर्यटन : अर्थ व व्याख्या
पर्यटन म्हणजे प्रवास. इंग्रजी भाषेतील 'टुरिझम' या संज्ञेचा हा पर्याय आहे. इंग्रजी भाषेत टुरीस्ट म्हणजे पर्यटक. ही

व्याख्या

स्वीस प्राध्यापक हुझीकेर व क्रॅप यांनी १९४२ मध्ये पर्यटनाची व्याख्या केली. "पर्यटन म्हणजे कायम स्वरूपाची वस्ती न करण्याच्या हेतूने अविनाशी व्यक्तींच्या सहवासातून आर्थिक उत्पादनाशिवाय

केलेले स्थलांतर होय. हे स्थलांतर संशोधन, व्यवसाय, मनोरंजन व ऐशआराम यासाठी केलेले असते. "

पर्यटन : एक उद्योग

आधुनिक काळात पर्यटनाच्या अनेक पैलूंचा विचार करणे आवश्यक आहे. पर्यटनाच्या अनेक पैलूंपैकी शैक्षणिक, वैद्यकीय, मनोरंजन, धार्मिक, सांस्कृतिक, नैसर्गिक व ऐतिहासिक इ. पैलू महत्वपूर्ण ठरतात.

आर्थिक दृष्टीकोनातून पर्यटन उद्योग महत्वाचा ठरतो. पर्यटन उद्योगामुळे सेवा उद्योगांना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त झाले आहे. वस्तू व त्यांचे उत्पादन, वितरण व सेवन हेच दीर्घकाळ आर्थिक विश्लेषणाचे प्रमुख चर्चा विषय होते. पर्यटनामुळे देशात परदेशात हजारो माणसांची वाढती वर्दळ व हालचाल ह्यामुळे सेवाक्षेत्राला एकूण उत्पादनाच्या वर्तुळात महत्वाचे स्थान प्राप्त होऊ लागले. पर्यटनामुळे व्यापारांचे प्रमाण व परिणाम ह्यांचा विस्तार झाला. हिमाच्छादीत पर्वत शिखरे, निर्मनुष्य समुद्रकिनारा, निर्मनुष्य वन प्रदेश या उपेक्षाणीय गोष्टी पर्यटन क्षेत्रात येऊ लागल्या व त्या प्रथम दर्जाच्या आर्थिक सत्ता ठरल्या.

पर्यटनावर पैशाचा जो प्रत्येक एकक खर्च होत असतो, तो संबंध अर्थव्यवस्थेत फिरत असतो आणि त्यामुळे त्याच्याशी ज्या-ज्या लोकांचा संबंध येतो त्यांचा वाढीव प्रमाणात फायदा होत राहतो. पर्यटनामुळे जो प्रत्यक्ष पैसा मिळतो, त्याहीपेक्षा राष्ट्रीय उत्पन्नामुळे गुणक परिणामामुळे जी भर पडते तीचे महत्व अधिक असते. पर्यटनातून त्या-त्या विभागातील लोकांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतात. त्यातून आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होते.

अर्थशास्त्रज्ञांनी पर्यटनाचा गुणक परिणाम भारताच्या बाबतीत ३.४ एवढा काढला आहे. दुसऱ्या शब्दात, एका पर्यटकाचा एक रुपया खर्च झाल्यास त्यामुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये ३.५ रु. किंमतीची उलाढाल होते. भारतात सन २०१७-१८ या काळात ८ टक्के रोजगार पर्यटन उद्योगातून निर्माण होण्यास मदत झाली आहे. पर्यटन उद्योगाच्या वाढीबरोबर देशातील बँकिंग सुविधा, आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ झाली आहे. पर्यटन मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालानुसार २०१७-१८ मध्ये ९.२ टक्के पर्यटनाचे जी.डी.पी.तील योगदान राहिले आहे. वर्ल्ड ट्रेव्हल्स अँड टुरिझम कौन्सिलने २०११ मध्ये वर्तविलेल्या अंदाजानुसार २०११ ते २०२१ या दशकात दरवर्षी ८.८ टक्के इतकी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

पर्यटन हा उद्योग जगातील सर्वात मोठा आणि झपाट्याने वाढणारा उद्योग आहे. युनायटेड नेशन्स वर्ल्ड टुरिझम ऑरगनायझेशन (UNWTO) ने स्पष्ट केल्याप्रमाणे जागतिक स्तरावर एकूण उत्पन्नात पर्यटनापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे प्रमाण ९ टक्के आहे. पर्यटन निर्यातीचा विचार केला असता सन २०१२ मध्ये १.३ ट्रिलियन यु. एस. डी. एवढी निर्यात झाली असून ती एकूण निर्यातीच्या ६ टक्के असलेली आढळून येते. या व्यवसायामुळे नवीन पर्यटन विपणनाला चालना मिळाली आहे.

जगातील काही देशांची तर बहुतांश अर्थव्यवस्थाच तेथील पर्यटनावर अवलंबून आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशातील पर्यटन गेल्या दशकात २५ ते ३० टक्क्यांनी वाढले आहे आणि त्यामुळे मिळणाऱ्या परकीय चलनात ४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

पर्यटनाचे फायदे

एका व्यक्तीने किंवा व्यक्ती समुहाने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी मनोरंजनासाठी, अभ्यासासाठी, कामासाठी केलेला प्रवास म्हणजे पर्यटन होय. पर्यटन हे फुरसतीचा वेळ आनंदात घालविण्याचे एक साधन म्हणून जगभरात लोकप्रिय झाले आहे.

पर्यटकांना लागणाऱ्या वस्तू व सेवा पूरविण्यासाठी प्रवासी सेवा, हॉटेल्स, मनोरंजन सेवा, परिवहन सेवा, गाईड अशा अनेक पर्यटनासाठी संबंधीत व्यवसायांचा विकास होतो व लोकांना रोजगार उपलब्ध होतो आणि पर्यटनाच्या ठिकाणी एक बाजारपेठ निर्माण होत असते.

पर्यटन उद्योगामध्ये पर्यटनाच्या अनेक बाबींचा समावेश होतो. सामाजिक पर्यटन, कृषी पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, शैक्षणिक पर्यटन, निसर्ग पर्यटन अशा प्रकारच्या पर्यटनामुळे पर्यटन उद्योगाला आज चांगले दिवस प्राप्त झाले आहेत. या पर्यटन उद्योगाच्या माध्यमातून अनेक देशांचा अनेक देशांशी प्रत्यक्ष संबंध येतो, त्यामुळे अनेक देशांच्या संस्कृतीची ओळख होते. अनेक देशातील अनेक वस्तूंची माहिती होते. त्यांच्या आवडी.निवडी माहिती होतात.

भारत आणि पर्यटन

भारतासारख्या विकसनशील देशात पर्यटन हे रोजगार निर्मितीचे तसेच आर्थिक विकासाचे एक महत्वपूर्ण स्रोत ठरले आहे. अलिकडे उपलब्ध माहितीनुसार चालू दशकात भारताने पर्यटन क्षेत्रात एकूण जीडीपीच्या ९.२ टक्के पर्यत योगदान दिले आहे. भारताच्या वाढत्या लोकसंख्येला रोजगार उपलब्ध करून देण्याची क्षमता शेती पाठोपाठ पर्यटन क्षेत्रात आहे. याबाबत दुमत नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे संपूर्ण जगभरात जलद गतीने विकसित होणाऱ्या या पर्यटन उद्योगात भारताचा ५ वा क्रमांक लागला आहे ही आपल्यासाठी अभिमानाची बाब आहे.

मार्च १९५८ मध्ये वाहतूक मंत्रालयात एका स्वतंत्र पर्यटन मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. पर्यटनाची सर्व खाती मंत्रालयाकडे सोपविण्यात आली. एक उपसंचालक व चार संचालकांची नेमणूक करून त्यांच्याकडे प्रशासन, प्रसिद्धी, जनसंपर्क, नियोजन व विकास ही कार्ये सोपविण्यात आली. १४ मार्च १९६७ रोजी भारतात स्वतंत्र पर्यटन व नागरी हवाई वाहतूक विभागाची स्थापना करण्यात आली.

भारतात काही राज्यात विदेशी पर्यटक विशेष प्रमाणात आकर्षित होतात. त्यामुळे त्या राज्यातील आर्थिक विकासात पर्यटन क्षेत्राचे स्थान महत्वपूर्ण आहे. पर्यटन व्यवसायाद्वारे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उत्पन्न प्राप्त होते. भारतातील पर्यटन क्षेत्राचा अभ्यास करतांना विदेशी पर्यटकांची संख्या, विदेशी मुद्रारूपी उत्पन्न व रोजगारातील योगदान तपासून पाहण्यात आले.

भारतात सन २०११ ते २०१८ या कालखंडात आलेले विदेशी पर्यटक व विदेशी मुद्रा

वर्ष	विदेशी पर्यटक		विदेशी मुद्रा	
	संख्या (कोटी)	प्रतिशत बदल	कोटी रु.	प्रतिशत बदल
२०११	६.३१	९.२	७७,५९१	१९.६
२०१२	६.५८	४.३	९४,४८७	२१.८
२०१३	६.९७	५.९	१,०७,६७१	१४
२०१४	७.६८	१०.२	१,२३,३२०	१४.५
२०१५	८.०३	४.५	१,३५,१९३	८.८
२०१६	८.८०	९.७	१,५४,१४६	१४.३
२०१७	१०.०४	४०.०	१,७७,८७४	१५.४
२०१८	१०.५६	५.२	१,९४,८८२	९.६

स्रोत — वार्षिक रिपोर्ट २०१८-१९, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार.

वरील तक्त्यावरून सन २०११ ते २०१८ या कालावधीत भारतात आलेल्या पर्यटकांच्या संख्येत व भारताला मिळणाऱ्या विदेशी मुद्रेत मोठ्या प्रमाणात दरवर्षी वाढ होतांना दिसत आहे.

भारतात सन २०११ ते २०१८ या कालखंडात पर्यटनातून निर्माण झालेला रोजगार

वर्ष	रोजगाराचे प्रतिशत प्रमाण
२०११	७.८
२०१२	७.९
२०१३	७.६
२०१४	९.४
२०१५	८.७
२०१६	८.५
२०१७	८
२०१८	८.१

स्त्रोत — वार्षिक रिपोर्ट २०१८.१९, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार.

वरील तक्त्यावरून पर्यटन क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होत असला तरी अनेक विकासात्मक बाबी करता येण्यासारख्या असून त्यामुळे पर्यटन क्षेत्रातील रोजगारीचे प्रमाण वाढू शकते.

विविधतेने नटलेल्या भारत देशाचे भौगोलिक व्यक्तिमत्व पर्यटन उद्योगाच्या विकासाकरीता अत्यंत अनुकूल आहे. येथे अनेक जाती, धर्म, परंपरा असलेले सव्वाशे कोटी लोक निवास करतात. भारतातील विदेशी पर्यटकांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतांना दिसत आहे. परिणामतः विदेशी मुद्रारूपी उत्पन्न व रोजगारातही लक्षणीय वाढ होतांना दिसत आहे. मूलतः विदेशी पर्यटक भारताकडे आकर्षित होतांना दिसतात.

१. विविध परंपरा व संस्कृती

भारतातील विविध परंपरा व उत्साहवर्धक धार्मिक विधी अनेकदा विदेशी पर्यटकांवर छाप सोडून जातात. भारतामध्ये साजरे होणारे सण पाहण्यासाठी हे पर्यटक मोठ्या प्रमाणात उत्साहाने भारतात येतात.

२. पदार्थातील विविधता

भारतीय खाद्यपदार्थांमध्ये असलेली विविधता परदेशी पर्यटकांना खास करून आवडते. शाकाहारी आणि मासाहारी अशा दोन्ही प्रकारचे पदार्थ भारतामध्ये उत्तम मिळतात.

३. भारतीय साहित्य, संगीत व चित्रकला

भारतातील साहित्य व संगीत विदेशातील लोकांना भुरळ घालतात. भारतात विविधतेमध्ये एकता आढळून येते. प्रत्येक राज्याची लोककला, संस्कृती, भाषा अनेकविध असल्यामुळे उत्तर भारतातील कथक नृत्य, दक्षिण भारतातील भरतनाट्यम, मणीपूरी नृत्य, मध्य भारतातील लोकनृत्य तसेच चित्रकलेचे दर्शन होते.

४. शिल्पकला व स्मारके

भारतातील शिल्पकला वाखाणण्यासारखी आहे. तसेच आग्राचा ताजमहल, दिल्लीचा कुतुबमिनार, कोनार्क सूर्य मंदिर, महाराष्ट्रातील अजिंठा वेरुळ लेणी पर्यटकांना आपल्याकडे आकर्षित करतात.

५. प्राकृतिक रचना व पर्यटन स्थळ

विविधतेच्या दृष्टीने भारताचा भूगोल हा अभिमानास्पद आहे. भारतात पर्वत, मैदान, पठारे व दऱ्या खोऱ्या आढळतात. हिमालयातून अनेक नद्यांचे उगम झालेले आहेत. दक्षिण भारतात दख्खनचे पठार व

उत्तरेला विंध्य व सातपूडा, पश्चिमेला सह्याद्री, दक्षिणेला निलगिरी पर्वत आहे. अशा विविध स्थळांसाठी भारत प्रसिद्ध आहे.

६. जंगले व वन्य पशुपक्षी

जम्मू काश्मीर, उत्तरांचल, केरळ ह्या राज्यात जंगलाचे प्रमाण मोठे आहे. गुजरातमध्ये सिंहाचे प्रमाण जास्त आहे. तसेच महाराष्ट्रात वाघ आहेत. पशुंचीही संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. हे पर्यटकांचे आकर्षण आहे.

७. भारताचा इतिहास

भारताला खूप मोठा इतिहास लाभला आहे. भारताचा इतिहास हा चित्रशिल्प आणि शिलालेखांच्या माध्यमातून सांगण्यात आलेला आहे.

८. अतिथी देवो भव

भारतामध्ये भारतीय पर्यटक मंडळाकडून अमीर खान यांच्या मार्फत 'अतिथी देवो भव' हा कार्यक्रम राबविण्यात आला आहे. त्यामुळे भारतात येणाऱ्या प्रत्येक विदेशी पर्यटकांचे हसतमुखाने स्वागत करण्यात येते.

निष्कर्ष

१. पर्यटन व्यवसायाला अधिक चांगले करण्यावर भर दिला जात आहे.

पर्यटकी पर्यटक मोठ्या संख्येने येत असल्यामुळे त्यांच्या राहण्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, सांस्कृतिक स्मारके, अभयारण्ये निर्माण करणे, याकरिता देशात स्वतंत्र पर्यटन मंडळे स्थापन करण्यात येत आहे. मध्यवर्ती पर्यटन खाते ही सर्वोच्च पातळी म्हणून व पर्यटन विकास परिषद ही सहाय्यक व प्रमुख सल्लागार संस्था म्हणून काम करते.

२. पर्यटनामुळे देशात पायाभूत सुविधांचा विस्तार होत आहे.

पर्यटन उद्योगाच्या वाढीबरोबर देशातील दळणवळण सुविधा, बँकिंग सुविधा, आरोग्य सुविधा, निवास सुविधा व अन्न सुविधांमध्ये वाढ होत आहे.

३. रोजगारात वाढ

पर्यटनातून त्या त्या भागातील लोकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होते. भारतात २०१७-१८ मध्ये ८.१ टक्के रोजगार पर्यटन उद्योगातून उपलब्ध होण्यास मदत झाली आहे. पर्यटकांना मदत करण्यासाठी गाईड, हस्तकला, शिल्पकला व चित्रकला इ. वस्तू रोजगार उपलब्ध करीत आहेत.

४. परिवहन सेवांचा विकास

पर्यटनामुळे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जावे लागते त्यामुळ जाणे येणे करण्यासाठी परिवहन सेवांचा विकास होतो. यामध्ये टूर ट्रॅव्हल्स व्यावसायिकांना रोजगार उपलब्ध होत आहे.

५. निवास व्यवस्थेचा विकास

पर्यटक प्रवास करून निवास करीत असतात अशा पर्यटनस्थळी निवासाची सोय उपलब्ध होण्यासाठी हॉटेल्स, भवन, निवास, लॉज, धर्मशाळा, विश्रामगृहे इ.चा विकास होत आहे व त्यातून रोजगार निर्माण होत आहे.

६. परकीय चलन

पर्यटन हा परकीय चलन मिळवून देणारा व्यवसाय आहे. परदेशीय पर्यटकांमुळे परकीय चलनात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.

७. 'अतिथी देवो भव' या संकल्पनेला रुजविण्यासाठी भारत सरकारने उचललेल्या पावलांना यश प्राप्त होतांना दिसत आहे.

पर्यटन विकासासाठी उपाययोजना

पर्यटनाला चालना देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने या दिशेने प्रभावी पाऊले उचलण्यासाठी आवश्यकता आहे.

१. भारतात निसर्गसौंदर्य, ऐतिहासिक वस्तू, वारसा, संस्कृती, खाद्य संस्कृती, तीर्थक्षेत्रे या सर्वांतील विविधता ह्यात मोठ्या प्रमाणात पर्यटन क्षमता आहे. पर्यटनाला उपयुक्त बाबी भारतात पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत. केवळ ते आकर्षक पद्धतीने ग्राहकांसमोर मांडण्याची आवश्यकता आहे.
२. पर्यटनाचे नियोजन करणे, परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांना सुविधा उपलब्ध करणे, त्यांना संरक्षण देणे तसेच विद्यार्थ्यांना संशोधन करण्याकरिता विशेष सवलती देणे, परिणामतः निरनिराळ्या जाती, धर्म, भाषा, चालीरिती, सांस्कृतिक विविधता असलेल्या भारतासारख्या देशात पर्यटन हे राष्ट्रीय एकात्मता साधण्याचे प्रभावी साधन ठरेल.
३. पर्यटन व्यवसायाच्या विकासात स्त्रियांची भूमिकाही महत्वपूर्ण आहे. म्हणून पर्यटनाचा विकास झाल्यास स्त्रियांनाही रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होतील. त्यातून त्यांना आर्थिक उत्पन्न मिळविता येवून स्त्रियांचे आर्थिक सक्षमीकरण होवू शकेल. थोडक्यात, पर्यटन व्यवसायातून देशाचा विकास साधतांना स्त्री सक्षमीकरणास देखील मोठ्या प्रमाणावर हातभार लागेल.
४. भारत हा खेड्यांचा देश आहे. भारतातील ६५ टक्के जनता ही खेड्यात राहते. सोबतच भारत भौगोलिकदृष्ट्या संपन्न, प्रथा, परंपरा, संस्कृती, आदरातीर्थ्य व सुंदर अशा ग्रामीण शेतीने नटलेला देश आहे. म्हणूनच पर्यटनाच्या संदर्भात ग्रामीण पर्यटन ही संकल्पना उदयास आली. एवढेच नव्हे तर ग्रामीण भागातील पर्यटन हा नवीन उदयोन्मुख असा मोठा उपक्रम ठरू शकतो. ज्यामुळे ग्रामीण जनतेला आर्थिक व सामाजिक लाभ प्राप्त होऊ शकतील. ग्रामीण व कृषी पर्यटनाचा विकास केल्यास पर्यटकांसाठी एक नवीन दालन निर्माण होऊ शकतील. ग्रामीण व कृषी पर्यटनाचा विकास होवून राज्य व शेतकरी या दोन्हीच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा घडून येईल.
५. निसर्गात असणाऱ्या विविध औषधी की ज्या विविध आजारावर वापरता येतात अशा नैसर्गिक औषधांची निर्मिती करून त्याबद्दलची माहिती जर पर्यटकांना करून देण्यात आली तर अशा वनस्पतींचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढून रोजगारात वाढ करता येईल.
६. पर्यटनाचा एक हिस्सा म्हणून पर्यावरणाकडे बघितल्या जाते. यासाठी जर पर्यावरण शिक्षण असणारे लोक असतील तर त्या भागातील पर्यावरणासंबंधीची माहिती शाळा, कॉलेज व पर्यटकांना दिली गेली तर थोडी फार रोजगार निर्मिती तर होईलच सोबतच पर्यावरण जागृतीही करता येईल.
७. दुर्गम भागातील रस्त्यांचा विकास करण्यात यावा. यामुळे दळणवळण सुविधा निर्माण होवून पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होईल व देशाच्या विकासालाही गती मिळेल.
८. पर्यटनाच्या विकासांमुळे नवीन गुंतवणूकदारांना आकर्षिक करणे भाग होते. त्यामुळे परकीय गंगाजळी राज्याला उपलब्ध होण्यास मदत होते.
९. खाजगी वाहतूकदाराकडून हजारो पर्यटकांची लुट थांबवावी म्हणून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वाढवावी लागेल.
१०. परकीय पर्यटकांना सौंदर्याची वागणुक देवून सुरक्षा व्यवस्था चोख करावी.
११. पर्यटनाच्या माध्यमातून आर्थिक विकास साधतांना पर्यावरणाचा समतोल आणि स्वच्छता याला प्राधान्य द्यावे.

१२. ज्या पर्यटन स्थळांकडे पर्यटकांचा ओघ आहे. त्या स्थानांकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे.
१३. पर्यटन क्षेत्रात पर्यटकांची गर्दी वाढावी म्हणून पर्यटन महोत्सवाचे ही आयोजन करता येईल.
१४. पर्यटन क्षेत्रापर्यंत पोहचण्यासाठी मदत करणाऱ्या विविध सत्तांच्या विकासाचे विशेष प्रयत्न करावे.

या दिशेने पावले उचलल्यास भारतीय पर्यटन क्षेत्राचे भविष्य नक्कीच उज्ज्वल झाल्याशिवाय राहणार नाही व भविष्यात भारत देश जागतिक पातळीवर उच्च पर्यटन विकास झालेला देश असेल. यासाठी शासनाचीच नव्हे तर संपूर्ण समाजाचीही भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे.

संदर्भ

१. पर्यटन भूगोल — नागतोडे डॉ. पी. एम., प्रा. पारधी.
२. पर्यटन भूगोल — शिंदे डॉ. एस. बी.
३. 'विदर्भ पर्यटन सुवर्ण आशा' डॉ. फडणवीस मृणालीनी, श्री. रेणूका प्रकाशन, नागपूर
४. 'प्रवास पर्यटनाचे नवे पैलू' भोसले यशोधरा, मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे, जानेवारी २००५.
५. योजना — मे २०१५.
६. लोकराज्य — ऑक्टो. २०१५.
७. पर्यटन मंत्रालय — अहवाल.

ISSN: 2249-894X Impact Factor : 5.7631(UIF)

Volume - 8 | Issue - 9 | June - 2019

REVIEW OF RESEARCH

International Online Multidisciplinary Journal



डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आर्थिक विचार



डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आर्थिक विचार

डॉ. प्रा. प्रज्ञा बागडे

अर्थशास्त्र, विभागप्रमुख , डॉ. मधुकरराव वासनिक पी. डब्ल्यू. एस.कला व
वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर.

प्रस्तावना : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय संविधानाचे निर्माते, दलितांचे उद्धारक, समाजसुधारक,
कायदेतज्ञ नव्हते, तर ते एक जगप्रसिद्ध अर्थतज्ञही होते. डॉ. आंबेडकरांचे आर्थिक चिंतन.....

Page No :-1

Editor - In - Chief - Ashok Yakkaldevi



Content

Sr. No.	Title and Name of The Author (S)	Page No.
1	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आर्थिक विचार डॉ. प्रा. प्रज्ञा बागडे	1
2	An Economic Development Of Agro Based Coir Industry In Tamilnadu T. Thamizhvanan and Dr. R. Rajendran	7
3	Muthumariyamman Temple, Thayamangalam In Sivagangai District - A Historical View A. Meenakshi Sundaram and Dr. P. Thangamuthu	15
4	Professional Development-Some Important Aspects Rahela Khatoun and Prof. Siddiqui Mohd. Mahmood	21
5	Isolation And Identification Of Actinomycetes From Garden Soil At Miraj, In Sangli District Oliver P. Madhale, Vinay V. Chougule and Ujwala V. Mane	27
6	A Study On Financial Performance Of Tata Motors Limited Dr. C. Vadivel and Mrs. K. Satya Bhama	33
7	A Curb On Criminalisation Of Politics Dr. Raj Kumar	39
8	Development And Standardisation Of Critical Thinking Test In Social Studies At Secondary Level Dr. Rajesh R. V.	43
9	A Study On Menopause Health Status Of Women In Tamil Nadu Buvaneswari R. P., Madhavan M. and Prabha N.	49
10	Urbanization In Telangana - A Study Of Greater Hyderabad Dr. M. Laxman	61
11	Role Of Teacher In Developing Students' Skill In Listening, Speaking, Reading And Writing (LSRW) In English Dr. Karabi Konwar	69
12	The Wancho Language: Origin And Linguistic Status Dr. Partha Pratim Phukon	73



डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आर्थिक विचार

डॉ. प्रा. प्रज्ञा बागडे

अर्थशास्त्र, विभागप्रमुख, डॉ. मधुकरराव वासनिक पी. डब्ल्यू. एस.कला व वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर.

प्रस्तावना

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय संविधानाचे निर्माते, दलितांचे उद्धारक, समाजसुधारक, कायदेतज्ञ नव्हते, तर ते एक जगप्रसिद्ध अर्थतज्ञही होते. डॉ. आंबेडकरांचे आर्थिक चिंतन त्यांच्या संपूर्ण सामाजिक चिंतनाचा सार आहे. जी सामाजिक क्रांती ते करू पाहात होते. ते सर्व आर्थिक परिवर्तनच होते. त्यांच्या आर्थिक विचारांचा केंद्रबिंदू दलित, शोषित, पीडितांचा उद्धार व कल्याण हाच होता. ते ना पूंजीवादाचे समर्थक होते ना कट्टर समाजवादाचे. मध्यममार्गी होते. म्हणून ते 'सम्यक समायोजनाला' अधिक महत्त्व देत होते. त्यांनी न्यूनतम इच्छांवर आधारित जीवन उत्कृष्ट मानले. 'सम्यक आजीविके' वर भर दिला. ते स्वतः आत्मसंयम, मितव्ययता आणि नियंत्रित इच्छांचे जीवन जगले.



डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे
आर्थिक विचार

डॉ. आंबेडकर कायदेतज्ञ, इतिहासतज्ञ, राजनितिज्ञ, शिक्षणतज्ञ तसेच धर्म आणि समाजशास्त्राचे जाणकार असल्यामुळे त्यांनी अहिंसावादी राज्य व समाजवादाची संकल्पना प्रस्तुत केली, डॉ. आंबेडकरांचे आर्थिक प्रारूप आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, धार्मिक, तंत्रज्ञान आणि मानवतावादी मूल्यांचे मिश्रण आहे. त्यांनी आर्थिक तथ्यांचे विश्लेषण अनुभवावर व वैज्ञानिक मापदंडांच्या आधारावर केले म्हणून बाबासाहेबांचे संपूर्ण आर्थिक विचार वैज्ञानिक होते.

संशोधनाची उद्दिष्टे

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांवर संशोधन करित असतांना खालील उद्दिष्टे ठरविण्यात आली.

१. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आर्थिक विचार जाणून घेणे.

२. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आर्थिक कार्य जाणून घेणे.

३. सद्यःस्थितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांची समर्पकता अभ्यासणे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : एक अर्थतज्ञ

डॉ. आंबेडकरांनी भांडवलाशाही

व समाजवादी अर्थव्यवस्थांचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर त्यापैकी कोणतीही अर्थव्यवस्था भारताला पोषक नाही असे त्यांचे मत झाले. त्यांच्या मते, भांडवलाशाही अर्थव्यवस्थेत आर्थिक विषमतेला व शोषणाला भरपूर वाव आहे तर समाजवादी अर्थव्यवस्थेत व्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होऊन रक्तरंजित क्रांतीची शक्यता असते, म्हणून त्यांनी मध्यममार्ग म्हणून मिश्र अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार केला. म्हणून मिश्र अर्थव्यवस्थेचा पाया हा डॉ. आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांचा परिपाक होय असे म्हणावे लागेल. त्यांच्या आर्थिक विचारांमुळे भारताचे

पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु बरेच प्रभावित झालेले होते, म्हणूनच स्वतंत्र भारताचे आर्थिक धोरण ठरविताना त्यांनी डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांना अधिक महत्त्व दिले. वर्तमानातील भारतीय अर्थव्यवस्था ज्या स्थितीत आहे त्या स्थितीतही बाबासाहेबांचे आर्थिक विचार प्रासंगिक वाटतात. त्यांचे विचार एक शताब्दी पुढे होते. त्यांच्या आर्थिक विचारांचे गांभीर्य आजच्या आर्थिक आणि सामाजिक आवश्यकतेनुसार आहे. त्यांच्या विचारांची चर्चा आज जगातले अर्थशास्त्रज्ञ करित आहेत. ज्या

विकासाचा विचार आज आम्ही करीत आहोत, त्याचा बाबासाहेबांनी स्वातंत्र्यापूर्वीच प्रारंभ केला होता.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आर्थिक विचार

आधारभूत मानवतावादी नैतिकमूल्ये त्यांच्या आर्थिक विचारांना प्रभावित करतात. डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या आर्थिक तंत्रात व्यापार, बँकिंग, रुपया, कृषी, जातीगत अर्थनीती, औद्योगिकरण, मजुरी, श्रमिकांचे कल्याण, राज्यसमाजवाद, भूमी-सुधार, राजस्व इ. वर आपले विचार व्यक्त केले. हे मांडतांना त्यांनी धर्म, नैतिकता, संस्कृती, राजनीती, कायदा, सामाजिक व्यवहार सारख्या बाबींवरही पूर्ण लक्ष ठेवले.

विकासाची अर्थनीती

स्वातंत्र्योत्तर भारताचे विकासविषयक आर्थिक धोरण काय असावे याचे विवेचन डॉ. आंबेडकरांनी 'स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज' या ग्रंथात केले आहे. या संदर्भात त्यांनी गरीबी हटाव, विषमता निर्मूलन आणि शोषण मुक्तता यावर भर दिला. त्यांनी मर्यादित राष्ट्रीयीकरणाचा पुरस्कार केला. शेतजमीन आणि अवजड उद्योगधंद्यावर सामूदायिक मालकी असावी, उत्पादनाचे लोकशाही पद्धतीने भेदभाव न करता वाटप व्हावे अशी त्यांची भूमिका होती. राज्य संस्थेने योग्य पद्धतीने आर्थिक व्यवहारांचे नियोजन करावे की, ज्यायोगे खाजगी उद्यमशीलतेला धक्का न लावता जनतेची उत्पादकता जास्तीत जास्त राहिल व संपत्तीचे समान वाटप होईल असे विचार मांडले.

कृषी

भारतातील लहान धारणक्षेत्रे ही भारतीय शेतीतील गंभीर समस्या असून लहान धारणक्षेत्रे विखुरलेली असल्याने ही समस्या अधिकच गंभीर झाली आहे. शेती हा भारतातील सर्वात मोठा व्यवसाय असून त्यावर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या जास्त तर दुसरीकडे शेतीची उत्पादकता कमी आहे. या संदर्भात त्यांनी तीन प्रश्न उपस्थित केले. पहिला प्रश्न म्हणजे धारणक्षेत्राचे विखंडन मूळातच का होते ? दुसरा, 'किफायतशीर धारणक्षेत्र' कसे ठरवायचे ? आणि तिसरा, विखुरलेल्या व लहान धारणक्षेत्राच्या समस्येवरील उपाय कोणता ?

वारसाहक्क हे जमिनीच्या विभाजनाचे मूळ कारण नसून शेतीवर असणारा लोकसंख्येचा अतिरिक्त भार हेच मूळ कारण आहे. शेतकऱ्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा निम्न असतो म्हणून लोक लहान-लहान तुकडे करण्याचे पत्करत नसून उपजीविकेचे दुसरे कोणतेही साधन नसल्याने त्यांना तसे करणे भाग पडते. दुसरा कोणता मार्ग असता तर त्यांनी हे तुकडे करणे सोडून दिले असते असे त्यांचे मत होते. या सर्व समस्यांवर उपाय म्हणजे 'औद्योगिकरण'. औद्योगिकरणामुळे शेती क्षेत्रातील बेकार श्रमिक बिगर शेतीक्षेत्रात सामावून घेतले जातील. उपजीविकेसाठी त्यांना इतरांवर अवलंबून रहावे लागणार नाही. हे श्रमिक स्वतः काम करून राष्ट्रीय उत्पन्नात भर घालतील व शेतजमिनीवरील भार कमी होईल, परिणामी विभाजन व विखंडन कमी होईल. अशारीतीने भारतीय शेतीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी 'औद्योगिकरण' हा एकच प्रभावी व खात्रीशीर उपाय त्यांनी सांगितला.

जमीन महसूल

उत्पन्नावर जमीन महसूल आकारणे अन्याय आहे असे आंबेडकरांचे मत होते. सर्वांकडून सारखा कर वसूल करणे योग्य नाही. काही विशिष्ट रकमेपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना जमीन महसूलात माफी मिळाली पाहिजे, म्हणूनच जमीन महसूल संहितेचे १०७ वे कलम रद्द करून जमीन महसूल प्राप्तीकराच्या कक्षेत आणला पाहिजे असे विचार त्यांनी व्यक्त केले.

सहकारी शेती

विखुरलेल्या व लहान धारण क्षेत्राच्या समस्येवर उपाय म्हणून त्यांना सहकारी शेती योग्य वाटत होती. एका विशिष्ट आकाराची सहकारी शेते अस्तित्वात आणल्यास छोट्या शेतकऱ्यास विनाशापासून वंचित करता येईल. सहकारी शेतीमुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील मालकी हक्क कायम राहिल. शेतकऱ्यास त्याच्या

धारणक्षेत्राला लागून असलेल्या धारणक्षेत्रास जोडल्याशिवाय जमीन कसता येणार नाही. सहकारी शेत जसे मोठ्या आकारमानाचे असेल तसे ते एकसंघही असेल.

सामुदायिक शेती

कूळ कायदे व जमिनीच्या एकत्रीकरणाने भूमिहीनांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. डॉ. आंबेडकरांच्या मते, पडीत जमीन लागवडीखाली आणल्याने भूमिहीनांचा प्रश्न सुटू शकेल. जमीनदारीचे उच्चाटन झाल्यानंतर शेतकऱ्याला जमिनीची वैयक्तिक मालकी न देता सरकारने जमिनीचे मालक व्हावे या दृष्टीने सामुदायिक शेतीवर त्यांनी भर दिला.

शेती हा 'शासकीय उद्योग' असावा असे आंबेडकरांचे मत होते. शासनाने सर्व जमीन ताब्यात घेऊन ज्यांची जमीन घेतली असेल त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी नंतर गावातील जमिनीचे भाग करून ते ग्रामस्थांना विशिष्ट अटींवर कसण्यासाठी द्यावेत. शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आधार असून शेतीतील उत्पादन वाढीसाठी यंत्रप्रधान शेती, विस्तृत शेते, सहकारी व सामुदायिक शेतीचा त्यांनी पुरस्कार केला. त्यांच्या स्वतंत्र मजदूर पक्षाच्या जाहिरनाम्यातही या बाबींचा उल्लेख आढळतो.

खोती पद्धती

डॉ. आंबेडकरांनी खोतीपद्धती विरुद्ध रत्नागिरी येथील दलित वर्गाच्या परिषदेत आवाज उठवला. खोती प्रदेशातील शेतकऱ्यांचे रक्त शोषण थांबवून त्यांना माणुसकीचे हक्क मिळवून देण्यासाठी खोतीपद्धती समूळ नष्ट केली पाहिजे असे त्यांचे मत होते. खोतीपद्धती जमीन महसूल संहितेत येत नाही हा स्वतंत्र विषय आहे असे ते मानत. जमीन कसणाऱ्यांना कुळांचे वहीवाटीचे हक्क मिळावेत व रयतवारी पद्धती आणावी यासाठी मुंबई विधीमंडळात १९३७ मध्ये त्यांनी खोती पद्धती रद्द करण्यासंबंधीचे विधेयक मांडले.

चलनविषयक

१९४७ साली 'हिस्ट्री ऑफ इंडियन करन्सी अँड बँकिंग' यामध्ये त्यांनी भारतासाठी आदर्श चलन पद्धती कोणती यावर मूलगामी विचार मांडले आहेत. भारतासाठी आदर्श चलन पद्धती कोणती हा वाद निर्माण झाला त्यावेळी दोन पर्याय उपलब्ध होते. पहिला पर्याय—सुवर्ण परिणाम, ज्यामध्ये सोन्याच्या नाण्यांचा वापर चलन म्हणून अभिप्रेत असतो व दुसरा पर्याय—सुवर्ण विनियम परिमाण, ज्यामध्ये कागदी नोटांचा चलन म्हणून वापर होतो आणि कागदी रूपये घेऊन ठरावीक दराने सोने देण्याची सरकारने हमी घेतलेली असते.

प्रा. केन्स व इतर अर्थतज्ञांनी सुवर्ण विनियम परिमाण लवचिक असल्याने व या व्यवस्थेत चलननिर्मिती ही देशातील सोन्याच्या साठ्यावर अवलंबून नसल्याने ही पद्धती भारतासाठी योग्य आहे, असे प्रतिपादन केले. परंतु डॉ. आंबेडकरांनी याला प्रखर विरोध केला. त्यांच्या मते, या व्यवस्थेत चलननिर्मिती लवचिक असल्यामुळे ती अनिर्बंध होऊ शकते. त्यातून भाववाढ निर्माण होऊन रूपयाची किंमत घसरू शकते. सुवर्ण विनियम परिमाण असताना भारतात अशी भाववाढ झाली याचे साधार विवेचन डॉ. आंबेडकरांनी दिले. त्यांना सुवर्ण परिमाण पद्धती हीच भारतासाठी योग्य असून त्यासाठी ऐतिहासिक पुरावे देऊन सुवर्ण परिमाण पद्धतीत भारतात किमती कशा स्थिर होत्या हे दाखवून दिले.

चलननिर्मिती करणाऱ्या (रिझर्व्ह बँक) संस्थेच्या चलन निर्मितीवर परिणामकारक अंकुश असण्याची आवश्यकता आहे, असा युक्तिवाद १९२६ मध्ये नेमलेल्या 'हिल्टन यंग कमिशन' पुढे साक्ष देतानाही त्यांनी केला. आंबेडकरांच्या चलनविषयक मतांचा विचार न करता भारत व इतरत्र केन्स यांच्या भूमिकेचा स्वीकार केला. परंतु आजची परिस्थिती पाहता त्यांची भूमिका निश्चितच योग्य होती असे म्हणावे लागेल. आज केंद्र सरकारची अर्थसंकल्पीय तूट वाढत असून रिझर्व्ह बँकेला पतपुरवठा वाढवावा लागतो. त्यामुळे चलन फुगवटा व त्या अनुषंगाने येणारी भाववाढीची समस्या याला तोंड द्यावे लागत आहे. चलननिर्मितीच्या क्षमतेवर अंकुश ठेवण्यासंबंधीची त्यांची भूमिका भविष्याचा वेध घेणारी होती यात शंका नाही.

सार्वजनिक आय.व्यय

'अॅडमिनिस्ट्रेशन अॅन्ड फायनान्स ऑफ दि ईस्ट इंडिया कंपनी' व दि इव्होल्यूशन ऑफ प्रोव्हिन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया' या दोन्ही प्रबंधात त्यांचे सार्वजनिक आय.व्यय विषयक विचार आढळतात. ईस्ट इंडिया कंपनीचे प्रशासन व वित्तव्यवस्था यामध्ये सन १७९२ ते १८५८ मध्ये कसे बदल झाले व ते भारतीयांना कसे अन्यायकारक ठरले याविषयी त्यांनी आपले विचार व्यक्त केले. ब्रिटिश शासन या ना त्या मार्गाने स्वतःचा फायदा करून घेत व त्याची झळ भारताला सोसावी लागे. जवळ.जवळ साठ वर्षांच्या कालखंडात भारतीय जनतेची प्रचंड आर्थिक पिळवणूक करण्यात आली. १८५८ मध्ये इंडिया कंपनी बरखास्त झाल्यानंतर कर्जाचा बोझा दरिद्री भारतावर टाकून अन्याय केला आहे तसेच महसूलाचा विनियोग भारताशी संबंधित नसलेल्या बाबींवरही करण्यात येत आहे हे त्यांनी दाखवून दिले. दुसऱ्या प्रबंधातून ब्रिटिश केंद्रसरकार आणि त्या काळची घटक राज्ये यांच्यातील आर्थिक संबंधाविषयीचे विचार व्यक्त होतात. १८३३ ते १९२१ या प्रदीर्घ कालखंडात हे आर्थिक संबंध कसे विकसित होत गेले याविषयी त्यांनी सविस्तर विवेचन केले आहे.

जल संपत्ती व विद्युत धोरण

देशाच्या आर्थिक विकासाला हातभार लावणारे महत्वाचे घटक या अनुशंगाने जल संपत्ती व विद्युत धोरण या विषयी डॉ. आंबेडकरांचे विचार अतिशय महत्वाचे आहे. त्यांनी जल संपत्तीचे नियोजन व विद्युत धोरण या संदर्भात महत्वाचे कार्यही केले आहे. राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून जल संपत्तीचे नियोजन करण्यासाठी १९४५ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सेंट्रल वाटर कमिशनची स्थापना केली. त्यांच्या मते, "आपल्या देशातील नैसर्गिक संपत्तीचे नियोजन करून त्या संपत्तीचा योग्य उपयोग केला तर देशाचा विकास होऊ शकतो". मंत्री पदावर असतांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांकडे वाटर रिसोर्सेस आणि इलेक्ट्रिक पावर या दोन कमिट्यांचा अतिरिक्त भार होता. या कमिट्यांचे डॉ. आंबेडकर प्रमुख होते.

विद्युत विकासाच्या कार्यात देखिल डॉ. आंबेडकरांनी केलेले कार्य महत्वाचे आहेत. विद्युत बाबत राष्ट्रीय धोरण डॉ. आंबेडकरांनी तयार केले होते. विद्युत शक्तीच्या संदर्भात धोरण ठरविण्यासाठी कमेटी सप्टेंबर १९४३ मध्ये नियुक्त करण्यात आली. यात विद्युत राष्ट्रीय मालकीची असावी, विद्युतीच्या विकासासाठी केंद्रीय संघटन निर्माण व्हावे असे महत्वाचे निर्णय विद्युत शक्तीच्या संदर्भात घेण्यात आले आणि ते राबविण्यात डॉ. आंबेडकरांची महत्वाची भूमिका होती.

श्रमविभागणी

हिंदू समाजव्यवस्थेतील चातुर्वर्ण्य पद्धती ही श्रम विभागणीच्या तत्त्वावर आधारलेली आहे. यावर टीका करताना त्यांनी ही श्रमविभागणी नसून श्रमिकांची विभागणी आहे व ती अमानवी आहे असे सांगितले. जगात इतरत्र कोठेही अशी श्रम विभागणी नाही. यामुळे भारताचा आर्थिक विकास व प्रगती खुंटली आहे. या व्यवस्थेने श्रमशक्ती व भांडवल यांची उपयुक्तता ज्या ठिकाणी जास्त आहे त्या ठिकाणी वापरले जात नाही हे स्पष्ट केले.

अस्पृश्यता.एक आर्थिक पिळवणूक

जातीव्यवस्था व अस्पृश्यता यासारख्या समस्यांचे विश्लेषण करणारे ते बहुदा पहिलेच विचारवंत असावेत. त्यांच्या मते, अस्पृश्यता ही केवळ धार्मिक रचनाच नसून गुलामगिरीपेक्षाही भयंकर आर्थिक रचना आहे. गुलामगिरीत गुलामाची किंमत कमी होऊ नये म्हणून मालक त्याला कपडे— लत्ते देतो, खाऊ—पिऊ घालतो पण अस्पृश्यता या रचनेत मालक कोणतीही जबाबदारी न स्विकारता या समाजाची आर्थिक पिळवणूक करतो. म्हणून त्यांचे स्पष्ट मत होते की, जोपर्यंत व्यावसायिक स्वरूपाचे परिवर्तन होणार नाही तो पर्यंत खालच्या वर्गामध्ये आर्थिक उत्थान होऊ शकत नाही. सामाजिक स्तरावरील अस्पृश्यता, जातीभेद या सारखे अभिशाप महात्मा गांधींच्या सहानुभूतीपूर्ण नीतीने दूर होऊ शकणार नाही तर त्यासाठी आंबेडकरांनी आर्थिक स्तरावर मूलभूत संस्थागत परिवर्तन आवश्यक मानले.

महिला विकास

डॉ. आंबेडकरांनी आर्थिक विकासामध्ये महिलांच्या योगदानाला महत्त्वपूर्ण मानले आहे. म्हणूनच त्यांनी संविधानाच्या माध्यमातून महिलांना स्वतंत्र अधिकारच मिळवून दिलेले आहेत. कारण स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय या जीवनमूल्यांवर आधारित नवीन समाजरचना निर्माण व्हावी अशी त्यांची अपेक्षा होती. त्यांचे असे मत होते की, देशातील सक्षम, बुद्धीमान, कौशल्यपूर्ण मानवसंपत्तीच्या निर्मितीत मातांचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. त्यांचे स्पष्ट मत होते की, महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्यापासून, आत्मनिर्णयाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले तर राष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला मर्यादा पडतील म्हणून त्यांनी स्त्रियांसाठी आर्थिक अधिकार, आर्थिक संरक्षण व मजुरी संबंधी कायद्यात तरतूदी केल्या आहेत. सद्यःस्थितीतील महिलांना जे व्यावसायिक व आर्थिक स्वातंत्र्य मिळत आहे, त्याची सशक्त आधारशीलाच डॉ. आंबेडकरांनी ठेवली आहे. यावरून असे लक्षात येते की डॉ. आंबेडकर हे खऱ्या अर्थाने महिलांचे उद्धारक होते.

डॉ. आंबेडकरांचे अर्थशास्त्रीय लेखन

१. एम. ए. ची पदवी संपादन करण्यासाठी कोलंबिया विद्यापीठास सादर केलेला प्रबंध 'अॅडमिनिस्ट्रेशन अॅन्ड फायनान्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी (१९१५).
२. जरनल ऑफ दी इंडियन इकॉनॉमिक सोसायटीमध्ये प्रकाशित लेख— स्मॉल होल्डींग्ज इन इंडिया अॅन्ड देअर रेडिमिज् (१९१८).
३. पीएच.डी. साठी सादर केलेला प्रबंध. 'द इन्व्होल्यूशन ऑफ प्रोव्हिन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया' (१९२५).
४. डी. एस्सी. साठी सादर केलेला प्रबंध— 'द प्रॉब्लेम ऑफ दी रूपी, इट्स ओरिजिन अॅन्ड इट्स सोल्यूशन' (१९३२).
५. 'बहिष्कृत भारत' पत्रिकेतील अग्रलेख— 'महार आणि त्यांचे वर्तन' दि. २.१६, ३०.९.१९२७.
६. 'बहिष्कृत भारत' पत्रिकेतील अग्रलेख— 'खोती उर्फ शेतकरी वर्गाची गुलामगिरी' दि. ३.५.१९२९. नागपूर.

निष्कर्ष

डॉ. आंबेडकरांची दृष्टी अतिशय सूक्ष्म होती. त्यांचा अभ्यास सखोल होता. सखोल अभ्यासामुळेच ते जगाच्या आर्थिक परिवर्तनाशी अवगत होते. भारतीय समाजात असलेली गरीबी व विषमता दूर करण्यासाठी त्यांनी ठोस उपाय सांगितले. शेती संदर्भातील विशेषतः छोट्या धारणक्षेत्राच्या बाबतीत मांडलेले विचार आजच्या परिस्थितीत उपयुक्त ठरतात. त्यांनी व्यक्त केलेल्या विचारांच्या आधारे जर आपण धोरणे आखलीत तर निश्चितपणे ग्रामीण भागातील शोषितांना त्यांचा न्याय हक्क मिळेल. आजही भारताच्या राज्यघटनेत राज्य सरकार व केंद्रसरकार यांचे हितसंबंध ठरविण्यासाठी दर पाच वर्षांनी वित्त आयोग नेमावा लागतो. डॉ. आंबेडकरांचे या संदर्भातील विचार पायाभूत मानावे लागतील.

डॉ. आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांमध्ये स्वार्थाला कोणतेही स्थान नव्हते. त्यांच्या जीवनाचा उद्देशच कमजोर वर्गाचा उद्धार करणे हा होता. त्यांच्या मते, विकासाच्या नैतिकतेचा मापदंड सामाजिक न्याय आहे. जोपर्यंत देशामध्ये बहुसंख्यांक लोकांना रोजगार व रोटी मिळणार नाही तोपर्यंत सामाजिक न्याय हा केवळ देखावा आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या संपूर्ण विचारांमध्ये मानवतावादी सूत्रच सर्वत्र आढळते. त्यांनी खऱ्या स्वरूपात मानवतावादाच्या उपलब्धीसाठी श्रमाचे महत्त्व स्वीकारले आहे. ते मानवतावादी भावनांच्याप्रती समर्पित असे क्रांतीकारी अर्थतज्ञ होते.

Impact Factor – 6.261

ISSN – 2348-7143

INTERNATIONAL RESEARCH FELLOWS ASSOCIATION'S
RESEARCH JOURNEY

Multidisciplinary International E-research Journal

PEER REFREED & INDEXED JOURNAL

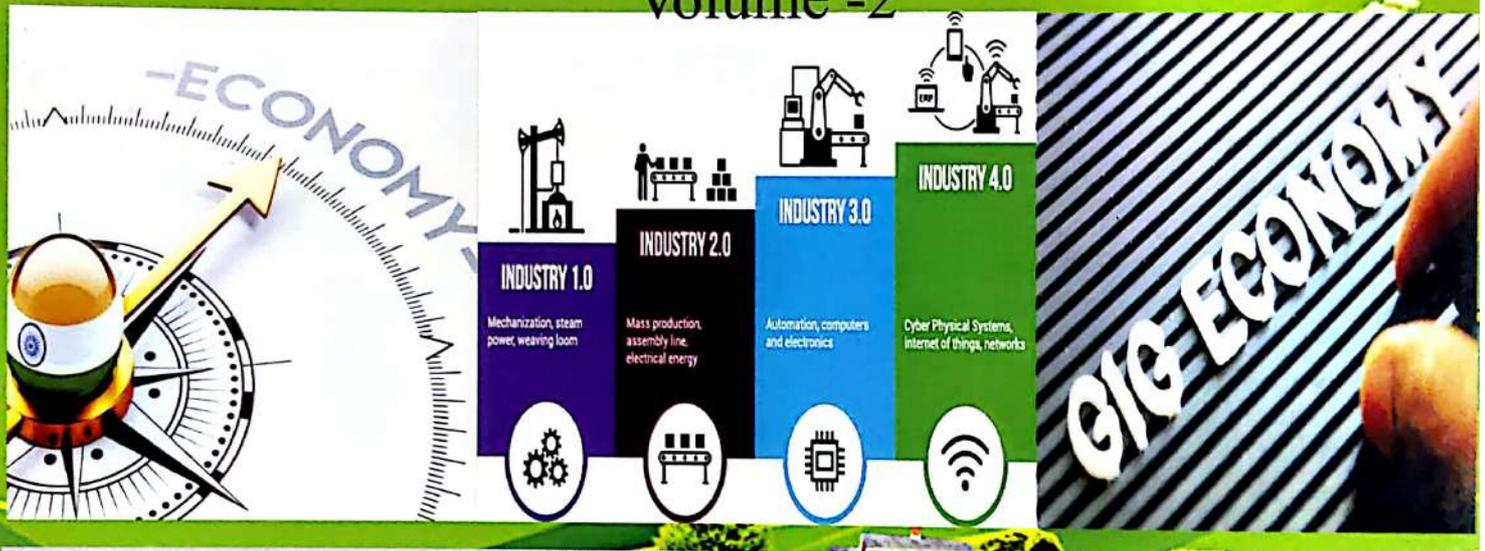
December -2019

SPECIAL ISSUE-CCV

भारतीय अर्थव्यवस्था : स्थिती व दिशा

Indian Economy : Condtion & Direction

Volume -2



Guest Editor

Dr. Subodh kumar Singh
(Principal)

Prof. Ravindra B. Shende
. HOD, Dept of Economics
Lokmanya Mahavidyalaya,
Warora, Dist- Chandrapur (MS)

Chief Editor

Mr. Dhanraj T. Dhangar,
Assist. Prof. (Marathi)
MGV's Arts & Commerce College,
Yeola, Dist – Nashik [M.S.] INDIA



This Journal is indexed in :

- Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
- Cosmos Impact Factor (CIF)
- Global Impact Factor (GIF)
- Universal Impact Factor (UIF)
- International Impact Factor Services (IIFS)
- Indian Citation Index (ICI)
- Dictionary of Research Journal Index (DRJI)

For Details Visit To : www.researchjourney.net

SWATIDHAN PUBLICATIONS

No.	Title of the Paper	Authors' Name	Page No.
52	लघू उद्योगांचि प्रगती दूरुपरेषा	प्रा. डॉ. आर. ए. फुलकर	210
53	एक आर्थिक विचारवंत - डॉ. आंबेडकर	डॉ. संगीता जी. टक्कामोरे	216
54	भारतीय अर्थव्यवस्था सद्यस्थिती व आव्हाने	श्री. मदन जी. प्रधान, डॉ. जयंतकुमार एम. मस्के,	220
55	भारतीय अर्थव्यवस्थेत किकेट खेळाची भुमिका	प्रा. उत्तम रामचंद्र देउळकर	223
56	भारतीय अर्थव्यवस्थेत शाश्वत शेती आजच्या काळाची गरज	डॉ. कल्पना भजनी / डॉ. कांचनमाला क्षीरसागर	226
57	भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थितीतथा आर्थिक सर्वेक्षण	प्रा. डॉ. प्रिति ई. बंडे	230
58	जागतिकीकरणाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेतील प्रवास: एक आर्थिक अध्ययन	प्रा. डॉ. अमोल गिरीधरराव आवंडकर	233
59	ग्रामीण विकास व दारिद्रय निर्मुलन कार्यक्रमांची परिणामकारता	डॉ. एस पी. झांबरे,	236
60	भारतातील वस्तु व सेवा कर - एक विश्लेषण	प्रा. डॉ. विठ्ठल निलकंठ ठावरी	238
61	लोकसंख्यावाद :- एक सामाजिक समस्या	प्रा. बाळकृष्ण कारु रामटेके	242
62	लिंगभाव आणि विकास-अर्थकारणाचे स्त्रीवादी दृष्टीकोणातून विश्लेषण	डॉ. प्रविण दिगांबर मुधोळकर	246
63	जागतिकीकरणाचे परिणाम	प्रा. डॉ. मेघमाला अं. मेश्राम	251
64	जागतिकीकरण आणि भारताची राष्ट्रीय सुरक्षा	प्रा. तानाजी माने	254
65	आर्थिक मंदी उद्भण्याची कारणे आणि उपाययोजना	डॉ. रंजना सुखदेव लांजेवार	257
66	भारतातील ग्रामिण विकासाचे वास्तव: एक अवलोकनात्मक अभ्यास	प्रा. डॉ. मंगेश कडू	260
67	गिग अर्थव्यवस्थेचा (Gig Economy) फ्रिलान्सच्या (Freelance) दृष्टीकोणातून भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम - एक नवप्रवर्तनात्मक अध्ययन	प्रा. हितेश मा. दडमल	263
68	कृषी विकासात शिक्षण व संशोधनाचे महत्व	डॉ. विठ्ठल धिनमिने	267
69	आदिवासी विकास विभागाच्या योजना आणि आदिवासी शेतकरी	प्रा. एन. एस. गेडाम	272
70	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे अर्थशास्त्रीयदृष्टिकोण	प्रा. निलेश अरूण दूर्गे	276
71	Industry 4.0 आणि भारत	प्रा. निहार अशोक बोदले	281
72	कृषीआधारीत उद्योग व ग्रामीण विकास	प्रा. डॉ. प्रजा बागडे	285



कृषीआधारीत उद्योग व ग्रामीण विकास

प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे

विभागप्रमुख, अर्थशास्त्र

डॉ. मधुकरराव वासनिक पी.डब्ल्यू.एस. कला व वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर

प्रस्तावना :

भारत हा खेड्यांनी बनलेला देश आहे. त्यामुळे जोपर्यंत खेड्यांचा म्हणजे ग्रामीण भागाचा विकास होणार नाही तोपर्यंत भारताचा विकास होणे शक्य नाही. भारताच्या विकासाचे प्रतिबिंबच मुळात खेड्यांच्या म्हणजेच ग्रामीण भागाच्या विकासात आहे. म्हणूनच ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास हा जागतिककरणाच्या स्पर्धेत कळीचा मुद्दा ठरला आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील पंचवार्षिक योजना आराखड्यातून सरकारने सातत्याने ग्रामीण विकासाला अग्रक्रम दिलेला आहे. ग्रामीण भागातील दारिद्र्य निर्मूलन, रोजगार वृद्धी व समृद्धी याकरिता असंख्य महत्वाकांक्षी ग्रामीण विकास योजना सुरु केल्या आहेत. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून त्याची फळे जोपर्यंत ग्रामीण जनतेला मिळणार नाही तोपर्यंत ग्रामीण भारताच्या विकासाचे ध्येय पूर्ण होणार नाही. ह्या दृष्टीने जागतिकीकरणाच्या व स्पर्धेच्या काळातही ग्रामीण भागातील ६८ टक्के लोकसंख्या उपेक्षित राहू नये, यासाठी सरकारने ग्रामीण भागाच्या विकासात सातत्य ठेवून विकासाची जो वाढविणे आवश्यक झाले आहे.

कृषी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मूलाधार आहे. भारतातील ६८ % लोकसंख्येपैकी ५८ % लोकसंख्या उपजीविकेसाठी कृषी क्षेत्रावर विसंबून आहे. मोठ्या प्रमाणावरील दारिद्र्य हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे लक्षण असलेले दिसून येते आणि ग्रामीण दारिद्र्य हे बेरोजगारी व अल्परोजगारीचे फलन आहे. कृषीप्रधान राष्ट्रांचा विकास हा त्या देशातील ग्रामीण विकास व शेती आधारित उद्योगांच्या विकासावर अवलंबून असतो. स्थानिक कच्चा माल, कमी भांडवल, अल्प तंत्रज्ञान, रोजगारीची अधिक क्षमता इ. दृष्टीकोनातून शेती आधारित उद्योग हे ग्रामीण भागात स्थापन होतात त्यामुळे त्यांचे ग्रामीण भागाच्या विकासातील भूमिका महत्वाची ठरते.

ग्रामीण भागात रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधीची उपलब्धता करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागातील भांडवल व मनुष्य बळाचा प्रभावी वापर व्हावा यासाठी शेती आधारित उद्योगांची स्थापना करून कृषी क्षेत्रात अर्थात ग्रामीण भागाचा विकास साधने शक्य आहे. प्रस्तुत शोधनिबंधात ग्रामीण भागातील शेती आधारित उद्योगांचे महत्त्व त्यांच्या समस्या व संधी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

कृषी उद्योग :

भारतातील शेती आधारित उद्योगास कृषी उद्योग, शेतीपूरक उद्योग, ग्रामीण उद्योग, शेती उद्योग असेही म्हणले जाते. ज्या उद्योगात शेतमालावर विविध प्रक्रिया केल्या जातात व ते उद्योग बहुतांशी ग्रामीण भागात सुरु केले जातात त्यांना शेती आधारित उद्योग म्हणतात. अनेक उद्योगधंदे याखाली येतात. उदा. - कापड उद्योग, तेलबिया व तेलापासून होणारे उत्पादने, तंबाखू, फळांवरील प्रक्रिया, मद्यार्क, साखर कारखाने, वनोत्पादने, लाकडाच्या वस्तू, चामड्याच्या वस्तू इ. उद्योगधंदे ह्या वर्गात मोडतात. अल्पभांडवलात आणि अल्पवेळात पूर्ण होणाऱ्या अनेक कृषी उद्योगांना अजूनही वाव आहे.

व्याख्या: The National Council of Applied Economics Research नुसार, 'शेतमालावर प्रक्रिया करणारे शेतीसाठी लागणारी अवजारे, खते, बी-बियाणे, किटकनाशके इ. निर्माण करणाऱ्या उद्योगांना कृषी उद्योग म्हणतात'.

शेती आधारित उद्योग व इतर उद्योग यात फरक करण्याच्या दृष्टीने नियोजन आयोगाने चार निकष निश्चित केले आहेत. हेच निकष पुढे राष्ट्रीय विकास परिषदेकडूनही मान्य करण्यात आले आहेत.

१. शेतीकरिता प्रभावी आदाने (Inputs) निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे.
२. शेतमालावर प्रक्रिया करण्यासाठी व त्यांचे रूपांतर करण्यासाठी मदत करणे.
३. प्रक्रिया केलेल्या वस्तूंना चांगला मोबदला मिळवून देण्याची खात्री देणे.
४. शेतीचे उत्पादन वाढविण्यास मदत करणे.

कृषी आधारित उद्योगांचे महत्त्व:

भारत हा विकसनशील देश असून या देशाच्या ग्रामीण विकासात शेती आधारित उद्योगांची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरत आहे.

१. भारतातील गावांची समृद्धी व पुनर्निर्माण कृषी आधारित उद्योगांच्या माध्यमातूनच शक्य आहे. बिजेन्द्रनाथ बॅनर्जी यांनी विकसित व औद्योगिक देशांच्या अनुभवावरून असे मत मांडले होते की, देशाच्या एकूण विकासात ग्रामीण व कृषी उद्योगांचे महत्त्व अत्यंत महत्वाचे आहे.



विकासात कृषी उद्योग महत्वाचे आहेत. कृषी क्षेत्र व औद्योगिक क्षेत्र एकमेकांचे प्रतिस्थापन करू शकत नाही. त्यामुळे ते एकमेकांना पुरक आहेत म्हणून दोन्ही क्षेत्रांचा विकास साधणे गरजेचे आहे.

२. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी देखील राष्ट्रीय विकास परिषदेतील आपल्या भाषणात म्हटले होते की, कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी दिल्याशिवाय सर्व समावेशक विकासाचे ध्येय साध्य करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे विशेषत्वाने लक्ष देण्याची गरज आहे.

३. ग्रामीण औद्योगिकरणामुळे भांडवलात गतीशीलता आणता येते. उद्योग कौशल्यामध्ये गतीशीलता आणता येते. ग्रामीण लोकांचे शहराकडे होणारे स्थलांतरण थांबवून खेडी ओस व शहरे बकाल होण्यापासून वाचविता येतात.

४. ग्रामीण भागाच्या समतोल विकासासाठी या उद्योगांचे योगदान जास्त आहे. हे उद्योग शहरात केंद्रीत न होता ग्रामीण भागात केंद्रीत होत असल्यामुळे शहरीकरणाचे वाढते दुष्परिणाम टाळता येतात व ग्रामीण भागाचे अस्तीत्व निर्माण होईल.

५. आपल्या देशात भांडवलाचा तुटवडा असल्याने कमी भांडवलात हे उद्योग करता येतात. या उद्योगासाठी लागणारा कच्चा माल, हा स्थानिक स्वरूपाचा असल्याने तो कमी किंमतीस व गुणवत्ताधारक मिळतो. त्यामुळे या उद्योगातील उत्पादन कमी खर्चात होण्यास मदत होते.

६. ग्रामीण भागात शेती आधारित उद्योगांच्या विकासांमुळे सामाजिक व आर्थिक सुविधांचा विकास होतो. तसेच साठागृहे, बाजारपेठ, यांच्या विकासासाठी, निर्यात वृद्धी व सहकाराच्या विकास आणि ग्रामीण उपक्रमशीलतेसाठी या उद्योगांचे महत्त्व जास्त आहे.

७. या उद्योगांच्या विकासांमुळे लोकांना वाढत्या प्रमाणात रोजगार मिळत असून त्यांचे उत्पन्न वाढते. त्यामुळे त्यांची ग्रामीण बचत वाढत जाऊन भांडवल निर्मितीस हातभार लागतो.

८. जलद ग्रामीण औद्योगिकरणामुळे विकसनशील देशात रोजगारीच्या संधीमध्ये वाढ होते. ग्रामीण भागातील कृषी आधारित उद्योगात निर्माण झालेल्या रोजगारीमुळे तेथील कृषी क्षेत्राच्या भरभराटीस सहाय्य होते.

९. शेती आधारित उद्योग हे ग्रामीण भागात स्थापन होत असल्यामुळे ग्रामीण बेकारी व ग्रामीण दारिद्र्य कमी होण्यास मदत होते.

१०. कृषी आधारित ग्रामोद्योगांमुळे औद्योगिक विकेंद्रीकरण करणे शक्य होते. राष्ट्रीय उत्पन्नाचे समान वितरण होण्यास मदत होते.

११. जगातील अनेक विकसनशील देशांनी ग्रामीण विकासासाठी कृषी आधारित उद्योगांना प्राधान्य दिले आहे.

१२. देशातील आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी व ग्रामीण क्षेत्राचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी या उद्योगांचे महत्त्व आहे.

१३. आपल्या देशात नैसर्गिक साधन संपत्ती विपूल प्रमाणात असून तिचा पर्याप्त वापर होण्यासाठी शेती आधारित उद्योग महत्वाचे ठरतात.

१४. या उद्योगात औषधी वस्तूंचे उत्पादन होत असल्याने डोंगराळ व दुर्गम भागात वास्तव्य असलेल्या आदिवासी समाजाच्या विकासात मदत होते.

१५. या उद्योगांचे स्वरूप लहान असल्याने ते अल्पशा जागेत सुरु करता येतात. त्यामुळे उत्पादकास स्थीर घटकांवर जास्तीचा खर्च करावा लागत नाही.

१६. शेती आधारित उद्योगांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत गुणात्मक परिवर्तन करणे शक्य होते.

कृषी आधारित उद्योगांसमोरील समस्या:

१९९० च्या दशकात भारत सरकारने मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. मूळात मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार म्हणजे आव्हानांचे पॅकेज होते.

१. उद्योगाला लागणारा कच्चा माल साठवून ठेवण्याची पुरेशी व्यवस्था नसल्यामुळे केवळ तीन महिने पुरेले एवढाच कच्चा माल साठवून ठेवता येतो. तसेच तयार उत्पादन साठवून ठेवण्यासाठी व्यवस्था आवश्यक आहे. ती उपलब्ध नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करून महामान उत्पादनाचे फायदे घेता येत नाही.

२. जिथे धान्य, फळे आणि भाजीपाला निर्माण होतो तिथे त्या प्रमाणात त्यांच्या संकलनाची, साठवणुकीची आणि निर्यातीसाठीच्या योग्य यंत्रणेची व्यवस्थाच उपलब्ध नाही परिणामी फळे आणि भाजीपाला यांचे जितके उत्पादन होते त्याच्या ४० टक्क्याहून अधिक उत्पादनाच्या साठवणुकीची योग्य व्यवस्था नसल्याने नासाडी होते. शेती क्षेत्रातील उत्पादकता ही एक चिंतेची बाब आहे.

३. उस आणि कापूस ह्या सारखी पिके पैशाची पिके म्हणून शेतकऱ्यांनी स्वीकारली असली तरी त्यांना मिळणाऱ्या दरांच्या तुलनेत त्यांचा उत्पादन खर्च तसेच देशातील आयात-निर्यात धोरण या सर्वांचा परिणाम या पिकांच्या लागवडीवर सातत्याने होत असतो.



४. कधी कधी उत्पादन उत्तम दर्जाचे असूनही आय.एस.आय. किंवा एगमार्क यासारखे मानांकन प्राप्त झालेले नसल्यामुळे निर्यातक्षम उत्पादन असतांनाही प्रत्यक्ष निर्यात करणे शक्य झालेले नाही.
 ५. सहकार चळवळीने काही प्रदेशात उत्पादन वाढले खरे पण कालांतराने सहकारी चळवळीतील व्यावसायिक दृष्टीकोणात अभाव व राजकारणात प्रवेश करण्यासाठीची एक पायरी म्हणून सहकारी संस्थांचा वापर करणे यातून सहकारी चळवळी आणि उस शेती यावर आरिष्ट निर्माण झाले.
 ६. शेतजमीनीचा वापर अन्य कारणांसाठी वाढत गेल्याने शेतजमीन घटायला लागली. शेती परावलंबी व्हायला लागली आणि त्यातून छोटा शेतकरीही कर्जबाजारी झाला व आत्महत्या करू लागला.
 ७. उद्योग स्थापन करण्यासाठी प्रशिक्षणाची गरज असते. त्यामुळे प्रशिक्षणाखेरीज ग्रामीण लोक उद्योग करण्यास शक्य नाही आणि सोयीच्या ठिकाणी व सोयीच्या वेळी प्रशिक्षण उपलब्ध होत नाही.
 ८. उत्पादीत मालाच्या विक्रीसाठी, बाजारपेठ विस्तारण्यासाठी मालाला आकर्षक वेष्टनाची गरज आहे. त्यासाठी प्रशिक्षणाची गरज आहे.
 ९. स्थानिक पातळीवर मागणी होत नसल्यामुळे प्रक्रिया, पॅकिंग व वाहतुकीचा खर्च बराच जास्त येतो.
- याव्यतिरिक्त लोकांच्या आवडी-निवडीनुसार उत्पादन करणे अशक्य होत आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे हे उद्योग मेटकुटीस आले आहे. या उद्योगांमधील वस्तूंच्या किंमतीचा प्रश्नही जटील झाला आहे.
- उपाययोजना:

अभ्यास करित असतांना कृषी आधारित उद्योगांच्या समस्यांचा विशेष अभ्यास करण्यात आला. त्या समस्यांचा अनुशंगाने काही उपाययोजना या ठिकाणी विशद केल्या आहेत.

१. शेती आधारित उद्योगांची स्थापना ग्रामीण भागात करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या आधारभूत सोयी-सुविधा जसे की पाणी, रस्ते, अधिकोष, प्रशिक्षण संस्था इ. निर्माण केल्यास ग्रामीण शेती आधारित उद्योग सुरु करण्याची प्रेरणा ग्रामीण लोकांना मिळेल. त्यातून रोजगार निर्मिती, उत्पन्न वाढ, दारिद्र्य निर्मूलन यासारख्या गोष्टी साधल्या जातील.
 २. शेती आधारित उद्योग ग्रामीण भागात स्थापन केले तरी त्यामध्ये उत्पादित होणाऱ्या उत्पादनाला देशी बाजारपेठेसोबत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी म्हणून निर्यातक्षम उत्पादन करण्यासाठी उद्योजकांना प्रेरित करण्यासाठी निर्यातक्षम आवश्यक सुविधा त्यांना सहज आणि सोपेपणाने उपलब्ध व्हावी यासाठी शासनाने प्रयत्न करावे.
 ३. भारतात ८० टक्के कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे प्रमाण आहे. हा शेतकरी जे उत्पादन घेतो ते बाजारपेठेत नेल्यानंतर त्या चांगल्या दर्जाचा नाही, त्यात ओलावा अधिक आहे, माती अधिक आहे अशी कारणे दाखवून मालाचे वजन मूळतः असा त्यापेक्षा किमान १० टक्के कमी मानले जाते. बाजारपेठेच्या यंत्रणेसाठी पून्हा शेतकऱ्याला वेगळे पैसे द्यावे लागतात. असा पद्धतीने होणारे शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी मुळात उद्योगाचे निकष लावून शेती नियोजन करावयास हे उद्योजकाची मानसिकता प्रत्येक गावापर्यंत कशी पोहचेल यादृष्टीने प्रयत्न व्हावेत.
 ४. शेती आधारित उद्योगांच्या विकासासाठी शेती आधारित उद्योग विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात यावे. अंतर्गत या उद्योगांसाठी प्रशिक्षण, वित्तपुरवठा, अनुदान देवून ग्रामीण तरुणांना शेती आधारित उद्योग स्थापन करण्यास आकर्षित करता येईल.
 ५. कृषी आधारित उद्योग ग्रामीण भागातच आणि शेतकरी, शेतमजूर यांनी सहकारी तत्वावर किंवा बचतगटाच्या माध्यमातून सुरु करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे. जेणेकरून ग्रामीण भागातील लोकांच्या उत्पन्न स्तरात वाढ होवून ग्रामीण विकास शक्य होईल.
 ६. वेगळा कृषी अर्थसंकल्प दरवर्षी सादर करण्यात यावा जेणेकरून एकूणच कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी आर्थिक तरुण करणे शक्य होईल. शेती आधारित उद्योगांना विशेष प्राधान्य देवून ग्रामीण विकास पर्यायाने राष्ट्र विकास साधण्यास या होईल.
 ७. या व्यतिरिक्त या उद्योगांच्या विकासाकरीता बँकांनी अल्प व्याजदराने कर्ज पुरवठा करावा, देशातील सौचिक सुधारणा करणे व वाढविणे आवश्यक आहे, भारनियमन पद्धत बंद करावी, साठागृहे व गोदाम व्यवस्थेत सुधारणा करावी, नियंत्रित बाजारपेठेची संख्या वाढवावी, वाहतूक व दळणवळण सुविधा गुणवत्ताधारक व आवश्यक इतकी असणे आवश्यक आहे, निर्यातवृद्धीसाठी सरकारने निर्यात कर रद्द करून निर्यातीवरील बंधने दूर करावीत.
 ८. शेती आधारित उद्योगांच्या विकासासाठी प्रशिक्षण व संशोधन सुविधा उपलब्ध करावी. या उद्योगांना आधुनिक तंत्रज्ञान खरेदी करण्याकरीता सरकारने कर्जपुरवठा करावा. तसेच उद्योगांच्या विकासासाठी अनुदाने द्यावीत.
- सरकारने वरीलप्रमाणे उपाय केल्यास या उद्योगांच्या विकासास मदत होईल. भारत हा खेड्यांचा देश आहे असे सुधारली तर ग्रामीण भागात सुधारणा होतील म्हणून ग्रामीण भागात चालणारे शेती आधारित उद्योग हे ग्रामीण विकास आधारस्तंभ आहेत असा सर्व पातळीवर विचार होणे आवश्यक आहे.



संधी:

१. आज भारतीय शेती आधुनिकतेकडे वळू पाहते आहे. भारतीय शेतकरी परंपरागत पिकांसोबतच आता नवनवीन उत्पादन घेतो आहे. उत्तम दर्जाच्या शेतमालावर अनेक प्रकारच्या प्रक्रिया केल्या जात आहेत. उर्वरीत माल शीतगुहात माटवतो आहे. नवीन प्रयोग करण्याची क्षमता दिवसेंदिवस वाढत आहे. सर्वात महत्वाचं म्हणजे देश- विदेशातील बाजार समजून घेतो आहे. हे स्वप्नवत वाटणारं चित्र आता भारतातही मोठ्या प्रमाणात दिसू लागलं आहे.

२. भारतातील शेतमाल प्रक्रिया उद्योगांचे ग्राहक शंभरावर देशात आहेत आपल्याकडे मॉल्समध्ये शेतमाल प्रक्रिया उद्योगांच्या वस्तू उपलब्ध आहेत त्या वस्तू अमेरिकेतील काही मॉल्समध्ये देखील उपलब्ध आहेत. आपल्याकडे पॅकींग फुडचं महत्त्व वाढत चाललं आहे. मॉल्समध्ये कापून निवडून तयार केलेल्या पालेभाज्यांच्या विक्रीत खूपच वाढ झालेली दिसते.

३. सरकार मेक इन इंडिया अंतर्गत तब्बल १४ हजार कोटी रुपये शेती प्रक्रिया उद्योगांसाठी खर्च करणार आहे. देशामध्ये ४२ मेगा फूड पार्क्स उभारले जाणार आहे. त्यापैकी ५ फूड पार्क्सची उभारणी पूर्ण झालीय. यातून तीन लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होवून सुमारे १२ लाखावर शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. गुजरात राज्यातील खेडा गावात सुरु केलेल्या अमूल प्रकल्पानं आज विशालकाय रूप धारण केले आहे.

निष्कर्ष:

कृषी आधारित उद्योग व ग्रामीण विकास ह्या अध्ययनातून खालील निष्कर्ष निघाले आहेत. आग्र्याचा पेढा, चितव्यांची बाकरवडी, अमूलचं आईसक्रीम, हल्दीरामची मिठाई, बंगाली मिठाई, महाराष्ट्रीयन पापड या सर्वांनी जागतिक बाजारपेठेत आपलं स्थान मिळवलं आहे. ते स्थान मिळवणं नव्याने पदार्पण केलेल्या उद्योगांनाही शक्य आहे. गरज आहे मो फक्त इच्छा शक्ती आणि परिश्रमाची.

१. मेक इन इंडियाच्या संकल्पनेतील ग्रामीण रोजगाराचे, उत्तम दर्जाच्या उत्पादनाचे व निर्यात वाढीचे उद्दिष्ट शेती आधारित उद्योगातून साध्य होईल. यातून ग्रामीण विकास करण्याचे स्वप्न खऱ्या अर्थाने साध्य होईल.

२. शेतातील उत्पादित मालावर प्रक्रिया करणे, खऱ्या अर्थाने कृषी उद्योग मोठ्या प्रमाणात विकसीत होण्याला वाव आहे. प्रामुख्याने फळ प्रक्रिया उद्योग मोठ्या प्रमाणात विस्तारवा लागेल.

३. देशातील ग्रामीण भागात कृषी प्रक्रिया उद्योग सुरु केल्यास शेतातील कच्च्या मालाला तेथेच बाजारपेठ उपलब्ध होईल. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारून व रोजगारात वृद्धी होवून ग्रामीण भागातील होणारे स्थलांतर थांबेल.

४. मेक इन इंडिया अंतर्गत या उद्योगांसाठी ज्या सुविधा व सवलती देऊ केल्या गेल्या आहेत त्याचा फायदा भारतातील शेतकरी व उद्योजक कसा घेणार ही अत्यंत महत्वाची बाब आहे.

५. अन्न प्रक्रिया उद्योगात दळलेले धान्य, साखर, खाद्यतेल, पेये, फळे आणि भाजीपाला प्रक्रिया व दुग्धजन्य पदार्थ यांचा समावेश आहे. या उद्योगांना प्रोत्साहन मिळावे.

६. मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्यासाठी भांडवलाची गरज असते. परंतु ते सहजतेने उपलब्ध होत नाही.

७. कृषी पर्यटन उद्योगही हा नव्यानेच विकसीत होणारा उद्योग आहे. त्यामध्ये वाढ होणे आवश्यक आहे.

८. कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीत भारताचा सध्या ६ वा क्रमांक आहे तितका कायम राहावा यासाठी विशेष प्रयत्न व्हावे.

संदर्भसूची:

१. कविमंडन विजय, कृषी अर्थशास्त्र, मंगेश प्रकाशन, नागपूर.

२. देसाई - भालेराव, भारतीय अर्थव्यवस्था, निराली प्रकाशन, पुणे.

३. मिश्र डॉ. जयप्रकाश, (२००७) 'कृषी अर्थव्यवस्था', साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आग्रा.

४. डमढरे एस.व्ही., भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रथम आवृत्ती २००८, डायमंड पब्लि. पुणे.

५. ढाले रविन्द्र, डॉ.पंजाबराव देशमुख यांचे कृषीविषयक आर्थिक विचार, २००९.

६. वायमे प्रा. गोवर्धन कल्याण, 'स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारतीय कृषीचा विकास : एक दृष्टिक्षेप', ऑगस्ट २०१२.

७. संतोष दास्ताने, महाराष्ट्र वार्षिक २०१३, नितीन प्रकाशन, पुणे.

८. उद्योजक, दिपक देशमुख, मार्च २०१३, एप्रिल २०१३.

९. वाणी डॉ. निता 'कृषी अर्थशास्त्र', प्रशांत पब्लिकेशन्स, जळगांव, २०१५.

१०. अर्थसंवाद, जुलै - सप्टेंबर, २०१५

११. अर्थसंवाद, जानेवारी - मार्च, २०१६.



ISSN 2394-5303

Printing[®] Area

Issue-65, Vol-02 May-2020

Peer Reviewed International Refereed Research Journal



Editor
Dr. Bapu G. Gholap

14) CHILD ABUSE AND NEGLECT: A SOCIAL TRAUMA Dr. Hansa Tomar, Gadchiroli	67
15) EFFECT OF COVID-19 ON TOURISM INDUSTRY IN INDIA Dr. Krishna Kumar Verma, Shahjahanpur	72
16) पंढरपुरातील वारकरी मठ, फड व त्यांची ऐतिहासिक परंपरा प्रा. डॉ. प्रकाश फड, परळी वै.	75
17) महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे योगदान डॉ. प्रज्ञा बागडे, नागपूर	78
18) समुदायाच्या आरोग्यामध्ये अन्न संरक्षण पध्दतीचे महत्व प्रा. डॉ. मृणालिनी भूषण बंड, वर्धा	84
19) झोंबी या आत्मचरित्रात्मक कादंबरीतील डॉ.आनंद यादवांचे संघर्षमय जीवन प्रा.डॉ. डी. ए. पाटील, जि. धुळे	87
20) भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ आणि स्वदेशी चळवळीची वाटचाल भगवान ईश्वरलाल परदेशी, जि. धुळे	90
21) महानुभव पंथ - शिकवण व तत्त्वज्ञान प्रा.डॉ. हिरालाल रामदास चौधरी, जि. धुळे	92
22) खानदेशातील आदिवासी लोकजीवनात मोह वृक्षाचे महत्व प्रा.डॉ. रमाकांत अंबादास चौधरी, जि.धुळे	94
23) भूराजनितीच्या संदर्भात बलुचिस्थानचे महत्व - एक अभ्यास प्रा.डॉ. आर. एस. पवार, जि.धुळे	96
24) मराठा घराण्यातील स्त्रियांचे लोकोपयोगी व सार्वजनिक हिताची कामे - एक दृष्टिक्षेप प्रा. डॉ. रमेश धनराज जाधव, जि.धुळे	99
25) मानवी स्थलांतरामुळे निर्माण झालेल्या सामाजिक समस्यांचे मानसशास्त्रीय अध्ययन प्रा.डॉ. मोरे रविंद्र विठ्ठल, जि. धुळे	102
26) भारतीय इतिहासलेखनातील स्त्रीवादी विचार प्रवाह प्रा.डॉ. सतिश कदम, जि. बीड	105

- स्मरणिका, पंढरपूर डिसेंबर १९९४ पृ. ४"
५. निकते. प्र. द. "श्री संत शिरोमणी नामदेव महाराज पलखी सोहळा" पुणे १९८६
६. कराडकर बंडोबोवा "श्री गुरु देहूकर महाराज फड" - स्मरणीका पंढरपूर डिसेंबर १९९४ पृ. ५
७. गरूड तु. बा. "सार्थ हरिपाठ" ज्ञानेशाचा आत्मयोग, पुणे २०००, पृ. ४०
८. श्री. डॉ. बेणारे गोपाल "राणा पंढरीचा" कृष्णा ऑफसेट पंढरपूर पृ. ४२
९. उपरोक्त, पृ. ४३



महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे योगदान

डॉ. प्रज्ञा बागडे

अर्थशास्त्र विभागप्रमुख,

डॉ. मधुकरराव वासनिक पी. डब्ल्यू. एस. कला व
वाणिज्य महाविद्यालय नागपूर

गोषवारा :

महाराष्ट्राचा झालेला विकास हा देशाच्या सामर्थ्याचे प्रतिक आहे. आज महाराष्ट्र सरकारने ट्रिलियन डॉलर इकॉनामीचे उद्दिष्ट ठरविले आहे आणि हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमीत सहज शक्य आहे. शिवाजी महाराजांचा जन्म ही घटनाच महाराष्ट्राच्या इतिहासाला कलाटणी देणारी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची निर्मिती करून रयतेमध्ये स्वराज्य, स्वभाषा, स्वसंस्कृती, आर्थिक व सामाजिक विकास विषयी जागृती घडवून आणली. महाराजांनी ३५ वर्षे केलेला संघर्ष हा मुळी राजा होण्यासाठी नव्हताच तर तो संघर्ष होता अन्यायाने पिचलेल्या गोर, गरीब व उपेक्षित जनतेला त्यांचे हक्क मिळवून देणे, त्यांच्या जीवनात स्थैर्य आणणे, शांतता प्रस्थापित करणे आणि त्यांचे जीवन भयमूक्त करणे यासाठी त्यांनी स्वपराक्रमाने स्वराज्याची स्थापना केली एवढेच नव्हे तर स्वराज्याच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक विकासासाठी राबविलेली धोरणे महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देणारी ठरली. शिवाजी महाराजांचे महाराष्ट्राला व इतिहासाला असणारे हे योगदान विसरता कामा नये.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आर्थिक सुबत्तेसाठी उदबोगांवर जितका भर दिला तितका इतर कोणत्याही शासनकर्त्यांनी दिला नाही. राज्याचे कोषागार नेहमी श्रीमंत असावे म्हणून प्रजेचा आर्थिक छळ न करता योग्य व माफक दरात शेतसाय, करवसुली

झाली पाहीजे अशी ताकीद महाराजांनी त्यांच्या चिटणीसांना दिली होती. व्यापार, उदिम, संपत्ती, संरक्षण व अर्थनियोजन याबाबत महाराजांचे विचार व योजना काळाच्याही फार पुढे होत्या आणि म्हणून आजचा महाराष्ट्र हा देशाचे सामर्थ्यशाली राज्य आहे.

विजयशब्द : स्वराज्य, महसूल, रयत, शेती, शेतसारा, व्यापार, चलनव्यवस्था, औद्योगिकरण, आरमार, जाणता राजा.

प्रस्तावना :

महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात विकसनशील राज्य आहे. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने भारतातील तिसरे व लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसरे मोठे राज्य आहे. महाराष्ट्राला पराक्रमाची, त्यागाची व देशप्रेमाची परंपरा लाभली आहे. ही जशी शूरवीरांची भूमी आहे तशीच ती संत. महंत व ऋषी. मूर्तीचीही भूमी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखा शूर, पराक्रमी राजा या महाराष्ट्राला लाभला. त्यांनी सर्वधर्म समभावाचे पालन करून हिंदवी स्वराज्य रयतेचे राज्य स्थापन केले.

महाराजांनी महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात मोलाचे योगदान दिले आहे. 'रयत सुखी तर राजा सुखी' हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यकारभाराचे प्रधान सूत्र होते. विशेषतः प्रशासकिय, जमिन महसूल, जल. व्यवस्था, राजकीय, लष्करी, मुलकी, न्यायालयीन, उद्योग, परराष्ट्रीय आरमार, शैक्षणिक, धार्मिक, वतन, महिला यांच्या धोरणाप्रमाणेच कृषी धोरण वर्तमान तसेच भविष्यकाळासाठी हजारो वर्ष मार्गदर्शक ठरणारे आहे. आजचा महाराष्ट्र हा शिवाजी महाराजांच्या अथक् प्रयत्नातून उदयास आलेला महाराष्ट्र आहे.

विषयाचे महत्व :

या शोधपत्रामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दुरगामी अशा आर्थिक विचारांची समर्पकता अभ्यासता येते. त्याची राजकीय कारकीर्द तर प्रकाशमान होतीच. परंतु त्यांच्या आर्थिक धोरणावर प्रकाश टाकल्याने त्यांचे आर्थिक विचार, कार्य समाजापुढे येण्यास मदत होईल. शिवाजी महाराज केवळ राज्याचे शासक नव्हते तर समाजकारण, शेती, उद्योग अशा विविध क्षेत्रामध्ये माणसे घडविणारे एक कुशल नेतृत्व होते, हे समजण्यास मदत होईल. त्यांच्या आर्थिक धोरणांमुळे महाराष्ट्राच्या

अर्थव्यवस्थेला गती कशी प्राप्त झाली याचे स्पष्टीकरण करता येईल. एकूणच, महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासातील शिवाजी महाराजांचे योगदान स्पष्ट होण्यास मदत मिळेल. संशोधनाची उद्दिष्टे :

१) छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जीवन परिचय अभ्यासणे.

२) शिवाजी महाराजांच्या आर्थिक धोरणांचा अभ्यास करणे.

३) महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासात शिवाजी महाराजांचे योगदान तपासणे.

गृहीत :

१) महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासात शिवाजी महाराजांचे महत्वपूर्ण योगदान आहे.

व्याप्ती व मर्यादा :

प्रस्तुत संशोधनपत्रात आर्थिक दृष्टिकोणातून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विविध विचारांचा, धोरणांचा व कार्याचा अभ्यास करण्यात आला. परंतु शब्द मर्यादित मुळे त्यांचा जीवन परिचय व आर्थिक धोरणे थोडक्यात मांडण्यात आली आहेत. प्रस्तुत संशोधन हे दुय्यम सामग्री व त्यांच्या आर्थिक धोरणांशी संलग्न मर्यादीत आहे.

संशोधन पध्दती :

प्रस्तुत संशोधन हे प्रामुख्याने दुय्यम सामग्रीवर आधारित आहे. या संशोधनासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजावर लिखित सहित्य, शासकीय प्रकाशने, संदर्भ ग्रंथ इत्यादी बाबींचा आधार घेण्यात आला आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जीवन परिचय :

एखाद्या व्यक्तीमत्वाला काळ घडवितो तर काही व्यक्तीमत्व अशी असतात की, जी काळालाच घडवितात. अशा व्यक्तीमत्वांपैकी एक मोठे व्यक्तीमत्व म्हणजे 'छत्रपती शिवाजी महाराज'. छत्रपतींच्या व्यक्तीमत्वाचा व कारकिर्दीचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला असता काही गोष्टी समोर येतात. शौर्य, पराक्रम, शारीरिक सक्षमता, ध्येयवाद, कुशल संघटन करून नियोजनबद्ध प्रशासन, मुत्सद्दीपणा, धाडस, द्रष्टेपणा असे उच्च कोटीचे गुण महाराजांच्या व्यक्तीमत्वात एकवटलेले दिसतात.

शिवाजी महाराजांनी साध्या भोळ्या मावळ्यांचे

सघटन करून त्यांच्यामध्ये निष्ठा व ध्येयवाद जागृत केला. स्वतः शपथ घेवून हिंदवी स्वराज्य स्थापनेच्या कार्यात वाहून घेतले. सामान्य रयतेची व्यवस्था, शेतकऱ्यांची व्यवस्था, लढवय्या शूर सरदारांची व्यवस्था, धार्मिक स्थानाची व्यवस्था अशा अनेक व्यवस्था करवून व ठरवून दिल्या. अष्टप्रधान मंडळाची स्थापना करून हिंदवी स्वराज्याच्या राज्यकारभाराची परिपूर्ण व्यवस्था निर्माण केली. खचलेल्या रयतेच्या मनात स्वाभिमानाचा, पराक्रमाचा व स्वराज्यनिष्ठेचा हुंकार जागृत केला.

महाराजांनी दाखवलेले कौशल्यच त्यांना 'जाणता राजा' बनवू शकले. एवढेच नव्हे तर रयतेची स्वतःच्या मुलाप्रमाणे काळजी घेवून 'लोककल्याणकारी राजा' बनले. शिस्तबद्ध लष्कर व सुसंघटित प्रशासकीय यंत्रणेच्या बळावर महाराजांनी एक सामर्थ्यशाली आणि प्रागतिक राज्य उभे केले. सतराव्या शतकात जागृत झालेल्या तो स्वाभिमान, ती स्वराज्यनिष्ठा आजही महाराष्ट्राला प्रेरणा देते. महाराष्ट्राचा विकास, ऐश्वर्य, समृद्धी वाढविण्यासाठी प्रेरणा देते.

शिवाजी महाराजांची आर्थिक धोरणे :

१७ व्या शतकात महाराष्ट्रातील आर्थिक जीवन हे शेती व शेतीवर आधारित उद्योगांवर आधारलेले होते. शेती हाच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा होता. शिवाजी महाराजांनी राज्याच्या आर्थिक सुबत्तेसाठी उद्योगांवरही भर दिला. चैल, दाभोळ, कल्याण, कोल्हापूर, पुणे, वेंगुला, रायगड, राजगड, राजापूर या ठिकाणी बाजारपेठा वसविल्या होत्या. अरब राष्ट्रे व पूर्व किनाऱ्यावरील आफ्रिकन राष्ट्रे यांच्याबरोबर स्वराज्यातून व्यापार वाढविला होता. व्यापार, उदीम, अर्थनियोजन याबाबत शिवाजी महाराजांचे विचार, योजना, धोरणे काळाच्याही पुढे होते आणि म्हणून आजचा महाराष्ट्र समृद्ध व प्रगत आहे.

१. शेती व जमीन महसूल धोरण :

शिवकाळात जमीन महसूल ही राज्याच्या उत्पन्नामध्ये एक महत्वाच्या उत्पन्नाची बाब होती. पूर्वापार जमीन महसूल पध्दतीत छत्रपतींनी बदल घडवून आणले. जमीन महसूल निश्चित करण्यासाठी राज्यातील सर्व जमीनीची मोजणी करवून घेतली. जमीनीच्या मोजणीसाठी 'शिव काठी' चा वापर करण्यात आला.

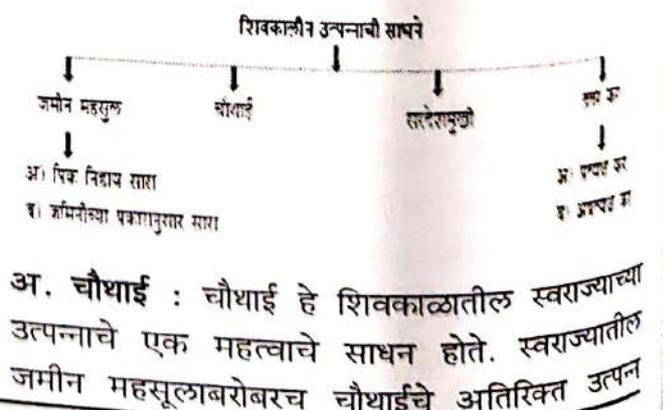
जमीनीची मोजणी करण्यासाठी अमीन, काटकर, कारकून असे अधिकारी नेमले जात. एकूण जमीन किती, त्यातील पिकाऊ किती व पडीक किती याची नोंद अधिकारी करित होते. मोजलेल्या पिकावू जमीनीवर महसूलाची आकारणी केली जाई. तसेच कोणते व किती पिके घेतली जातात याची माहिती घेतली जात असे. याला 'पिक पाहणी' असे म्हणत असे. प्रत्येक गावच्या व परगणाच्या अशा नोंदी घेतल्या जात व त्यानुसार सारा आकारणी निश्चित केली जाई.

मुस्लीम काळातील महसूल विक्री पध्दती बंद करून रयतवारी पध्दती सुरु केली. जहागिरी, वतने देण्याची पध्दतही बंद केली. तसेच शेतसारा वावतीतील दलाली पध्दती बंद केली. थेट सरकारमध्ये कर भरण्याची व्यवस्था केली. सारा निश्चिती रयतेच्या संमतीने केली जाऊ लागली. शेतसारा हा लागवडीखालील जमिनीवरच आकारला जात असे. पडीत जमिनीवर कोणताही शेतसारा आकारला जात नसे. नव्याने लागवडीखाली आणलेल्या जमीनीवर शेतकऱ्याला सवलती मिळत असे. गरीब शेतकऱ्यांना विशेष मदत दिली जाई, शेतसारा माफ केला जाई.

शेती सुधार योजना :

शिवाजी महाराजांनी शेतकऱ्यांना शेतीसाठी अवजारे, जनावरे तसेच बियाणे, धान्य खरेदीसाठी रोक रक्कम सरकारी खजिन्यातून देण्याची पध्दत सुरु केली. जिरायती जमिनी बागायती करण्यासाठी बंधारे बांधणे, पाट काढून देणे अशी व्यवस्था राज्यांनी करून दिली होती. अधिकाधिक जमिन लागवडीखाली आणण्यासाठी व उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन दिले.

३. शिवकालीन उत्पन्नाची साधने :



अ. चौथाई : चौथाई हे शिवकाळातील स्वराज्याच्या उत्पन्नाचे एक महत्वाचे साधन होते. स्वराज्यातील जमीन महसूलाबरोबरच चौथाईचे अतिरिक्त उत्पन्न

मिळत असे. 'चौथाई' म्हणजे शत्रूपासून आपल्या प्रदेशाचे संरक्षण करण्यासाठी आणि लुटमारीपासून संरक्षण मिळविण्यासाठी द्यावयाचा कर होता. चौथाई म्हणजे स्वराज्याबाहेरील प्रदेशातून वसूल करण्यात आलेला एकूण उत्पन्नाचा एक चतुर्थांश भाग घेण्याचा मराठ्यांचा हक्क होता. शिवकाळापासून हा कर मराठे स्वराज्याबाहेरील प्रदेशातून वसूल करू लागले. जिंकलेल्या प्रदेशातून किंवा शत्रुच्या प्रदेशातून चौथाईची रक्कम गोळा केली जात असे.

ब. सरदेशमुखी : सरदेशमुखी म्हणजे उत्पन्नाचा १/१० हिस्सा. सरदेशमुखी हा कर केवळ स्वराज्यातून घेतला जाई. हा राज्याचा खास हक्क असून 'स्वामी' ह्या नात्याने सरदेशमुखीच्या बदल्यात स्वराज्यातील जनतेचे शत्रु पासून संरक्षण केले जाई. १६७६-७७ मध्ये कर्नाटक स्वारी करून तेथील संस्थानिकावर चौथाई, सरदेशमुखी बसवली.

क. इतर कर : शिवकाळात इतरही अनेक कर वसूल केले जात असत.

१) प्रत्यक्ष कर : शिवकाळात वैयक्तिक उत्पन्न, विविध व्यवसाय आणि मालमत्ता यावर कर लावले जात असत. वैयक्तिक करात इनामपट्टी, मिरासपट्टी, देशमुख पट्टी, धनगर पट्टी, तेलपट्टी, वेठबिगारी, मोहतरफा इ. करांचा समावेश होता.

२) अप्रत्यक्ष कर : शिवकाळात अप्रत्यक्ष करात जकात कर, दलाली, जनावरांवरील कर, आवश्यक वस्तुंवरील कर, न्यायालयीन कर, वारसा विषयक कर अशा विविध करांचा समावेश होता. प्रदेशातून स्वदेशात येणाऱ्या व स्वराज्यातून बाहेर जाणाऱ्या मालावर जकात कर बसविला जात होता.

३) संकीर्ण कर : यात अबकारी कर, खर्चापट्टी किंवा गावखर्च, नुकसानपट्टी, गडी तंखाखू इ. कर होते.

४) शिवकाळातील व्यापार व उद्योग धोरण :
शिवकाळात खेडे हे अर्थव्यवस्थेचा पाया होता. शेतीबरोबरच इतर काही उद्योगधंदे केले जात होते. खेड्यातील कारागीरांनी स्थलांतर करू नये म्हणून शेतीबरोबरच कारागीरांना गावामध्येच उद्योगधंदे उभारण्यासाठी सर्व प्रकारच्या सोयी उपलब्ध करून

देण्याकडे गावगाड्यांचा कल होता.

अ) शिवकालीन व्यापार :

शिवकाळात महाराष्ट्राचा व्यापार उदिम वाढीस लागला. महाराजांच्या स्वराज्य स्थापनेमुळे मराठी माणसाला व्यापाराच्या व उद्योगाच्या अनेक नव्या संधी प्राप्त झाल्या. छत्रपतींनी राज्यातील उद्योगधंदे चालविण्यासाठी कारागीर, व्यावसायिक व व्यापारी यांना अनुकूल परिस्थिती निर्माण करून दिली. व्यापार वाढीस लागला म्हणून अंतर्गत व परकीय व्यापाराकडे लक्ष दिले. भिवंडी, कल्याण, कोल्हापूर, पुणे, रायगड, राजापूर सारख्या ठिकाणी बाजारपेठा वसविल्या. अरब राष्ट्रे व पूर्व किनाऱ्यावरील आफ्रिकन राष्ट्रे यांच्याबरोबर स्वराज्यातून व्यापार चालत असे.

१६७४ नंतर शिवाजी महाराजांनी आपल्या राज्यातील व्यापार वृद्धीकडे लक्ष दिल्याचे समजते. महाराजांनी इंग्रजांशी मैत्रीचे संबंध प्रस्तापित करून व्यापारी करार केला होता. नाविक, मुलकी व लष्करी अधिकाऱ्यांना व व्यापाऱ्यांना शक्य तेवढ्या सवलती देऊन व्यापारास उत्तेजन दिले. महाराजांचे व्यापार विषयक धोरण उदारमतवादी असल्यामुळे शिवकाळात महाराष्ट्रात व्यापार वाढीस लागला.

ब) शिकालीन उद्योगधंदे :

१) ग्रामीण उद्योगधंदे : या काळातील व्यवसाय जातीवर आधारलेले होते. आपल्या जाती बाहेरचे व्यवसाय करण्याची फारशी प्रथा नव्हती. ग्रामीण भागातील बलुतेदार व अलुतेदार हे शेतीला पुरक असे व्यवसाय करीत असत. कापड तयार करणारे कोष्टी, लाकडी वस्तू तयार करणारे सुतार, शेतीसाठी लागणारी अवजारे बनविणारे लोहार, कातडी वस्तू बनविणारे चांभार, तेल वाढणारे तेली, दारु उत्पन्न करणारे कलाल, लोकरी कपडे बनविणारे धनगर, मूर्ती बनविणारे कारागीर असे अनेक व्यावसायिक खेड्यात राहत.

२) लाकुड उद्योग व जहाज बांधणी : शिवकाळात लाकुड व जहाज बांधणी व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर चालू होता. शिवाजी महाराजांनी आरमार उभारणीवर लक्ष दिल्याने जहाज बांधणी व्यवसायास उत्तेजन मिळाले. कोकण किनाऱ्यावरील कल्याण, भिवंडी पनवेल, राजापूर, देवगड, मालवण अशा बंदरात जहाज

बांधणी कारखाने होते. येथे शिख, पाल, गलबत ही अर्वाचिन काळातील जहाजे बांधली जात. भारतीय जहाज बांधणी उद्योगाची ती पहिली पायरी होती. इंग्रजांच्या तोडीचे आरमार बनविता आले नसले तरी मराठा आरमाराचा सागरी दबदबा इंग्रज, डच, फ्रेंच, अशा सर्वच परकीयांना पळताभूई करणारा ठरला.

३) धातुकाम : शिवकाळात धातुकाम हा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर चालत होता. नित्योपयोगी वस्तू बनविण्यासाठी सोने, चांदी, तांबे, पितळ व लोखंड या मुख्य धातुंचा व्यवसाय स्वराज्यात सर्वत्र चालत असे. नाण्यांचा उपयोग विविध भांडी बनविण्यासाठी होत असे. तांब्याचा वापर देवळाच्या कळसाचे वरचे भाग बनविण्यासाठी व हलकी नाणी तयार करण्यासाठी केला जात असे. तांबे व जस्त यांचा उपयोग अवजारे, शस्त्रास्त्रे बनविण्यासाठी केला जात असे.

४) कापड उद्योग : शिवकाळात कापसापासून तयार केलेल्या विविध वस्तू दिसून येतात पुरुष व स्त्रियांचे पोशाख, भोंगडी अंगरखे, शाली, लांब कोट, पगड्या, साड्या दुपट्टे, उपरणे, चिट, रेशमी, पोगाटे अशी विविध वस्त्रे बनविली जात. पागोटी मुख्यतः खानदेशातील फैजपूर, नांदेड, जालना, शहादा, पैठण व जुन्नर याठिकाणी बनविली जात. बऱ्हापूर, नागपूर, सासवड, गंगासागर ही चिटाच्या उत्पादनाची प्रमुख केंद्रे होती. नागपूर, माहेश्वर, चांदवड व सोलापूर येथे तलम धोतरे बनविली जात.

५) मीठ व साखर उद्योग : कोकणात सागर किनारपट्टीवर मीठ उत्पादनाचा महत्वाचा उद्योग होता. ठाणे व कूलाबा जिल्ह्यातील पेण, पनवेल, नागोठाणे, रेवडंडा व ठाणे ही १७ व्या शतकातील मीठाच्या उत्पादनाची प्रमुख केंद्रे होती. शिवकाळात मीठ उद्योग दुय्यम धंदा होता. सुगीचा काळ संपल्यावर लोक मीठाच्या उद्योगाकडे वळत. कोकणातून देशाच्या सर्व भागात मीठाचा व्यापार चालत असे. तसेच परदेशातही निर्यात होत असे.

साखरेचे उत्पादन उसाच्या उत्पादनाच्या भागातच होत असे. पांढरी साखर, खडी साखर व कच्ची साखर किंवा गुळ हे साखरेचे तीन प्रकार होते. साष्टी प्रांतात साखर व गुळ मोठ्या प्रमाणात तयार करण्याचा उद्योग

जोरत होता.

५. शिवकालीन चलन व्यवस्था :

शिवकाळात चलनाच्या वापराऐवजी वस्तूविनिमय पध्दतीला अधिक महत्व होते. रोख चलनाची गरज दैनंदिन व्यवहारात पडत नसे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या नाण्यांसाठी मूळ प्रमाणभूत नाणे म्हणून विजयनगराच्या होन ह्या नाण्याचा स्वीकार केला आणि स्वतः शिवराई हे सोन्याचे नाणे म्हणून विजयनगराच्या सोन्याच्या नाण्याच्या धर्तीवर पाडून घेतले.

अ) शिवकालीन सोन्याची नाणी : शिवकाळात गंबर, मोहर, पुतळी, सणगरी, शिवराई (पादशाही, देवराई, अच्युतराई, रामचंद्राई, सतलामी, इब्राहिमी, टिपको, धारवाडी, कावेरी, पाक, चांदवडी, वेंगर्ला, वेल्लो, आदवानी, देवनहडी, व्यंकटराई, त्रिसुळी, ताडपत्री, फणम, कॅक्रम इ. सोन्याची नाणी प्रचलित होती. गंबर हे नाणे मुंबई परिसरात प्रचलित होते. मोहर हे नाणे प्रामुख्याने राज्याला भेट म्हणून देण्यासाठी उपयोगात आणले जात होते. मोहर होन हे शिवकाळातील सोन्याचा रुपया होता. एका मोहरची किंमत १३ रु होती.

ब) चांदीची नाणी : शिवाजी महाराजांनी आपल्या काळात चांदीची नाणी पाडलेली नव्हती. अब्बासी, अश्रफी, रीयाल, लाटी, महमुदी, रुपया, टका ही चांदीची नाणी वापरत होती. लारी हे चांदीचे नाणे इराणमध्ये पाडलेले होते. रुपयामध्ये आलमगिरी रुपया, चलनी रुपया, खजाती रुपया या प्रकारची नाणी आढळतात.

क) तांब्याची नाणी : शिवकाळातील तांब्याच्या नाण्यात शिवरायी, सजगणी, तिरुका, रुका, पैसा, दाम, अडका, जितल या नाण्यांचा समावेश होता.

ड) पैसा : शिवकाळात पैसा हे तांब्याचे नाणे वेगवेगळ्या आकाराचे असे. त्याच्या एका बाजुला श्री राजा छत्रपती तर दुसऱ्या बाजुला फुल, तलवार, सूर्य, बाण, चंद्र बेलाची पाने, ग्रह, तारे, यापैकी एक चित्र कोरलेले असे. तर तिरुका पैशाचा आकार लहान होता. त्यामुळे छत्रपती पैशाला मोठा पैसा व तिरुका पैशाला छोटा पैसा असे म्हटले जात होते.

इ) शिवकाळातील इतर नाणी : शिवकाळातील नाणे पध्दती व विजयनगरमधील नाणे पध्दती यात

बरेच साम्य होते. 'वराह' किंवा 'होन' ह्या सुवर्ण नाण्यांची लहान नाणी म्हणजे प्रताप, दरण, चवल, दुबल, पल व वीस ही होती. थोडक्यात शिवकालीन चलनव्यवस्थेत सोन्याची, चांदीची, व तांब्याची नाणी चलनात प्रचलित होती.

६. रयतेचे उत्पन्न तेच राजाचे उत्पन्न :

छत्रपती शिवाजी महाराजांना जाणीव होती की, शेती ही रयतेचे मुख्य बलस्थान असून संपुर्ण प्रजेचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे. प्रत्यक्ष शेतात राबणारा रयत हाच खरा शिवकालीन शेतीचा आधार होता. त्याचा व्यवसाय हा समाजातील महत्वाचा व्यवसाय मानला जात होता. त्याचे उत्पन्न हेच राजाचे उत्पन्न होते. शेती हे केवळ उपजिविकेचे साधन नसून रयतेच्या उत्पन्नाचे स्रोत होते.

७. पशूधनाला महत्व :

छत्रपती शिवाजी महाराज पशुपालनाबाबत देखील तेवढेच जागरूक होते. दुष्काळी परिस्थितीत पशुधन जगविण्यासाठी चारा, पाणी व अन्नधान्य पुरविण्याबाबत अष्टप्रधान मंडळाला सक्त आदेश दिलेले असत. म्हणून पावसाचे पाणी अडवावे व वर्षभर पशुपालन आणि शेतीच्या विविध कामासाठी त्याचा उपयोग करावा असा त्यांचा आग्रह असे.

८. वृक्षसंवर्धन :

शिवाजी महाराजांनी आज्ञापत्रे आजही दखल घेण्यासारखी आहेत. त्यांनी वृक्षाचे महत्व सांगितले. आजही वृक्ष संवर्धनाचा त्यांचा संदेश आचरणात आणण्याची गरज आहे.

निष्कर्ष :

महाराष्ट्राचे आद्य दैवत मानले जाणारे छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे गुणांचा खजिणा. स्वराज्यातील जनतेला औदार्य दाखवितांना त्यांनी कुठेच भेदाभेद केला नाही. एवढेच नाही तर कोणी चुकल्यास त्याच्या विरोधात कृती करण्यास त्यांनी मागेपुढेही पाहीले नाही. कठोर निर्णय घेतांना प्रसंगी मश्टुपणाही दाखविला.

शिवाजी महाराजांनी कृषी क्षेत्रात खूप मोलाचे योगदान दिले आहे. 'रयत सुखी तर राजा सुखी' हे त्यांच्या राज्य कारभाराचे प्रमुख सूत्र होते. कृषी धोरणाप्रमाणेच विशेषतः प्रशासकीय, जमिन महसूल,

जल, राजकीय, लष्करी, मुलकी, न्यायालयीन, उद्योग, परराष्ट्रीय आरमार, शैक्षणिक, धार्मिक, वतन, महिला या संबंधीचे धोरणे वर्तमान तसेच भविष्यकाळासाठी हजारे वर्ष मार्गदर्शक ठरणारी आहेत. म्हणूनच शिवाजी महाराजांना द्रष्टा महापुरुष म्हटले जाते.

आर्थिक विकासासाठी शेती विकासाशिवाय पर्याय नाही असे सांगून त्यांनी आर्थिक नियोजनात शेतीला प्राधान्य दिले. शेतीला केवळ उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून न पाहता ती व्यापारी तत्वावर केली पाहिजे व शेतीला पुरक उद्योगाची जोड देणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. शेतीप्रमाणे उद्योगधंदेही महत्वपूर्ण भूमिका बजावतात म्हणून त्यांची उद्योगासंबंधीची धोरणेही महत्वपूर्ण होती. शेतीवर आधारित उद्योग सुरू करून शेती व उद्योगाची सांगड घातली पाहिजे त्यामुळे ग्रामिण भागातील लोकांना स्थलांतर करण्याची गरज पडत नाही. त्यासाठी ते ग्रामीण उद्योगधंद्यांना आर्थिक सहाय्यही करत व सवलतीही देत. यावरून ते औद्योगिक विकास व रोजगार निर्मिती बद्दल दक्ष व प्रयत्नशील होते असे दिसते.

अर्वाचिन काळात औद्योगिक सुरक्षितता यावर जो भर दिला त्याची जाणीव तीनशे वर्षापूर्वीच शिवरायांना होती. व स्वराज्यात त्याबाबत जागृती व्हावी या विचाराने शिवाजी महाराज पावले टाकत. आज सैन्यकपात व शेतीला आलेले गौणत्व बघता शिवाजी महाराजांच्या राजकारणाची व अर्थकारणाची समर्पकता आजही आहे. असे वाटते.

आर्थिक विकास हा केवळ वस्तू व सेवांच्या उत्पादनाशी निगडित नसून समाजाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये विकासात्मक बदल घडून येणे होय. यात समाजात विविध घटकांपर्यंत विकासाचे फायदे पोहचविणे अपेक्षित असते. रोजगाराच्या संधी वाढविणे, दारिद्र्य कमी करणे, आर्थिक विषमता कमी करणे, समाजातील सर्व घटकांचे जीवनमान उंचावणे ह्या बाबी देखील अपेक्षित आहेत. नेमके हेच जाणून शिवाजी महाराजांनी आपल्या राज्यकारभाराची व आर्थिक विकासाची धोरणे राबवून महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला गती दिली व एक यशस्वी शासनकर्ता म्हणून नावलौकीक मिळविला.

शिवाजी महाराजांनी राज्याच्या विकासासाठी

आखलेली औद्योगिक धोरणे प्रभाविपणे राबविल्यामुळे महाराष्ट्राच्या औद्योगिकीकरणाला शिवकाळातच चालना मिळून आजचा महाराष्ट्र औद्योगिकदृष्ट्या विकसित व प्रगत दिसतो. एकूणच यावरून महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे योगदान सिध्द होते. एवढेच नाही तर छत्रपतींच्या या महाराष्ट्राने कृषी, साहित्य, कला, शिक्षण, क्रिडा, संस्कृती, न्याय, चित्रपट, संगीत, सहकार, संगणक व विज्ञान अशा विविध क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेतली आहे. आजही शिवरायांच्या योगदानाची जाणीव ठेवत, वैभवशाली इतिहास जपत महाराष्ट्र प्रगतीची नवनवी शिखरे पादाक्रांत करित आहे.

संदर्भ सूची :

- १) आठवले सदाशिव: शिवाजी व शिवयुग.
- २) महंढे गजानन भास्कर: श्री राजा शिवछत्रपती भाग . १.
- ३) सरदेसाई गोविंद सखाराम : मराठी रियासत खंड. १.
- ४) सरदेसाई बी. एन. : मराठ्यांच्या सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक इतिहास.
- ५) कुलकर्णी अ. रा., डॉ. देशपांडे प्र. न. : मराठ्यांचा इतिहास भाग . १.
- ६) शिवाजी महाराजांचे विकास धोरण दिशा देणारे: लोकमत, २८ जाने. २०१३.
- ७) <https://maharashtratimes.intimes.com>.
- ८) <https://www.lokrajya.com.shivaji>
- ९) <https://www.saamtv.com.marathi>
- १०) <https://www.loksatta.com>.



समुदायाच्या आरोग्यामध्ये अन्न संरक्षण पध्दतीचे महत्त्व

प्रा. डॉ. मृणालिनी भूषण बंड
गृहअर्थशास्त्र विभाग,
प्रियदर्शनी महिला महाविद्यालय वर्धा

सारांश :-

सामाजिक आरोग्य म्हणजे आपण ज्या समाजाचे घटक आहोत. त्या सर्वांशी चांगले वागणे, राहणे, सामाजिक प्रश्न किंवा अडचणी सोडवण्याचा आपणांमार्फत प्रयत्न करणे असे म्हणता येईल.

हे सर्व करण्यासाठी मनुष्याला उत्तम अन्नपदार्थाची आवश्यकता असते. कारण उत्तम अन्नपदार्थाने मनुष्याचे योग्य पोषण होवून त्याचे कार्यशक्ती वाढते. त्याचबरोबर योग्य विचार कलम मनुष्य सुखी-समाधानी, आनंदी जीवन जगू शकते. परंतु अन्नामध्ये कमी दर्जाचे किंवा जीवाणू युक्त पदार्थ मिसळल्यास ते मानवी आरोग्यास अपायकारक होवू शकते. अन्नातील असुरक्षित पदार्थांमुळे मनुष्य अनेक आजारांना बळी पडू शकतो.

अशा असुरक्षित अन्नामुळे शरीर आपले कार्य नीट करू शकत नाही. शरीराच्या वाढीस अडथळे येतात. म्हणून दुषित अन्न असे ओळखावे व अन्न दुषित होवू नये म्हणून त्याचे संरक्षण कसे करावे याचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.

मुख्य शब्द :- समुदाय, आरोग्य, अन्न संरक्षण.
प्रस्तावना :-

पूर्वीपासून आपल्या खाद्यसंस्कृतीमध्ये अन्न संरक्षणाचा उपयोग करून खाद्यपदार्थ टिकवून ठेवण्याची परंपरागत पध्दत आहे. साधारणतः उन्हाळ्यामध्ये भाज्या वाळविणे, पापड करणे इ. पदार्थ केले जात असत. परंतु आज जागा व वेळेच्या अभावी वाळविण्याची ही

विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीचा इतिहास
1891-1970

ISSN - 2249-5134



Perspectives

A National Interdisciplinary Annual Research Journal

Peer Reviewed
Research Journal for
Interdisciplinary
Studies in Arts
Commerce &
Social Sciences

Vol. I
Special Issue (VIII)
2020



Dr. Madhukarrao Wasnik
PWS Arts and Commerce College
Kamptee Road, Nagpur - 26.
(Reaccredited 'B' by NAAC)



Scanned with OKEN Scanner

Perspectives

A National Interdisciplinary Annual Research Journal February 2020

अनुक्रमणिका

अ.क्र.	शोध पेपरचे शिर्षक	संशोधकाचे नाव	पृष्ठ क्र.
विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीचे शिलेदार			
1	विठोबा रावजी मुनपंडे यांचे विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीतील योगदान	डॉ. विमल राठोड	1 ते 4
2	गुरूवर्य किसन फागोजी बन्सोड - दलित स्त्रियांचा उद्धार	डॉ. आनंद गणवीर	5 ते 10
3	श्री. किसन फागुजी बन्सोड : विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीतील एक खंबीर नेतृत्व	डॉ. कैलाश फुलमाळी	11 ते 12
4	किसन फागुजी बन्सोड यांचे लेखन चित्रणातून वंचितांच्या उध्दाराचे कार्य	प्रा. डॉ. प्रमोद बोधाने	13 ते 14
5	वंचितांच्या अधिकारासाठी झटणारे समाजसुधारक : किसन फागोजी बन्सोड.	डॉ. गोपीचंद कठाणे	15 ते 17
6	विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीत किसन फागुजी बन्सोडचे वृत्तपत्रिय योगदान	डॉ. प्रदिप ढोले	18 ते 20
7	आंबेडकरी चळवळीतील देवाजी खोब्रागडे यांचे कार्य	डॉ. अविनाश फुलझेले	21 ते 25
8	विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीतील देवाजीबापू खोबरागडे यांचे योगदान	प्रा. डॉ. नरेश कवाडे	26 ते 29
9	विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीतील नेते नानासाहेब गवई यांचे सामाजिक, राजकीय आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्य	डॉ. राजू खरडे	30 ते 32
10	महात्मा कालीचरण नंदागवळी यांचे आंबेडकरी चळवळीतील योगदानाचे ऐतिहासिक विश्लेषण	प्रा. पंकज वामन मून	33 ते 34
11	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विदर्भातील सांगाती. रेवाराम विठोबा कवाडे	डॉ. यशवंत पाटील	35 ते 38
12	बाबू एल. एन. हरदास यांचे सायमन कमिशन व नागपूर डिप्रेस्ड क्लासेस मधील योगदान	प्रा. आशिष थुल	39 ते 40
13	"डॉ. अम्बेडकर के आंदोलनों में बाबू हरदास एल.एन. का योगदान"	प्रा. किशोर चौरे	41 ते 44
14	धम्मरक्षक अॅड. बाबू आवळे	डॉ. संजय गजभिये	45 ते 53
15	हरिदास बाबू आवळे यांचे विदर्भातील समता सैनिक दलातील योगदान	डॉ. चंद्रशेखर पाटील	54 ते 59
16	विदर्भातील आंबेडकर चळवळीत दशरथ पाटील यांचे योगदान	डॉ. अफरोज शेख	60 ते 62
17	गं. म. ठवरे यांचे विदर्भातील शैक्षणिक योगदान : एक अभ्यास	डॉ. लखपती गायकवाड	63 ते 64
18	बॅरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे विदर्भातील एक राजकीय व सामाजिक नेतृत्व	अरुण ज्ञानेश्वर बरडे	65 ते 69
19	विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीतील बॅ. राजाभाऊ खोबरागडे यांचे सामाजिक व राजकीय कार्य	डॉ. अनिल बाभळे	70 ते 73
20	बॅरि. राजाभाऊ खोब्रागडे यांचे विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीतील योगदान	रत्नदिप गणवीर	74 ते 77
21	विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीत रामरतन जानोरकर यांचे योगदान	विनायक जामगडे	78 ते 80
22	दादासाहेब कुंभारे यांचे आंबेडकरी चळवळीत योगदान	डॉ. सुशांत चिमणकर	81 ते 83
23	आंबेडकरी चळवळीत दादासाहेब गवई यांचे योगदान	डॉ. मोहन वानखडे	84 ते 87
24	वैदर्भिय आंबेडकरी चळवळीतील एक ग्रंथप्रेमी शिलेदार श्री वसंत मुन	प्रा. गामिनी मेश्राम	88 ते 90
25	इतिहास संशोधक वसंत मुन	डॉ. लखन इंगळे	91 ते 92
26	विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीतील राजकीय व सामाजिक कर्मनिष्ठ नेतृत्व - अॅड. सखाराम एम. मेश्राम	डॉ. कमलाकर तागडे	93 ते 95
27	विदर्भिय आंबेडकरी चळवळीत डॉ. मधुकरराव वासनिक यांचे योगदान	डॉ. एन. लांडगे	96 ते 100
28	वामनराव गोडबोले यांचे धम्मदीक्षा सोहळ्याचे वित्तीय व्यवस्थापन	प्रा. नरेंद्र सरोदे	101 ते 102
29	एक कर्तृत्ववान नेतृत्व मा. नाशिकराव तिरपुडे साहेब	प्रा. असंगवज्र मैत्रेय	103 ते 104
विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीतील रणरागिनी			
30	विदर्भातील आंबेडकरी महिलांची विसाव्या शतकातील सामाजिक चळवळ	डॉ. टी. जी. गेडाम	105 ते 108
31	विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीत महिलांचे योगदान	प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे	109 ते 113
32	विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीत महिलांचे योगदान	डॉ. सुजाता गौरखडे	114 ते 117
33	"विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीत महिलांचे योगदान"	डॉ. ज्वाला भा. डोहाणे.	118 ते 120

विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीतील कर्तबगार महिला

प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे

विभागप्रमुख, अर्थशास्त्र

डॉ. मधुकरराव वासनिक पी. डब्ल्यू. एस.

कला व वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर

गोषवारा-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुरु केलेली सामाजिक समतेची, स्वातंत्र्य व बंधुत्वाची चळवळ सर्व स्तरापर्यंत पोहचविण्यासाठी आंबेडकरी जनता कटीबद्ध आहे. त्यातही आंबेडकरी चळवळीतील स्त्री ही स्वतःची जबाबदारी समजून चळवळीत काम करित आहे, आपले योगदान देत आहे. आंबेडकरी चळवळीतून ती स्वाभिमानी, स्वावलंबी व आत्मनिर्भर होताना दिसत आहे तसेच सर्व क्षेत्रांमध्ये तीने आघाडी घेण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. मग ते साहित्याचे क्षेत्र असो, शैक्षणिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र किंवा आर्थिक क्षेत्र असो. १९७० पर्यंत विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीत योगदान दिलेल्या स्त्रीयांमध्ये प्रामुख्याने जाईबाई चौधरी, अंजनीबाई देशभ्रतार, सुलोचनाबाई डोंगरे, सीताबाई गायकवाड, गीतीबाई पवार, कितीबाई पाटील, इंदिराबाई पाटील, नलीनीताई लढके, पारवताबाई मेश्राम, दमयंतीबाई देशभ्रतार, चंद्रिकाबाई रामटेके, गीताबाई भगत, सोनुबाई लांजेवार, सुगंधाताई शेंडे यांचे योगदान विशेष राहिले आहे. आज महिलासंबंधी सर्वत्र चालू असलेल्या समाज परिवर्तनाच्या अनेक चळवळीचा पायाच या कर्तबगार महिलांनी घातला आहे. वरील महिला आंबेडकरी चळवळीच्या प्रत्यक्षयोद्धा राहिलेल्या आहेत. स्त्री शिक्षण व स्त्री सुधारणा हा महात्मा जोतीबा फुले, सावित्रीबाई फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा वारसा यांनी पुढे चालविला होता. यांच्या अथक प्रयत्नांमुळेच आंबेडकरी चळवळीतील पुढच्या पीढ्यांतील महिलांना दिशा दिलेली आहे. समाजातील कोणत्याही स्त्रीवर अन्याय व अत्याचार झाल्यास त्याविरुद्ध संघर्ष करण्यात आंबेडकरी चळवळीतील स्त्रीया आघाडीवर असतात. असे असले तरी आजही ग्रामीण भागातली दलित स्त्री पाहिजे त्या प्रमाणात सक्षम झालेली दिसत नाही. म्हणून आजही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुरु केलेली सामाजिक समतेची, स्वातंत्र्य व बंधुत्वाची चळवळ गतीशील ठेवून सर्व स्तरापर्यंत व प्रामुख्याने ग्रामीण भागात पोहचविण्याची गरज आहे. त्यासाठी नवीन पीढीतील महिलांनी चळवळीला हातभार लावण्याची एवढेच नव्हे तर चळवळीत सक्रीय सहभाग देण्याची गरज आहे.

बीजशब्द - चळवळ, योगदान, गुलामगिरी, बहिष्कृत, नेतृत्व, समाजसेवा, रुढी-परंपरा, आत्मसन्मान.

संशोधन पद्धती : ऐतिहासिक संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आलेला आहे.

प्रस्तावना- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या दलित मुक्ती आंदोलनाचा महत्वाचा कालखंड म्हणजे १९२७ चा महाडचा सत्याग्रह आणि १९५६ चे धर्मांतर. या काळातच बाबासाहेबांच्या विविध आंदोलनाला सहकार्य देत आपल्या घरादाराची पर्वा न करता कमरेला पदर खोचून अनेक महिला घराबाहेर पडल्या. वर्णव्यवस्थेने लादलेल्या गुलामीचे जोखड झुगारून समतेच्या लढ्यात सामील झाल्या. त्या काळात चळवळीत भाग घेण्यासाठी स्त्रीयांचे मन वळविणे सोपे नव्हते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्त्रीयांनी वाढत्या संख्येने चळवळीत सहभागी व्हावे, अशी वेळोवेळी आव्हाने केलेली दिसतात.

दलित स्त्रीच्या जीवनाची झालेली कोंडी फुटण्यास आंबेडकरी चळवळीमुळे प्रथम सुरुवात झाली. स्त्रीया सभेत श्रोता म्हणून हजेरी लावू लागल्या. त्यापैकी काही धोटाईने भाषणे करू लागल्या. काही शिकलेल्या स्त्रीयांनी लेखनी हातात धरून आपल्या आकांक्षा, दुःखे बोलून दाखविण्यास प्रारंभ केला. मोर्चे, मिरवणूका, सत्याग्रह, मोहिमा यात भाग घेऊन काहींनी त्यासाठी तुरुंगवासही सोसला. दमयंतीबाई देशभ्रतार, गीताबाई गायकवाड, शांताबाई दानी यांच्यासारख्या स्त्रीयांनी स्थानिक स्वराज्य तसेच विधानमंडळाच्या निवडणूकाही लढल्या. आज आंबेडकरी चळवळीतील अनेक स्त्रीयांचा स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये सकारात्मक सहभाग आढळून येतो. अनेक स्त्रीया सरपंच म्हणून, सभापती म्हणून तिरंगा फडकवितांना दिसून येतात. एकंदरच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेद्वारे स्त्रीला प्रदान केलेल्या अधिकारांमुळे व आंबेडकरी आंदोलनातील महिलांच्या सक्रीय योगदानामुळे आजची आंबेडकरी समाजातील स्त्री प्रत्येक क्षेत्रात प्रवेश करून आपला उसा उमटवित आहे.

शोध निबंधाचे उद्देश- प्रस्तुत शोध निबंधाचे उद्देश खालीलप्रमाणे आहेत.

- १) आंबेडकरी चळवळीतील महिलांचे अध्ययन करणे.
- २) आंबेडकरी चळवळीतील महिलांचे योगदान तपासणे.

उपकल्पना- १) आंबेडकरी चळवळीत स्त्रीयांचे योगदान आहे. वरील उद्देश व उपकल्पना घेऊन प्रस्तुत प्रोव्हिजन लिहिण्यात आला आहे. शोध निबंध लिहितांना विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीत प्रत्यक्षपणे सक्रीय सहभाग असल्याने स्त्रियांची निवड करण्यात आली. तसेच त्यांनी चळवळीत दिलेल्या योगदानाला अधोरेखित करण्यात आले.

२० जुलै १९४२ साली नागपूरत बाबासाहेबांच्या नेतृत्वात दलित महिला परिषद भरली होती. त्यानंतर २५ हजारहून अधिक महिलांनी हजेरी लावली होती. याच वर्षी दलित महिला फेडरेशनच्या कार्यकारणीमध्ये बऱ्याच महिला चळवळीत उतरल्या होत्या. त्यानंतर १९४६ चा पुणे करार सत्याग्रह, धर्मांतर व पुढे रिपब्लिकन पक्षाच्या भूमिहीनांचा सत्याग्रह, नामांतर यासारख्या आंदोलनातून महिला हिरीरीने पुढे आल्या. एकूणच आंबेडकरी चळवळीत महिलांचे काय योगदान राहिले आहे? याचे या ठिकाणी अध्ययन करण्यात आले आहे.

१. जाईबाई चौधरी : सवर्णांच्या शाळेत जिथे अस्पृश्य मुलांना बसण्याची सोय नव्हती तिथे मुलींची गोष्ट फार दुर्घट होती. त्यामुळे मुलींना शिकविण्याबाबत समाजात उदासिनता असणे स्वाभाविक आहे. मुलींनी शिकावं ही तळमळ जाईबाई चौधरीच्या मनात होती. यादृष्टीने जाईबाई चौधरी यांनी नागपूर येथे अस्पृश्य मुलींसाठी १९२४ साली शाळा सुरु केली. एका अस्पृश्य स्त्रीने अशा प्रकारची शाळा सुरु करावी ही एक अभूतपूर्व अशी घटना होती. १९४५ च्या मधील फेडरेशनच्या त्या प्रमुख कार्यकर्त्या होत्या. प्रतिकूल परिस्थितीत कसा विजय मिळवावा याचा आदर्श जाईबाईंनी सादर दिला.

२. अंजनीबाई देशभ्रतार : 'आंबेडकर प्रकाश संघ' पाचपावली, नागपूर विभागातर्फे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जून १० ते १४ एप्रिलपर्यंत साजरी करण्यात आली. त्यावेळी महिला परिषदेच्या अंजनीबाई देशभ्रतार ह्या होत्या. त्या प्रसंगी त्यांनी प्रबोधनपर भाषण केले. अंजनीबाई व कृष्णराव देशभ्रतार या दांपत्याने श्री संत चोखामेळा उर्फ अस्पृश्य मुलींचे वसतीगृह सुरु केले. अशा विविध क्षेत्रात त्यांनी प्रत्यक्ष काम करून बाबासाहेबांच्या चळवळीत सक्रीय सहभाग घेतला.

३. सुलोचनाबाई डोंगरे : सुलोचनाबाई डोंगरे यांनी नागपूर शहरातील गोकुळपेठ येथे नव्याने सुरु झालेल्या डिप्रेस क्लॉसिंग गर्ल्स होस्टेलमध्ये सुपीरटेंडचे काम केले. सासरे व पती दोघेही बाबासाहेबांच्या चळवळीत काम करित असल्यामुळे त्यांच्यासोबत राहून सुलोचनाबाईंना सामाजिक कार्याची आवड उत्पन्न झाली. दलित समाजाच्या सभा-संमेलनास त्या ह्या राहू लागल्या. वेळप्रसंगी भाषणेही देऊ लागल्या. भाषणात त्या आपले विचार अतिशय कणखरपणे स्पष्टरीत्या व्यक्त करित व श्रोत्यांवर त्याचा प्रभाव पडत असे. परोपकारी, स्वाभिमानी वृत्तीच्या सुलोचनाबाईंमध्ये बाबासाहेबांच्या चळवळीमध्ये राहून प्रखर आत्मविश्वास निर्माण झाला होता. ही बाव बाबासाहेबांच्या कानावर होती म्हणून १९४२ मध्ये 'अखिल भारतीय महिला परिषद' नागपूर या अधिवेशनाचे अध्यक्षपद त्यांना देण्यात आले. या अधिवेशनात २० जुलै ते २३ सप्त महिला वर्गासमोर त्यांनी उद्बोधक भाषण दिले. विशेष म्हणजे ह्या प्रसंगी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वतः ह्या होते. सन १९४४ साली कानपूरला महिला अधिवेशनासाठीही गेल्या होत्या.

४. राधाबाई कांबळे : राधाबाई कांबळेचे कर्तृत्व लक्षणीय होते. राधाबाई कांबळे ह्या अत्यंत बाणेदार, निडर वृत्तीच्या आणि धडाडीच्या कार्यकर्त्या होत्या. त्या स्वतः गिरणी कामगार होत्या. तेथील मजुरांच्या सभा, सत्याग्रह, संमेलने व इत्यादीत त्या नेहमीच आघाडीवर असत. त्यांनी बाबासाहेबांच्या झुंझार नेतृत्वाखाली मजूर संघटनेचे कार्य केले. दलित कामगारांवर हल्ले होत तेव्हा राधाबाई कांबळे या दलित स्त्री कामगारांचे नेतृत्व करू लागल्या. त्यांनी स्त्रीयांना तिखटपणे पुढ्या सोबत नेण्याचा आदेश दिला होता. हल्ला करणाऱ्यांवर ह्या स्त्रीया तिखटाचा वापर करित. त्यामुळे स्त्रीयांना ह्या लावण्यास कुणी धजत नसत. त्या चौथी शिकलेल्या असूनही त्यांचे भाषण मात्र अत्यंत स्फूर्तीदायक व बोधप्रद असे. सन १९४९ मध्ये गिरणी कामगारांची मोठ्या प्रमाणात कपात झाल्यामुळे हजारो गिरणी कामगारांचे संसार उध्वस्त होऊन ते म्हणून त्यांनी सुमारे १०० मजूर स्त्रीयांचा एक मोर्चा नागपूर मंत्रालयावर नेला. या मोर्चाचे नेतृत्व राधाबाईंनी केले. राधाबाईंनी सचिवालयावर धडक मोर्चा घेऊन जाताच लेबर सेक्रेटरी श्री. बेन्हाड यांनी स्त्रीयांच्या तक्रारी नीट ऐकून घेतल्या व सहानुभूतीपूर्वक गिरणी कामगारांचा विचार केला जाईल असे आश्वासन दिले. इतकेच नव्हे तर नोकर कपात ताबडतोब थांबविण्यात आली होती.

५. लक्ष्मीबाई नाईक : सन १९२९ ला लक्ष्मीबाईंनी अमरावती येथे अस्पृश्य महिला समाजाची स्थापना केली. सन १९३० ला शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनच्या स्थापनेच्या वेळी लक्ष्मीबाई बाबासाहेबांना भेटल्या तेव्हा बाबासाहेबांनी त्यांना विचारले 'तुम्ही शिकलेल्या आहात पुढे कोणते कार्य करणार?' लक्ष्मीबाईंनी ताबडतोब उत्तर दिले, 'आम्ही समाज सेवा करणार' असे म्हणून बाबासाहेबांना फार आनंद झाला होता. १४ ऑक्टोबर १९५६ ला त्यांनी बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली त्यानंतर त्यांच्या अंतःकरणात नवीन शक्ती, स्फूर्ती उत्पन्न झाली. लक्ष्मीबाई बाबासाहेबांनी दाखवून दिलेल्या आत्मउन्नतीच्या, बौद्ध धर्माच्या

प्रसार कार्याच्या मार्गाला लागल्या व शेवटी त्या भिक्षुणी बनल्या आणि गावोगावी बौद्ध धम्माचा प्रसार व प्रचार करित गेल्या.

६. **विरेन्द्राबाई तीर्थकर** : विरेन्द्राबाईंचे शिक्षण सातवीपर्यंत झाले होते त्यानंतर नार्मल स्कूलचे ट्रेनिंग घेऊन त्या शिक्षिका म्हणून नागपूर कॉर्पोरेशनच्या शाळेत नोकरी करू लागल्या. विरेन्द्राबाईंनी जन्मभर अविवाहीत राहून अशिक्षित महार वस्तीतील मुलांमुलींना एकत्र करून शिक्षणाचे बीज त्यांच्या मनात पेरणे सुरु केले. तसेच इतरही वस्त्यावस्त्यात जाऊन शिक्षण व स्वच्छता यांचे धडे देऊ लागल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीसाठी त्यांनी आपले पूर्ण आयुष्य वाहून घेतले होते. सामाजिक कार्यासाठी आपले संपूर्ण जीवन वाहून घेणारी व त्यासाठी आजन्म अविवाहीत राहणारी विरेन्द्राबाईंसारखी महिला मिळणे कठीणच.

७. **रतीबाई पुराणिक** : रतीबाई विशेष सुशिक्षित नव्हत्या तरी त्या वाचनप्रीय व बहुश्रुत होत्या. सार्वजनिक चळवळीत त्या मुलांमुलींना भाग घेत असत. वर्षा येथे पहिली बहिष्कृत भारत भगिनी परिषद त्यांच्याच परिश्रमाने भरली होती. बहिष्कृत भारत, ब्राम्हणेत्तर, विजयी मराठा वगैरे पत्रांचा त्यांनी बहिष्कृत वर्गात प्रसार केला होता. देशभक्त जमनालाल बजाज यांनी आपले लक्ष्मीनारायणाचे देऊळ अस्पृश्य वर्गासाठी खुले केले. याचे श्रेयही काही अंशी रतीबाईंना जाते. सन १९११ साली त्यांना वैधव्य आले तेव्हापासून त्यांनी आपले आयुष्य समाजसेवेत घालवले.

८. **कीर्तीबाई पाटील** : सन १९४२ मध्ये अस्पृश्य वर्गातील मॅट्रिक झालेल्या त्या पहिल्याच महिला होत्या. त्यामुळे १९४२ च्या नागपूरच्या महिला परिषदेच्या स्वागत समितीत कीर्तीबाई स्वागताध्यक्ष होत्या. सन १९४५ ला मुंबईला दलित फेडरेशनच्या परिषदेला त्या आवर्जून हजर होत्या. बाबासाहेबांच्या सभा जेव्हा-जेव्हा नागपूरला होत तेव्हा-तेव्हा त्या आवर्जून सभेला हजर राहत. नामांतराच्या लढ्यात त्यांचे सक्रीय योगदान राहिले आहे. कीर्तीबाईंनी 'पॉल कॅरस' या लेखकाच्या 'दी गाय्सेल ऑफ बुद्धा' या इंग्रजी पुस्तकाचे मराठीत भाषांतर केले आणि 'तथागताची सत्यगाथा' या नावाने ते प्रसिद्ध केले. त्याचप्रमाणे 'बौद्धांची जीवनचर्चा' व 'बौद्ध जिज्ञासा' नावांची आणखी दोन पुस्तके लिहिली व ती प्रकाशित झाली.

९. **इंदिराबाई पाटील** : इंदिराबाई पाटील यांचे घर म्हणजे समाजकार्य करणाऱ्या व्यक्तींचा, येणाऱ्या-जाणाऱ्या लोकांचा जणू अड्डाच बनलेला असे. सतत वर्दळ असायची. लहानपणापासूनच वडीलांचे बाबासाहेबांच्या चळवळीतील कार्य पाहून इंदिरांना जणू वारसा हक्काप्रमाणे समाजकार्याची ओढ लागली. पतीसुद्धा बाबासाहेबांच्या चळवळीतील कार्यकर्ते. अशारितीने सासर आणि माहेर बाबासाहेबांच्या चळवळीत गुंतलेले होते. म्हणूनच बाबासाहेबांच्या क्रांतीकारक चळवळीमध्ये त्याही सामिल झाल्या. २० जुलै १९४२ साली अखिल भारतीय अस्पृश्य महिला परिषदेचे पहिले अधिवेशन नागपूरला घेण्यात आले. त्या महिला परिषदेच्या जनरल सेक्रेटरी इंदिराबाई पाटील ह्या होत्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वतः त्या परिषदेला हजर होते.

१०. **नलीनीताई लढके** : नलीनीताई लढके यांचे पती आनंदराव लढके डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी चालविलेल्या दलितोद्धारका चळवळीचे सक्रीय कार्यकर्ते होते. रामराज्य परिषदेचे करपात्री महाराज महिला परिषदेमध्ये हिंदू कोडबील विरुद्ध प्रचारचे भाषण करणार होते. ते विरोधात काय बोलतात हे ऐकण्यासाठी नलीनीताई गेल्या होत्या. करपात्री महाराजांच्या भाषणातील मुद्दे हिंदू कोडबीलासंबंधी नव्हते. तसेच आम्हाला कायद्याची गरज नाही. अशा अर्थाचे भाषण त्यांनी महिलांसमोर केले. नलीनीताईंनी तिथे बोलण्याची परवानगी मागितली व हिंदू कोडबिलांमुळे स्त्रियांना मिळणारी सुरक्षितता व करपात्री महाराजांच्या निवेदनाचा फोलपणा भाषणात स्पष्ट केला. सन १९७७ च्या ५ सप्टेंबरला 'माध्यमिक मराठवीरल आदर्श शिक्षिका' म्हणून त्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार देण्यात आला. महाराष्ट्र शासनातर्फे सावित्रीबाई फुले ८६-८७ हा पुरस्कारही त्यांना मिळाला. नंतर त्या अनेक संस्थांवर सदस्य, अध्यक्ष तसेच सेक्रेटरी राहिल्या.

११. **दमयंती देशप्रतार** : दमयंतीबाईंचे आईवडील दोघेही बाबासाहेबांच्या चळवळीत होते. नेहमी सभा-मिटीगना जात, समाजकार्यात भाग घेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्याबद्दल घरात नेहमीच चर्चा असायची. पुढारी लोक जात-येत असत. अशा वातावरणात त्या वाढल्या. सन १९५३ साली सिद्धार्थ प्राथमिक संघात त्या सेक्रेटरी झाल्या. १९५६ साली धर्मांतर केल्यानंतर अखिल भारतीय शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन या संस्थेच्या सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय क्षेत्रात त्या काम करू लागल्या. रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना त्यावेळी झाली. ऑल इंडिया रिपब्लिकन पार्टी नागपूर विभागाच्या त्या संघटक होत्या. नाशिकच्या शांताबाई दानी, विदर्भातील दमयंतीबाई यांनी महिला मंडळाच्या माध्यमातून संबंध महाराष्ट्रभर धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि कामगार क्षेत्रात दौरा केला. मराठवाड्यात शिरसगाव येथे अस्पृश्य बायकांना नमन करून धोंड काढण्यात आली. त्यावेळी १५-२० हजार महिलांचा त्यांनी नागपूरला मोर्चा काढला आणि शासनाकडे गुन्हेगारांना कडक शासन व्हावे अशी मागणी केली. सन १९६४ ला दादासाहेब गायकवाडांच्या नेतृत्वाखाली भूमिहीनांचा "Perspective" A National Interdisciplinary Annual Research Journal -Vol.I Issue-VIII-2020 ISSN-2249-5134

- सत्याग्रह झाला त्यावेळी दयमंतीबाई सत्याग्रहात होत्या. त्यांना १५ दिवसांची जेल झाली. झोपडपट्टीचे मोर्चा चालवत यशस्वी करण्यासाठी दयमंतीबाईंनी अनेक महिलांसह संघर्ष केला. सन १९६७ साली रिपब्लिकन पक्षातर्फे एम. फार. म. साठी निवडणूक लढल्या. १९६९ ते १९७५ मध्ये महानगरपालिका नागपूरमध्ये काॅर्पोरेटर होत्या. १९८८ ला काॅर्पोरेटर आमदार म्हणून निवडून आल्या. ४ जून १९८५ ला मंत्री झाल्या. नागपूरच्या नामांतर मोर्चात त्या आघाडीवर होत्या.
- १२. पारबताबाई मेश्राम :** पारबताबाईना बाबासाहेबांचा मोठाच अभिमान वाटायचा. १० वर्षांच्या होत्या तेव्हा नागपूर बाबासाहेबांच्या कार्यासाठी फिरायच्या. राधाबाई कांबळे यांच्या सोबत कधी-कधी सभेला तर कधी मोर्चात जायच्या. बाबासाहेब निवडणूकीला उभे राहिले तेव्हा वस्त्या-वस्त्यात, गावा-गावात प्रचारासाठी फिरल्या. त्या प्रचारासाठी मंडारा, भंडारा, कामठी, इंदोरा येथे जाऊ लागल्या. १४ ऑक्टोबर १९५६ ला बुद्ध धम्माचा स्विकार केला. जुने देव-देवना काढून टाकले आणि बुद्ध धम्माच्या प्रसार प्रचारासाठी आयुष्य वाहून घेतले.
- १३. चंद्रिका रामटेके :** चंद्रिका रामटेके आई वडीलांच्या लाडात वाढलेल्या एकुलत्या एक. बाबासाहेबांच्या चळवळी त्यांनी स्वतःला सामील केले. एका निवडणूकीत रिपब्लिकन पक्षाला मतदान होऊ नये म्हणून मतदान करू देऊ नये जिकडे-तिकडे असंतोष पसरला होता. जाळपोळ सुरु झाली. त्याही मातीच्या तेलाची शिशी आणि माचिस घेऊन फिर होत्या. आग लावून द्यायच्या, घर पेटलं म्हणून पळापळ व्हायची आणि तेवढ्या वेळात मतदान करायच्या. पोलिसांना अटकाव केला तेव्हा 'खबरदार महिलांना मारल तर' असे त्यांना म्हटले होते. १९५६ नंतर चंद्रिकाबाईंनी खेड्यात जाऊन बौद्ध धम्माचा प्रसार केला. भूमिहीनांच्या सत्याग्रहाच्या वेळी १०० वर महिला तुरुंगात गेल्या होत्या. बापांना एकत्र करायचं काम चंद्रिकाबाईंच होतं. बौद्धांना सवलती मिळाल्या पाहिजेत या मागणीसाठी त्या दिल्लीला कुंभार, दादासाहेब गायकवाडांसोबत गेल्या होत्या.
- १४. शुद्धमती बोंघाटे :** शुद्धमतीबाईंनी बाबासाहेबांच्या चळवळीत काम केले. त्या नेहमीच अग्रेसर राहिल्या. नामांतर लढा असो, बौद्धांच्या सवलतीसाठी असो किंवा दलितांच्या अन्याय अत्याचारांचा निषेध करणारा असो, शुद्धमती बोंघे असायच्या. त्या बाबासाहेबांच्या चळवळीत लहानपणापासूनच भाग घ्यायच्या. दलित चळवळीची पाळेमुळे तेव्हापासून त्यांच्या रुजली होती. सन १९४२ च्या अखिल भारतीय महिला परिषदेला त्या हजर होत्या. या अधिवेशनात ठिकठिकाणी बाबांच्या आदेशावरून वस्त्या-वस्त्यात समता सैनिक दल स्थापन केले. बाबासाहेब ज्या वेळी नागपूर यायचे त्यावेळी शुद्धमती उत्साहाने प्रत्येक कार्यात भाग घ्यायच्या. सन १९५६ ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व लाले अनुयायांसोबतच शुद्धमतीने आपल्या आईवडीलांसोबत बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. सन १९८० सालापासून समता सैनिक दलाच्या महिला नागपूर विभागाचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषविले.
- १५. सोनूताई लांजेवार :** सोनूताईंचे वडील नेहमीच बाबासाहेबांचे नाव घ्यायचे, सभा-भाषणांना जायचे, चर्चा चालवत वडील बाबासाहेबांचे कट्टर अनुयायी होते. सन १९५६ साली कुटुंबियांसोबत दीक्षा घेतली. सोनूताईंनी बाबासाहेबांना १९५६ साली पाहिले. त्यावेळी बाबासाहेबांचे भाषणही ऐकलं होतं. १९५६ साली १४ ऑक्टोबरला धर्मातराच्या वेळेसच उपस्थित होत्या. त्यानंतर त्या भारतीय बौद्ध महासभा, नागपूर या संस्थेच्या विदर्भ विभागाच्या अध्यक्षा झाल्या. १९५६ ला त्या भारतीय बौद्ध महासभेच्या अध्यक्षा झाल्या.
- १६. सुधाताई रामटेके :** सुधाताई लहानपणीच समता सैनिक दलाच्या तुकडीत सामिल झाल्या होत्या. सत्याग्रह, मोर्चा आदी आंदोलनात तर आघाडीवरच होत्या. लढाऊवृत्ती लहानपणापासूनच होती. सन १९४२ साली संपूर्ण देशात ब्रिटीशांच्या विरोधात भारत छोडो आंदोलनाची नांदी सुरु होती. त्यावेळी बाबासाहेबांनी 'डिप्रेसड क्लासेस' नावाची संस्था स्थापन केली होती. त्यावेळी आंदोलनातील विचार विनिमयात सुधाताईंनी भाग घेतला होता. या संस्थेचे पहिले अध्यक्ष १९४२ मध्ये जुलै महिन्यात नागपूरला झाले. या अधिवेशनात महिलांचेही अधिवेशन भरविण्यात आले तेव्हा बाबासाहेबांच्या हस्ते महिला मंडळाची स्थापना करण्यात आली. त्यामध्ये सुधाताई सहसचिव होत्या. १९५६ ला धम्माचे समारंभ नागपूरला झाला त्यावेळी अनेक स्त्रीयांनी लोकांना खाद्य पुरविले त्यात सुधाताई सुद्धा होत्या. नामांतर मोर्चात आठवण सांगतांना त्या म्हणाल्या होत्या, 'नोकरी करणाऱ्या स्त्रीयांना समाजकार्यासाठी फार वेळ देता येत नाही तो सामाजिक बांधिलकीची जाणीव त्यांनी ठेवावी'.
- १७. सुगंधाताई शेंडे :** सुगंधाताई शेंडे या दलित समाजातील पहिल्या पीढीतील आघाडीच्या समाजसेविका. महाराष्ट्रात अग्रगण्य लेखिका, प्रसिद्ध शिक्षणतज्ञ, आदर्शवादी विचारवंत व तत्वज्ञ म्हणून ओळखल्या जातात. महाराष्ट्रातील परतण्या स्त्रीयांमधील पहिल्या मॅट्रिक उत्तीर्ण, पहिल्या पदवीधर, पहिल्या साहित्यिक, पहिल्या राजपत्रीत स्त्री अधिकारी होण्या मान सुगंधाताईंना जातो. शासनाने सावित्रीबाई पुरस्कार व दलित मित्र राज्य पुरस्कारने त्यांचा सन्मान केला आहे. पहिले बौद्ध साहित्य संमेलन नागपूर येथे आयोजित करण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. भंडारा येथील बौद्ध साहित्य संमेलनात "Perspective" A National Interdisciplinary Annual Research Journal -Vol.I Issue-VIII-2020 ISSN-2249-5134

COVID-19 Pandemic Special

ISSN - 2249-5134

Perspectives

A National Interdisciplinary Annual Research Journal

Peer Reviewed
Research Journal for
Interdisciplinary
Studies of Arts
Commerce &
Social Sciences

**Vol. I
Special Issue (IX)
July 2020**



Dr. Madhukarrao Wasnik
PWS Arts and Commerce College
Kamptee Road, Nagpur - 26.
(Reaccredited 'B' by NAAC)



Scanned with OKEN Scanner

17	सर्वांगीण विकासासाठी कोरोनानंतरची आव्हाने	प्रा. डॉ. वर्षा गंगणे	91-96
18	कोरोना महामारी आणि केंद्र सरकारचे आर्थिक पॅकेज	प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे	97-105
19	कोविड-१९ : आत्मनिर्भर भारत अभियान	डॉ. जितेन्द्र सावजी तागडे	106-110
20	भारतीय अर्थव्यवस्थेची मंदीसदृश्य स्थिती: एक दृष्टीक्षेप	डॉ. प्रशांत म. पुराणिक	111-119
21	कोरोनोत्तर काळातील व्यवस्था परिवर्तनाद्वारे शाश्वत विकास साधणारे महात्मा गांधी यांचे प्रारूप	प्रा. केदार रविंद्र केंद्रेकर,	120-124
22	कोरोना विषाणू व्हायरसचे सामाजिक जिजनाच्या विविध घटकांवर होणारे परिणाम आणि उपाय	डॉ. अश्रू जाधव	125-128
23	विश्वव्यापी कोरोना व्हायरस नंतरची आव्हाने	डॉ. निशा अशोक कळंबे	129-134
24	कोरोनाच्या काळात प्रसारमाध्यमांचा समाज मनावरील अनिष्ट परिणाम	डॉ. अमित पांडे	135-139
25	लॉक डाऊन नंतर उच्च शिक्षणातील बदल आणि आव्हाने	डॉ. जे.एस. हटवार	140-143
26	कोविड-१९ मुळे देशाचा अर्थव्यवस्थेत मोलाची भर टाकणाऱ्या शेतकऱ्यांची अवस्था	डॉ.बी.व्ही.श्रीगीरीवार	144-146
27	कोरोना महामारीमुळे स्थलांतरीत मजुर व शेती क्षेत्रावर झालेले परिणाम	प्रा. अलका वाल्मीक पाटील प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे	147-151
28	कोरोना साथीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम	कु. माधुरी रा. बोठरे	152-154
29	कोरोना महामारी के प्रभाव	डॉ. रजनी हारोडे	155-158
30	कोविड-१९ सर्वेक्षण- भारतीय जनसमुदाय पर जागरूकता मूल्यांकन एक अध्ययन	डॉ. जयंत कुमार वी. रामटेके	159-164
31	कोरोनाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम	डॉ.सिध्दार्थ हरिदास मेश्राम	166-172

कोरोना महामारीमुळे स्थलांतरीत मजुर व शेती क्षेत्रावर झालेले परिणाम

प्रा. अलका वाल्मीक पाटील

प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे

सारांश :

आज संपूर्ण जगावर महाभयंकर संकट आले आहे व त्या संकटाचे नाव कोविड-१९ अर्थात कोरोना व्हायरस असे आहे. कोरोना विषाणुमुळे जागतिक महासत्ता असलेले सर्व देश भयाण अशा महामारीला सामोरे जात आहेत. भारताने या संकटातुन सावण्यासाठी लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला आहे. लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर मोठ्यामोठ्या शहरातील सर्व उद्योग धंदे बंद पडले व मजुरांचा उदरनिर्वाहाचा भरण्याचा प्रश्न निर्माण झाला. काम बंद असल्यामुळे मजुरांनी आपल्या गावी जाण्यास सुरुवात केली. बस व ट्रेन किंवा वाहतुकीचे इतर साधने बंद असल्यामुळे अनेक मजुर पायी हजारो मैल दुसऱ्या राज्यात जाण्यास तयार झाले. पायी जात असतांना अनेक मजुरांचे व लहान मुलाचे हाल झाले जसे, पायी चालल्यामुळे त्यांच्या पायाला जखमा झाल्या, त्यांना वेळेवर जेवन मिळाले नाही किंवा पिण्यासाठी पाणी मिळाले नाही याचा परिणाम असा झाला की अनेक मजुर हे कोरोना महामारीपेक्षा या त्रासांनीच मरण पावले. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील हे फार मोठे आणि दीर्घकाळ सुरु असलेले स्थलांतर आहे. या पूर्वी असे स्थलांतर हे फाळणीच्या वेळी झाले होते. मात्र या स्थलांतराचा कालावधी फाळणीच्या स्थलांतरापेक्षा निश्चितच मोठा आहे.

भारतामध्ये बहुसंख्य लोकांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन शेती आहे.परंतु आज भारतीय शेती व शेतकरी मोठ्या संकटामध्ये अडकला आहे याचे कारण म्हणजे कोरोना या महाभयंकर रोगामुळे भारत बंद असल्यामुळे शेतमालाला जास्त किंमत मिळत नाही. अनेक शेतकऱ्यांचा शेतमाल शेतातच खराब झाला किंवा अत्यंत कमी किंमतीला विकला गेला. या सर्व परिस्थितीतुन बाहेर निघण्यासाठी शासनाने योग्य पाऊल उचलले गरजेचे आहे.

बीजशब्द : अर्थव्यवस्था, स्थलांतर, शेती, उपासमार, बेरोजगारी, लॉकडाऊन.

प्रस्तावना:

संपूर्ण जग जेव्हा २०२० या नवीन वर्षामध्ये प्रवेश करित होते त्यावेळी चीनमधील वुहान या शहरामध्ये हुआनान सीफुड मार्केटमध्ये छोट्या मोठ्या दुकानदाराचे मासं व मासेतसेच इतर प्राण्यांचे मास विक्रीचे दुकाने आहेत. कोरोनाची सुरुवात डिसेंबर २०१९ च्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये चीनच्या आरोग्य विभागाच्या डॉक्टर व नर्सने कोरोना विषाणू परसण्याची पूर्वसूचना दिली. चीनच्या डॉक्टरांना सर्वात जास्त मरीज हुआनान सीफुड मार्केटमध्ये आढळून आले आणि त्यानंतर या महामारीचा फैलाव संपूर्ण वुहान शहरामध्ये झाला. जानेवारी २०२० मध्ये डब्ल्यू. एच. ओ. ला चीन सरकारने या महामारीविषयी माहिती दिली. त्यानंतर ११ जानेवारी २०२० ला कोरोना महामारीमुळे पहिला रुग्ण मरण पावला त्यानंतर या विषाणूचा फैलाव जापान, दक्षिण कोरीया आणि थायलंड या देशामध्ये झाला. त्यानंतर ३० जानेवारी २०२० ला भारतातील केरळ या राज्यामध्ये कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळला पण भारत सरकारला या महामारीविषयी जास्त माहिती नव्हती आणि डब्ल्यू. एच. ओ. ने ही महामारी जागतिक महामारी म्हणून घोषित केली नव्हती. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यामध्ये डब्ल्यू. एच. ओ. ने या विषाणूला जागतिक महामारी म्हणून घोषित केले. तेव्हा पर्यंत विविध देशासोबतच भारतामध्ये सुद्धारुग्ण संख्या वाढत गेली. नंतर या

विषाणूच्या नियंत्रणासाठी अनेक देशांनी विविध उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली. त्यामध्ये कमी अधिक प्रमाणात काही देशांना यश आले परंतु जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशांमध्ये हा विषाणू प्रचंड प्रमाणात वाढत गेला. भारत देश हा जास्त लोकसंख्येचा देश असून भारतामध्ये या विषाणूचा प्रभाव वाढत गेला त्यामुळे भारत सरकारने या विषाणूच्या नियंत्रणासाठी मार्च महिन्यामध्ये लॉकडाऊन केले व या लॉकडाऊनमुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या.

संशोधनाचे उद्देश :

१. कोरोना विषाणूमुळे स्थलांतरीत मजुरावर झालेल्या परिणामांचा अभ्यास करणे.
२. कोरोना विषाणूमुळे शेती क्षेत्रावर झालेल्या आर्थिक परिणामांचा अभ्यास करणे.

संशोधन पद्धती :

प्रस्तुत संशोधन हे प्रामुख्याने प्राथमिक व दुय्यम सामग्रीवर आधारित असून या संशोधनासाठी वर्तमानपत्रे, टि. व्ही. चॅनल, व मासिके इत्यादी साधनांचा आधार घेण्यात आलेला आहे.

स्थलांतरीत मजुरावर झालेला परिणाम :

भारत सरकारने २४ मार्च २०२० रोजी लॉकडाऊन जाहीर केले तेव्हा अनेक समस्या निर्माण झाल्या त्यामधील सर्वात मोठी समस्या ही मजुरांची समस्या होय, एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात उदरनिर्वाह करण्यासाठी गेलेल्या मजुर वर्गाची होय. लॉकडाऊनमुळे सर्व व्यवसाय बंद झाले व त्या मजुरांना कामावरून कमी करण्यात आले. हातावरचे पोट असल्यामुळे मजुर इतर राज्यात जाऊन किरायाने राहून काम करित असल्यामुळे त्यांना किराया देण्यास किंवा आर्थिक बाबतीत अडचण निर्माण होऊ लागली. म्हणून मजुर स्वतःच्या घरी परत येण्यास सुरुवात झाली आणि लॉकडाऊनचा कालावधी हळूहळू वाढत गेला तशी तशी त्यांची आर्थिक समस्या वाढत गेली त्यामुळे ते स्वतःच्या गावी परतू लागले. परंतु लॉकडाऊनमुळे संपूर्ण भारतातील शासकीय वाहतुक व्यवस्था उदा. रेल्वे, बस बंद असल्यामुळे परत येण्यास व स्वतःच्या राज्यात परत जाण्यास अडचणी निर्माण झाल्या. अशा परिस्थितीत मजुर वर्ग उपासपोटी व पैसे नसल्यामुळे पायदळी आपल्या गावी जाण्यास मजबूर झाला. या दरम्यान हजारो मजुरांचा कोरोना महामारीपेक्षा इतर संकटांनी जीव गेला. जसे, उपाशी, जास्त पायदळी चालणे, पिण्याच्या पाण्याअभावी, तर काही पायदळी जात असतांना रेल्वेखाली चिरडून मरण पावले. अशा प्रकारे स्थलांतरीत मजुरांचा विचार न करता शारसाने जाहीर केलेली देशबंदी ही मजुरांसाठी खूपच त्रासदायक ठरली. आज जुलै २०२० सुरु असून सुद्धा देशामध्ये सुरु असलेली देशबंदी सर्व आर्थिक व्यवहार ठप्प करून आहे व सर्व मजुरांना या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.

महाराष्ट्र राज्याची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहरात सर्वात जास्त कोरोना रुग्ण असल्यामुळे या शहरात स्थलांतरीत मजुरांचे प्रमाण जास्त होते. यामध्ये १२ लाख मजुर एकट्या मुंबई शहरातून होते, इतर राज्यात स्थलांतरीत करतांना त्यांच्या स्वतःच्या राज्यामध्ये प्रवेश करतांना कमी रुग्ण संख्या असलेल्या राज्यांनी मजुरांना प्रवेश करण्यास अटकाव केला. यामुळे ते मजुर स्वतःच्या राज्यातही जावू शकले नाही व शासनाने स्थलांतरीत मजुरांसाठी योग्य व्यवस्था व उपाययोजना केल्या नाहीत.

तक्ता

कोरोना महामारीमुळे भारतातील स्थलांतरीत मजुरांचे प्रमाण

अ. क्र.	शहरी एकत्रीकरण	स्थलांतरीत लोकसंख्येची एकूण टक्केवारी	आंतरराज्यीय एकूण स्थलांतरण	कोरोनाची संख्या
१	दिल्ली	४३.१	८७.८	८९८
२	मुंबई	५४.९	४६.०	८८०
३	कोलकत्ता	४०.८	१८.२	२९
४	चेन्नई	५१.०	११.८	१४९
५	बंगलोर	५२.३	३५.१	७१
६	हैद्राबाद	६४.३	०७.१	२३६
७	अहमदाबाद	४८.७	२४.१	१३४
८	पुणे	६४.८	२२.३	१९०
	शहरी भारत	४७.०	२१.६	Share of Covid 19 cases in these metro cities to total cases is 38 %

Source: <https://www.mohfw.gov.in/pdf/DistrictWiseList354.pdf> accessed on 13th April, 2020).

शेती क्षेत्रावर झालेले आर्थिक परिणाम

भारत हा जगातील एक सर्वात मोठी व जुनी कृषीवर आधारित अर्थव्यवस्था असलेला देश असून, 'कृषी' हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहे. तसेच भारत हा कृषीप्रधान ग्रामीण व्यवस्थेचा विकसनशील देश आहे. शेती हा भारतीय लोकांचा मुख्य व्यवसायच नसून, ती भारतीय लोकांची जीवन पद्धती आहे. बहुसंख्य लोकांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन शेती आहे. कोरोना विषाणूमुळे शेतीच्या मालाच्या किंमतीवर मोठा परिणाम झाला. हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे की, कोरोना विषाणूची महामारी आल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था अन्नधान्याच्या किंमतीत लक्षणीय वाढ अनुभवत होती. आकडेवारीनुसार असे दिसून येते की, अन्नधान्य महागाईची सुरुवात झाली पण शेतकऱ्यांच्या शेतातील माल वाहतुक व्यवस्था बंद असल्यामुळे बाजारापर्यंत पोहचवण्यात शेतकऱ्यांना अडचण निर्माण झाली. त्यामुळे भाजीपाला, फळे व अन्नधान्याच्या साठवणूकीची व्यवस्था नसल्याने माल शेतामध्येच खराब होवून शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. त्याचा परिणाम म्हणून लोकांना लागणाऱ्या अत्यावश्यक वस्तूंच्या किंमतीमध्ये प्रचंड वाढझाली याचा फायदा शेतकऱ्यांना न होता निवडक व्यापारी वर्गाला झाला.

तक्ता

लॉकडाऊनपूर्व व लॉकडाऊन नंतर किरकोळ आणि ठोक शेतमालाच्या किंमतीत बदल

शहर	किंमत	गहु	गव्हाचे पीठ	हरभरा दाळ	तुर दाळ	भुईमुंग तेल	बटाटा	कांदा
चेन्नई	ठोक	५.०	०.०	१०.८	१५.१	—	२९.६	- ०.२
चेन्नई	किरकोळ	६.१	०.०	१०.३	८.८	४.८	३०.०	१०.०
दिल्ली	ठोक	०.०	२.९	०.७	८.६	०.०	१०.४	-२७.०
दिल्ली	किरकोळ	०.०	६.५	१३.२	२.४	५.६	१४.१	- ०.४

कोलकत्ता	ठोक	—	५.७	११.०	२.१	०.७	३६.९	०.०
कोलकत्ता	किरकोळ	—	९.६	९.२	२.३	०.८	३०.८	०.०
मुंबई	ठोक	-४.०	०.०	१६.७	१३.७	१.७	१०.५	-१३.४
मुंबई	किरकोळ	०.०	-२.४	१८.३	१२.९	४.३	२०.३	१३.२

Source- change in Post-Lockdown Week 3 (5-11 April, 2020) over Pre-Lockdown Week (15-21 March, 2020). Wholesale: Wholesale price.

भारतामध्ये साधारणतः जुन महिन्यामध्ये पहिला पाऊस पडल्यानंतर खरीप हंगामध्ये पेरणीला सुरुवात होते. शेतकऱ्यांचा शेतमाल कोरोना महामारीमुळे विक्री झाला नाही तर काही शेतकऱ्यांनी अत्यंत कमी किंमतीला आपला शेतमाल विक्री केला त्यामुळे आर्थिक संकट उभे राहिले. या वर्षी कोरोना महामारीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्यामुळे पेरणीसाठी लागणारे बी-बियाणे, खते व इतर सामग्रीसाठी घेण्यासाठी शेतकऱ्याला व्याजाने पैसे घ्यावे लागले. शासनाने जाहीर केलेल्या विविध योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचल्या नाहीत त्यामुळे झाले असे की शेतकऱ्यांना सावकारापासून किंवा खाजगी संस्थाकडून जास्त व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागेल यामुळे येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांपूढे आर्थिक संकट येणार आहे.

निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोधनिबंधाच्या अभ्यासावरून काही निष्कर्ष काढले असून ते पुढीलप्रमाणे,

- १) भारतामध्ये लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर सर्व व्यवहार ठप्प झाल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाले, होत आहेत.
- २) कोरोना महामारीचे संक्रमण वाढत असल्यामुळे अनेक उद्योग धंदे बंद पडले व यामुळे अनेक मजुर बेरोजगार झाले.
- ३) लॉकडाऊनमुळे मजुरांच्या हातातील काम गेले व मजुरांनी गावी जाण्यास सुरुवात केली असतांनी अनेक मजुरांचे हाल झाले व काही मजुर मरण पावले. यामध्ये कोरोना महामारीमुळे मरण पावलेल्या मजुरांपेक्षा इतर कारणाने मजुर मरण पावल्याचे जास्त प्रमाण आहे.
- ४) लॉकडाऊनमुळे शेतमालाच्या किंमतीमध्ये प्रचंड वाढझाली परंतु याचा फायदा शेतकरी वर्गाला झाला नाही यामुळे त्यांचे नुकसान झाले.
- ५) कोरोना महामारीमुळे शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे नसल्यामुळे त्यांना भविष्यात आर्थिक अडचणी निर्माण होतील.

समारोप :

प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये स्थलांतरीत मजुर व शेती क्षेत्रावर कोरोना महामारीमुळे काय परिणाम झाले याचा अभ्यास करण्यात आला आहे. संपूर्ण जगामध्ये कहर घालणाऱ्या कोरोना आजाराने भारतात प्रवेश केल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थाच बदलून गेली. भारतात लॉकडाऊन घोषित केल्यानंतर अनेक उद्योग धंदे बंद पडले यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले. अनेक मजुर इतर राज्यात काम करण्यासाठी गेले त्यांना परत यावे लागले. प्रवासादरम्यान मजुरांचे जे हाल झाले ते खुपच भयंकर स्वरूपाचे आहेत, अनेक मजुरांचे अन्न व पिण्या अभावी निधन झाले. लॉकडाऊनचा प्रभाव इतर क्षेत्रांप्रमाणेच शेती क्षेत्रावर सुद्धा झाला. शेतकऱ्यांचा शेतमाल विकला न गेल्याने किंवा कमी दराने विकला गेल्याने त्यांच्या हातात पैसा उरला नाही. याचा

परिणाम असा झाला की, जुन महिन्यामध्ये पाऊस पडल्यानंतर पेरणी करण्यासाठी त्यांना पैश्यासाठी सावकरावर अवलंबून राहावे लागले. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या सर्व संकटाचा आढावा घेऊन सरकारने ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी योग्य कृतीची आवश्यकता आहे.

संदर्भ सूची

- १) पाटील यशोधन (संपा.) मासिक, 'मुक्त शब्द', एप्रिल २०२०, मुंबई.
- २) इंडिया टुडे, अप्रैल, २०२०
- ३) लोकसत्ता -१९/४/२०२०
- ४) लोकसत्ता -२४/४/२०२०
- ५) लोकसत्ता -२७/४/२०२०
- ६) <https://www.mohfw.gov.in/pdf/DistrictWiseList354.pdf> accessed on 13th April, 2020).
- ७) ICAR-National Institute of Agricultural Economics and Policy Research, Covid- 19 Lockdown and Indian Agriculture : Options to reduce the impact, April 2020, New Delhi.

प्रा. अलका वाल्मीक पाटील
विभागप्रमुख, अर्थशास्त्र
एस. एस. गर्ल्स कॉलेज, गोंदिया
मो. ९७६६७२५५९५
Email- alkapatil3106@gmail.com

प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे
विभागप्रमुख, अर्थशास्त्र
डॉ. मधुकरराव वासनिक पी.डब्ल्यू.एस.कला ववाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर.
मो. ९६६५०१८४३२
Email-pradnya.mahendra@gmail.com

COVID-19 Pandemic Special

ISSN - 2249-5134

Perspectives

A National Interdisciplinary Annual Research Journal

Peer Reviewed
Research Journal for
Interdisciplinary
Studies of Arts
Commerce &
Social Sciences

**Vol. I
Special Issue (IX)
July 2020**



Dr. Madhukarrao Wasnik
PWS Arts and Commerce College
Kamptee Road, Nagpur - 26.
(Reaccredited 'B' by NAAC)



17	सर्वांगीण विकासासाठी कोरोनानंतरची आव्हाने	प्रा. डॉ. वर्षा गंगणे	91-96
18	कोरोना महामारी आणि केंद्र सरकारचे आर्थिक पॅकेज	प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे	97-105
19	कोविड-१९ : आत्मनिर्भर भारत अभियान	डॉ. जितेन्द्र सावजी तागडे	106-110
20	भारतीय अर्थव्यवस्थेची मंदीसदृश्य स्थिती: एक दृष्टीक्षेप	डॉ. प्रशांत म. पुराणिक	111-119
21	कोरोनोत्तर काळातील व्यवस्था परिवर्तनाद्वारे शाश्वत विकास साधणारे महात्मा गांधी यांचे प्रारूप	प्रा. केदार रविंद्र केंद्रेकर,	120-124
22	कोरोना विषाणू व्हायरसचे सामाजिक जिवनाच्या विविध घटकांवर होणारे परिणाम आणि उपाय	डॉ. अश्रू जाधव	125-128
23	विश्वव्यापी कोरोना व्हायरस नंतरची आव्हाने	डॉ. निशा अशोक कळंबे	129-134
24	कोरोनाच्या काळात प्रसारमाध्यमांचा समाज मनावरील अनिष्ट परिणाम	डॉ. अमित पांडे	135-139
25	लॉक डाऊन नंतर उच्च शिक्षणातील बदल आणि आव्हाने	डॉ. जे.एस. हटवार	140-143
26	कोविड-१९ मुळे देशाचा अर्थव्यवस्थेत मोलाची भर टाकणाऱ्या शेतकऱ्यांची अवस्था	डॉ.बी.व्ही.श्रीगीरीवार	144-146
27	कोरोना महामारीमुळे स्थलांतरीत मजुर व शेती क्षेत्रावर झालेले परिणाम	प्रा. अलका वाल्मीक पाटील प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे	147-151
28	कोरोना साथीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम	कु. माधुरी रा. बोठरे	152-154
29	कोरोना महामारी के प्रभाव	डॉ. रजनी हारोडे	155-158
30	कोविड-१९ सर्वेक्षण- भारतीय जनसमुदाय पर जागरूकता मूल्यांकन एक अध्ययन	डॉ. जयंत कुमार वी. रामटेके	159-164
31	कोरोनाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम	डॉ.सिध्दार्थ हरिदास मेश्राम	166-172

कोरोना महामारी आणि केंद्र सरकारचे आर्थिक पॅकेज

प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे

सारांश :

चीनमध्ये निर्माण झालेल्या या विषाणूने संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थांवर खूप मोठ्या प्रमाणात परिणाम केला आहे. आज विविध देशांना त्यांच्या अर्थव्यवस्थांना उभारी देण्यासाठी विविध माध्यमांतून, विविध क्षेत्रांसाठी विविध प्रयत्न करावे लागत आहेत. कोरोनापासून होणारी जीवितहाणी टाळण्यासाठी लॉकडाऊन करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. परिणामतः संपूर्ण आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले वस्तूचे उत्पादन, मागणी व पुरवठा विस्कळीत झाले. या महामारीचा सामना करण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने वेळोवेळी आर्थिक पॅकेज जाहीर केलीत. ती एकूण २० लाख ९७ हजार कोटी रुपयांची आहेत. या पॅकेजमुळे भारताला नेमका कसा व किती फायदा होणार हे येणारा काळ ठरवेल. आज मात्र शेतकरी, उद्योजक व ज्यांनी नोकरी व व्यवसाय गमवीला ते सर्वच भयभीत व त्रस्त आहेत. त्यामुळे ह्या पॅकेजकडे केवळ एक सुरुवात या दृष्टीकोनातून बघावे लागेल. एकंदरच कोरोनाचे संकट फार मोठे आहे परंतु त्याहीपेक्षा मोठी देशापुढील आर्थिक आव्हाने आहेत. त्यासाठी सरकार एकटे पुरेसे पडणार नाही तर सामाजिक प्रतिसादही आवश्यक आहे. कोरोना महामारीला संधीच्या दृष्टीकोनातूनही पाहावे लागेल कारण भारतात उपलब्ध असलेली मोठी बाजारपेठ, स्वस्त मनुष्यबळ, तरुणांची मोठी संख्या ह्या बाबी सकारात्मक आहेत. शेवटी, सर्वांच्या मुलभूत गरजा भागविणारी विकेंद्रीत, स्वदेशी श्रमजीवींचा सन्मान करणारी अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्था व संस्कृती निर्माण करणे ही सर्वांची आर्त हाक असेल.

बीजशब्द : अर्थव्यवस्था, लॉकडाऊन, पॅकेज, स्थलांतरीत मजूर, अंदाजपत्रक, आरोग्य, आव्हाने, प्रस्तावित खर्च.

प्रस्तावना :

एका लहानशा विषाणूने अवघे जग उद्ध्वस्त केले आहे. कोरोनामुळे ओढवलेल्या ह्या अभूतपूर्व संकटाची कोणी कल्पनाही केली नव्हती. सध्या जगभरात सर्वच देशांमध्ये जो संघर्ष करावा लागत आहे तो म्हणजे पहिला जीव वाचविण्याचा व दुसरा उपजीविकेचा. ह्या दोन्ही आव्हानांना आपल्याला एकाच वेळी सामोरे जावयाचे आहे. आपण जर लॉकडाऊन वाढवत गेलो तर हे खरे आहे की, अधिकाधिक लोकांचे प्राण वाचतील. परंतु त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक महामंदी येऊ शकते परिणामतः उपासमारीने लोक मरू शकतात. या ऊलट अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी जर लॉकडाऊन काढले तर कोरोनाची साथ मोठ्या प्रमाणात पसरेल व मोठ्या प्रमाणात जीवित हानी होवू शकते. त्यामुळे ह्या दोन्ही टोकांचा मध्य गाठणे हे खरे आव्हान आपल्या व सर्वच देशांसमोर आहे

चीनमधून सुरुवात झाली असली तरी या विषाणूने संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम केला आहे. संपूर्ण जग कोरोनाचा सामना करण्यात गुंतले असतांना काही काळ सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्था वाऱ्यावर सोडल्यासारख्या झाल्या होत्या. आज विविध देशांना त्यांच्या अर्थव्यवस्थांना तसेच जागतिक अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्याशिवाय पर्याय नाही त्यासाठी जगभरातल्या मध्यवर्ती बँका पुढे आल्या आहेत. त्यामध्ये भारताच्या रिझर्व्ह बँकेचाही समावेश आहे. निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर आपण लक्ष ठेवून असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले होते. बाजारात रोख तरलता निर्माण करण्यासाठी आवश्यक पावले

उचलली जाणार असल्याचेही नमूद केले होते, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी मुंबई, दिल्ली, पुणे, ठाणे, नोएडा, गुरुग्राम, अहमदाबाद ह्या सारखी शहरे कोरोनामुळे जर्जर आहेत. अशा स्थितीत उद्योग आणि शेतीचे गाडे पूर्वपदावर आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना कुठलाही धोका न पत्करता, जोखिमात कोणताही पैलू दुर्लक्षित न ठेवता सर्वांचा विचार करावा लागेल. या सर्व दृष्टीकोनातून केंद्र सरकारने २० मार्च २०२० पासून आपले विविध आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहेत. त्या आर्थिक पॅकेजचा विश्लेषणात्मक अभ्यास ह्या शोध निबंधात केला आहे.

संशोधनाचे उद्देश :

१. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करणे.
 २. भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर असलेल्या आव्हानांचे अध्ययन करणे.
 ३. अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी जाहीर केलेल्या केंद्र सरकारच्या विविध पॅकेजचे अध्ययन करणे.
- उपकल्पना — कोरोना महामारीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारचे आर्थिक पॅकेज पुरेसे नाही.

कुठल्याही आरिष्टाचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम हा त्या-त्या आरिष्टाच्या तीव्रतेवर अवलंबून असतो. तसेच ते जेव्हा येते तेव्हाची देशाची आर्थिक स्थिती काय होती यावर देखील तो परिणाम अवलंबून असतो. त्यामुळे कोरोनाचं आरिष्ट ज्यावेळी आपल्या देशावर आले त्यावेळी आपल्या अर्थव्यवस्थेची काय स्थिती होती हे लक्षात घेण्यात आली. त्यात प्रामुख्याने खालील बाबी लक्षात आल्या-

१. कोरोना आरिष्ट येण्यापूर्वीच आर्थिक विकासाचा दर मंदावत चालला होता.
२. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वृद्धी दर २०१९ च्या शेवटच्या तिमाहीत ४.७० टक्के होता.
३. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे वित्तीय क्षेत्र सुद्धा कमकुवत झालेले होते.
४. देशातील वैद्यकीय संरचना (Health Infrastructure) पुरेशी भक्कम नव्हती. लोक स्वास्थ्यवर केंद्र सरकारचा केलेला खर्च हा राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ १ टक्का होता.
५. देशात मोठे असंघटीत क्षेत्र आहे. ज्यामध्ये स्थलांतरीत (Migrant) मजुर किंवा परंप्रांतीय मजुरांची संख्या खूप मोठी आहे.
६. भारतातील २०.४४ दशलक्ष कामगार हॉटेल उद्योगावर अवलंबून आहेत. म्हणजे एकूण रोजगाराच्या ६० टक्के आहेत.
७. भारतातील १८ प्रमुख शहरात देशाचा २५ टक्के रोजगार उपलब्ध आहे. यात असंघटीत क्षेत्रात १८.७० दशलक्ष आहे. सरकारी क्षेत्रात ३०.५० दशलक्ष व खाजगी क्षेत्रात १९.५० दशलक्ष रोजगार उपलब्ध आहे. भारतातील ६५ टक्के असंघटीत क्षेत्र खाजगी मालकांच्या ताब्यात आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतात २४ मार्च पासून लॉकडाऊन सुरु झाले. त्याचा अर्थव्यवस्थेवर तीव्र परिणाम झाला व विकास दरात मोठ्या प्रमाणात घट झाली. लॉकडाऊनमुळे सर्व आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले. वस्तूचे उत्पादन, मागणी व पूरवठा विस्कळीत झाले. उद्योग धंदे बंद झाल्याने लोकांना नोकरी मजुरी गमवावी लागली. भारतातच नाही तर जगातील अर्थव्यवस्थेत मंदीसदृश परिस्थितीला मागणी व पूरवठ्यातील बदल कारणीभूत ठरले आहेत. आज जगातले सर्वच देश आपआपल्या परीने ह्या आव्हानांचा सामोरे जाण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

भारतात १३५ कोटी लोकांच्या देशात लॉकडाऊन करणे, तो कायम ठेवणे, मॅनेज करणे हे फारच मोठे आव्हान आहे. ह्यात एक सकारात्मक गोष्ट घडली ती म्हणजे Covid-19 ची महामारी हे सरकारवरचे आरिष्ट न राहता त्याला एक जनआंदोलनाचे स्वरूप आले. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे हे त्यांच्यात उत्तम संबंध साधून सामान्य जनताही ह्या लढाईमध्ये उतरले आहेत. ही फार महत्वाची गोष्ट आहे. ह्या महामारीचा सामाना करण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने वेळोवेळी आर्थिक पॅकेज जाहीर केलेत.

या शोधनिबंधात केंद्र सरकारच्या सर्व आर्थिक पॅकेजचा अभ्यास केला आहे व त्याचे मूल्यमापन करण्याचा प्रयत्नही केला आहे. भारतात लॉकडाऊन २४ मार्च २०२० ला जाहीर झाले आणि पहिले पॅकेज २६ मार्च २०२० ला आले म्हणजे ३६ तासानंतर आले. त्याला मी अध्ययनात पॅकेज नं. १ असे नाव दिले आहे. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेचे मोठे पॅकेज आले. त्यानंतर खूप गॅप घेवून ४८ दिवसानंतर केंद्र सरकारचं दुसरं पॅकेज आलं. तिसरं पॅकेज १५ मे ला आलं. चौथं पॅकेज १६ मे ला आणि शेवटचं पॅकेज १७ मे ला आलं. ह्या सर्व पॅकेजचा आपण ह्या शोधनिबंधात आर्थिक दुष्टीकोनातून अभ्यास करणार आहोत. या सर्व पॅकेजची एकूण रक्कम आहे २० लाख ९७ हजार कोटी रुपये आहेत. म्हणजे जवळजवळ २१ लाख कोटी रुपयांचे आहे. अमेरिकेचे पॅकेज त्यांच्या GDP च्या १० टक्के होते. बहुतेक देशांचे पॅकेज त्यांच्या GDP च्या १० टक्केच्या खालीच आहेत. मलेशियाने मात्र अपवाद केला त्यांनी ते पॅकेज त्यांच्या राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १६ टक्के एवढे दिले. भारताचे पॅकेज हे भारताच्या GDP च्या १०.५० टक्के एवढे आहे. हे निश्चितच मोठे आहे. त्याचा क्रमवार अभ्यास शोधनिबंधात करण्यात आला आहे.

२१ लाख कोटींचे हे पॅकेज सर्व केंद्र सरकारचे पॅकेज नाही. त्यात ८ कोटी रुपयांचे पॅकेज हे रिझर्व्ह बँकेने दिलेले आहे. त्यामुळे ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिले की केंद्र सरकारचं जे पॅकेज आहे ते २१ लाख कोटी रुपयांचे नसून १३ लाख कोटी रुपयांचे आहे. अर्थात रिझर्व्ह बँक ही सुद्धा केंद्र सरकारच्याच मालकीची असल्यामुळे हे सुद्धा सरकारचे पॅकेज असे म्हटले जाते. म्हणजेच यात विभागणी आहे ती १३ लाख कोटी रु. केंद्र सरकारचे व ८ लाख कोटी रु. रिझर्व्ह बँकेचे. क्रमाक्रमाने आलेल्या पॅकेजेसला क्रमांक देऊन या ठिकाणी मांडणी करून त्याचे विश्लेषण करण्यात आले आहे.

पॅकेज क्र. १ —पहिले पॅकेज २६ मार्च २०२० ला आहे. त्या पॅकेजचा भर दुर्बल घटकांवर होता. मात्र त्यामध्ये स्थलांतरीत कामगारांना विसरले. हे अतिशय महत्वाचे पॅकेज होते. त्यामध्ये तळातले जवळपास ८० कोटी लोक आहेत. पॅकेजमध्ये ह्या सर्वांसाठी प्रत्येकी ५ किला गहू किंवा तांदूळ तसेच १ किलो डाळ दर मानसी दर महिन्याला असे तीन महिने देण्याची तरतूद केली आहे. याचा एकूण खर्च आहे ३० हजार ५०० कोटी रुपयांचा आहे. हा सर्वच खर्च अंदाजपत्रकातून जाणार नाही. बजेट २०२०-२१ मध्ये 'Food Subsidy' खुप मोठी आहे. अंदाजपत्रकाच्या व्यतिरिक्त जो अतिरिक्त निधी आहे तो ५००० कोटी रु. परंतु एकूण खर्च त्यांनी दाखविला आहे तो ३०,५०० कोटी रुपयांचा म्हणजे एकूण प्रस्तावित खर्चाच्या साधारण १६.४ टक्के.

दुसरे, उज्वलामध्ये संमिलित झालेले गरीबी रेषेखालील कुटुंबियांसाठी तीन महिन्यांसाठी एलपीजी सिलेंडर विनामूल्य मिळणार आहे. ही अतिशय उत्तम योजना आहे. त्याचा लाभ साधारण ८.३ लक्ष कोटी लोकांना

होणार आहे. त्यावर केलेला खर्च हा १३ हजार कोटी रुपये आहे. हे तेरा हजार कोटी रुपये सर्व अंदाजपत्रकाच्या व्यतिरिक्त खर्चातून येणार आहे. ही एक मोठी जमेची बाजू आहे.

तिसरी महत्वाची बाब ह्या पॅकेजची ही आहे की मनरेगाचा मजुरीचा दर वाढविलेला आहे. पूर्वी जो १०० रु. होता तो वाढवून २०२ रु. केलेला आहे. मनरेगा योजनेच्या खाली वर्षातून १०० दिवस मजुरी देणे बंधन आहे, कायदा आहे. त्याचप्रमाणे दर माणसाला प्रतिव्यक्ती २००० रु. अतिरिक्त मिळणार आहे. २००० रु. रोजी म्हणजे १०० दिवसांसाठी २००० रु. ह्यासाठी २६ हजार ४०० कोटी रु. अंदाजपत्रकाच्या व्यतिरिक्त खर्च केले जाणार आहे. ही महत्वाची गोष्ट आहे. विधवा, जेष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग यांच्यासाठी २६० कोटी रु. एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजे प्रत्येकी १ हजार रु. असे तीन महिने ह्या लाभार्थी मिळेल. जनधन योजनेमध्ये ज्या महिला सामील झालेल्या आहेत. त्या महिलांना तीन महिन्यांसाठी ५०० प्रत्येकी असे दिले जाणार आहे. तो खर्च आहे ९९०० कोटी रु. आहे. हा खर्चही अंदाजपत्रकाच्या व्यतिरिक्त आहे. शेतकऱ्यांसाठी इथे अतिरिक्त खर्च नाही. मात्र त्यांना जे पी. एम. किसान योजनेअंतर्गत दोन-दोन हजार तीन हप्त्यांमध्ये मिळतात त्यातला पहिला हप्ता लवकर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. संघटन कामगारांना म्हणजे जवळजवळ ४ लाख ८ हजार कोटी कामगारांना Employees Provident Fund : त्यांना जो शेअर भरावा लागतो तो आणि सेवा योजकांना जो शेअर भरावा लागतो तो म्हणजे १२-१२ टक्के शेअर हे तीन महिन्यांसाठी केंद्र सरकार देणार आहे आणि ह्यावर २५०० कोटी रु. खर्च होणार आहे. या सर्व योजनांमधून लोकांचा नियोजित खर्च वाढणार आहे. लोकांची क्रयशक्ती वाढणार आहे. लोकांना हातातला पैसा वाढणार आहे. ही सर्व रक्कम एकत्र केली तर १,०३,००० कोटी रु. आहेत. त्यात अतिरिक्त खर्च जो आहे तो ५९ हजार ६०० कोटी रु. एवढा आहे. म्हणजे एकूण रकमेच्या साधारण ५ टक्के आहे.

त्यानंतर एक छोटे पॅकेज आणखी आले होते. त्यात काही उपाययोजना होत्या. त्यामध्ये एक उपाययोजना होती ती 'Emergency Health Care Response Package'. त्यासाठी १५,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ही तरतूद अंदाजपत्रकाच्या व्यतिरिक्त होती. त्यामुळे पहिल्या पॅकेजचा एकूण खर्च १,१७,९०० कोटी रुपये आहे. त्यापैकी अंदाजपत्रकाच्या व्यतिरिक्त केलेला खर्च आहे ७४,६०० कोटी रुपयांचा साधारण ६३ टक्के म्हणजे अंदाजपत्रकात ज्या तरतूदी केल्या होत्या त्याच्यापलीकडे जाऊन ६३ टक्के अतिरिक्त तरतूदी केलेल्या आहेत. यात इतरही योजना आहेत. उदा. महिलांचे 'Self Help Group' आहेत त्या गटांना कुठलेही तारण न ठेवता जे कर्ज दिले जाते त्याची मर्यादा १० लाख पर्यंत होती ती आता २० लाखांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. याचा फायदा ७ कोटी महिलांना मिळणार आहे. त्या कामगारांना तीन महिन्यांचा पगार त्यांची मजुरी आगावू मिळू शकते. त्याचा लाभ जवळजवळ ५ कोटी कामगारांना होणार आहे. बांधकाम मजुरांसाठी राज्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत की ३०,००० कोटी रुपयांचा कल्याण निधी निर्माण करावयाचा आहे. त्यामधून बांधकाम मजुरांना त्याचा फायदा करून देणे निर्देश देण्यात आले आहेत. करात कपात केलेली नाही त्यामुळे एकंदर टॅक्स जो भरावयाचा आहे तो तेवढाच राहणार आहे. मात्र त्यात थोडासा वेळ मिळू शकेल. सर्व प्रकारचा संकीर्ण खर्च (Miscellaneous) ३७,१०० कोटी रु. आहे. त्या पॅकेजचा एकत्रिकरण केलं तर १,९२,८०० कोटी रु. होतात. म्हणजे आणखी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १६ टक्के ह्यातील काही तरतूदी आधीच अंदाजपत्रकात केलेल्या होत्या अंदाजपत्रकाच्या व्यतिरिक्त केलेल्या नव्या तरतूदी आहेत ७४,६०० कोटी रुपयांच्या म्हणजे साधारण ३८ टक्के खर्च हा अंदाजपत्रकाच्या व्यतिरिक्त केलेला आहे.

पॅकेज नं. २- रिझर्व्ह बँकेचे एकूण मोठे पॅकेज ८ लाख कोटी रुपयांचे आहे. ह्या पॅकेजचा मुख्य उद्देश तरलता उपलब्ध करून देणे हा होता. विविध मार्गांनी पैशाची चणचण दूर करण्यासाठी म्हणजे बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी ही तरतूद रिझर्व्ह बँकेने केली होती. त्यासाठी त्यांनी Cash Reserve Ratio (CRR) कमी केला. म्हणजेच बँकांजवळची पैशाची उपलब्धता वाढविली. त्यामुळे त्यांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढली. तसेच रिझर्व्ह बँकेने Long Term Ratio of Ratio केले. त्यामध्ये काही विशिष्ट क्षेत्रांना कर्ज देण्यासाठी बँकांना अतिरिक्त तरलता उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ही सर्व रक्कम अतिशय महत्वाची आहे ती बँकांना कर्ज देण्यासाठी उपलब्ध होणार आहे. म्हणजेच मोठ्या प्रमाणावर निधीची उपलब्धता वाढेल.

पॅकेज क्र. ३- दुसऱ्या टप्प्यावर केंद्र सरकारचे ५ पॅकेजेस आले त्यात पहिले म्हणजे हे १४ मे २०२० ला आले. हे पॅकेज केवळ MSME साठी होते. (MSME- Mini, Small, Medium Enterprises) हे पहिले पॅकेज ५,९४,६०० कोटी रुपयांचे आहे. MSME ला विविध प्रकारे मदत करण्यासाठी, एकंदरीत मोठ्या प्रमाणावर त्यांना Credit Support मिळावा, त्यांना पुन्हा उभे राहता यावे यासाठी एवढी प्रचंड रक्कम आहे. यात प्रत्यक्ष खर्च अंदाजपत्रकाच्या व्यतिरिक्त जो केलेला आहे तो मात्र तुलनेने फारच कमी आहे. तो १६५०० कोटी रु. आहे. म्हणजे एकंदरीत प्रस्तावित खर्चाच्या २.७७ टक्के आहे. मात्र त्यामध्ये MSME साठी अतिशय महत्वाच्या योजना मांडलेल्या आहेत.

पॅकेज क्र. ४- हे पॅकेज विशेष करून 'Vulnerable Section' साठी व स्थलांतरीत मजुरांसाठी आले. ही एक मोठी दिरंगाई आपल्याला म्हणता येईल. त्यामध्ये प्रत्येक स्थलांतरीत कामगाराला ५ किलो धान्य, १ किलो चना डाळ दोन महिन्यांसाठी देण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यासाठी ३५०० कोटी रु. प्रायोजित खर्च आहे. हा सर्व अतिरिक्त खर्च आहे. त्यात अनेक योजना आहेत. उदा. एक देश एक रेशन कार्ड. ह्यात सूक्ष्म कर्जा (Micro Loan) साठी चांगली तरतूद आहे. फेरीवाल्यांसाठी (Street Vendors) १०,००० रु. कर्जाची योजना आहे. लहान धंद्यासाठी ज्यांनी मुद्रा योजनेच्या अंतर्गत कर्ज घेतलेले आहे त्यांनी वेळेवर परत केले तर २ टक्के कपात व्याजाच्या दरावर सूचविली आहे. यात महत्वाची बाब म्हणजे मध्यम वर्गीयांसाठी गृहकर्जाची 'Credit link Scheme' होती त्याला १ वर्षांचे Extension दिलेले आहे. त्याचा फायदा २.५० लाख लाभार्थींना होणार आहे. याची एकंदरीत संख्या ३ लाख १ हजार कोटी रुपये होती. त्यापैकी प्रत्यक्ष खर्च म्हणजे अंदाजपत्रकाव्यतिरिक्त खर्च १५,३०० कोटी रु. होता.

पॅकेज क्र. ५- हे पॅकेज १६ मे ला पूर्णपणे शेती क्षेत्रासाठी आहे. त्यामध्ये खूप योजना आहेत. उदा. शेतीसाठी पायाभूत निधी (Agriculture Infrastructure Fund) जो १ लाख कोटी रुपयांचा तयार करणार आहेत. सूक्ष्म उपक्रमांसाठी एक योजना आहे. मत्स्यपालनासाठी एक मोठी योजना आहे. या योजना दीर्घकालीन फायद्याच्या आहेत. मात्र यामध्ये सरकारने कुठलाही अतिरिक्त पैसा टाकलेला नाही. केवळ पशुपालनाच्या योजनेमध्ये सरकारने १५ हजार कोटी रु. आणि दुसऱ्या एका छोट्या योजनेमध्ये ५०० कोटी रु. नव्याने टाकले आहे. ह्या योजना अतिशय महत्वाच्या आहेत. परंतु त्याचा उपयोग ताबडतोब होणार नाही. आणि त्याचं प्रत्यंतर लगेचच येणार नाही यात काही शेती सुधार (Agricultural Reforms) दिलेले आहेत. ते फार महत्वाचे आहेत. उदा. जीवनावश्यक वस्तूंच्या कायद्यामध्ये (Essential Commodity Act) बदल सुचविले आहेत. कृषी विपणनात सुधार केलेले आहेत. 'Contract Farming' परवानगीचा

प्रस्ताव आहे. या सर्व उपाययोजना दीर्घकालीन स्वरूपाच्या आहेत. त्यातून ताबडतोब लोकांच्या हातात काही मिळणार नाही. ह्या पॅकेजचा एकूण खर्च १ लाख ५० हजार कोटी आहे. मात्र प्रत्यक्ष अंदाजपत्रकाच्या व्यतिरिक्त आहे तो केवळ २००० कोटी म्हणजे एकंदरीत खर्चाच्या १.३३ टक्के आहे.

पॅकेज क्र. ६- हे पॅकेज १६ मे ला आले. ते 'Structural Reform' साठी आहे. यात विविध क्षेत्रांमध्ये खाजगीकरण मोठ्या प्रमाणात करण्याचे प्रायोजित आहे. कोळसा, खनीज खाणीच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण होणार आहे. डिफेन्स प्रॉडक्शनमध्ये एक नकारात्मक यादी असणार आहे. ती डिफेन्स क्षेत्रामध्ये लागणाऱ्या वस्तूंची यादी असेल. ज्या वस्तू भारतातच तयार कराव्या लागतील त्या डिफेन्स आयात करण्याची परवानगी असणार नाही. उर्जा क्षेत्रा (Power Sector) मध्ये केंद्रशासीत प्रदेशांमध्ये उर्जा वितरण कंपन्या आहेत त्या सर्वांचे खाजगीकरण होणार आहे. सामाजिक पायाभूत क्षेत्रांमध्ये विद्युत् रुग्णालयाच्या क्षेत्रामध्ये व्यवहार्यता निधी २० टक्के पासून वाढून ३० टक्के पर्यंत करणार आहे. महत्वाची बाब आहे. 'Social Infrastructure' च्या बाबतीत ८१०० कोटी अशी अतिरिक्त अंदाजपत्रकाच्या व्यतिरिक्त केलेली आहे. ही जमेची बाजू आहे. या पॅकेजचा एकूण खर्च ८१०० कोटी आहे. हा सर्व खर्च सरकारनेच केलेला आहे त्यामुळे तो अतिरिक्त आहे.

पॅकेज क्र. ७- हे शेवटचे पॅकेज आहे. ह्यामध्ये महत्वाची गोष्ट म्हणजे ह्यात स्थलांतरीत कामगार अत्यांच्यासाठी केलेली तरतूद योग्य आहे. जे परप्रांतीय मजूर आपापल्या गावांमध्ये गेलेले आहेत तेथे ते मनरेगाच्या योजनेखाली कामे मिळावित म्हणून ४०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. अत्यंत चांगली तरतूद आहे. ह्या पॅकेजमध्ये आणखी काही महत्वाच्या घोषणा केलेल्या आहेत. 'Public Sector Streamline' करायचे आहे. म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर त्यांचे खाजगीकरण होणार आहे. ह्या सेक्टरमध्ये चार किंवा पाचच युनिट असतील. उदा. Oil जर असेल तर त्यात ४ किंवा ५ कंपन्या असतील बाकीच्या कंपन्यांनी ह्या कंपन्यांमध्ये जोडून घ्यायचे आहे. याचा खूप मोठा परिणाम होऊ शकतो. एक अतिशय महत्वाची परवानगी आहे. ती म्हणजे राज्य सरकारवर बंधने असतात की त्यांनी कित्याक काढावे. राज्य सरकारांना त्यांच्या GDP च्या ३ टक्के पर्यंत कर्ज काढण्याची परवानगी असते. ती मर्यादा आता वाढवून ५ टक्के पर्यंत करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यांना आता जास्त रक्कम उपलब्ध करू शकते.

या सर्व पॅकेजचा एकंदरीत विचार केल्यावर असे दिसते की हे सर्व पॅकेज एकूण २१ लाख कोटी रुपयांचे आहेत. त्यापैकी ८ लाख कोटी RBI कडून आलेले आहे. उरलेले साधारण १३ लाख कोटी रुपयांचे सरकार कडून आलेले आहेत. त्या १३ लाख कोटीपैकी प्रत्यक्ष अंदाजपत्रकाच्या व्यतिरिक्त खर्च १.५६५ कोटी रुपयांचा हा काही फार अवाढव्य आहे असे म्हणता येणार नाही. परंतु या अंतर्गत ज्या घोषणा मांडण्यात आलेल्या आहेत त्या निश्चितपणे चांगल्या आहेत, परंतु पुरेशा नाहीत. ही केवळ सुरुवात आहे.

निष्कर्ष व शिफारशी

वरील अध्ययनावरून पुढील प्रमाणे निष्कर्ष काढले आहेत व त्यावर योग्य अशा शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.

१. कोरोनामुळे त्रस्त झालेल्या भारतीयांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २० लाख ९७ कोटी रुपयांचा आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. त्यापैकी ७ लाख कोटी रुपयांच्या योजना पूर्वीच जाहीर केल्या होत्या. त्यात आणखी १३ लाख कोटीची भर घालून २० लाख कोटी हा आकर्षक आकडा जाहीर केला.

- पैशातून भारताला नेमका कसा व किती फायदा होईल हे येणारा काळच सांगेल परंतु आजवरच्या अनुभवांवरून फार काही उत्साहवर्धक घडेल अशी आशा सर्वसामान्यांमध्ये उरलेली नाही. समाज माध्यमांमधून सर्व सामान्यांनी ज्या प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत त्यावरूनच हेच दिसत आहे.
२. कोव्हीड १९ ची महामारी ज्या प्रमाणे देशाने हाताळली त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित हानी जी होवू शकली असती ती टाळण्यात आपण निश्चितच यशस्वी झालो आहोत ही अभिमानाची गोष्ट आहे परंतु दुसरीकडे सर्वात वाईट गोष्ट घडली ती स्थलांतरीत मजूरांबाबत. देशात पसरलेले परंप्रांतीय मजूरांवर आलेली परिस्थिती हा आपल्या देशावर लागलेला मोठा कलंक आहे त्यांच्या बाबतीत देशातील व्यवस्था अपूरी पडली असे म्हणण्यापेक्षा संपूर्ण व्यवस्थापनामध्ये त्यांचा विचारच झाला नाही असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे त्यांच्यावर फार मोठा अन्याय झाला आहे हे मान्य करावे लागेल. अनेक मुख्यमंत्र्यांनी ते कबुलही केले आहे.
 ३. केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी १ लाख ६३ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. परंतु त्यासाठी सरकारच्या खजीन्यावर तातडीने भार पडणार तो केवळ ६ हजार कोटी रुपयांचा. शेती क्षेत्रात वी-बियाणे, खते, किटकनाशके या साऱ्यांसाठी सरकारने तरतूद करणे आवश्यक होते. त्याचा शेतकऱ्यांपर्यंत पूरवठा करण्याची सोय करावयास हवी होती. परंतु २० लाख कोटीत हे बसले नाही. शेतकऱ्यांना सध्या सांत्वना, आश्वासने व आमीषांची गरज नाही. गरज आहे ती रोख रकमेची. ती भागविली गेली नाही तर शेतकरी पेरणी कशी करणार? वाढीव हमी भाव, बाजारपेठ संरचनेतील सुधारणा काय कामाच्या?.
 ४. देशात आरोग्यासारख्या महत्वाच्या क्षेत्रावर केवळ १ टक्केच्या जवळपास खर्च केला जातो तो कधीच पुरेसा नव्हता. परंतु कुठल्याही सरकारने त्याची कधीही गांभीर्याने दखल घेतली नाही. परंतु कोरोनाने मात्र देखल घेण्यासाठी भाग पाडले.
 ५. आज देशात गरज आहे ती गरीब, मध्यमवर्गीय व उद्योजक अशा सर्वांना आत्मविश्वास व आधार देण्याची. तो आधार जाहिर केलेल्या ह्या पॅकेजमधून मिळू शकेल काय? हा प्रश्न आहे.
 ६. बेरोजगारी व पगार कपात यामुळे बाजारात पैसाच कमी येणार असेल तर मागणीला उठाव येणार कुठून? मागणीलाच आहोटी लागली तर व्यापार व्यवसायात वाढ होण्याची आशा तरी कशी केली जाऊ शकते?

शिफारशी

१. हे पॅकेज म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेला नव्याने उभारी देण्यासाठीची सुरुवात आहे. ह्या पॅकेजमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था किती उभी राहू शकेल हे येणारा काळच ठरवेल. वित्त मंत्र्यांनी सांगितले असले की, यानंतर पॅकेज येणार नाही. परंतु ही सर्व पॅकेज अर्थव्यवस्था पूर्ववत आणण्यासाठी पुरेसे नाही ही केवळ सुरुवात आहे. यानंतर आणखी पॅकेजेसची गरज भासणार आहे. ह्या पॅकेजला 'Survive Package' म्हणता येईल. यानंतरचे पॅकेज लागेल ते 'Growth Revival' चे पॅकेज लागेल. म्हणजे आर्थिक विकास पुन्हा आणण्यासाठी पॅकेज लागणार आहे. त्यानंतरही आपल्याला पॅकेजची गरज भासू शकते ती 'Financial Sector Reform' साठी. कारण आपली वित्तीय रचना खीळखीळी झालेली आहे. एकंदर जी दुरवस्था आलेली आहे त्यातून बाहेर आल्याशिवाय शाश्वत विकास साधता येणार नाही. त्यानंतरचे पॅकेज लागू शकेल 'Structural Reform' साठी जरी याआधी ते दिले असले तरी अशी यानंतर तीन पॅकेजेस आणखी आणावी लागतील असे वाटते. ती कधी येणार, कोणत्या स्वरूपत येणार हे आज सांगता येणार नसले तरी येणारा काळच ठरवणार आहे.

२. MSME क्षेत्र पूर्ण क्षमतेने सुरु झाले तर दोन कोटी नोकऱ्या पुन्हा उपलब्ध होऊ शकतात. परंतु वाटते तेवढे सोपे नाही. कच्च्या मालाच्या टंचाई व मागणीचा अभाव या अडचणी आहेतच. कामगार उपलब्ध होणार नाही ही मोठी समस्या उभी आहे. याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे.
३. कोरोनाचे संकट मोठे आहेच परंतु त्यानंतरची आर्थिक आव्हाने त्याहूनही मोठी आहेत. कोरोनाशी साम्य करण्यासाठी टाळेबंदीच्या चक्रव्यहात शिरलेल्या देशाची सुटका करावयाची असेल तर ज्या जिल्हात मोठा संसर्ग झालेला नाही अशा ठिकाणी पुन्हा अर्थचक्र फिरवावे लागतील. स्थलांतरीत मजुरांना परत बोलवावे लागतील त्यासाठी राज्यांना आणि केंद्र सरकारलाही पुढाकार घ्यावा लागेल.
४. कोरोनाची सुरुवात होताच सरकारने लगेच निर्णायक सर्वंकष प्रतिसाद दिला. सरकारचा याविषयीचा दृष्टीकोन व्यापक होता. परंतु अनेक उपाय करुनही कोरोनाची घोडदौड सुरुच राहिली. म्हणूनच लढाईत केवळ सरकार एकटे पुरेसे पडणार नाही. त्यासाठी सामाजिक प्रतिसादही अपेक्षित आहे.
५. पर्यावरण, परिस्थितीजन्य निसर्गव्यवस्था हा मानवाच्या भरणपोषण, जनकल्याणाचा मुलाधार असून प्रकल्प, योजना, बांधकामे, पर्यावरणीय परिणामाची शहानिशा केल्याखेरीज राबवू नयेत. एकंदरीत यात विकास व प्रशासनाचा ढाचा यात आमूलाग्र बदल करुन सर्वांच्या मूलभूत गरजा भागविणारी विकेंद्रीत, स्वदेशी, श्रमजीवीचा सन्मान करणारी अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्था व संस्कृती निर्माण करणे ही सर्वांचे आर्त हाक असेल.
६. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर संधीच्या दृष्टीकोनातून पाहिले तर भारतामध्ये उपलब्ध असलेली मंडे बाजारपेठ, तरुणांची मोठी संख्या, तंत्रज्ञानाची ओळख, अन्यदेशांपेक्षा स्वस्तात मिळणारे मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांची उपलब्धता या जमेच्या बाजू आहेत. तसे झाल्यास भारतामध्ये रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध होऊ शकतात.
७. कोरोनामुळे प्रत्येकाचे राहणीमान कमी होणार आहे. ही गोष्ट सर्व समाजाने स्विकारायला हवी. सरकारने देखील आयातीत वस्तूवरील करात वाढ करुन त्यापासून मिळणारे उत्पन्न लोकांच्या कल्याणासाठी कार्यक्रमांवर खर्च करायला हवे. हा खर्च केल्यामुळे बाजारातील मागणीत वाढ होवून देशाच्या अर्थकारणाला चालना मिळेल.
८. लॉकडाऊनची झळ प्रत्येकाला सोसावी लागत आहे. पूर्वीसारखे कामधंदे सुरु व्हावेत, व्यापार, उद्योग पुन्हा बहरावेत. कारखान्यांच्या यंत्रांचा पुन्हा खणखणाट सुरु व्हावा व श्रमिकांचे देह पुन्हा कामाने विघड्यावेत असे प्रत्येकाला वाटते. थोडक्यात पुन्हा जैसे थे व्हावे हे सहजशक्य नाही याची कल्पना आहे पण अशक्यही नाही.
९. बँकांच्या कर्जाचे हप्ते भरण्यात काही महिन्यांची सुट देवून छोट्या व्यापाऱ्यांचा प्रश्न सुटणार नाही स्वयंरोजगार करणाऱ्या ह्या छोट्या व्यापारांनाही मदत करण्याचे धोरण तयार करावे लागेल.
१०. कोरोनापूर्व जग आणि कोरोना नंतरचे जग असा भेद करुन नव्या जगातील संधीवर लक्ष केंद्रीत करावे लागेल. त्यासाठी वेळोवेळी आर्थिक तरतूदही सरकारद्वारे केल्या जाव्यात. सोबतच योग्य अंमलबजावणीचीही गरज आहे.

संदर्भ सूची

१. लोकमत वृत्तपत्र, १३ मे २०२०.
२. लोकमत वृत्तपत्र, १४ मे २०२०.
३. लोकमत वृत्तपत्र, १६ मे २०२०.
४. लोकमत वृत्तपत्र, १७ मे २०२०.

लोकमत वृत्तपत्र, १८ मे २०२०.

Effects of covid-19 pandemic on Indian Economy and Marginalised sections- 2 June 2020.

International Webinar on Impact of COVID-19 on Global Economy- 12 June 2020.

National Webinar on Economic Impact of CORONA Pandemic and Indian Government Policies- 16 June 2020.

National Webinar on COVID-19 and Rural Development Issues and Policies- 19 June 2020.

National Webinar on Covid-19 : Challenges and Solution before the Indian Govt. - 23 June 2020.

T.V. Channels- Aajtak, ABP Maza.

प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे

विभागप्रमुख, अर्थशास्त्र

डॉ. मधुकरराव वासनिक पी.डब्ल्यू.एस.कला व

वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर.

मो. ९६६५०९८४३२

Email-pradnya.mahendra@gmail.com

ISSN : 2249-5134

PERSPECTIVES

(A National Interdisciplinary Annual Research Journal)

*Peer Reviewed
National Research
Journal for
Interdisciplinary
Studies in Arts
Commerce &
Social Sciences*

Special focus on

Buddhist Archaeology & Pali Literature

Vol- I,
Issue (X)
2021



Dr. Madhukarrao Wasnik
P.W.S. Arts, Commerce & Science College

Kamptee Road, Nagpur - 26
(Reaccredited 'B' by NAAC)

Official Website : www.pwscollge.edu.in Email : principal@pwscollge.edu.in



Scanned with OKEN Scanner

17	सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाचे जनक : बुध्द	प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे	110-117
18	सम्राट अशोकाच्या शिलालेखांचे बुध्द धम्मास योगदान	प्रा. वसुंधरा पाटील	118-124
19	साठोत्तरी दलित-आंबेडकरी कादंबरी आणि बौद्ध तत्त्वज्ञान	अमित वासुदेव गजभिये डॉ.मनिषा नागपुरे	125-131
20	पुरातत्त्व संस्कृतीमध्ये पाली भाषेचे महत्त्व व बौद्ध तत्त्वज्ञान	अरविंद रामचंद्र टिकले	132-137
21	सम्राट अशोक व तृतीय बौध्द संगिती	डॉ. सीमा लालचंद गोलाईत	138-140
22	भगवान बुद्ध आणि त्यांचे आर्थिक तत्त्वज्ञान	कु. माधुरी रा. बोटरे	141-143

सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाचे जनक : बुद्ध

प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे

सारांश — गौतम बुद्धांनी बौद्ध धम्माच्या रुपाने एक नविन विचार जगासमोर ठेवला. त्यांनी आर्थिक व सामाजिक समतेचा विचार मांडून जगाला कल्याणाचा मार्ग दाखविला. त्यासाठी त्यांनी सम्यक उपजिविकेवर भर दिला. संपत्तीच्या अतिरिक्त संग्रहाचा विरोध केला. मानवाने सत्य मार्गाने, नीतीने, न्यायाने मिळविलेल्या साधन सामुग्रीवर उपजिविका केली पाहिजे असे त्यांना वाटत होते. त्यांनी लालसेने मिळविलेल्या संपत्तीचा व त्यासाठी स्विकारलेल्या मार्गाचा विरोध केला. त्यांनी मनुष्याला मानसिक गुलामगिरीतून मुक्त करून मानवता आणि मुलभूत अधिकार प्राप्त करण्याची दिशा दाखविली आहे. समाजाच्या निकोप वाढीसाठी व आर्थिक विकासासाठी शिक्षण आवश्यक असल्याने बुद्धाने सार्वत्रिक शिक्षणाचाही पुरस्कार केला. त्यांनी संपत्तीचे समन्यायी वाटप, सुयोग्य नियोजन व गुंतवणूकीमुळे शांती आणि प्रगती बरोबरच अपराध मुक्त समाज निर्मितीची चर्चा कुटुंबात सुत्तात सांगितली आहे. भगवान बुद्ध प्राचीन भारतातील पहिले विचारवंत होते की ज्यांनी श्रमिक वर्गाच्या कल्याणाची काळजी घेण्याचे आव्हान केले. यावरून बुद्धाची श्रमिकाविषयीची तळमळ आणि दुरदृष्टी लक्षात येते. एकंदरच त्यांनी जगामध्ये एक नविन आदर्श, नविन चेतना, नविन विचारधारा, नविन क्रांती व नविन परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडली आहे. आज समाजात हिंसा, अन्याय, अत्याचार वाढीस लागले आहे. त्यासाठी आजही आपल्याला बुद्धांच्या आर्थिक व सामाजिक समतेचे आणि सर्वसमावेशक विकासाचे तत्वज्ञान आत्मसात करून त्यानुसार आचरण करण्याची गरज आहे.

बीजशब्द — तृष्णा, गरज, सम्यक आजिविका, संपत्तीची निर्मिती, सम्यक विनियोग, संपत्तीचे वितरण, बचत, संघ.

प्रस्तावना — गौतम बुद्धांना प्रामुख्याने बौद्ध धम्म संस्थापक या नावाने ओळखले जाते. परंतु त्यांनी केवळ धम्मासंबंधीच विचार मांडले नाहीत तर मानवी जीवनात असे एकही क्षेत्र नाही, की ज्याबाबत त्यांनी समाजाला उपदेश केलेला नाही. गौतम बुद्धांनी बौद्ध धम्माच्या रुपाने एक नवीन विचार जगासमोर ठेवला. त्यांनी मानवी जीवनाच्या सर्वांगीन विकासाच्या दृष्टीने विचार मांडले. त्यांचे धार्मिक विचार हे त्यांच्या अफाट ज्ञानाची एक विचारधारा आहे. सोबतच सामाजिक व आर्थिक समतेचा विचार मांडून जगाला कल्याणाचा मार्ग दाखविला. समाजात समानता, शांतता, प्रेमभावना, आणि सर्वसमावेशक विकास करायचा असेल तर आर्थिक व सामाजिक विषमता दूर करणे आवश्यक आहे. हे ओळखून त्यांनी आर्थिक व सामाजिक विषमता दूर करण्याचे मार्ग सांगितले. त्यांनी आपले विचार एका विशिष्ट वर्गापुरते, समाजापुरते मर्यादित ठेवले नाही तर 'बहुजन कल्याण' हा त्यांच्या उपदेशाचा मूळ आधार होता. बुद्धांच्या विचारांकडे धार्मिक चष्यातून बघितले जात असल्यामुळे बुद्ध हा केवळ धर्म संस्थापक होता व तो धर्म आपला नसल्यामुळे त्याचा आपला काही संबंध नाही अशी धारणा झालेली आहे. नाही तर बुद्ध हे जगातील पहिले शिक्षण तज्ञ, पहिले अध्यापन शास्त्रज्ञ, पहिले मानसशास्त्रज्ञ, पहिले अर्थशास्त्रज्ञ असे सर्वच बाबतीत पहिले ठरले असते. मी या ठिकाणी बुद्ध जगातील पहिले अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून विचार करते.

बौद्ध धम्मात आर्थिक व सामाजिक विषमतेला स्थान नाही. बहुजन व लोकतंत्र याला सर्वात उच्च स्थान आहे. बौद्ध धम्म एक जीवन पद्धती आहे. एक आचरक संहिता आहे. त्यांनी विज्ञानावर आधारलेला एक व्यवहारिक, ब्राम्हणवादाचा विरोध करून समानता, एकता, राष्ट्रीयता स्वतंत्रता, करुणा, मैत्री, न्याय, आणि विश्व बंधुत्वाचा मार्ग स्थापित केला. मनुष्याला मानसिक गुलामीतून मुक्त करून मानवता आणि

मुलभूत अधिकार प्राप्त करण्याची दिशा दाखविली आहे. त्यांनी जगामध्ये एक नवीन आदर्श, नवीन चेतना, नवीन विचारधारा, नवीन क्रांती व नवीन परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडली आहे. मानवाने आदिम युगापासून वर्तमान युगापर्यंत जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात खुप विकास केला. मानवाच्या भौतिक सुख साधनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली. सुख-समृद्धीत वाढ होवूनही मानवी जीवनात असंख्य प्रश्न निर्माण झाले. मानवा-मानवात द्वेष भावना वाढत गेली. हिंसा, अन्याय, अत्याचार वाढीस लागले. कारण गौतम बुद्धांनी सांगितलेले आर्थिक समतेचे तत्व आपण विसरत चालले आहेत. हे टाळण्यासाठी आपल्याला नव्याने बुद्धांचे आर्थिक समतेचे, सर्व समावेशक विकासाचे तत्वज्ञान व विचार आत्मसात करून त्यानुसार आचरण करण्याची गरज आहे. या अनुशंगाने विषयाची निवड करण्यात आली आहे.

अध्ययनाची उद्दिष्टे -

१. बुद्धकालीन अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करणे.
२. बुद्धांच्या आर्थिक विचारांचा अभ्यास करणे.
३. आजच्या संदर्भात बुद्धांच्या आर्थिक विचारांची गरज लक्षात घेणे.

उपकल्पना -

१. सद्यःस्थितीत बुद्धांच्या आर्थिक विचारांची गरज आहे.

जागतिकीकरणाच्या सध्याच्या युगात आर्थिक विकास हाच मनुष्य जीवनाचा अविभाज्य भाग झाल्याचे दिसते. आर्थिक विकासाच्या अनुशंगाने सामान्य जनतेच्या प्रगतीला चालना मिळणे आवश्यक आहे. कारण राष्ट्राचा विकास हा शेवटी प्रत्येक व्यक्तीच्या विकासावर अवलंबून असतो. मनुष्यातील 'समाज' हा राष्ट्राची उभारणी करतो. परंतु सध्या तसे चित्र दिसत नाही. आर्थिक विकासाची फळे काही ठराविक लोकांनाच चाखायला मिळतात. सामान्य माणूस मात्र त्याच्या मुलभूत गरजाही पूर्ण करू शकत नाही. प्रगतीच्या नावावर मनुष्य भौतिक साधन संपत्तीचा गुलाम बनला आहे. मनुष्याची आंतरिक प्रगती वृद्धिंगत व्हावी जेणेकरून खऱ्या अर्थाने समाजाच्या प्रगतीला चालना मिळेल. या दिशेने प्रयत्न करण्याची कुणालाही गरज भासत नाही. परिणामी मानवी मूल्यांचा झपाट्याने न्हास होत आहे. मानवाने विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी झेप घेतली. चंद्र आणि मंगळ मोहिमा यशस्वी केल्या. परंतु नैतिक मूल्यरहीत ही प्रगती कितीही झपाट्याने पुढे गेली तरी एक वेळ अशी येईल की, मनुष्य आणि प्राणी यांच्या व्यवहारात फरक करणे कठीण होईल.

अशा निराशाजनक परिस्थितीत सामाजिकदृष्ट्या स्थिर अर्थव्यवस्थेची जगाला नितांत आवश्यकता आहे. ज्या व्यवस्थेत मनुष्याच्या अत्युच्च नैतिक विकासाला व मानवी मूल्यांना प्राधान्य असेल. बुद्धांच्या विचारावर आधारित सामाजिक व आर्थिक विकासाला चालना देणारी आधुनिक व प्रगतीशील व्यवस्था निर्माण झाल्यास या स्थितीवर मात करणे सहज शक्य आहे. कारण बुद्धांचा विचार हा भौतिक विकासाबरोबर मनुष्याच्या आंतरिक प्रगतीला व मानवतेला चालना देणारा आहे.

बुद्धांच्या सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाच्या संकल्पना

१. मनुष्याच्या गरजा आणि इच्छा किंवा तृष्णा - बुद्धाने सर्व प्रकारच्या पारंपारीक दैवी संकल्पना, कर्मकांड इत्यादींचा त्याग करून मानवी मन, इच्छा, चिंता, भावना, आर्थिक प्रक्रिया कशा असतात यावर त्यांनी लक्ष केंद्रीत केले आहे. वस्तूंचे उत्पादन, विनिमय आणि वापर करतांना त्यांनी लाभदायक व हानीकारक या दोन्ही बाजूंचा विचार केला आहे. हा विचार त्यांनी त्यांच्या दुःख मुक्तीच्या सिद्धांतात मांडला आहे. मानवी

कल्याण कशात आहे हे सांगतांना त्यांनी मध्यम मार्ग सुचविला आहे. मानवी जीवनातील सर्व दुःखाचे कारण तृष्णा किंवा लोभ हे असून त्यांनी गरज आणि इच्छा (लोभ) यात फरक केला आहे.

आजवर जगातील अर्थशास्त्रज्ञांनी आर्थिक समस्यांचे विवेचन करतांना अमर्याद गरजा आणि मर्यादित साधने यावरच लक्ष केंद्रित केलेले आहे. पण गरज आणि इच्छा यांचा एकाच वेळी विचार करण्याचा प्रयत्न केला गेला नाही. माणसाला भूक लागली तर त्याला पोट भरण्यासाठी काहीतरी अन्न लागते. त्याला खरच भूक लागली तर तो आपली भूक भागविण्यासाठी जे खाण्यासाठी उपलब्ध असेल ते खाऊन आपली भूक भागवितो. त्यावेळी तो मला हेच हवे असा हट्ट करित नाही. ही आहे गरज. परंतु हट्ट करून वांच्छित पदार्थ खाण्याचा त्याचा हट्ट असेल तर ती त्याची गरज नसून इच्छा असते. तेथून समस्येला सुरुवात होते. यालाच बुद्धाने तृष्णा म्हटले आहे.

जगातील अर्थतज्ञांनी गरजांची संख्या अमर्याद असल्याचे सांगितले आहे. परंतु अनंत असणाऱ्या या गरजा नव्हेत. त्या इच्छा आहेत. खरं म्हणजे सजीवांच्या नैसर्गिक गरजा मर्यादितच असतात. ज्या अमर्यादित असतात त्या इच्छा होत. अमर्यादित इच्छांना आधुनिक अर्थतज्ञांनी गरजा म्हटल्यामुळे संपूर्ण अर्थशास्त्राची दिशाच बदलून गेली आहे. इच्छा अमर्यादित असल्यामुळे त्या पूर्ण करण्यासाठी साधने कमी पडतात. म्हणून आर्थिक समस्या निर्माण होतात. अशा गरजांचे नव्हे तर इच्छांचे आर्थिक दृष्टीने वर्गीकरण करण्याची आवश्यकता असते. आवश्यक, कमी आवश्यक आणि चैनीच्या इच्छा असे तीन प्रकारात गरजांचे वर्गीकरण केले की, मग उपलब्ध असलेल्या मर्यादित साधनांच्या सहाय्याने त्यांची पूर्तता करण्यासाठी त्यांचा प्राधान्यक्रम लावला जातो. वास्तवात गरजांचे कारण अज्ञात नसते. परंतु इच्छा किंवा तृष्णेमुळे माणसाला त्याचे कारण कळत नाही. त्यामुळे तृष्णा हेच अज्ञानाचे व दुःखाचे कारण आहे असे दिसून येते. जगातील प्रत्येक गोष्टीमध्ये काही ना काही कारण असते. या तर्काच्या आधारावर बुद्ध माणसाला विवेक वादाकडे नेतात. त्यासाठी त्यांनी 'प्रतित्य समुत्पाद' हा सिद्धांत मांडला. विश्वातल्या प्रत्येक घटनेमागे कोणते तरी कारण असतेच. हा मुद्दा लक्षात घेऊन बुद्धाने दुःखाचे कारण शोधून काढले व त्यावर उपाय म्हणून आर्य अष्टांगिक मार्ग सुद्धा सांगितला. तोपर्यंत पूर्व जन्माच्या पापांचा परिणाम हेच कारण सांगितले जात असे.

मानवी गरजा नैसर्गिक असल्या तरी आर्थिक समस्या निर्माण होण्यासाठी कोणते तरी कारण असतेच. याचा विचार धम्मपदाच्या तेविसाव्या भागामध्ये आढळते. भूक किंवा तहान लागली तर ती स्वप्रयत्नाने भागवावी लागते. हा निसर्गाचा नियम आहे. परंतु माणूस हा सामाजिक प्राणी असल्यामुळे केवळ आपल्या वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक गरजांचा विचार करून चालत नाही. तर समाजाचा किंवा देशाचा विचार सुद्धा करावा लागतो. यातूनच अर्थशास्त्राचा जन्म होतो. मानवी इच्छा अमर्यादित असल्यामुळे त्यांचे प्राधान्य क्रमाने वर्गीकरण करण्याचे तंत्र बुद्धाने सांगितले. इच्छा वाढत गेल्याने गरजा भागल्या तरी तृष्णा संपत नाही आणि त्यातूनच संचय करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागते व समस्या निर्माण होतात. त्या सोडविण्याचे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र होय. अशी साधी व सोपी व्याख्या आहे. असा आर्थिक दृष्टीकोन बुद्धाच्या अर्थशास्त्रात मिळतो.

२. संपत्तीची निर्मिती - अन्न, वस्त्र निवारा व आरोग्य ह्या मनुष्याच्या मुलभूत गरजा भागविण्यासाठी संपत्तीची गरज भासते. आर्थिक स्थैर्य आणि देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक तीन बाबींची बुद्धाने व्याघ्र पज्ज सुत्तात चर्चा केली आहे. त्या तीन बाबी पुढीलप्रमाणे-

१. उत्थान संपदा (कुशल व प्रामाणिक प्रयत्नांद्वारे संपत्तीची निर्मिती)

२. आरक्ष संपदा (संपत्तीची सुरक्षा व बचत) आणि

३. समजिविकता (साधन संपत्तीच्या मर्यादित राहून जीवनयापन करणे)

संपत्तीच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देतांना बुद्ध प्रामुख्याने त्या काळात प्रचलीत सहा बाबींची चर्चा करतात.

१. शेती
२. व्यापार
३. पशुपालन
४. संरक्षण सेवा
५. शासकीय सेवा
६. व्यावसायिक सेवा

ह्या व्यवसायांच्या माध्यमातून संपत्ती अर्जित करण्याला बुद्धाने मान्यता दिलेली आहे. संपत्ती अर्जनाचे हे मार्ग समाजातील सर्व घटकांशी निगडीत आहेत. एवढेच नव्हे तर समाजाच्या प्रगतीला चालना देणारे आहेत. हे व्यवसाय करण्यासाठी वर्णाची किंवा जातीची कोणतीही अट नव्हती. कोणीही आपल्या योग्यतेनुसार कोणताही व्यवसाय करायला स्वतंत्र होता. परिणामी समाजाची झपाट्याने आर्थिक प्रगती होऊ लागली. बुद्धाच्या संपत्ती निर्मिती या क्रांतीकारी विचारामुळे आर्थिक भरभराट झाली.

३. संपत्तीचे समान वितरण — देशातील संपत्तीचे असमान वितरण हे सुद्धा बुद्धाच्या आर्थिक विचार प्रणालीत बसत नाही. आर्थिक विकासात जिथे उत्पादन हा एक महत्वपूर्ण भाग असतो, त्यापेक्षाही महत्वपूर्ण भाग असतो वितरण प्रणाली. आवश्यकतेपेक्षा अधिक संग्रह यामुळे आर्थिक संकट निर्माण होत असते. काही लोकांजवळ अपार धनसंपत्ती तर काहींच्या जीवनात अभाव हे त्यांना मान्य नव्हते. म्हणून गौतम बुद्धांनी संतुलीत वितरण प्रणालीवर भर दिला. त्यांच्या मते वितरण प्रणाली ठिक नसणे हे जसे आर्थिक हिनतेचे कारण आहे त्याचप्रमाणे अनावश्यक खर्च हे सुद्धा गरीबीचे फार मोठे कारण असते. तसेच दुसऱ्याच्या प्रती करुणा, मैत्री भावना नसणे हे सुद्धा आर्थिक असमानता वाढविण्यास कारणीभूत ठरत असतात. गौतम बुद्धांनी करुणा, मैत्री व त्यागाचा संदेश दिला. केवळ सर्व सामान्य व्यक्तित्व नाही तर सम्राट अशोकांनी त्यांच्या ह्या संदेशाला आत्मसात करून तत्कालीन समाजात समतेचा प्रसार केला.

नैसर्गिक संसाधनांचा अतिरेकी वापर करून मानवाचे आर्थिक शोषण केल्याने माणसात हिंसात्मक प्रवृत्ती निर्माण होते. परिणामतः देशाच्या सुरक्षेसाठी संरक्षणावरील खर्च वाढतो. त्यामुळे नैसर्गिक संसाधनांचा पर्याप्त उपयोग करण्याचा सल्ला बुद्धांच्या अर्थशास्त्रात आहे. आर्य अष्टांगिक मार्गामध्ये आठ सम्यक मार्गांचा उल्लेख आहे. या सम्यक आठ मार्गाने जीवन जगणे म्हणजे, बौद्ध अर्थशास्त्राचा स्वीकार केल्यास संपूर्ण जगातील प्रत्येक देशाचा व प्रत्येक व्यक्तीचा हमखास विकास होऊ शकते. यात शंका नसावी. याच दृष्टीने सम्राट अशोकाचे साम्राज्य हे लोक कल्याणकारी समजले जाते. समृद्धी, सौख्य, समाधान नांदत असल्यामुळे या देशाला 'सोने की चिडिया' असे संबोधले जात असे. या आर्थिक धोरणांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम, रुग्णालये, वसतीगृहे, उद्याने, विश्रामगृहे व निसर्गाचे जतन केले जात होते. त्यामुळे संपूर्ण जगात जम्बुद्विप प्रसिद्ध होता. त्यांच्या मते, जन्मतः सर्व मनुष्य मात्र समान असून त्या सर्वांना चांगले जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. समाजातील विशिष्ट घटकांनी सर्व सुखांचा उपभोग घ्यावा व काहींनी अतिशय अभावात जगावे हे त्यांना अमान्य होते. कारण हे निसर्ग निर्मित नसून मानव निर्मित समाज रचनेचे परिणाम होते. ते गौतम बुद्धांना अमान्य होते. जरी समाजात सर्व व्यक्ती एकाच प्रकारचे आयुष्य जगू शकत नाही हे बुद्धांना मान्य होते तरी एका घटकाने दुसऱ्या घटकाचे शोषण करावे हे त्यांना मान्य नव्हते. त्यामागे माणसाची अतिरेकी तृष्णा कारणीभूत होती. त्यामुळेच गौतम बुद्धांनी तृष्णेचा त्याग करायचा सांगितले.

४. संपत्तीचा विनियोग — मनुष्याने त्याच्या कुटुंबाच्या कल्याणाकरीता संपत्तीचा विनियोग कसा करावा याची तपशीलवार चर्चा पत्तकम्म सुत्तात आढळते.

१. अन्न, वस्त्र व अन्य गरजांवरील खर्च
२. आई वडील, पत्नी, मुले व नोकराच्या देखभालीचा खर्च
३. आजारपण व अन्य कठीण प्रसंगी करावयाचा खर्च
४. दान धर्म करण्यासाठी करावयाचा खर्च
५. राज्याचे कर वेळेवर भरणे
६. मृतांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ आवश्यक बाबींसाठी करावयाचा खर्च
७. नातेवाईकांसाठी करावयाचा खर्च

८. अभ्यागतांसाठी करावयाचा खर्च आदि बाबींचा यात प्रामुख्याने समावेश आहे.

खर्चाच्या तपशीलाकडे बारकाईने पाहिल्यास बुद्धाने समाज जीवनातील प्रत्येक बाबींचा विचार केल्याचे दिसते. समाजाचा गाडा योग्य पद्धतीने चालविण्यासाठी आवश्यक सर्व बाबी यात आढळतात. बुद्धाने केवळ आध्यात्मिक विकासाचाच नव्हे तर समाजाच्या दैनंदिन व्यावहारिक बाजूंचाही अतिशय सूक्ष्म रितीने विचार केला असल्याचे दिसून येते.

५. बचतीचे महत्व — बुद्धाने बचतीचा नेहमी पुरस्कार केला आहे. कारण बचतीमुळे देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळते. कर्माच्या माध्यमातून पैसा उभारण्याची प्रथा बुद्ध काळातही अस्तित्वात होती. बौद्ध साहित्यात बुद्ध काळातील अनाथपिण्डक आदि अनेक श्रेष्ठींचा उल्लेख आढळतो. हे श्रेष्ठी राज्यासोबतच सामान्य लोकांना देखील कर्ज उपलब्ध करीत असत. तथापि बुद्धाने अत्याधिक कर्ज काढण्याच्या प्रवृत्तीचा विरोध केला. कर्जमुक्त जीवन सुखकारक असल्यामुळे कर्जमुक्त समाज निर्मितीचा बुद्धाने पुरस्कार केला. बुद्ध एकांत जीवन जगणाऱ्या श्रमणाची तुलना सर्व प्रकारच्या कर्जातून मुक्त व बचतीतून स्वतःच्या कुटुंब व मुलांची योग्य पद्धतीने देखभाल करणाऱ्या व त्यातून आनंद प्राप्त करणाऱ्या सुखी व्यक्तीशी करतात. मिळकतीचा योग्य वापर आणि त्यातून करावयाच्या बचतीचे महत्व बुद्धाने सिंगालोवाद सुत्तात विषद केले आहे. सिंगाल (श्रृंगाल) नावाच्या गृहपती पुत्राला त्याच्या बचतीचे चार भाग करण्यास सांगितले. एक भाग त्याच्या व कुटुंबियांच्या दैनंदिन गरजांची पूर्तता करण्यासाठी, दोन भाग व्यापार उदिमात गुंतवणूक करण्यासाठी व चौथ्या भाग आणिबाणीच्या प्रसंगी खर्च करण्यासाठी राखून ठेवण्याचा सल्ला बुद्धाने दिला आहे.

६. सम्यक आजिविका — गौतम बुद्धानी आर्थिक समतेसंबंधी विचार मांडतांना त्यांनी वैयक्तिक साधन सामुग्रीच्या संग्रहाचा पूर्ण विरोध केला नाही. एका सीमेपर्यंत त्याची व्यक्तीला गरज भासू शकते हे ते मान्य करतात. मात्र सोबतच अतिरिक्त संग्रहाचा त्यांनी विरोध केला. यासाठी त्यांनी सम्यक उपजिविकेवर भर दिला. अर्थातच मानवाने सत्य मार्गाने, नीतीने, न्यायाने उपजिविका केली पाहिजे. असे त्यांना वाटत होते. त्यांनी लालसेने मिळविल्या जाणाऱ्या संपत्तीचा व त्यासाठी स्विकारलेल्या मार्गांचे विरोध केला. त्यांच्या मते, अशा मार्गामुळे मानवाची शोषणाची प्रवृत्ती वाढते. त्यामुळे आर्थिक असमानता निर्माण होते. ही आर्थिक असमानता दूर करण्यासाठी त्यांनी सम्यक उपजिविकेवर भर दिला. २ व्यक्ती जेव्हा जास्तीत जास्त भौतिक सुखाच्या मागे धावते तेव्हा तिला पुरेसे समाधान कधीच मिळत नाही. उलट अनेक आर्थिक प्रश्न निर्माण होतात व दुःखाचे प्रमाण वाढते. भौतिक सुखासाठी विविध वस्तूंचा उपभोग घेणे आवश्यक असते. म्हणजेच एक प्रकारे वासनांच्या आहारी जाणे होय. अशा प्रकारे वासनांमधून मिळणारे समाधान हानिकारक असू शकते. त्यामुळे खऱ्या सुख समाधानाचा त्याग करावा लागतो. म्हणून स्वतःच्या गरजा पूर्ण करतांना इतर

घटकांना (मनुष्य, पशु, पक्षी, सजीव आणि निसर्ग) हानी पोहचणार नाही हे मूळ तत्व लक्षात घेऊन सम्यक ज्ञानाने आयुष्य जगणे आवश्यक आहे यालाच 'सम्यक आजिविका' म्हटलेले आहे.

७. श्रम आणि कामगार कल्याण — भगवान बुद्ध सर्वात जास्त महत्वाचे स्थान श्रमाला देतात. कामगार लोकांचा ते सन्मान करीत असत. ते श्रमिक संस्कृतीचे होते. श्रमाचा अर्थच असा होतो की कोणाच्याही कृपेवर जीवन न जगता स्वतःच्या श्रमाद्वारे मुक्त अवस्थेपर्यंत पोहचणे होय. भगवान बुद्धांना शारीरिक श्रमाविषयी कोणत्याच प्रकारची अरुची नव्हती. त्यांनी शेतीला अमृत फलदायी म्हटले आहे. त्यांनी मानसिक आणि शारीरिक दोन्ही प्रकारच्या श्रमाला समान महत्त्व दिले आहे.

त्याकाळात कामगारांची अवस्था गुलामासारखी होती. कारण हा वर्ग शुद्र वर्णात मोडत असल्यामुळे सेवा करण्यासाठीच त्यांचा जन्म झाला आहे असा समज प्रचलित होता. संपत्ती निर्मितीत या वर्गाच्या श्रमाचे महत्वाचे योगदान असले तरी त्यांच्या सुखसोयीकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करण्यात येत होते. भगवान बुद्ध प्राचीन भारतातील पहिले विचारवंत होते ज्यांनी श्रमिक वर्गाच्या कल्याणाची काळजी घेण्याचे आवाहन केले. याविषयीचा उल्लेख दीघनिकायातील सिंगालोवाद सुत्तात आढळतो. या सुत्तात कामगार आणि मालक यांचे संबंध कसे असावेत विशेषतः कामगारांप्रति मालकाची जबाबदारी काय असावी या विषयी सांगतांना बुद्ध म्हणतात. १. मालकाने कामगारांच्या क्षमतेनुसार कामाचे वाटप करावे. २. कामगारांना पुरेसे वेतन व भोजन द्यावे. ३. श्रमिकांच्या आजारपणात त्यांची उचीत देखभाल करावी आणि ४. राजा व निवृत्तीचे फायदे वेळेवर द्यावे. या तरतूदीकडे पाहता बुद्धाची श्रमिकांविषयीची तळमळ आणि दुरदृष्टी लक्षात येते. आजच्या राज्यकर्त्यांना यातून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे.

८. बाजार रचना — भांडवलवादी आर्थिक विचारांनुसार उद्योजक, व्यापारी, विक्रेता जास्तीत जास्त नफा मिळविण्याचा प्रयत्न करतो. त्यात उपभोक्ता वा ग्राहकांचे हित, कल्याण नसते. परंतु बौद्ध अर्थशास्त्रानुसार अहिंसा या तत्वावर आधारीत बाजाराची रचना असावी. यामध्ये व्यापारी, विक्रेत्यांसोबत ग्राहकांचेही हित साधण्यावर भर दिला जातो. म्हणजेच इच्छेची तीव्रता कमी करण्याचा विचार बौद्ध अर्थशास्त्र सांगते.

बुद्धाच्या आर्थिक विचारसरणीनुसार अधिकाधिक समाधान मिळविण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करतांना कष्टाची तीव्रता वाढत जाते. परंतु इच्छांची तीव्रता कमी असल्यास पर्याप्त समाधान प्राप्त होऊ शकते. आयात-निर्यातीमुळे खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारणे हे आपल्या खुल्या अर्थव्यवस्थेचे धोरण आहे. मात्र भौतिक वस्तूंचा उपयोग मर्यादित ठेवला, तर देशातच स्थानिक आवश्यक वस्तू निर्माण करून विदेशी वस्तूवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.

९. संघाची संकल्पना — जेव्हा माणूस समुहाने राहतो तेव्हा निर्माण होणाऱ्या समस्या व्यक्तिगत वा कौटुंबिक न राहता त्यांचे स्वरूप सामाजिक बनते. म्हणूनच बुद्धाने व्यक्तिगत समस्येबरोबर समाजाच्या समस्यांचा विचार करून संघाची संकल्पना मांडली. संघाची स्थापना करून सामुहिक प्रयत्नातून समाजाच्या गरजा व समस्या दूर कराव्यात असे बुद्धांचे अर्थशास्त्र सांगते. बुद्धांच्या आर्थिक व्यवस्थेचा विचार मानवी जीवनातील सहकारी आणि सुसंवादी प्रयत्नांच्या विकासाचा पाया आहे. स्वतःचा विकास करून आत्मनिर्भरता प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न करण्यास बुद्धांचा विचार उपयुक्त आहे.

असा बुद्धांच्या अर्थशास्त्राविषयीचा विचार श्रीलंकेच्या अर्थतज्ञ नेव्हल करुणा तिलके मांडतात. इ. स. १९७२ पासून भूतानचा राजा जिग्मे सिंग्ये वांगचुक आणि त्यांच्या सरकारने बुद्धांच्या तत्वज्ञानावर आधारित 'सकल राष्ट्रीय आनंद निर्देशांक' ही संकल्पना स्वीकारून त्यांचा देशाच्या विकासाचा आढावा घेण्यासाठी

उपयोग केला. अमेरिकेतील क्लेअर ब्राउन या अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापिकेने सुद्धा बुद्धाच्या या मानवी विकासाच्या आर्थिक विचारांना अर्थव्यवस्थेच्या चौकटीत बसवून पर्यावरणाचे संरक्षण व उच्च दर्जाचे समाज जीवन कसे असावे यासाठी बुद्धाच्या मध्यम मार्गास महत्व दिले. इतकेच नव्हे तर नोबल पुरस्कार प्राप्त करणारे भारतीय अर्थतज्ञ अमर्त्य सेन यांनी देखील व्यक्तीचा व राष्ट्राचा विकास करण्यासाठी बुद्धाच्या मार्गाचा अवलंब करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.

१०. अपराधमुक्त समाजनिर्मिती – मनुष्याने आपल्या दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी संपत्ती मिळविण्यात काही आक्षेपार्ह नाही. मात्र अनाठायी संपत्ती संचय करण्याच्या प्रवृत्तीचे गुलाम बनता कामा नये. असा इशारा बुद्धाने दिला आहे. कारण असे करणे मनुष्याच्या भौतिक व मानसिक सुखासाठी घातक आहे. एखाद्या व्यक्तीकडे आवश्यकतेपेक्षा जास्त साधन संपत्ती असल्यास स्वतःच्या कुटुंबाबरोबरच अन्य नातेवाईक व मित्र आणि गरजूंना मदत केल्यास व्यक्तीच्या आर्थिक समाधानाबरोबरच समाजाच्या नैतिक व अध्यात्मिक विकासाला हातभार लागतो. संपत्तीचे समन्यायी वाटप, सुयोग्य नियोजन व गुंतवणुकीमुळे शांती आणि प्रगतीबरोबरच अपराध मुक्त समाज निर्मितीची चर्चा कूटदन्त सुत्तात आढळते.

११. शिक्षणाचा पुरस्कार – मनुष्याच्या सामाजिक व आर्थिक विकासात शिक्षणाचे महत्व अनन्य साधारण आहे. शिक्षणाशिवाय ते स्वतःची भौतिक व अध्यात्मिक प्रगती करू शकत नाही. समाजाच्या प्रगतीसाठी व शांततामय सहजीवनासाठी शिक्षण हे महत्वाचे साधन आहे. शिक्षणामुळे वैचारिक शक्ती प्रगल्भ होते. समाजाच्या निकोप वाढीसाठी व आर्थिक विकासासाठी शिक्षण अत्यावश्यक असल्याने बुद्धाने सार्वत्रिक शिक्षणाचा पुरस्कार केला. लोहिच्य सुत्तामध्ये बुद्ध आणि लोहिच्य यांच्यामध्ये जो संवाद झाला त्यावरून ही बाब स्पष्ट होते. मनुष्याने शैक्षणिकदृष्ट्या बहुश्रुत होण्याची सूचना बुद्धाने केलेली आहे. या बाबतचा उल्लेख सुत्तनिपातातील महामङ्गल सुत्तात आढळतो. यामध्ये प्रामुख्याने तीन बाबींचा उल्लेख आहे. यात यशस्वी उद्योग करण्यासाठी यासंबंधातील पहिली बाब म्हणजे सर्वसामान्य शिक्षण (बहुश्रुत होणे) आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. दुसरी बाब म्हणजे उद्योग किंवा व्यापार करण्यासाठी त्यातील कौशल्य प्राप्त करणे आणि तिसरा व तेवढाच महत्वाचा मुद्दा म्हणजे हे सर्व यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी उच्च प्रतीची मानसिक एकाग्रता अत्यंत गरजेची असल्याचे प्रतिपादन बुद्धाने केले आहे.

यावरून बुद्धाचे अर्थशास्त्र हे वैज्ञानिक ज्ञानाच्या चौकटीवर आधारलेले असून वैयक्तिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय क्षमतेच्या सामान्य उद्दिष्टांपर्यंत पोहचण्यासाठी बुद्धाचे अर्थशास्त्र मार्गदर्शन करते असे म्हणता येईल. मानवाच्या आर्थिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी बुद्धाचे अर्थशास्त्र उपयुक्त असून त्याचा आर्थिक दृष्टीने विचार होणे गरजेचे आहे. कारण पाश्चात्य आर्थिक विचार भौतिक साधन—संपत्तीला अधिक महत्व देते. परंतु भौतिक संपत्ती लालसा व इच्छेला उत्तेजन देते त्यामुळे लोक आपल्या गरजा व इच्छा पूर्ण करण्यासाठी, भरपूर पैसा मिळविण्यासाठी संपूर्ण जीवनभर धडपडत असतात. परंतु बौद्धांच्या अर्थशास्त्रात यालाच दुःखचे कारण म्हटले आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य व शिक्षण या सारख्या मुलभूत गरजांची पूर्तता करण्यासाठी इतर भौतिकवादी इच्छा कमी करणे आवश्यक आहे.

प्रस्तूत शोधनिबंधात मानव विकासाच्या व आर्थिक विकासाच्या दिशेने योग्य वाटचाल करण्यासाठी गौतम बुद्धांचे सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाचे विचार कसे उपयुक्त आहे. हें स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. त्यांनी मानवी, आर्थिक व सामाजिक समतेसाठी अशा सिद्धांताचे प्रतिपादन केले की जे आजही मानवतेच्या व आर्थिक विकासाच्या दृष्टीनेच नाही तर सर्वसमावेशक विकासाच्या दृष्टीनेही

वाटचाल करण्यासाठी उपयुक्त आहेत. त्यांच्या ह्या सिद्धांताचे पालन केल्यास समाजात स्वातंत्र्य, आर्थिक व सामाजिक समता, न्याय, बंधुभाव प्रस्थापित होऊ शकेल.

निष्कर्ष - भगवान बुद्धाने आपले सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाचे विचार चक्कवल्ली सिंहनाद सुत्त आणि कुट्टन्त सुत्त यामध्य व्यक्त केले आहे. त्यांनी चोरी, हिंसा, घृणा, निर्दयता यासारख्या गुन्ह्यामुळे व अनैतिक कार्यामुळे दारिद्र्यता येते असे सांगितले आहे. अशा गुन्हेगारांना आपण शिक्षा देऊन थांबवू शकत नाही. माणसाची भूकेमुळे आनंद, शांती, स्वास्थ्य समाप्त होते. त्यासाठी अशी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे की ज्यामुळे जगात एकही व्यक्ती उपाशी राहणार नाही. तसेच राज्याची अर्थव्यवस्था आणि न्यायप्रणालीमध्ये सुधारणा केली पाहिजे. शिक्षा देऊन तुरुंगात ठेऊन शारीरिक दंड देऊन गुन्हेगारांवर नियंत्रण ठेऊ शकत नाही. गुन्हेगारी व हिंसा दारिद्र्याचे स्वाभाविक परिणाम आहेत. आज भारतात अनेक भागात हिंसा आणि आतंकवाद वाढतांना दिसत आहे. तेव्हा बुद्धांनी दिलेला कुट्टन्तामधला उपदेश अधिक प्रासंगिक ठरतो. आज जगात आर्थिक असमानता वाढत आहे. आर्थिक साम्राज्य वादाचा उदय होत आहे. शक्तीशाली देश कमजोर देशांवर वर्चस्व प्रस्थापित करीत आहेत. राजकीय नियमांचे पालन होत नाही. कलह वाढत आहे. संयुक्त परिवार विभक्त होत आहेत. वृद्ध आणि शक्तीहीन किंवा गरीब लोकांच्या प्रती उपेक्षांच्या भावना वाढत आहे. अशा परिस्थितीत भगवान बुद्धाचे अर्थशास्त्र अधिक प्रासंगिक वाटते.

संदर्भसूची

१. जाटव डी. आर. (चतुर्थ संस्करण, २००३): भगवान बुद्ध और कार्ल मार्क्स, समता साहित्य सदन, पृ. ६१, ६२.
२. भन्ते संघ रक्षित (१९७३): बुद्ध धम्म के दस आधार स्तंभ. अनुवादक श्रामणेस विमल किर्ती भिक्खू, पृ. ७६
३. पगारे हरिभाऊ (जुलै, १९७०): बौद्ध धर्म मार्गदिप, मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई, प्रथम आवृत्ती. पृ. ४९
४. जाटव डी. आर. (चतुर्थ संस्करण, २००३): भगवान बुद्ध और कार्ल मार्क्स, समता साहित्य सदन, पृ. ११३, ११७.
५. गौतम मुंशीलाल (२००८): बुद्धाचा मानवतेला संदेश, सिध्दार्थ गौतम शिक्षण व संस्कृती समिती, धनसारी अलिंगड, दुसरी आवृत्ती.
६. कौशल्यायन भदन्त आनंद (१९९३): धम्मपद, भिक्खुवग्गो, गाथा ७, प्रकाशक बुद्ध भुमी प्रकाशन, नागपूर. पृ. क्र. ८६
७. कवि माधवी (२००७): तुलनात्मक धर्म, विद्या प्रकाशन, नागपूर, जानेवारी. पृ. क्र. ५६.
८. जाधव राजा (२००५): डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि बुद्ध धम्म सम्यक आकलनाची दिशा पृ. क्र. ९०, संदेश प्रकाशन, नागपूर.
९. जीवने रमेश (२००१): जात्यंतिक आर्थिक क्रांतीची दिशा, प्रकाशक फुले आंबेडकर धम्म साहित्य संस्कृती महासभा यवतमाळ.पृ.क्र. ९.
१०. मासिक लोकराज्य (ऑक्टोबर २००६): महाराष्ट्र शासन, धम्म दिक्षा विशेषांक, पृ. क्र. १२२.

प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे

विभागप्रमुख, अर्थशास्त्र

डॉ. एम. डब्ल्यू. पी. डब्ल्यू. एस. कला,
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, नागपूर.